भारतीय रिज़र्व बैंक

बुलेटिन

फरवरी 2022

खंड 76 अंक 2

अध्यक्ष
माइकल देबब्रत पात्र

संपादन समिति
अजित आर. जोशी
देब प्रसाद रथ
राजीव रंजन
सितिकंठ पट्टनायक
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवाडकर
तुषार बरन दास
पुलस्त्या बंद्योपाध्याय

संपादक
शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के
निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा
मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है।
इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए
बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है।
हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए
लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2022

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
https://bulletin.rbi.org.in पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य 1

2021 – 22 के लिए मौद्रिक नीति वक्तव्य

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संलल्प,
8-10 फरवरी 2022 7

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य 11

भाषण

आरबीआई की महामारी पर कार्रवाई : विस्मृति से बाहर आना –
माइकल देबब्रत पात्र 15

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति 23

जॉम्बी और सृजनात्मक विध्वंस की प्रक्रिया 53

मददगार के रूप में बैड बैंक :
भारत के लिए विभिन्न देशों के अनुभवों से सीख 67

भारतीय विनिर्माताओं के रुख पर कोविड-19 का प्रभाव 79

वर्तमान सांख्यिकी **95**

हाल के प्रकाशन **142**

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य

*गवर्नर का वक्तव्य**

शक्तिकांत दास

मेरा यह कथन है कि, महामारी ने एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बना लिया है। कमी के संकेतों के बावजूद, कई देशों में दैनिक संक्रमणों की रिकॉर्ड संख्या और परिणामी रोकथाम के उपाय आर्थिक गतिविधियों की गति को प्रभावित कर रहे हैं, विशेष रूप से संपर्क-गहन क्षेत्रों में, यहां तक कि आपूर्ति में व्यवधान जारी है और प्रतिबंधित कार्यबल की भागीदारी श्रम बाजारों को सख्त करती है। कई देशों में मुद्रास्फीति बहु-दशक के उच्च स्तर पर है, विभिन्न मौद्रिक नीति इरादों और कार्यों द्वारा विकसित समष्टि आर्थिक वातावरण को अत्यधिक अनिश्चित बना दिया जा रहा है। वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव दृष्टिकोण में द्विपक्षीयता की परतें जोड़ रहे हैं।

कोविड-19 के ओमिक्रोन वेरियंट द्वारा संचालित एक अत्यधिक संक्रामक तीसरी लहर के बावजूद, भारत शेष दुनिया से बहाली का एक अलग पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार, भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष-दर-वर्ष सबसे तेज गति से बढ़ने की ओर अग्रसर है। यह बहाली बड़े पैमाने पर टीकाकरण और निरंतर वित्तीय और मौद्रिक समर्थन द्वारा समर्थित है। एक बार फिर, हमारे अग्रिम पंक्ति के योद्धा सराहनीय रूप से कर्तव्य की ओर अग्रसर हुए हैं।

जैसे-जैसे हम महामारी की बार-बार लहरों से मूल्यवान अनुभव प्राप्त करते हैं, वैसे-वैसे हमारी प्रतिक्रियाएँ भी सूक्ष्म और अंशशोधित होती जा रही हैं। जीवन की रक्षा करना सर्वोपरि है; और आजीविका की रक्षा प्राथमिकताओं के पदानुक्रम में बढ़ रही है। कमजोर लोगों, वेतन पाने वालों और सबसे अधिक पीड़ित लोगों की आर्थिक और वित्तीय स्थितियों को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तदनुसार, लक्षित रोकथाम रणनीतियों पर जोर दिया जा रहा है और सार्वभौमिक टीकाकरण और बूस्टर खुराक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दृष्टिकोण को हमारे कार्यस्थलों और हमारे दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से पूरक के रूप में लिया जा रहा है। ये प्रयास आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान की सीमा को सीमित करने के लिए किया जा रहा है।

मौद्रिक नीति समिति के विचार-विमर्श

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 8, 9 और 10 फरवरी 2022 को हुई और वर्तमान समष्टिआर्थिक स्थिति और संभावनाओं के आकलन के आधार पर, इसने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया। एमपीसी ने 5 से 1 के बहुमत से निर्णय लिया कि यह सुनिश्चित करते हुए कि आगे चलकर मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, और टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को पुनर्जीवित करने और उसे बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाया रखा जाए। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही है। रिवर्स रेपो दर भी 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

एमपीसी ने अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रोन वेरियंट से आर्थिक गतिविधियों के लिए संभावित नकारात्मक जोखिमों को चिह्नित किया। आश्वस्त रूप से, लक्षण अपेक्षाकृत हल्के बने हुए हैं और संक्रमण की गति जितनी तेज़ी से बढ़ी है, उतनी ही तेज़ी से कम हो रही है। हालांकि, आर्थिक गतिविधियों की गति में कुछ कमी आई है, जो उच्च आवृत्ति संकेतकों में परिलक्षित होता है, जैसे कि विनिर्माण और सेवाओं दोनों के लिए क्रय प्रबंधकों के सूचकांक, तैयार स्टील की खपत और ट्रैक्टरों, दोपहिया और यात्री वाहनों की बिक्री। संपर्क-गहन सेवाओं की मांग अभी भी कम है। आगे बढ़ते हुए, रबी की उछाल भरी संभावनाओं, मजबूत निर्यात मांग, निभावकारी मौद्रिक और तरलता की स्थिति, ऋण उठाव में सुधार, और केंद्रीय बजट 2022-23 में पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे पर निरंतर दबाव से बहाली की गति को तेज करने के लिए सकारात्मक आवेग उत्पन्न हो रहे हैं।

एमपीसी ने यह भी नोट किया कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अपनी पिछली बैठक के बाद से अधिक बढ़ी है, लेकिन मोटे तौर पर प्रत्याशित सीमा के साथ। दिसंबर में मुद्रास्फीति में वृद्धि पूरी तरह से कीमतों में महीने-दर-महीने गिरावट के बावजूद प्रतिकूल

* गवर्नर का वक्तव्य - 10 फरवरी 2022

आधार प्रभावों के कारण हुई थी। अनाज के बड़े बफर स्टॉक और प्रभावी आपूर्ति पक्ष उपाय, खाद्य मुद्रास्फीति के लिए शुभ संकेत हैं। मुख्य मुद्रास्फीति ऊंची बनी हुई है, लेकिन मांग-प्रेरित दबाव अभी भी कम है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में नए सिरे से उछाल पर कड़ी निगरानी की जरूरत है।

समग्र रूप से, हेडलाइन मुद्रास्फीति क्यू4:2021-22 में सहिष्णुता बैंड के भीतर चरम पर होने की उम्मीद है और फिर एच2:2022-23 में लक्ष्य के करीब मध्यम, तथा मौद्रिक नीति को समायोजित रहने के लिए जगह प्रदान करता है। इसी समय, उत्पादन अपने पूर्व-महामारी स्तर से मुश्किल से ऊपर है, जबकि निजी खपत अभी भी पिछड़ रही है। वैश्विक हेडविंड जोर दे रहे हैं। कुल मिलाकर, मुद्रास्फीति और विकास की संभावनाएं, विशेष रूप से मुद्रास्फीति संभावना में सुधार, ओमिक्रोन और वैश्विक स्पिलओवर से संबंधित अनिश्चितताओं द्वारा प्रदान की गई सुविधा को ध्यान में रखते हुए, एमपीसी का विचार था कि निरंतर नीति समर्थन एक टिकाऊ और व्यापक- आधारित बहाली की आवश्यकता है।

घरेलू वृद्धि

भारत में, 2021-22 के लिए 9.2 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि इसे 2019-20 में जीडीपी के स्तर से मामूली रूप से ऊपर ले जाती है। निजी खपत, घरेलू मांग का मुख्य आधार, अपने पूर्व-महामारी स्तर को पीछे छोड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों में लगातार वृद्धि, वैश्विक वित्तीय बाजारों की अस्थिरता में वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति बाधाओं से संभावना के लिए जोखिम बढ़ सकता है।

भविष्य में, पूंजीगत व्यय और निर्यात पर सरकार के जोर से उत्पादक क्षमता में वृद्धि और कुल मांग को मजबूत करने की उम्मीद है। इससे निजी निवेश में भी भीड़ होगी। आरबीआई की नीतिगत कार्रवाइयों से उत्पन्न अनुकूल वित्तीय स्थितियां निवेश गतिविधि को गति प्रदान करेंगी। आरबीआई द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि क्षमता उपयोग बढ़ रहा है, और व्यापार और उपभोक्ता विश्वास पर दृष्टिकोण आशावादी क्षेत्र में बना हुआ है, जिससे निवेश के साथ-साथ खपत की मांग का समर्थन प्राप्त होगा । सर्दियों की फसल की बुआई की अच्छी प्रगति से कृषि की संभावनाएं उज्ज्वल हुई हैं।

कुल मिलाकर, निकट अवधि की वृद्धि की गति में कुछ कमी आई है जबकि वैश्विक कारक प्रतिकूल हो रहे हैं। आगे देखते हुए, घरेलू वृद्धि चालकों में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2022-23 के लिए 7.8 प्रतिशत, क्यू1: 2022-23 में 17.2 प्रतिशत ; क्यू2 में 7.0 प्रतिशत ; क्यू3 में 4.3 प्रतिशत ; और क्यू4 में 4.5 प्रतिशत पर अनुमानित है।

मुद्रास्फीति

सीपीआई मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र हमारे अनुमानों के साथ निकट संरेखण में चला गया है। खासतौर पर, खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी से काफी राहत मिल रही है। खाद्यान्न उत्पादन में सुधार की संभावनाओं और सर्दियों की ताजा फसल की आवक पर सब्जियों की कीमतों में गिरावट की उम्मीद से आशावाद और बढ़ रहा है। इसके अलावा, सरकार द्वारा मजबूत आपूर्ति पक्ष हस्तक्षेप और घरेलू उत्पादन में वृद्धि के कारण दालों और खाद्य तेल की कीमतों में नरमी जारी रहने की संभावना है।

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होना, हालांकि, मुद्रास्फीति संभावनाओं के लिए एक बड़ा अपसाइड जोखिम प्रस्तुत करता है। मुख्य मुद्रास्फीति सहनशीलता परीक्षण स्तरों पर उच्च बनी हुई है, हालांकि पिछले नवंबर में पेट्रोल और डीजल से संबंधित कर कटौती के निरंतर पारित होने से कुछ हद तक इनपुट लागत दबावों को कम करने में मदद मिलेगी। मांग में निरंतर कमी को देखते हुए बिक्री मूल्य पर इनपुट लागत दबावों का प्रसार कम रहा। इसके अलावा, जैसे-जैसे ओमिक्रोन जोखिम के घटने और आपूर्ति श्रृंखला के दबाव में कमी आती है, मुख्य मुद्रास्फीति में कुछ नरमी आ सकती है। शेष राशि पर, प्रतिकूल आधार प्रभावों के कारण जो बाद में नरम हो गया ति4 को 5.7 के साथ, 2021-22 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान 5.3 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। विशेष रूप से, प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण जनवरी 2022 के लिए सीपीआई रीडिंग ऊपरी सहनशीलता बैंड के करीब जाने की उम्मीद है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए और सामान्य मानसून की धारणा पर, व्यापक रूप से संतुलित जोखिमों के

साथ, 2022-23 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत, 2022-23 के ति1 में 4.9 प्रतिशत; ति2 में 5.0 प्रतिशत; ति3 में 4.0 प्रतिशत और ति4 में 4.2 प्रतिशत पर अनुमानित है।

वर्तमान समय में, घरेलू मौद्रिक नीति का संचालन मुख्य रूप से उभरती मुद्रास्फीति और विकास की गतिकी के अनुरूप है, भले ही हम अनिश्चित वैश्विक विकास और भिन्न मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाओं के स्पिलओवर के प्रति सतर्क हैं। हमारी मौद्रिक नीति मध्यम अवधि में मूल्य स्थिरता के अपने प्राथमिक जनादेश द्वारा निर्देशित होती रहेगी, साथ ही एक मजबूत और निरंतर आर्थिक बहाली भी सुनिश्चित करेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमारे कार्यों को सुविचारित और अच्छी तरह से संदेशित किया जाएगा।

वित्तीय स्थिरता

एक मजबूत और अच्छी तरह से काम करने वाला वित्तीय क्षेत्र संवृद्धि और विकास की नींव को मजबूत करता है। रिज़र्व बैंक ने चलनिधि की कमी को कम करने, बाज़ार में विश्वास बहाल करने और वित्तीय बाज़ार के अन्य क्षेत्रों में संक्रामक को रोकने के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाकर वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हम बैंकिंग और गैर-बैंक वित्तीय दोनों क्षेत्रों के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को भी मजबूत कर रहे हैं ताकि कमजोरियों की पहचान, आकलन और निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम किया जा सके।

इस प्रकार, महामारी से प्रेरित अस्थिरता के बावजूद, भारतीय वित्तीय प्रणाली लचीली बनी हुई है और अब जैसे ही बहाली जोर पकड़ेगी और निवेश गतिविधि तेज होंगी ऋण मांगों को पूरा करने के लिए एक बेहतर स्थिति में है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का तुलन-पत्र पिछले वर्षों की तुलना में उच्च पूंजी पर्याप्तता, एनपीए में कमी, उच्च प्रावधानीकरण कवर और बेहतर लाभप्रदता के साथ अपेक्षाकृत मजबूत हैं।

हालांकि, हमें, बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्रों पर महामारी के प्रभाव के प्रति सतर्क रहना होगा जब विनियामक राहतों और समाधानों के प्रभाव पूरी तरह से काम करेंगे। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाएगा कि वे तेजी से गतिशील और अनिश्चित आर्थिक परिस्थिति में लचीलापन बनाने के लिए अपने कॉर्पोरेट सुशासन और जोखिम प्रबंधन कार्यनीतियों को और मजबूत करें। उन्हें पूंजी वृद्धि और उपयुक्त बफर के निर्माण की प्रक्रिया को जारी रखने की भी आवश्यकता है।

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति

महामारी ने सदी का संकट दिया है, जिसमें स्वास्थ्य आघात एक व्यापक आर्थिक और वित्तीय झटके में बदल गया है। ऐसी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए आरबीआई ने कई उपाय किए। नतीजतन, उधार लेने की लागत दशकों में अपने सबसे निचले स्तर तक गिर गई और स्प्रेड सभी रेटिंग एजेंसियों में संकुचित हो गई। सरकारी प्रतिभूतियों, कॉरपोरेट बॉन्ड और डिबेंचर के रिकॉर्ड स्तर जारी किए गए। कॉरपोरेट संस्थाएं लाभप्रदता में सुधार करते हुए और भविष्य के कैपेक्स के आय को बरकरार रखते हुए उच्च लागत वाले ऋण को मूल रूप से डिलीवरेज करने और उसे कम करने में सक्षम रही हैं। कुल मिलाकर, वित्तीय क्षेत्र पूरी तरह से कार्यरत रही और बहाली की प्रक्रिया को सहारा दिया है। हमारे आकलन में, भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत कार्रवाइयों ने एक सहज और व्यवस्थित तरीके से वांछित परिणाम प्राप्त किए हैं।

इन उद्देश्यों को निरंतर आधार पर प्राप्त करने के साथ, रिज़र्व बैंक ने अपने निभावकारी रुख के समर्थन में पर्याप्त चलनिधि बनाए रखते हुए, गतिशील आधार पर चलनिधि को पुनर्संतुलित करने की ओर रुख किया है। इस पुनर्संतुलन में दो-तरफा परिचालन शामिल हैं: पहला, मुख्य परिचालन के रूप में 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी की ओर से एक रात्रिय (ओवरनाइट) स्थायी दर प्रतिवर्ती रेपो से चलनिधि को पुनर्संतुलित करना, जो फरवरी 2020 के संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे में परिकल्पित विभिन्न अवधियों की परिष्करण नीलामियों द्वारा समर्थित है; और दूसरा, अल्पकालिक चलनिधि बेमेल और कमी को पूरा करने के लिए 1-3 दिन की परिपक्वता की रेपो नीलामी आयोजित करना, उदाहरण के लिए जनवरी 2022 के तीसरे सप्ताह के दौरान उम्मीद से अधिक जीएसटी बहिर्वाह के हालिया मामले में। प्रभावी चलनिधि प्रबंधन की कुंजी 'समय' और एक सूक्ष्म और फुर्तीला दृष्टिकोण है जो

जिस तरीके से तरलता झुकती है उस तरीके से तेजी से प्रतिक्रिया करता है।

आरबीआई के पुनर्संतुलन परिचालन के परिणामस्वरूप, अगस्त 2021 में पुनर्संतुलन शुरू होने के बाद से स्थायी दर रिवर्स रेपो के तहत दैनिक औसत अवशोषण में तेजी से कमी आई है। हालाँकि, इसी अवधि में कम होने के बावजूद समग्र प्रणाली चलनिधि, बड़े अधिशेष में बनी हुई है। ओवरनाइट विंडो से दीर्घावधि के लिए अधिशेष चलनिधि के माइग्रेशन को दर्शाते हुए, प्रभावी प्रतिवर्ती रेपो दर – स्थायी दर प्रतिवर्ती रेपो की भारित औसत दर और लंबी परिपक्वता के वीआरआरआर - अगस्त 2021 के अंत में 3.37 प्रतिशत से बढ़कर 4 फरवरी 2022 तक 3.87 प्रतिशत हो गई।

यह विदित है कि 6 फरवरी 2020 को संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को जारी करते समय, दैनिक स्थायी दर रेपो और एक रिपोर्टिंग पखवाड़े के भीतर चार 14-दिवसीय मियादी रेपो को वापस ले लिया गया था। महामारी और संबंधित वर्क फ्रॉम होम और सामाजिक दूरी प्रोटोकॉल के मद्देनजर, एमएसएफ और स्थायी दर प्रतिवर्ती रेपो विंडो को सामान्य परिस्थितियों में केवल दिवसांत के बजाय पूरे दिन चालू किया गया था। चलनिधि प्रबंधन के इस निष्क्रिय तरीके ने महामारी की स्थिति में बेहतर काम किया ताकि बाजार की उभरती परिस्थितियों के अनुसार चलनिधि के पर्याप्त प्रावधान/अवशोषण को सुनिश्चित किया जा सके।

आरबीआई से चलनिधि की अल्पकालिक मांग सहित सामान्य स्थिति की प्रगतिशील वापसी के साथ, संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को और अधिक लचीला और दक्ष बनाने के लिए इसे बहाल करना तर्कसंगत है। तदनुसार, चार निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले, विभिन्न अवधियों के परिवर्तनीय दर रेपो परिचालन अब से नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) रखरखाव चक्र के भीतर विकसित चलनिधि और वित्तीय स्थितियों द्वारा आवश्यक होने पर आयोजित किए जाएंगे। दूसरा, 14 दिनों की अवधि के परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) और परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) चलनिधि की स्थिति के आधार पर मुख्य चलनिधि प्रबंधन उपकरण के रूप में काम करेंगे और सीआरआर रखरखाव चक्र के साथ मेल खाने के लिए आयोजित किए जाएंगे। तीसरा, इन मुख्य परिचालनों को आरक्षित रखरखाव अवधि के दौरान किसी भी अप्रत्याशित चलनिधि परिवर्तन से निपटने के लिए विशेष परिचालन द्वारा समर्थित किया जाएगा। लंबी परिपक्वता की नीलामी भी आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जाएगी। चौथा, 1 मार्च 2022 से, स्थायी दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ परिचालन सभी दिन केवल 17.30-23.59 घंटों के दौरान उपलब्ध होंगे, न कि 09.00-23.59 घंटों के दौरान, जैसा कि 30 मार्च 2020 को महामारी की स्थिति से निपटने के लिए लागू किया गया था। बाजार सहभागियों को सूचित किया जाता है कि वे शेष राशि को स्थायी दर प्रतिवर्ती रेपो से वीआरआरआर नीलामियों में अंतरित करें और परिचालन सुविधा के लिए ई-कुबेर पोर्टल में स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा का लाभ उठाएं[1]।

विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपये (आईएनआर) ने वैश्विक स्पिलओवर के बावजूद, उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों की तुलना में भी लचीलापन दिखाया है। उच्च विदेशी मुद्रा भंडार बफर और चालू खाता घाटे (सीएडी) के मामूली स्तर ने भारत की बाह्य क्षेत्र की स्थिरता को सहारा दिया है। 2021-22 की पहली छमाही में, सीएडी सकल घरेलू उत्पाद का 0.2 प्रतिशत था, जो वस्तुओं और सेवाओं के मजबूत निर्यात पर आश्रित था। कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों और घरेलू आर्थिक सुधार के अनुरूप गैर-तेल आयात में वृद्धि के कारण हाल के महीनों में माल व्यापार घाटा बढ़ गया है। हालांकि, आगे बढ़ने की मजबूत संभावनाओं के साथ आईटी सेवाओं के नेतृत्व में सेवाओं के उत्साहजनक निर्यात के कारण 2021-22 के दौरान सीएडी के सकल घरेलू उत्पाद के 2.0 प्रतिशत से नीचे बने रहने की संभावना है। इसके अलावा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह मजबूत बना हुआ है, जिनसे पूंजी प्रवाह के अन्य रूपों के साथ, सीएडी के इस मामूली स्तर को सहजता से वित्त पोषित करने की उम्मीद है।

[1] बैंकों को अपने दिन के अंत में सीआरआर शेष के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, आरबीआई ने अगस्त 2020 में एक वैकल्पिक स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रदान की है जिसके तहत बैंक एक विशिष्ट (या सीमा) राशि को पूर्व-निर्धारित करने में सक्षम हैं, जिसे वे दिन के अंत में बनाए रखना चाहते हैं। बैंकों द्वारा बनाए रखे गए किसी भी कमी या अतिरिक्त शेष राशि, एएसआईएसओ सुविधा के तहत सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) या रिवर्स रेपो बोलियां, जैसा भी मामला हो, को स्वचालित रूप से ट्रिगर करेगा।

मौद्रिक नीति के भिन्न रुख, भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों और लगातार आपूर्ति बाधाओं के कारण अत्यधिक अस्थिर और अनिश्चित वैश्विक वातावरण में, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं निरंतर आधार पर अस्थिर वैश्विक स्पिलओवर के प्रति संवेदनशील हैं। इस प्रकार, भले ही महामारी से उबरना अधूरा है, नीति निर्माताओं को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपनी ओर से, रिज़र्व बैंक इन स्पिलओवरों से घरेलू अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों को अलग करता रहा है और करता रहेगा। इसके अलावा, जबकि आरबीआई सरकारी उधार कार्यक्रम को सुचारू रूप से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा, बाजार सहभागियों की वित्तीय स्थितियों के व्यवस्थित विकास और प्रतिफल वक्र में भी हिस्सेदारी होती है। यह उम्मीद की जाती है कि बाजार सहभागी जिम्मेदारी के साथ शामिल होंगे और सहकारी परिणामों में योगदान देंगे जो सभी को लाभान्वित होगा।

अतिरिक्त उपाय

हमारे निरंतर मूल्यांकन के आधार पर कुछ अतिरिक्त उपायों की भी आज घोषणा की जा रही है। इन उपायों का विवरण मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और नियामक नीतियों (भाग-बी) पर वक्तव्य में निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उपाय निम्नानुसार हैं:

आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए ऑन-टैप चलनिधि सुविधाओं को बढ़ाना

आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए क्रमशः ₹50,000 करोड़ और ₹15,000 करोड़ की ऑन-टैप चलनिधि सुविधाओं की घोषणा मई और जून 2021 में महामारी की दूसरी लहर के दौरान की गई थी। बैंकों को दो योजनाओं के तहत उधार देने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए गए थे। तीसरी लहर द्वारा लाई गई निरंतर अनिश्चितताओं के कारण, दोनों योजनाओं को 31 मार्च 2022 से 30 जून 2022 तक बढ़ाया जा रहा है।

स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) - सीमाओं में वृद्धि

स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) योजना मार्च 2019 में सरकार और कॉरपोरेट्स द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा दीर्घकालिक निवेश की सुविधा के लिए शुरू की गई थी। इस योजना की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक रही है। इसलिए, इस योजना के तहत निवेश की सीमा को 1 अप्रैल 2022 से वर्तमान में ₹1.5 लाख करोड़ से ₹1.0 लाख करोड़ तक बढ़ाकर ₹2.5 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव है। यह सरकारी प्रतिभूतियों सहित घरेलू ऋण बाजार के लिए पूंजी के अतिरिक्त स्रोतों तक पहुंच प्रदान करेगा।

ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) दिशानिर्देशों की समीक्षा

सबसे पहले 2013 में जारी ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की समीक्षा की गई और सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए फरवरी 2021 में मसौदा दिशानिर्देश जारी किए गए। प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, सीडीएस संबंधी अंतिम निदेश आज जारी किए जा रहे हैं। ये दिशानिर्देश क्रेडिट डेरिवेटिव बाजार के विकास की सुविधा प्रदान करेंगे और भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को गहन बनाने में मदद करेंगे।

बैंकों को अपतटीय विदेशी मुद्रा निपटान - रुपया डेरिवेटिव बाजार में कारोबार करने की अनुमति

भारत में बैंकों को पहले से ही अनिवासियों को रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव जैसे ओवरनाइट सूचकांकित स्वैप (OIS) ऑफर करने की अनुमति दी गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि भारत में बैंकों को गैर-निवासियों और अन्य बाजार निर्माताओं के साथ अपतटीय विदेशी मुद्रा निपटान- ओवरनाइट सूचकांकित स्वैप (FCS-OIS) बाजार में लेनदेन करने की अनुमति दी जाए। यह तटवर्ती और अपतटीय बाजारों के बीच विभाजन को कम करेगा, अधिक कुशल मूल्य खोज को सक्षम करेगा और भारत में ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार को और गहन करेगा।

ई-रूपी (यूपीआई का उपयोग कर प्रीपेड डिजिटल वाउचर) के अंतर्गत अधिकतम सीमा में वृद्धि

एनपीसीआई द्वारा विकसित ई-आरयूपीआई प्री-पेड डिजिटल वाउचर का शुभारंभ अगस्त 2021 में किया गया था। एकल उपयोग नकदी रहित भुगतान वाउचर की सीमा ₹10,000 है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए ई-रूपी वाउचर की सीमा को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 प्रति वाउचर करने का प्रस्ताव है और ऐसे ई-रूपी वाउचर को एक से अधिक बार (जब तक वाउचर की राशि पूरी तरह से भुनाई नहीं

गवर्नर का वक्तव्य

जाती है) उपयोग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। इससे लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के वितरण में और अधिक आसानी होगी।

एमएसएमई प्राप्य वित्तपोषण के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे को सक्षम करना – टीआरईडीएस निपटान के लिए एनएसीएच अधिदेश सीमा को बढ़ाना

व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के व्यापार प्राप्य के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करती है। टीआरईडीएस में लेन-देन राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) प्रणाली के माध्यम से निपटाए जाते हैं। हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए और एमएसएमई की बढ़ती चलनिधि आवश्यकताओं के वित्तपोषण में आसानी को और बढ़ाने के लिए, टीआरईडीएस से संबंधित निपटनों के लिए एनएसीएच अधिदेश सीमा को मौजूदा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ करने का प्रस्ताव है।

आईटी आउटसोर्सिंग पर मास्टर निदेश (एमडी) और सूचना प्रौद्योगिकी सुशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन पद्धतियों पर मास्टर निदेश (एमडी)

महत्वपूर्ण आईटी सेवाओं की व्यापक आउटसोर्सिंग, आरबीआई की विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और ग्राहकों द्वारा डिजिटल चैनलों के बढ़ते उपयोग से, विनियमित संस्थाओं को महत्वपूर्ण वित्तीय, परिचालन और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इसलिए, मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और उन्हें समेकित करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, हितधारकों और जनता की टिप्पणियों के लिए दो मसौदा निदेश जारी किए जाएंगे: (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (आईटी आउटसोर्सिंग) निदेश, 2022; और (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (सूचना प्रौद्योगिकी सुशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन पद्धति) निदेश, 2022।

निष्कर्ष

हम कोविड-19 के अगले म्यूटेशन के बारे में निश्चित ज्ञान के अभाव में नाइटियन अनिश्चितता[2] की दुनिया में रह रहे हैं। अर्थव्यवस्था के भविष्य का अनुमान लगाने की क्षमता वायरस के विकास पर इतनी निर्भर है कि एक रोग का निदान उतना ही अच्छा या उतना ही बुरा है जितना कि दूसरा है और अल्पकालिक भी । यदि पिछले दो वर्षों में वायरस के साथ रहने ने हमें कुछ सिखाया है, तो यह कि विनम्र रहना है, लेकिन अपने आत्म-विश्वास पर दृढ़ रहना है, कभी भी साहस और आशावाद नहीं खोना है। जैसा कि महान लता मंगेशकर ने - जिन्हें हमने हाल ही में खो दिया - उनकी अमर आवाज में गाया: "आज फिर जीने की तमन्ना है"। इस खूबसूरत गीत की अगली पंक्ति के पीछे की भावना के साथ, उन्होंने आशावाद का एक शाश्वत संदेश दिया है।

हम, रिज़र्व बैंक में, घरेलू वित्तीय प्रणाली में विश्वास और साहस की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे हैं क्योंकि हमने व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ मजबूत और सतत विकास की नींव का पुनर्निर्माण किया। अनिश्चितता के सागर में यह हमारा सहारा रहा है। हम चुनौतियों के बीच निरंतर प्रयास करने की महात्मा गांधी की भावना से प्रेरित हैं: "संतुष्टि प्रयास में निहित है, …… पूर्ण प्रयास पूर्ण जीत है[3]।"

शुक्रिया । सुरक्षित रहें । स्वस्थ रहें । नमस्कार ।

[2] अर्थशास्त्र में, नाइटियन अनिश्चितता कुछ संभावित घटना के बारे में किसी भी मात्रात्मक ज्ञान की कमी है, जोकि मात्रात्मक जोखिम के विपरीत है। यह अपूर्ण ज्ञान की स्वीकृति है जो भविष्य की घटनाओं को अनिवार्य रूप से अप्रत्याशित बनाती है। इस घटना का नाम शिकागो विश्वविद्यालय के एक अर्थशास्त्री, फ्रैंक नाइट (1885-1972) के नाम पर रखा गया है, जिसका मौलिक कार्य जोखिम, अनिश्चितता और लाभ 1921 में प्रकाशित हुआ था।

[3] महात्मा गांधी का एकत्रित कार्य (सीडब्ल्यूएमजी), खंड 26, पी. 293

2021-22 के लिए मौद्रिक नीति वक्तव्य

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संलल्प, 8-10 फरवरी 2022

*मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प**

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (10 फरवरी 2022) को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए।

एलएएफ़ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर बनी हुई हैं।

- यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया।

ये निर्णय संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है।

इस निर्णय के पीछे के मुख्य विचार नीचे दिए गए विवरण में व्यक्त की गई हैं।

आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. दिसंबर 2021 में एमपीसी की बैठक के बाद से, अत्यधिक संक्रमित ओमिक्रोन वेरियंट के तेजी से प्रसार और संबंधित प्रतिबंधों ने वैश्विक आर्थिक गतिविधि को मंद कर दिया है। सेवाओं और विनिर्माण दोनों में कमजोरी के साथ वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) जनवरी 2022 में 18 महीने के निचले स्तर 51.4 पर फिसल गया। विश्व वस्तु व्यापार में वृद्धि जारी है। हालांकि, लगातार कंटेनर और श्रम की कमी, और माल ढुलाई की उच्च दरों से बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के अपने जनवरी 2022 के अपडेट में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2022 के लिए वैश्विक उत्पादन और व्यापार वृद्धि अनुमानों को संशोधित कर क्रमशः 4.9 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत के अपने पूर्व पूर्वानुमानों से घटाकर 4.4 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत कर दिया।

3. नवंबर के अंत में हुए क्षणिक सुधार के उलटने के बाद, वस्तुओं की कीमतें फिर से सख्त हो गईं और मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा दिया। परिसंपत्ति खरीद को समाप्त करने और अनुमान से पहले नीति दरों में बढ़ोत्तरी सहित कई केंद्रीय बैंकों द्वारा नीति सामान्यीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के कारण वित्तीय बाजार अस्थिर हो गए हैं। सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल सभी परिपक्वता अवधि में मजबूत हुए और इक्विटी बाजारों ने सुधार क्षेत्र में प्रवेश किया। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में मुद्रा बाजारों ने हाल के सप्ताहों में उभयगामी विचरण का प्रदर्शन किया है, जिसका मुख्य कारण अमेरिकी दर वृद्धि की गति और मात्रा पर उच्च अनिश्चितता के साथ इक्विटी से मजबूत पूंजी बहिर्वाह है। उत्तरवर्ती ने यूएस बांड प्रतिफल में वृद्धि और अस्थिर गति का नेतृत्व किया।

घरेलू अर्थव्यवस्था

4. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 7 जनवरी, 2022 को जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान (एफएई) ने भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि को 2021-22 के लिए 9.2 प्रतिशत पर रखा, जो इसकी महामारी-पूर्व (2019-20) स्तर को पार कर गया। निजी खपत को छोड़कर जीडीपी के सभी प्रमुख घटक, अपने 2019-20 के स्तर को पार कर गए। अपनी 31 जनवरी की विज्ञप्ति में, एनएसओ ने 2020-21 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को (-) 7.3 प्रतिशत के अनंतिम अनुमान से संशोधित करके (-) 6.6 प्रतिशत कर दिया।

* 10 फरवरी 2022 को जारी

5. उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक जनवरी 2022 में मांग के कुछ कमजोर होने का रुझान देते हैं जो देश में ओमिक्रोन वेरियंट के तेजी से प्रसार से संपर्क-गहन सेवाओं पर कर्षण को दर्शाता है। ग्रामीण मांग संकेतक - दोपहिया और ट्रैक्टर की बिक्री - दिसंबर-जनवरी में संकुचित हुई। 4 फरवरी 2022 तक रबी के तहत बोया गया क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 प्रतिशत अधिक था। शहरी मांग संकेतकों में, आपूर्ति बाधाओं के कारण उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और यात्री वाहनों की बिक्री नवंबर-दिसंबर में संकुचित हुई, जबकि जनवरी में घरेलू हवाई यातायात ओमिक्रोन के प्रभाव से कमजोर हुआ। निवेश गतिविधि ने मिश्रित तस्वीर प्रदर्शित की - जबकि दिसंबर में पूंजीगत वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में नवंबर में वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) आधार पर गिरावट आई। जनवरी 2022 में लगातार ग्यारहवें महीने वस्तु निर्यात में तेजी रही; घरेलू मांग के कारण गैर-तेल गैर-सोने के आयात में भी विस्तार जारी रहा।

6. विनिर्माण पीएमआई जनवरी में 54.0 पर विस्तार क्षेत्र में रहा, हालांकि यह पिछले महीने के 55.5 से कम था। सेवा क्षेत्र के संकेतकों में, रेलवे माल ढुलाई, ई-वे बिल और टोल संग्रह ने दिसंबर-जनवरी में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की; पेट्रोलियम खपत में सुस्त वृद्धि दर्ज की गई और बंदरगाह यातायात में गिरावट दर्ज की गई। जहां जनवरी में तैयार स्टील की खपत में वर्ष-दर-वर्ष कमी आई, वहीं सीमेंट उत्पादन दिसंबर में दोहरे अंकों में बढ़ा। पीएमआई सेवाओं ने जनवरी 2022 में 51.5 पर विस्तार का प्रदर्शन जारी रखा, हालांकि इसकी गति दिसंबर के 55.5 से कमजोर हो गई।

7. बृहद प्रतिकूल आधार प्रभावों के कारण हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़कर 5.6 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष हो गई, जो नवंबर में 4.9 प्रतिशत थी। खाद्य समूह ने मुख्य रूप से सब्जियों, मांस और मछली, खाद्य तेलों और फलों के कारण दिसंबर में कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की, लेकिन सब्जियों की कीमतों के तीव्र प्रतिकूल आधार प्रभावों के परिणामस्वरूप वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। ईंधन मुद्रास्फीति दिसंबर में कम हुई लेकिन दोहरे अंकों में बनी रही। खाद्य और ईंधन को छोड़कर मूल मुद्रास्फीति या सीपीआई मुद्रास्फीति ऊंची बनी रही, हालांकि उसमें नवंबर के 6.2 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर में 6.0 प्रतिशत तक कुछ कमी आई जिसका मुख्य कारण परिवहन और संचार, स्वास्थ्य, आवास और मनोविनोद और मनोरंजन रहा।

8. समग्र प्रणाली चलनिधि बड़े अधिशेष में बनी रही, हालांकि एलएएफ के तहत औसत अवशोषण (स्थिर और परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो दोनों के माध्यम से) अक्टूबर-नवंबर 2021 के दौरान ₹8.6 लाख करोड़ से घटकर जनवरी 2022 में ₹7.6 लाख करोड़ हो गया। आरक्षित धन (नकद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित) 4 फरवरी 2022 को 8.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) तक विस्तारित हुआ। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा आपूर्ति (एम3) और बैंक ऋण में 28 जनवरी 2022 तक क्रमशः 8.4 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) हुई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2021-22 (4 फरवरी 2022 तक) में 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 632 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

संभावनाएं

9. दिसंबर 2021 की एमपीसी बैठक के बाद से, सीपीआई मुद्रास्फीति अपेक्षित प्रक्षेपवक्र के साथ आगे बढ़ी है। आने वाले समय में ताजा सर्दियों की फसल की आवक से सब्जियों की कीमतों में और कमी आने की उम्मीद है। दालों और खाद्य तेल की कीमतों में सौम्यता, सरकार के मजबूत आपूर्ति पक्ष हस्तक्षेप और घरेलू उत्पादन में वृद्धि के जवाब में जारी रहने की संभावना है। रबी की अच्छी फसल की संभावनाएं खाद्य कीमतों में आशावाद को बढ़ाती हैं। हालांकि, प्रतिकूल आधार प्रभाव जनवरी में खाद्य मुद्रास्फीति में पर्याप्त कमी को रोक सकता है। भले ही आपूर्ति की स्थिति 2022 के दौरान अधिक अनुकूल होने की उम्मीद है लेकिन कच्चे तेल की कीमतों की संभावनाएं भू-राजनीतिक गतिविधियों के कारण अनिश्चित बनी हुई है। जबकि मुख्य मुद्रास्फीति पर लागत-जन्य दबाव निकट अवधि में जारी रह सकता है, रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षणों ने आने वाले समय में विनिर्माण और सेवा फर्मों द्वारा बिक्री कीमतों में वृद्धि की गति में कुछ नरमी की ओर इशारा किया है, जो कमजोर प्रभाव अंतरण (पास-थ्रू) को दर्शाता है। संतुलित तौर पर, 2021-22 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान 5.3 प्रतिशत, जिसमें चौथी तिमाही का 5.7 प्रतिशत शामिल है, पर बनाए रखा गया है। 2022 में सामान्य मानसून की उम्मीद पर, 2022-23 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत अनुमानित है जोकि व्यापक रूप से संतुलित जोखिमों के साथ

चार्ट-1 सीपीआई मुद्रास्फीति का तिमाही पूर्वानुमान (व-द-व)

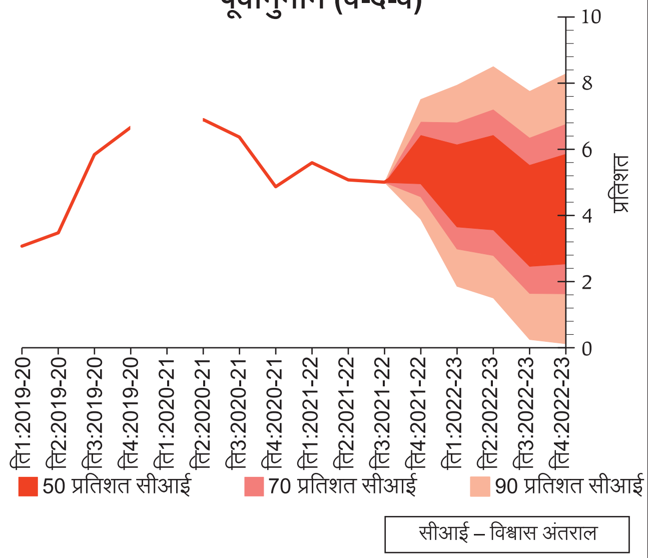

चार्ट – 2 वास्तविक जीडीपी संवृद्धि का तिमाही पूर्वानुमान (व-द-व)

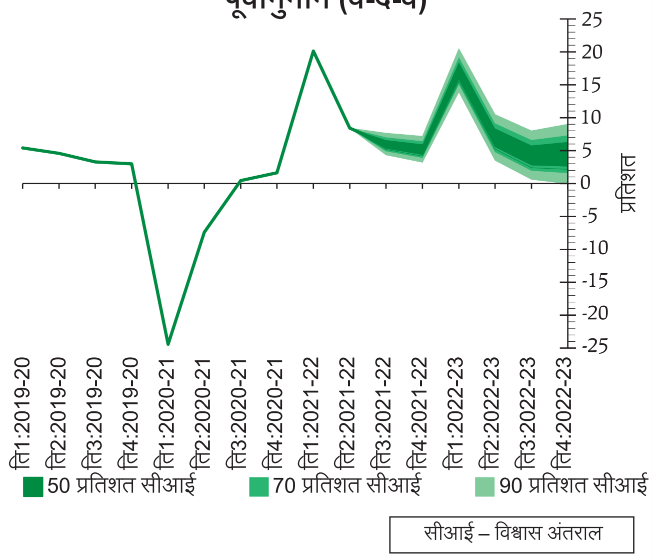

2022-23 की पहली तिमाही में 4.9 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 5.0 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 4.0 प्रतिशत; और 2022-23 की चौथी तिमाही में 4.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है (चार्ट 1)।

10. घरेलू आर्थिक गतिविधियों में सुधार अभी व्यापक आधार पर होना बाकी है, क्योंकि निजी खपत और संपर्क-गहन सेवाएं महामारी-पूर्व के स्तर से नीचे हैं। आने वाले समय में, रबी फसल की संभावनाएं कृषि और ग्रामीण मांग के लिए अच्छा संकेत देता है। बहाली पर महामारी की चल रही तीसरी लहर का प्रभाव पहले की लहरों के सापेक्ष सीमित होने की संभावना है, जिससे संपर्क-गहन सेवाओं और शहरी मांग के संभावनाओं में सुधार होगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में पूंजीगत व्यय में वृद्धि के माध्यम से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की घोषणाओं से बड़े गुणक प्रभावों के माध्यम से निजी निवेश में वृद्धि और भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। गैर-खाद्य बैंक ऋण में वृद्धि, सहायक मौद्रिक और चलनिधि की स्थिति, वस्तु निर्यात में सतत बढ़ोत्तरी, क्षमता उपयोग में सुधार और स्थिर व्यापार संभावनाएं समग्र मांग के लिए शुभ संकेत हैं। वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता, अंतरराष्ट्रीय पण्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतों में, और निरंतर वैश्विक आपूर्ति-पक्ष व्यवधानों ने संभावनाओं के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा किया है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.8 प्रतिशत पर अनुमानित है, जो कि 2022-23 की पहली तिमाही में 17.2 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 7.0 प्रतिश; तीसरी तिमाही में 4.3 प्रतिशत; और 2022-23 की चौथी तिमाही में 4.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है (चार्ट 2)।

11. एमपीसी इस बात पर ध्यान देता है कि मुद्रास्फीति 2022-23 की पहली छमाही में कम होने की संभावना है और उसके बाद लक्ष्य दर के करीब जाने की संभावना है, जिससे निभावकारी बने रहने के लिए जगह उपलब्ध हो सके। सरकार की ओर से सामयिक और उपयुक्त आपूर्ति पक्ष उपायों से मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली है। इनपुट लागत में संभावित वृद्धि एक आकस्मिक जोखिम है, खासकर तब, जब अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं। महामारी से पहले की प्रवृत्ति के साथ घरेलू सुधार गति पकड़ रही है, लेकिन निजी खपत अभी भी पिछड़ रही है। कोविड-19 ने भावी संभावनाओं के लिए कुछ अनिश्चितता प्रदान करना जारी रखा है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित उपायों से सकल मांग में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। हालाँकि, प्रणालीगत उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण और सतत आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से मुद्रास्फीति के दबाव से प्रेरित वित्तीय बाजार की अस्थिरता से बढ़ती बाधाओं के कारण वैश्विक समष्टि आर्थिक वातावरण को 2022 में वैश्विक मांग में गिरावट के साथ चित्रित

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22

किया गया है। तदनुसार, एमपीसी का निर्णय है कि जारी घरेलू बहाली अभी भी अधूरी है और उसे निरंतर नीति समर्थन की आवश्यकता है। इस संदर्भ में एमपीसी ने नीति रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने और यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।

12. एमपीसी के सभी सदस्य – डॉ. शंशाक भिडे, डॉ. आशिमा गोयल, प्रो. जयंत आर. वर्मा, डॉ. मृदुल के. सागर, डॉ. माइकल देवव्रत पात्र और श्री शक्तिकांत दास ने नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया।

13. प्रो. जयंत आर. वर्मा को छोड़कर एमपीसी के सभी सदस्यों अर्थात् डॉ. शंशाक भिडे, डॉ. आशिमा गोयल, डॉ. मृदुल के. सागर, डॉ. माइकल देवव्रत पात्र और श्री शक्तिकांत दास ने सर्वसम्मति से यह सुनिश्चित करते हुए कि आगे चलकर मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, और टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को पुनर्जीवित करने और उसे बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने के लिए मतदान किया। प्रो. जयंत आर. वर्मा ने संकल्प के इस भाग पर संदेह व्यक्त किया।

14. एमपीसी की बैठक का कार्यवृत्त 24 फरवरी 2022 को प्रकाशित किया जाएगा।

15. एमपीसी की अगली बैठक 6-8 अप्रैल 2022 के दौरान निर्धारित है।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) चलनिधि उपाय; (ii) वित्तीय बाज़ार; (iii) भुगतान और निपटान प्रणाली तथा; (iv) विनियमन और पर्यवेक्षण से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है।

I. चलनिधि उपाय

1. आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹50,000 करोड़ की मीयादी चलनिधि सुविधा की अवधि को बढ़ाना

5 मई 2021 को, देश में कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए तत्काल चलनिधि के प्रावधान को बढ़ावा देने हेतु रेपो दर पर ₹50,000 करोड़ की ऑन-टैप चलनिधि विंडो की घोषणा की गई थी, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की थी। बैंकों को 31 मार्च 2022 तक ऐसे ऋण के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण के विस्तार के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत ऋण के त्वरित वितरण के लिए प्रोत्साहित किया गया था। बैंकों से इस योजना के तहत एक कोविड -19 ऋण बही तैयार करने की प्रत्याशा थी। एक अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में, ऐसे बैंक प्रतिवर्ती रेपो विंडो के तहत आरबीआई के पास कोविड-19 ऋण बही की राशि तक अपनी अधिशेष चलनिधि को रेपो दर से 25 बीपीएस कम, अर्थात् प्रतिवर्ती रेपो दर से 40 बीपीएस अधिक दर पर जमा करने के लिए पात्र थे। बैंकों ने कोविड -19 से संबंधित आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए (4 फरवरी 2022 तक) अपने ₹9,654 करोड़ की निधियों को नियोजित किया है। योजना की प्रतिक्रिया को देखते हुए, अब इस विंडो को पहले की घोषणा के अनुसार 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 30 जून 2022 तक करने का प्रस्ताव है।

2. संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए ऑन टैप चलनिधि विंडो की अवधि को बढ़ाना

4 जून 2021 को, कुछ संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध तीन वर्ष तक की अवधि के साथ रेपो दर पर ₹15,000 करोड़ की एक अलग चलनिधि विंडो खोलने का निर्णय लिया गया था। प्रोत्साहन के रूप में, ऐसे बैंक इस योजना के अंतर्गत बनाई गई कोविड-19 ऋण बही की राशि तक अपनी अधिशेष चलनिधि को आरबीआई के पास जमा करने के पात्र थे। कोविड-19 ऋण बही की इस राशि को रेपो दर से 25 बीपीएस कम या, एक अलग तरीके से कहा जाए तो, प्रतिवर्ती रेपो दर से 40 बीपीएस अधिक दर पर जमा किया गया था। इस योजना के तहत आरबीआई से निधि प्राप्त किए बिना अपने स्वयं के संसाधनों को नियोजित कर ऋण प्रदान करने के इच्छुक बैंक भी इस प्रोत्साहन के लिए पात्र थे। बैंकों ने संपर्क गहन क्षेत्र के अंतर्गत संस्थाओं के लिए (4 फरवरी 2022 तक) ₹5,041 करोड़ की अपनी निधि को नियोजित किया है। योजना को मिली प्रतिक्रिया को देखते हुए अब इस विंडो को 30 जून 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

II. वित्तीय बाज़ार

3. स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) - सीमाओं में वृद्धि

देश में जारी ऋण लिखतों में स्थायी निवेश की सुविधा के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा सरकारी और कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) को 01 मार्च 2019 को प्रारंभ किया गया था। इस मार्ग ने दीर्घावधि निवेश होरीज़ोन वाले एफपीआई को एक अलग माध्यम, जो मूल रूप से व्यापक विवेकसम्मत नियंत्रण से मुक्त है, प्रदान किया। वीआरआर के तहत निवेश के लिए ₹1,50,000 करोड़ की एक प्रतिबद्ध निवेश सीमा निर्धारित की गई थी। वीआरआर की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए, जैसा कि वर्तमान सीमा के लगभग समाप्त होने से स्पष्ट है, 1 अप्रैल 2022 से वीआरआर के तहत निवेश सीमा को ₹1,00,000 करोड़ और बढ़ाकर ₹2,50,000 करोड़ करने का प्रस्ताव है। संशोधित निवेश सीमा आज अधिसूचित की जा रही है।

4. ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) दिशानिर्देशों की समीक्षा

ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) के लिए दिशानिर्देश पिछली बार जनवरी 2013 में जारी किए गए थे। कॉरपोरेट बॉन्ड, विशेष रूप से कम रेटिंग वाले जारीकर्ताओं के बांड के लिए, चलनिधि बाजार के विकास के लिए सीडीएस बाजार के महत्व को देखते हुए, 4 दिसंबर 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि इन दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाएगी। तदनुसार, सार्वजनिक परामर्श के लिए 16 फरवरी

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

2021 को मसौदा दिशानिर्देश जारी किए गए थे। प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए आज अंतिम निदेश जारी किए जा रहे हैं।

5. बैंकों को अपतटीय विदेशी मुद्रा में निपटान रुपया डेरिवेटिव बाजार में कारोबार करने की अनुमति देना

भारत में बैंकों को जून 2019 में यह अनुमति दी गई थी कि वे अनिवासियों को उनके ब्याज दर जोखिम से बचाव के लिए रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव को ऑफर करें। विदेशी संस्थाओं को भी भारत में बैंकों के साथ बचाव के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए प्रत्यक्ष या बैक-टू-बैक आधार पर भारत में बाजार निर्माता की विदेशी शाखा/ मूल/ समूह इकाई (विदेशी समकक्ष) के माध्यम से ओवरनाइट सूचकांकित स्वैप (ओआईएस) लेनदेन करने की अनुमति दी गई थी। इस पहल ने घरेलू ओआईएस बाजार में चलनिधि को बढ़ाया है, भागीदारी में विविधता को बढ़ावा दिया है और तटवर्ती और अपतटीय बाजारों के बीच विभाजन को कम किया है। देश में ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार को और बढ़ावा देने, तटवर्ती और अपतटीय बाजारों के बीच विभाजन को दूर करने और मूल्य खोज की दक्षता में सुधार करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि भारत के बैंकों को अनिवासियों और अन्य बाजार निर्माताओं के साथ अपतटीय विदेशी मुद्रा में निपटान होने वाले ओवरनाइट सूचकांकित स्वैप (एफ़सीएस-ओआईएस) बाजार में लेनदेन करने की अनुमति दी जाए। बैंक भारत में अपनी शाखाओं, अपनी विदेशी शाखाओं या अपनी आईएफ़एससी बैंकिंग इकाइयों के माध्यम से भाग ले सकते हैं। आज आवश्यक निदेश जारी किए जा रहे हैं।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

6. ई-रूपी (यूपीआई का उपयोग कर प्रीपेड डिजिटल वाउचर) के अंतर्गत अधिकतम सीमा में वृद्धि

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित और अगस्त 2021 में जारी ई-रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर एक व्यक्ति-विशिष्ट और उद्देश्य-विशिष्ट नकदी रहित वाउचर है और इसका उपयोग व्यक्तियों, कंपनियों या सरकारों द्वारा किया जा सकता है। ई-रूपी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर चलता है और इसकी सीमा ₹10,000/- प्रति वाउचर है और प्रत्येक वाउचर का उपयोग/ मोचन केवल एक बार किया जा सकता है। वर्तमान में ई-रूपी वाउचर का उपयोग बड़े पैमाने पर कोविड-19 टीकाकरण उद्देश्यों के लिए किए जा रहे हैं। विभिन्न राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा अन्य उपयोग के मामलों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की डिजिटल सुपुर्दगी की सुविधा के लिए, सरकारों द्वारा जारी किए गए ई-रूपी वाउचर की सीमा को बढ़ाकर ₹1,00,000/- प्रति वाउचर करने और ई-रूपी वाउचर के कई बार (जब तक वाउचर की राशि पूरी तरह से भुनाई नहीं जाती है) उपयोग की अनुमति देने का प्रस्ताव है। एनपीसीआई को आवश्यक निदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

7. एमएसएमई प्राप्य वित्तपोषण के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे को सक्षम करना – टीआरईडीएस निपटान के लिए एनएसीएच अधिदेश सीमा को बढ़ाना

व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्राप्तियों में छूट/ वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करता है। टीआरईडीएस निपटान राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) प्रणाली में अधिदेश के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में एनएसीएच अधिदेश की सीमा ₹1 करोड़ है।

वर्धित सहभागिता के माध्यम से नवोन्मेष और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए, अक्तूबर 2019 में रिज़र्व बैंक द्वारा टीआरईडीएस परिचालकों के 'ऑन टैप' प्राधिकरण की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 से एमएसएमई की परिभाषा को उनके वार्षिक कारोबार से जोड़ने के साथ जोड़कर संशोधित किया है। एमएसएमई की बढ़ती चलनिधि आवश्यकताओं और टीआरईडीएस प्लेटफार्मों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, टीआरईडीएस निपटान के लिए एनएसीएच अधिदेश सीमा को ₹3 करोड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

आवश्यक निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

IV. विनियमन और पर्यवेक्षण

8. आईटी आउटसोर्सिंग पर मास्टर निदेश (एमडी) और सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन पद्धतियों पर मास्टर निदेश (एमडी)

वित्तीय प्रणाली दक्षता में सुधार के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी के प्लेयरों के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियों तक आसान पहुंच प्राप्त

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

करने के लिए विनियमित संस्थाएं महत्वपूर्ण आईटी सेवाओं के व्यापक लाभ और आउटसोर्सिंग को महसूस कर रही है। इन व्यवस्थाओं से उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय, परिचालन और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह, बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए डिजिटल चैनलों पर ग्राहकों की बढ़ती निर्भरता ने विनियमित संस्थाओं के लिए परिचालन संबंधी लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य बना दिया है।

इसलिए, यह महसूस किया गया है कि आईटी आउटसोर्सिंग के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे, संकेन्द्रण जोखिम के प्रबंधन, आवधिक जोखिम मूल्यांकन और विदेशी सेवा प्रदाताओं को आउटसोर्सिंग जैसे पहलुओं के लिए उपयुक्त विनियामक दिशानिर्देशों की आवश्यकता है। सूचना सुरक्षा सुशासन और नियंत्रण, कारोबार निरंतरता प्रबंधन और सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा से संबंधित दिशानिर्देशों को भी अद्यतन और समेकित करने की आवश्यकता है।

तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त पहलुओं को संबोधित करने हेतु दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव किया है। हितधारकों और जनता की टिप्पणियों के लिए दो मसौदा निदेश जारी किए जाएंगे: (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (आईटी आउटसोर्सिंग) निदेश, 2022; और (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (सूचना प्रौद्योगिकी सुशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन पद्धतियां) निदेश, 2022।

भाषण

आरबीआई की महामारी पर कार्रवाई : विस्मृति से बाहर आना – माइकल देबब्रत पात्र

आरबीआई की महामारी पर कार्रवाई: विस्मृति से बाहर आना*

माइकल देबब्रत पात्र

प्रोफेसर मुचकुंद दुबे, अध्यक्ष, प्रोफेसर शांता सिन्हा, अध्यक्ष, प्रबंध समिति, प्रोफेसर सुजीत कुमार मिश्रा, क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी), डॉ सन्नी जोस, आरबीआई चेयर प्रोफेसर, सामाजिक विकास परिषद, हैदराबाद (इसके बाद सीएसडी) के संकाय और कर्मचारी, देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले छात्र, शोधकर्ता और संकाय, सहयोगियों और दोस्तों! 1997 से सीएसडी द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सी डी देशमुख स्मृति व्याख्यान श्रृंखला के तहत आज अपने विचार साझा करना वास्तव में एक सम्मान की बात है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद आरबीआई) के लिए इस व्याख्यान श्रृंखला का एक विशेष महत्व है। स्वर्गीय श्री चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। आरबीआई के साथ उनका जुड़ाव जुलाई 1939 में भी शुरू हुआ, जब उन्हें भारत सरकार द्वारा आरबीआई में संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया था। तीन महीने बाद, उन्हें बैंक के केंद्रीय बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया, दो साल बाद दिसंबर 1941 में डिप्टी गवर्नर के रूप में और फिर 11 अगस्त 1943 को गवर्नर नियुक्त किया गया। उन्होंने एक निजी शेयरधारकों के बैंक से एक राष्ट्रीयकृत संस्था में आरबीआई के परिवर्तन को संचालित किया। उनके नेतृत्व में, बैंकिंग कंपनियों के विनियमन के लिए एक व्यापक कानून बनाया गया था। उनके नेतृत्व में एक और ऐतिहासिक कानून ने उद्योग को दीर्घकालिक ऋण के प्रावधान के लिए पहली वित्तीय संस्था अर्थात्, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) की स्थापना की। उन्होंने जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी या विश्व बैंक) की स्थापना की। उनकी दूरदृष्टि और विचार आज भी आरबीआई के गलियारों में गूंजते हैं।

स्वर्गीय श्री देशमुख और उनकी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने 1962 में एक प्रमुख शोध और नीति अध्ययन संस्थान के रूप में सीएसडी की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई जो बड़े पैमाने पर समाज के लिए उनके कई उत्कृष्ट योगदानों में से एक है। आज, यह राष्ट्रीय गौरव का विषय है कि सीएसडी विकास योजना, सामाजिक न्याय और समानता के सामाजिक पहलुओं पर विशेष ध्यान देने के साथ नीति-उन्मुख अनुसंधान में संलग्न है। सीएसडी में अनुसंधान राज्य और लोगों के बीच संबंधों पर नीतियों के विविध प्रभावों का मूल्यांकन करना जारी रखा गया है। सीएसडी के साथ हमारा जुड़ाव भी 1985 से है जब आरबीआई चेयर प्रोफेसरशिप की स्थापना हुई थी। यह काफी संतोष की बात है कि हमारे कई अधिकारी सीएसडी के साथ अपने आत्म-साक्षात्कार में जुड़े रहे हैं।

इस पृष्ठभूमि में, मैं आज अपने संबोधन के विषय की ओर आता हूं, जो कि महामारी[1] के प्रति आरबीआई की प्रतिक्रिया है।

जब वर्ष 2020 की शुरुआत में कोविड-19 ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, तो मनुष्य अतीत की महामारियों से बेखबर हो गया था। फिर भी, सौ साल पहले और उससे पहले - 1817 और 1920 के बीच - हैजा, प्लेग और इन्फ्लूएंजा महामारी बार-बार दुनिया में आए और कहर बरपाया। दुनिया भर में मारे गए अनुमानित 70 मिलियन लोगों में से - मोटे तौर पर दो विश्व युद्धों के हताहतों के समान - भारत में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान था, और फिर भी किसी तरह, हमने उन यादों को मिटा दिया था। आखिरकार, रोगों के नियंत्रण में आश्चर्यजनक प्रगति हुई थी, भोजन और पोषण अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे और हमने प्राकृतिक आपदाओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपटना सीख

* 28 जनवरी, 2022 को सामाजिक विकास परिषद, हैदराबाद द्वारा आयोजित सीडी देशमुख स्मृति व्याख्यान में माइकल देबब्रत पात्र, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया मुख्य भाषण। सितिकंठ पट्टनायक, राजीव रंजन, इंद्रनील भट्टाचार्य, अभिलाषा की बहुमूल्य टिप्पणियाँ और विनीत कुमार श्रीवास्तव की संपादकीय मदद के लिए आभारी हैं।

1 'पैंडेमिक' शब्द ग्रीक शब्द पैंडेमोस से निकला है, जिसका अर्थ है सभी लोगों के लिए सामान्य।

लिया था। परिणामस्वरूप, आयुकाल, जो 1920 में 25 वर्ष जितनी कम थी, वर्ष 2020 तक बढ़कर 70 वर्ष हो गई थी[2]।

अगर हमें याद होता, तो हम इस तथ्य के लिए तैयार होते कि इन्फ्लूएंजा उत्परिवर्तन द्वारा पहले से मौजूद प्रतिरक्षा से बच सकता है। हमें याद होगा कि संक्रमण लहरों में होता है - 1918 के इन्फ्लूएंजा महामारी के मामले में चार लहरें आईं, जो 1920 तक चलीं। हमारी चेतना ने इस तथ्य को उभारा होगा कि बुखार और शरीर में दर्द के सामान्य लक्षणों से परे, संक्रमण जल्दी से न्यूमोनिक कर देता है, जिससे बैक्टीरिया फेफड़ों पर हमला कर सकें। अंत में, यह सामूहिक संचित ज्ञान का नुकसान है जिसने कोविड-19 को हमें जकड़ने की अनुमति दी। वास्तव में, स्मृति के इस नुकसान के परिणामस्वरूप तर्कहीन कार्रवाई हुई - 10 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ) द्वारा कोविड-19 को एक महामारी के रूप में घोषित करना और इसके बाद भारत का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जो मानव इतिहास में सबसे बड़े प्रवासों में से एक की वजह बन गया क्योंकि लोग इस डर से शहरों से भाग गए थे कि व्यापक रूप से इसे एक शहरी बीमारी के रूप में माना जाता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि वायरस उनके गांवों तक उनका पीछा कर रहा है। भूलने की यह बीमारी वैश्विक थी। उदाहरण के लिए, डब्ल्यूएचओ, जिसके पास महामारी घोषित करने का अधिदेश है, ने 2009 में एच1एन1 के संबंध में ऐसा किया था, लेकिन इस पर गंभीरता से सवाल उठाया गया क्योंकि यह असामान्य रूप से हल्का निकला, और जांच उन फार्मास्युटिकल उद्योगों पर केंद्रित थी जो उत्पादन और टीकों की बिक्री से लाभान्वित हुए थे। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (सार्स), मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम-कोरोनावायरस (एमईआरएस-सीओवी) और इबोला ने व्यापक तौर पर सचेत कर दिया था, लेकिन हताहतों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी और संक्रमण की घटनाएं स्थानीय थीं।

वर्ष 2020 की महामारी दुनिया भर में संक्रमण का कारण बना, और जीवन और आजीविका का भारी नुकसान हुआ। वर्ष 2021 के अंत तक, कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएं उत्पादन के पूर्व-महामारी के स्तर तक पहुंच सकती हैं या उससे अधिक हो सकती हैं, लेकिन मध्यम आय वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं को उत्पादन का बड़ा नुकसान हुआ है, सबसे अधिक बोझ कम आय वाले देशों पर पड़ रहा है। यह महामारी सरकारों और केंद्रीय बैंकों द्वारा तय की गई अभूतपूर्व नीतिगत प्रतिक्रिया के लिए भी उल्लेखनीय है। आईएमएफ का अनुमान है कि मार्च 2020 से अक्टूबर 2021 तक, 16.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या वैश्विक जीडीपी का 16.4 प्रतिशत महामारी की प्रतिक्रिया में राजकोषीय सहायता के रूप में गिरवी रखा गया था, जिसमें उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) द्वारा 14.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और सबसे कम विकसित देशों सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) द्वारा 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए गए थे। कुल मौद्रिक सहायता 19.0 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 18.4 प्रतिशत था, जिसमें एई द्वारा 16.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और ईएमई द्वारा 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता शामिल है।

सामूहिक विस्मरण के मद्देनजर, जिसके बारे में मैंने पहले बात की है, जीवन में एक बार वाली इस नीतिगत प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन किस चीज ने किया? यह 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफ़सी) था। आमतौर पर, वैश्विक संकटों के अनुपात में, ये सरकारें या राजकोषीय नीति होती है जो अग्रणी भूमिका का निर्वाह करती है, जबकि बैक ऑफिस के लिए अपनी रूढ़िवादिता और वरीयता के लिए जाने वाले केंद्रीय बैंक, अंतिम उधारदाताओं के रूप में सहायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि, जीएफसी की प्रतिक्रिया में, यह केंद्रीय बैंक थे जो आगे आए थे। उन्हें अपने मुख्य लिखत - ब्याज दर - के नुकसान का सामना करना पड़ा जो शून्य पर गिर आ गयी थी, जिसे तब निचली सीमा माना जाता था जिससे ब्याज दरों में गिरावट आ सकती है[3], जिसके बाद केंद्रीय बैंकों ने आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए अपनी बैलेंस शीट का उपयोग करके, प्रत्याशाओं को स्थिर करने के लिए आगे का मार्गदर्शन प्रदान करके, अनिश्चित भविष्य को स्थिर करके और प्रोत्साहन-वितरित राजकोषीय घाटे को प्रभावी ढंग से मुद्रीकृत करने के मुख्य पाप के आरोप की कीमत पर दीर्घकालिक प्रतिफल को सीधे प्रभावित करके अपरंपरागत उपायों को शुरू किया। उस अर्थ में, महामारी आने पर उनके पास किसी प्रकार का खाका था।

[2] इन अंतर्दृष्टि के लिए, मैं चिन्मय तुम्बे (2020): एज ऑफ पैंडेमिक्स (1817-1920): हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड, हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया, पर बहुत अधिक जोर देता हूं।

[3] हाल ही में, ब्याज दरें शून्य से भी नीचे ऋणात्मक क्षेत्र में आ गई हैं।

महामारी के खिलाफ प्रवृत्ति

डबल्यूएचओ द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित करने के छह दिनों के भीतर आरबीआई द्वारा उठाए गए पहले कदमों में से एक कारोबार निरंतरता बायो-बबल सृजित करना था। इस घटना में कि हममें से बाकी लोग संक्रमित हो गए, मुद्रा जारी करने, खुदरा और थोक भुगतान और निपटान प्रणाली, वित्तीय जैसी आवश्यक आरबीआई सेवाओं को रखने के लिए 150 चयनित अधिकारियों, कर्मचारियों और सेवा प्रदाताओं को 24X7 काम करने के लिए बबल में अलग रखा गया था। बाजार विनियमन एवं पर्यवेक्षण और चलनिधि प्रबंधन, केवल कुछ प्रमुख नाम हैं, जो नियमित आधार पर नागरिकों, व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों के जीवन को प्रभावित करते हैं। यह दूरदर्शी साबित हुआ। राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा के कुछ दिनों के भीतर, भारत में वित्तीय बाजार ध्वस्त हो गए, वित्तीय संस्थान चलनिधि की समाप्ती की चपेट में आ गए, और वित्त, समाप्त हो गया, जो अर्थव्यवस्था के पहियों को चलाते रहता है।

27 मार्च 2020 से आरबीआई ने महामारी से प्रेरित अव्यवस्थाओं और बाधाओं को दूर करने के लिए, कुल मिलाकर सौ से अधिक दोनों सिस्टम स्तर के और क्षेत्र, संस्था एवं वित्तीय लिखत विशिष्ट, कुछ पारंपरिक और लीक से हटकर उपाय पेश किए।

पारंपरिक उपायों के संदर्भ में, नीतिगत रीपो दर में दो चरणों में अभूतपूर्व 115 बीपीएस की कमी की गई। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत फिक्स्ड रेट रिवर्स रीपो दर पर ब्याज दर, जिसके तहत बाजार सहभागियों ने आरबीआई के साथ अपने अधिशेष जमा किए, संचयी रूप से 155 बीपीएस कम हो गए और यह मुद्रा बाजार दरों के विकास के लिए प्रभावी एंकर बन गया और यहां तक कि लंबी अवधि की ब्याज दरें भी। सीमांत स्थायी सुविधा के तहत बैंकों की चलनिधि तक पहुंच, एक उधार खिड़की, जिसकी कीमत पॉलिसी रीपो दर से 25 बीपीएस अधिक है, का विस्तार ₹1,37,000 करोड़ के करीब किया गया था। बड़े पैमाने पर खुले बाजार में खरीद संचालन और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में एक प्रतिशत अंक की कमी के बावजूद सिस्टम स्तर की चलनिधि को भी बढ़ाया गया था, जिसने बैंकों के संसाधनों को ₹1,37,000 करोड़ की सीमा तक मुक्त कर दिया था।

अपरंपरागत उपायों की ओर मुड़ते हुए, दीर्घावधिक रीपो परिचालन (एलटीआरओ) और लक्षित दीर्घावधिक रीपो परिचालन (टीएलटीआरओ) प्रणालीगत चलनिधि बढ़ाने, बैंकों की निधियों की लागत को कम करने और दीर्घावधिक ब्याज दरों को अधिक सीधे प्रभावित करने के लिए किए गए थे। जहां एलटीआरओ ने प्रणाली में समग्र चलनिधि को बढ़ाया, वहीं, टीएलटीआरओ ने धन की आवश्यकता वाले विशिष्ट क्षेत्रों में चलनिधि का संवितरण सुनिश्चित किया। इसके अतिरिक्त, जब मोचन की आशंका ने म्यूचुअल फंड उद्योग को जकड़ लिया, तो म्यूचुअल फंड (एसएलएफएमएफ) के लिए एक विशेष चलनिधि सुविधा लगभग एक सप्ताह के अंत में तैयार की गई थी। जब इन चलनिधि उपायों को संकटग्रस्त संस्थाओं को आरबीआई के धन को उधार देने में बैंकों के बीच जोखिम का सामना करना पड़ा, तो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) को क्षेत्र-विशिष्ट और छोटी संस्था-विशिष्ट चलनिधि बाधाओं को कम करने के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गयी। ऑन टैप टीएलटीआरओ ने विशिष्ट क्षेत्रों के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर और बैंक ऋण में विनियोजन के लिए बैंकों को चलनिधि प्रदान की। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में, आरबीआई ने महामारी के प्रभाव को कम करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अपने तुलन-पत्र को गिरवी रख दिया। अप्रैल से सितंबर 2021 तक, आरबीआई एक द्वितीयक बाजार सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-एसएपी) के माध्यम से आस्ति खरीद में लगा हुआ था, जिसमें खरीदी जाने वाली राशियों पर एक अग्रिम प्रतिबद्धता शामिल थी और सीधे प्रतिफल को प्रभावित करता था। कुल जी-एसएपी खरीद की राशि ₹2.2 लाख करोड़ थी। इसके अलावा, विशेष मुक्त बाजार संचालन (ओएमओ) में प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद और बिक्री शामिल है, जो चलनिधि तटस्थ थी, चलनिधि को अधिक समान रूप से प्रतिफल वक्र में संवितरित करने के लिए शुरू किया गया था, जिससे मौद्रिक संचरण की सुविधा हुई। कुल मिलाकर, 6 फरवरी, 2020 से ₹17.2 लाख करोड़ (2020-21 के सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद का 8.7 प्रतिशत) की चलनिधि बढ़ाने संबंधी कदम की घोषणा की गई[4]।

[4] स्वीकृत और उपयोग की गई राशि सहित इन सभी उपायों के विशिष्ट पहलुओं को *https://www.rbi.org.in/scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=3894* में प्रलेखित किया गया है।

फॉरवर्ड गाइडेंस (एफजी) को आरबीआई की रणनीति में प्रमुखता मिली। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के हर बयान में, यह दोहराया गया था कि नीतिगत रुख स्पष्ट समय-आकस्मिक और राज्य-आकस्मिक मार्गदर्शन सहित, उदार रहेगा। वित्तीय बाजारों को आश्वासन दिया गया था कि रिज़र्व बैंक बहाली को बनाए रखने के लिए अनुकूल वित्तीय स्थिति बनाए रखेगा। इससे चलनिधि का डर दूर हो गया और बाजार की धारणा मजबूत हुई।

जहां मौद्रिक और चलनिधि उपायों ने तत्काल घबराहट को दूर किया, वहीं रोजमर्रा की गतिविधि में अव्यवस्था और वित्त तक पहुंच ने व्यक्तियों, छोटे और बड़े व्यवसायों में ऋण शोधन क्षमता संबंधी चिंताओं को सामने लाया, और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच आसन्न आस्ति गुणवत्ता दबाव की आशंका पैदा कर दी। तदनुसार, आरबीआई ने विनियामकीय उपायों की एक श्रेणी लॉन्च किया जिसमें ऋण स्थगन; आस्ति वर्गीकरण ठहराव; कार्यशील पूंजी वित्तपोषण में ढील और ब्याज की मोहलत; समूह एक्सपोजर मानदंडों में वृद्धि; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दिए गए अग्रिमों का पुनर्गठन; और मुख्य पहलों का उल्लेख करने के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) अपेक्षाओं में कटौती शामिल था। इन कदमों ने महामारी से प्रभावित उधारकर्ताओं को एक अस्थायी राहत प्रदान की और ऋण देने वाली संस्थाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया, जिससे वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता बरकरार रही। उधारकर्ताओं और बैंकिंग प्रणाली दोनों पर दबाव कम करने के लिए कई प्रतिचक्रीय विनियामकीय उपाय भी किए गए जिनमें व्यक्तिगत आवास ऋण के लिए जोखिम भार का युक्तिकरण; बैंकों के विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो के लिए संशोधित जोखिम भार; और बैंकों पर लाभांश का भुगतान करने पर प्रतिबंध शामिल है।

तकनीकी मोर्चे पर, आरबीआई ने “कम नकदी” पर निर्भर समाज के लिए मार्ग पर डिजिटल पैठ, अभिनव भुगतान विकल्प और उपभोक्ता जागरूकता की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया। कुछ पहलों को सामाजिक दूरी और महामारी के संपर्क प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अनुकूलित किया गया था, जिसमें (i) डिजिटल बैंकिंग चैनलों, एटीएम, इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है; (ii) साइबर सुरक्षा को मजबूत करना; (iii) ग्राहक शिकायतों के तेजी से निवारण के लिए तंत्र विकसित करना; और (iv) आरबीआई कहता है[5] के माध्यम से निरंतर और केंद्रित अभियानों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता में सुधार करना।

अब तक का रिपोर्ट कार्ड

इन उपायों का प्रभाव अभी भी सुलझ रहा है और यहां तक कि जब परिणाम पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, तब भी एक-से-एक सामंजस्य स्थापित करना मुश्किल हो सकता है, जिसमें कई गतिशील भाग शामिल हैं। इस चेतावनी के बावजूद, हालांकि, अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों की समग्र स्थिति - जो कि इन उपायों को चर्चा करने की मांग की गई है - आरबीआई की महामारी प्रतिक्रिया की प्रभावकारिता या अन्यथा के कुछ सबूत प्रदान करती है।

महामारी की शुरुआत से पहले, भारतीय अर्थव्यवस्था एक चक्रीय मंदी में थी, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि वर्ष 2019-20 में घटकर एक दशक में सबसे कम दर पर आ गई थी। नतीजतन, मौद्रिक नीति फरवरी 2019 से निभावकारी हो गई थी और फरवरी 2020 तक नीतिगत दर में 135 बीपीएस की संचयी कमी की गयी थी। मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप जून 2019 से प्रणाली स्तर की चलनिधि को अधिशेष में रखा गया था। फरवरी 2020 के अंत में, बाजार सहभागियों ने एलएएफ के तहत ₹3 लाख करोड़ के ऑर्डर की अतिरिक्त चलनिधि जमा की थी।

वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में महामारी की शुरुआत का पूरा खामियाजा भुगतना पड़ा। लोगों और वस्तुओं की गतिशीलता के सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर गिरने से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 24.4 प्रतिशत की गिरावट आई, जो दुनिया में सबसे गहरे में से एक था। अप्रैल में बेरोजगारी 24 प्रतिशत पर पहुंच गई, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि गतिविधि ने महामारी रोधी प्रदर्शित की और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने अवरोधन का एक उपाय प्रदान किया। अप्रैल में आयात में गिरावट के साथ निर्यात में 61

[5] ‘आरबीआई कहता है’ टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्रों, होर्डिंग्स, वेब बैनर, जीआईएफ, सोशल मीडिया और एसएमएस सहित सभी मास मीडिया का उपयोग करके आरबीआई द्वारा शुरू किया गया एक 360-डिग्री अभियान है।

प्रतिशत की गिरावट आई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन के लिए मूल्य कोटेशन एकत्र नहीं कर सका और उसे आरोपण का सहारा लेना पड़ा।

जून की शुरुआत में, महामारी का प्रकोप कम हो गया और संक्रमण की गति कम होने लगी। इसने अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से अनलॉक करने के लिए प्रोत्साहित किया जिसे पूरा होने में दिसंबर 2020 के अंत तक का समय लगा। जैसे-जैसे व्यवसायों ने कार्यस्थलों, किराने की दुकानों और फार्मेसियों के आसपास परिचालन और गतिशीलता को फिर से शुरू किया, वैसे-वैसे पलायन शुरू हुआ और बेरोजगारी दर 10.2 प्रतिशत तक कम हो गई। जून में मुद्रास्फीति बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई। भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 की दूसरी तिमाही में संकुचन में रही और यह वर्ष की दूसरी छमाही में ही था कि नीतिगत प्रोत्साहन, त्योहार से संबंधित खर्च और दबी हुई मांग के शुरू होने के कारण अनिश्चित और असमान बहाली ने आकार लेना शुरू कर दिया। इस बीच, आरबीआई के उपायों ने उधार लेने की लागत को 17 वर्षों में सबसे कम कर दिया और कॉरपोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र और डिबेंचर पर रेटिंग श्रेणियों में पूर्व-महामारी के स्तर तक सीमित कर दिया। अनुकूल वित्तीय स्थितियाँ उत्पन्न करके, आरबीआई ने बहाली का समर्थन किया। विभिन्न स्तरों की सरकारों और कॉरपोरेट्स ने इस अवसर का उपयोग वित्तीय बाजारों से रिकॉर्ड मात्रा में संसाधन जुटाने के लिए किया। कॉरपोरेट क्षेत्र में, डीलेवरेजिंग की सुविधा दी गई और कमजोरियों को कम करके और जारी बहाली में भागीदार बनने के लिए क्षेत्र को तैयार करके उच्च लागत वाले कर्ज को चुकाया जा सकता था। प्रचुर मात्रा में चलनिधि और आरबीआई के उपायों ने बैंक ग्राहकों के लिए धन की लागत को कम करते हुए, जमा और उधार दरों में नीतिगत दरों में कटौती का त्वरित और पूर्ण संचरण की सुविधा प्रदान की।

दूसरी लहर ने वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में रिकवरी को प्रभावित किया, लेकिन इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम गंभीर निकला। भारतीय अर्थव्यवस्था ने बाधित बहाली के साथ अपने प्रयास को नवीनीकृत किया, जिसने शेष वर्ष के दौरान सुदृढ़ता और गति प्राप्त की। यह अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो पूर्व-महामारी के स्तर को कम करेगा, और एक साल पहले 7.3 प्रतिशत की गिरावट से एक बदलाव को चिह्नित करेगा। निर्यात आशा की किरण रहा है, जिसमें अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में साल-दर-साल 49.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों, कमी और लोजीस्टिक नुकसान से प्रभावित हुआ है। घरेलू मांग के सामान्य स्थिति में लौटने से आयात मांग में वृद्धि हुई है। हालांकि रोजगार अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, और श्रम भागीदारी कम बनी हुई है। बैंक क्रेडिट ने गति प्राप्त करना शुरू कर दिया है जिसे बैंकों के तुलन-पत्र में दबाव कम होने से मदद मिली। मुद्रास्फीति हाल के महीनों में महामारी के उच्च स्तर से अधिक सहनीय स्तर तक कम हो गई है, हालांकि कच्चे तेल सहित उच्च वस्तुओं की कीमतों के बीच यह उच्च बना हुआ है।

संक्षेप में, आरबीआई के उपायों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसे बढ़ते वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण द्वारा बल मिला है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। निजी खपत और निवेश का काम अभी भी प्रगति पर है। आजीविका की बहाली और एमएसएमई का पुनरुद्धार एक कठिन कार्य है जो आगे किया जाना है। यह सुनिश्चित करते हुए कि आगे चलकर मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, आरबीआई संधारणीय आधार पर संवृद्धि को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करना जारी रखा है।

गवर्नर के वक्तव्य

जब इस अवधि का प्रमाणित कालक्रम दर्ज किया जाएगा, तो इतिहास कोविड-19 के प्रभाव को कम करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को महामारी के संकुचन की गहराई से बाहर निकालने में आरबीआई की भूमिका के साथ न्याय करेगा। मैं इतिहास के फैसले का अनुमान लगाने के दुस्साहस को खतरे में नहीं डालूंगा, लेकिन आज, भारत पहली लहर के सापेक्ष महामारी

की भविष्य की लहरों से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। इस यात्रा के दस्तावेजीकरण में, हालांकि, मुझे जो डर है वह यह कि इसे पूरी तरह से प्रशंसा नहीं मिल सकता है कि आरबीआई की महामारी प्रतिक्रिया को एक केंद्रीय एंकर के साथ शुरू किया गया था, यदि आप चाहें तो आवर्ती विचार कह सकते हैं, जो सब कुछ एक साथ एक सुसंगत पूर्णता में बांधता है। मैं गवर्नर के वक्तव्यों का उल्लेख करता हूं, जो आरबीआई की महामारी प्रतिक्रिया के संस्थागत ढांचे का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। मैं आपके साथ इन वक्तव्यों के कुछ उल्लेखनीय पहलुओं के बारे में एक अंदरूनी सूत्र के दृष्टिकोण को साझा करके भविष्य के आख्यान को संतुलित करने का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो कि तर्क, उच्च आवृत्ति संकेतकों और उपायों के सूक्ष्मता के बीच नज़रअंदाज़ हो जा सकता है।

गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने आत्म-विश्वास, दृढ़ विश्वास और दृढ़ता के छिपे हुए आंतरिक भंडार में गहराई से उतरते हुए, और महात्मा गांधी के शब्दों के प्रकाश द्वारा पथ प्रदर्शित, 27 मार्च 2020 से शुरू होकर अब तक 13 'महामारी' वक्तव्य दिए हैं। मौद्रिक नीति समिति ने असाधारण और अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए अपनी निर्धारित बैठक को पहले ही कर लिया।

वक्तव्यों की पहली उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे दूरदर्शितापूर्ण रहे हैं। वास्तव में, महामारी की औपचारिक घोषणा से पहले 6 फरवरी 2020 के बयान से ऐसा लग रहा था कि आने वाले बुरे दिनों का पूर्वाभास हो जाएगा। यह उस तरीके से परिलक्षित होता है जिसमें इसने बाजारों को आश्वासन दिया कि भविष्य की कार्रवाई के लिए नीतिगत स्थान उपलब्ध है, जिसे 'उपयुक्त समय पर' और 'उचित रूप से उपयोग' करने की आवश्यकता है। 27 मार्च 2020 के वक्तव्य ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए युद्ध स्तर के प्रयास को बढ़ाने का राष्ट्र से आह्वान किया, जबकि इस बात पर जोर दिया कि 'कठिन समय कभी नहीं रहता; केवल कठिन लोग और कठिन संस्था ही रहते हैं'। मेरी समझ में यह है कि अभूतपूर्व नुकसान और पृथक्करण की दृष्टि पहले से ही दिमाग में थी जब उस बयान ने आरबीआई को 'काम पर और मिशन मोड में' बताते हुए भयावह और तनावपूर्ण उम्मीदों को शांत कर दिया। यह पिछले खंड में उल्लिखित कई चलनिधि और विनियमकीय उपायों के साथ-साथ विवेकपूर्ण मानकों के आस्थगन को शामिल करते हुए लिखतों की शृंखला समूह को आक्रामक रूप से लागू करने के लिए लॉन्चिंग पैड बन गया।

दूसरा, ये वक्तव्य चतुर्दिक् निराशा के बीच प्रकाश और आशा की किरण थे। अदृश्य हत्यारे से लड़ने और विजयी होने के लिए राष्ट्र को लगातार प्रोत्साहन देने के अलावा, उन्होंने अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं - सरकारी कर्मियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्मचारी, डॉक्टर, स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा कर्मचारी; पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आवश्यक सेवाओं को चालू रखने वाले लोगों का उत्साहवर्धन किया और वायरस को मात देने के लिए उनके अथक प्रयास की सराहना की। आरबीआई में हमारे लिए संदेश विशिष्ट और व्यक्तिगत थे, जो बायो-बबल और इसके बाहर के लोगों तक पहुंचते थे, जिनमें वे भी शामिल थे जिन्होंने वक्तव्यों की तैयारी के लिए बौद्धिक, विश्लेषणात्मक और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की थी। दूसरी लहर में, 7 अप्रैल और 4 जून 2021 के वक्तव्यों ने वायरस का सामना करने के लिए मानवता की अदम्य भावना में विश्वास दोहराया, जिसमें कहा गया था कि समय का तकाज़ा डरने का नहीं बल्कि सामूहिक पराक्रम का है। 6 अगस्त 2021 के बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि आरबीआई "यथा उपयुक्त" मोड में, अपने सभी नीतिगत उपाय - मौद्रिक, विवेकपूर्ण या विनियामक - करने को तत्पर रहेगा। जैसे-जैसे दूसरी लहर कम हुई, अक्तूबर 2021 के वक्तव्य ने वैश्विक स्तर पर विकास के अलग-अलग रास्तों और अलग-अलग मौद्रिक नीति रुखों के बावजूद, भारतीय संवृद्धि-पथ में सामान्यीकरण और सुधार को मजबूत करने के लिए अर्थव्यवस्था को मार्गदर्शन प्रदान किया।

17 अप्रैल 2020 के वक्तव्य तक, यह स्पष्ट था कि प्रणाली स्तर की चलनिधि प्रदान करना पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि बैंकों की जोखिम विमुखता जैसी बाधाएं, छोटे, वंचितों और वास्तविक ऋणकर्ताओं के रास्ते में खड़ी थीं। इसने गवर्नर के बयानों की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता - एक व्यापक परामर्शी दृष्टिकोण - को सामने लाया, जिसमें उन सभी संस्थाओं तक सीधे पहुंचना शामिल था जो महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुई थीं, जिनमें छोटी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त

संस्थान (एमएफआई) शामिल हैं, यहां तक कि वैक्सीन निर्माता भी। जब बैंकों को उधार देने के लिए प्रेरित करना पर्याप्त नहीं था, तो आरबीआई ने ग्रामीण और सहकारी संस्थानों, एमएफआई और एचएफसी को ऋण देने के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) को प्रेरित किया। बाद के महीनों में, इस दृष्टिकोण से चलनिधि शृंखला का निर्माण और पुनर्गठन के लिए पहचाने जाने वाले विशिष्ट क्षेत्रों एवं आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं, संपर्क गहन सेवाओं और यहां तक कि व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए विनियामक राहत संभव हो सका।

चौथा, विशेष रूप से वित्तीय बाजारों के लिए, सतत और विश्वसनीय भावी मार्गदर्शन प्रदान करके वक्तव्य अपने आप में नीति का एक साधन बन गए। इसमें केंद्र की चिंताएँ समाहित हैं क्योंकि उस समय तक, आरबीआई ने पहले से ही पारंपरिक उपायों पर व्यावहारिक रूप से काम किया था, और अपरंपरागत उपाय शुरु कर दिए थे, जिसमें नीतिगत ब्याज दर और बैलेंस शीट नीतियों को विषम रूप से विस्तारित करना, यानी प्रणाली में चलनिधि डालने के लिए अपनी बैलेंस शीट का विस्तार शामिल है। वक्तव्यों ने वित्तीय स्थिरता, संवृद्धि के लिए अनुकूल वित्तीय स्थितियों और प्रतिफल वक्र की क्रमिक वृद्धि पर जोर दिया और सहकारी समाधान हासिल करने में बाजार सहभागियों और आरबीआई दोनों की साझा जिम्मेदारी है। अक्तूबर 2020 के वक्तव्य के समय तक, गवर्नर के बयानों ने आर्थिक बाहाली की दिशा में विचार करना शुरू कर दिया, अब तक के अधूरे रास्ते को देखते हुए और अधिक प्रयास करने और पुनर्जीवन के लिए आशान्वित होने का आह्वान किया। वित्तीय बाजारों में पैठ, डिजिटल भुगतान सुरक्षा, वित्तीय समावेश, उपभोक्ता संरक्षण और भुगतान और निपटान में नवोन्मेषों, जैसे गुणात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया गया। भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक बन गया, जिन्होंने बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच 365x24x7 त्वरित और निर्बाध निधि अंतरण की अपनी वास्तविक समय सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली चलाई।

पांचवां, वक्तव्य से मौद्रिक और राजकोषीय समन्वय में एक नई पारी की शुरुआत हुई। महामारी से संबंधित राजकोषीय प्रोत्साहन ने राजकोषीय घाटे को बढ़ा दिया और इसके परिणामस्वरूप केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा बाजार से उधारी का रिकॉर्ड स्तर बना। जैसा कि दिसंबर 2020 के वक्तव्य में बताया गया है, सरकार के लिए ऋण प्रबंधक और बैंकर के रूप में आरबीआई की भूमिका का परीक्षण किया गया था। कई वक्तव्यों में एक आवर्ती विषय यह रहा है कि आरबीआई के नीतिगत उपायों ने उधार कार्यक्रम के सुचारू मार्ग को सुनिश्चित करते हुए लगभग दो दशकों में सबसे कम उधार लेने की लागत और सार्वजनिक ऋण के स्टॉक की उच्चतम परिपक्वता सुनिश्चित की है। राज्यों के लिए, अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा बढ़ा दी गई थी और समेकित निधि से निकासी को नियंत्रित करने वाले नियमों में ढील दी गई थी। चलनिधि सुविधाओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली क्रेडिट गारंटी योजनाओं से जोड़ा गया था। मौद्रिक राजकोषीय समन्वय का एक उदाहरण, जिसे 7 अप्रैल 2021 के वक्तव्य द्वारा रिकॉर्ड में रखा गया था, सरकार द्वारा मौद्रिक नीति ढांचे में यथास्थिति बनाए रखना था और इस अवधि को विस्तारित कर सरकार और आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने को कहा गया था। फिर भी एक और उदाहरण है कि 4 जून, 6 अगस्त, 8 अक्तूबर और 8 दिसंबर, 2021 के वक्तव्य सरकार द्वारा मजबूत आपूर्ति-पक्ष हस्तक्षेपों का एक सेट है, जिसने तत्कालीन खाद्य मुद्रास्फीति की कमर तोड़ दी और हेडलाइन मुद्रास्फीति को सहनशीलता बैंड में वापस ला दिया।

छठा, वैश्विक संवृद्धि और दृष्टिकोण, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक स्पिलओवर के प्रभाव और मौद्रिक नीति की शुरुआत पर विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर गवर्नर की बातचीत से प्रत्यक्ष विचार सामने आए। अंत में, यह अंतर्दृष्टि अमूल्य साबित हुई। ऐसी स्थिति में जब कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं सख्त मौद्रिक नीति की दौड़ में शामिल हो रही थीं और उन्नत अर्थव्यवस्थाएं सामान्यीकरण की घोषणा कर रहे थे या नीतिगत दरों को बढ़ाने में ईएमई में शामिल हो रहे थे, भारत अपनी स्थिति पर कायम रहा और यह उन कुछ देशों में से एक है, जिन्होंने इसके बावजूद, निभावकारी मौद्रिक नीति[6] को बरकरार रखा है। यह तो समय ही बताएगा कि भारत ने इसे सही पाया है या नहीं, लेकिन अभी तक,

[6] वास्तव में, 8 दिसंबर, 2021 के वक्तव्य में कहा गया है कि "हमारा मकसद एक सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करना है जो कि सही समय पर हो।"

इस दृष्टिकोण ने अच्छा काम किया है और भविष्य में एक ऐसा रास्ता तय करने में मदद किया है जो दुनिया से अलग है।

निष्कर्ष

केंद्रीय बैंकों की पवित्र परंपरा में, एक संस्था के रूप में आरबीआई सुर्खियों की चकाचौंध से दूर, शांत और जमीन से जुड़ा रहना पसंद करता है। फिर भी संकट आने पर यह सफलतापूर्वक कार्य करता है। जब काम पूरा हो जाता है, स्थिति बहाल हो जाती है और समष्टि आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो जाती है तो यह पुन: शांत और चौकन्ना हो जाता है। महामारी भविष्य को आकार देना जारी रखती है, लेकिन आरबीआई सशस्त्र और लड़ाई के लिए तैयार रहता है। जैसा कि महामारी के अनुभव से पता चलता है - अत्यधिक अस्थिर और अनिश्चित परिस्थितियों का लगातार आकलन करते हुए और अर्थव्यवस्था को झटकों से बचाने के लिए तैयार रखते हुए, आरबीआई ने इस उद्देश्य के लिए अपने सभी लिखतों का, पारंपरिक और नए तरीके से उपयोग किया है। महामारी के सबक को आत्मसात किया जाएगा और आरबीआई पहले की तुलना में अधिक मजबूत और अधिक लचीला बनकर उभरेगा और संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता के अपने अधिदेश के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा।

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

जॉम्बी और सृजनात्मक विध्वंस की प्रक्रिया

मददगार के रूप में बैड बैंक :
भारत के लिए विभिन्न देशों के अनुभवों से सीख

भारतीय विनिर्माताओं के रुख पर कोविड-19 का प्रभाव

*अर्थव्यवस्था की स्थिति**

घरेलू समष्टिआर्थिक स्थितियां एक ऐसे रास्ते पर चल रही हैं जो वैश्विक विकास से अलग हो रहा है। भारत में, तीसरी लहर से उभरने के साथ ही आर्थिक गतिविधियां मजबूती और कर्षण प्राप्त कर रही हैं। मांग मानकों पर आशावाद और उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास में वृद्धि के साथ विनिर्माण और सेवाओं दोनों विस्तार में हैं। जैसे-जैसे व्यवसाय एक नई सामान्य स्थिति में लौटते हैं, नौकरी के परिदृश्य में सुधार की उम्मीद है। ग्रामीण मांग में कमी के कुछ संकेतों के साथ कृषि क्षेत्र की स्थिति मजबूत बनी हुई है। भले ही मौद्रिक नीति उदार बनी हुई है, वैश्विक उथल-पुथल ने वित्तीय स्थितियों में सख्ती ला दी है।

भूमिका

ओमिक्रॉन के कम विषाणुजनित प्रभावों को देखते हुए भारत में आर्थिक गतिविधि जनवरी में कुछ नरमी के दौर से उबर रही है। बेहतर योजना और रणनीति, आपूर्ति श्रृंखला लॉजिस्टिक्स के प्रबंधन और त्वरित डिजिटलीकरण ने फर्मों को महामारी के जोखिम को कम करने में मदद की। पहली दो लहरों के विपरीत, टीकाकरण की त्वरित गति, सामान्य आर्थिक स्थिति पर बेहतर संभावनाएं, घरेलू आय और खर्च के कारण समग्र उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास लचीला रहा।

16 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ा है, जिसमें लगभग 95 प्रतिशत वयस्क आबादी को पहली खुराक दी गई है, जबकि 77 प्रतिशत ने दोनों खुराक प्राप्त की हैं। अब तक 15-18 साल के आयु वर्ग में 5.24 करोड़ लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है। 16 फरवरी, 2022 तक 60 से अधिक आयु वर्ग के 1.79 करोड़ से अधिक लोगों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को एहतियाती खुराक का टीका लगाया गया है। दैनिक संक्रमण और संक्रमण की कुल संख्या में कमी के साथ, भारत तीसरी लहर से काफी आगे निकल गया है।

फरवरी 2022 में, मोबिलिटी संकेतक पूर्व-महामारी के स्तर पर पहुंच गए हैं जबकि बेरोजगारी में गिरावट आई है। जैसे-जैसे व्यवसाय नए सामान्य में लौटते हैं, काम पर रखने की गतिविधियों ने कर्षण प्राप्त कर लिया है - कई भारतीय फर्मों, वैश्विक बड़े फर्मों और स्टार्टअप ने भारत के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती योजनाओं की घोषणा की है[1]। माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत राजस्व संग्रह, मजबूत टोल संग्रह और ई-वे बिल जेनरेशन सभी चल रहे पुनरुद्धार को प्रतिबिंबित करते हैं। सरकार द्वारा घोषित उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कृषि क्षेत्र उत्साहित है। 2021-22 की चौथी तिमाही के दौरान उत्पादन की मात्रा, नए ऑर्डर और नौकरी के परिदृश्य जैसे मांग मानकों पर आशावाद के साथ विनिर्माण गतिविधि विस्तार में बनी हुई है। फर्मों को क्षमता उपयोग और समग्र वित्तीय स्थिति में और सुधार की उम्मीद है। सेवा क्षेत्र की फर्में मांग की स्थिति को लेकर आशावादी बनी रहीं, जबकि समग्र कारोबारी स्थिति, कुल बिक्री और रोजगार की स्थिति पर उनकी उम्मीदें मामूली रूप से कम हुई हैं।

इस पृष्ठभूमि में, शेष आलेख को पाँच खंडों में विभाजित किया गया है। अगले खंड में विकसित हो रही वैश्विक आर्थिक और वित्तीय बाजार की स्थिति को समझाया गया है। खंड III घरेलू अर्थव्यवस्था में वर्तमान विकास का विश्लेषण करता है। खंड IV उभरती वित्तीय बाजार स्थितियों की जांच करता है। अंतिम खंड चर्चा को सारांशित करता है।

II. वैश्विक व्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए दृष्टिकोण नकारात्मक जोखिमों से घिरा है। ओमिक्रॉन का समग्र गतिविधि पर दबाव जारी है क्योंकि कई क्षेत्रों में गतिशीलता प्रतिबंध और रोकथाम के उपाय फिर से शुरू हो गए हैं। इसके उत्परिवर्तन महामारी के भविष्य के

* यह आलेख मधुरेश कुमार, शशिधर एम. लोकरे, कुणाल प्रियदर्शी, राजीव जैन, विनीत कुमार श्रीवास्तव, हर्षिता केशन, रिग्जेन यांगडॉल, प्रशांत कुमार, जोबिन सेबेस्टियन, रचित सोलंकी, सक्षम सूद, प्रियंका सचदेवा, अभिनंदन बोराड, दीपिका रावत, जिबिन जोस, अवनीश कुमार, राजस सरॉय, आशीष थॉमस जॉर्ज, देबा प्रसाद रथ और समीर रंजन बेहरा के द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

[1] *https://www.india.com/business/new-year-new-job-heres-a-list-of-companies-with-promising-hiring-plans-for-2022-employment-opportunities-5201022/*

विकास के लिए उच्च अनिश्चितता प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि केंद्रीय बैंकों की बढ़ती संख्या भयप्रद मुद्रास्फीति के उच्च स्तर को देखती है और उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में मौद्रिक नीति को सख्त करने के लिए दौड़ती है, वैश्विक सुधार की गति जोखिम में है। वित्तीय स्थितियां सख्त हो रही हैं क्योंकि बाजार चलनिधि में बदलाव के लिए तैयार हैं और ब्याज दरों के बढ़ने से बांड और इक्विटी बाजारों के साथ-साथ उभरती दुनिया में मुद्रा बाजारों में व्यापक बिकवाली हो रही है। आपूर्ति की बाधाओं के साथ-साथ खाद्य और ऊर्जा की कीमतों का सख्त होना मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत और व्यापक बनाए हुए है। भू-राजनीतिक तनावों का बढ़ना परिदृश्य को अनिश्चितता की एक और परत प्रदान करता है।

25 जनवरी, 2022 को जारी अपने नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डबल्यूईओ) अपडेट में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) ने वैश्विक विकास को 2021 में 5.9 प्रतिशत से कम करके 2022 में 4.4 प्रतिशत करने का अनुमान लगाया है - जो अपने अक्टूबर 2020 के अनुमान से आधा प्रतिशत कम है (सारणी 1)। आईएमएफ ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति में व्यवधान को बढ़ी हुई मुद्रास्फीति के पैरोकारों के रूप में मानता है, इस पूर्वानुमान के साथ कि वे पहले की कल्पना से अधिक समय तक बने रहेंगे।

वैश्विक समग्र क्रय प्रबंध सूचकांक (पीएमआई), हालांकि अभी भी विस्तार क्षेत्र में है, जनवरी में गिरकर 18 महीने के निचले स्तर 51.4 पर आ गया (चार्ट 1ए)। कम आने वाले नए ऑर्डर के कारण वैश्विक सेवाओं का पीएमआई जनवरी में गिरकर 18 महीने के निचले स्तर 51.3 पर आ गया, जो दिसंबर में 54.7 था। नए कार्य आदेशों की कमजोर वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा में गिरावट, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और बढ़ते कोविड-19 संक्रमणों के कारण वैश्विक विनिर्माण पीएमआई भी जनवरी में 15 महीने के निचले स्तर 53.2 पर गिर गया – जो दिसंबर में 54.3 था। सौभाग्य से, पिछले महीनों (चार्ट 1 बी) के सापेक्ष जनवरी में

सारणी 1: जीडीपी वृद्धि का अनुमान – चयनित एई और ईएमई

(प्रतिशत)

देश	2021		2022	
	अक्टूबर 2021	जनवरी 2022	अक्टूबर 2021	जनवरी 2022
विश्व*	5.9	5.9	4.9	4.4
विकसित अर्थव्यवस्था				
यूएस	6.0	5.6	5.2	4.0
यूके	6.8	7.2	5.0	4.7
यूरो क्षेत्र	5.0	5.2	4.3	3.9
जापान	2.4	1.6	3.2	3.3
उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्था				
ब्राज़ील	5.2	4.7	1.5	0.3
रूस	4.7	4.5	2.9	2.8
भारत	**9.5**	**9.0**	**8.5**	**9.0**
चीन	8.0	8.1	5.6	4.8
दक्षिण अफ्रीका	5.0	4.6	2.2	1.9

स्रोत: आईएमएफ़।

इनपुट मूल्य दबाव और आपूर्तिकर्ताओं की डिलीवरी का समय कम हो गया है (चार्ट 1 बी)।

आपूर्ति श्रृंखला और रसद दबावों में मामूली कमी को दर्शाते हुए, यूनाइटेड नेशन्स कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवेलपमेंट (यूएनसीटीएडी) ने अब वैश्विक व्यापार और सेवा व्यापार की मात्रा को पिछली तिमाही के 0.2 प्रतिशत से 2021 की चौथी तिमाही में बढ़ाकर 2.2 प्रतिशत (क्यू-ओ-क्यू) कर दिया है। तदनुसार, विश्व पण्य वस्तु व्यापार की मात्रा 2021 में 9.1 प्रतिशत बढ़ी होगी। यह भी आईएमएफ और सीपीबी नीदरलैंड के पूर्वानुमान से प्राप्त है (चार्ट 2 ए और बी) ।

चार्ट 1: वैश्विक उच्च आवृति संकेतक

ए. वैश्विक पीएमआई

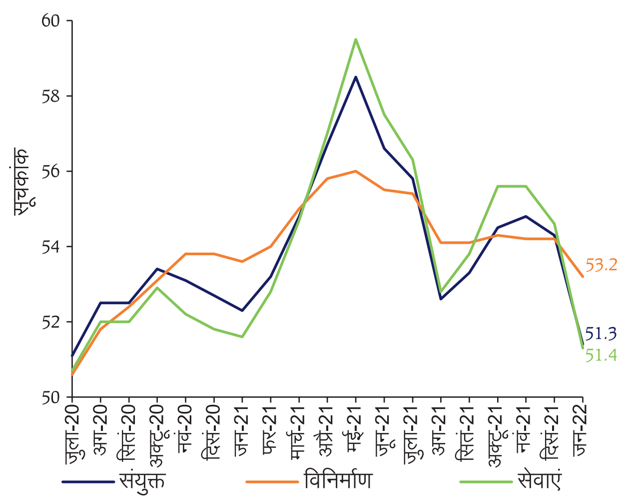

बी. विनिर्माण पीएमआई के चुनिंदा घटक

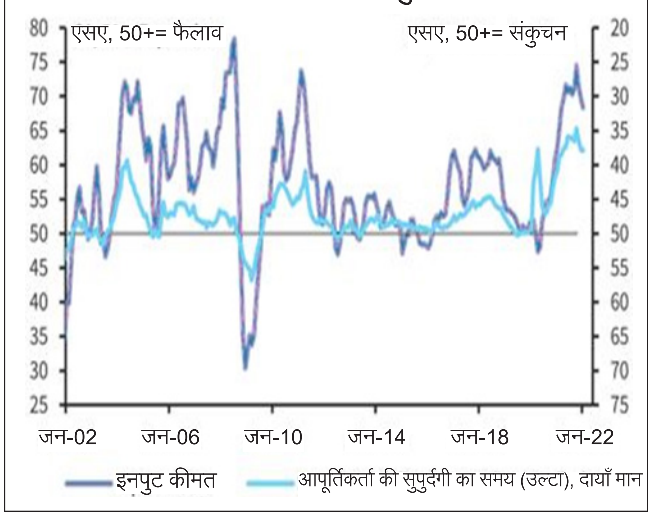

स्रोत: आईएचएस मार्किट; और बार्कलेय।

बाल्टिक ड्राई सूचकांक, सूखी थोक वस्तुओं के लिए शिपिंग शुल्क का एक उपाय, जनवरी में, दिसंबर 2020 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया (चार्ट 3)।

हालांकि, सभी प्रमुख समुद्री मार्गों पर कंटेनर फ्रेट दरें अभी भी उनके पूर्व-महामारी स्तरों से अधिक हैं (चार्ट 4ए)। चीन से अमेरिका के पश्चिमी तट के बंदरगाहों के लिए माल ढुलाई की दरें उनके पूर्व-कोविड स्तरों की तुलना में दस गुना अधिक रही, जिसका अर्थ है कि अमेरिका में माल की मजबूत मांग रही, आपूर्ति श्रृंखला की अड़चनें अमेरिकी बंदरगाहों पर अधिक टर्नअराउंड समय और ट्रक की कमी का कारण बनती हैं (चार्ट 4 बी)।

ब्लूमबर्ग कमोडिटी कीमत सूचकांक, जो नवंबर में गिर गया था, फरवरी के पहले सप्ताह में 7 साल के उच्च स्तर को छूने के

चार्ट 2: विश्व व्यापार की मात्रा का विश्लेषण

ए. माल और सेवाओं की विश्व व्यापार की मात्रा में रुझान

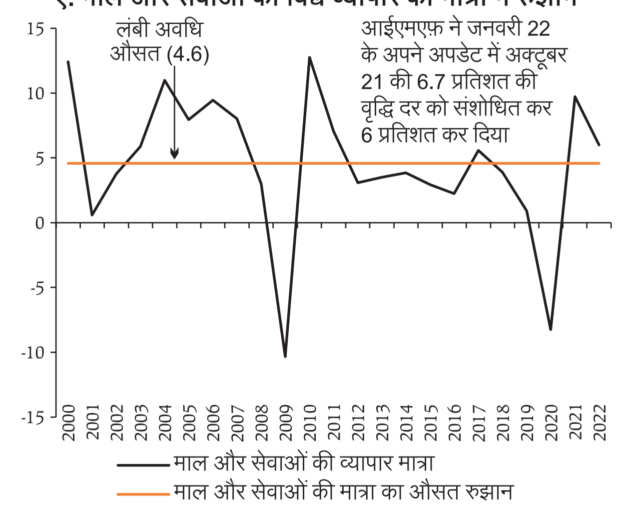

बी. विश्व पण्य व्यापार की मात्रा में रुझान

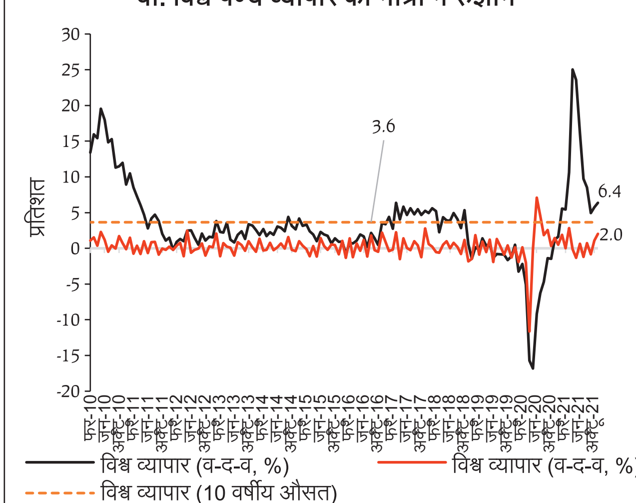

स्रोत: सीपीबी नीदरलैंड; और आईएमएफ़।

चार्ट 3: बाल्टिक ड्राइ सूचकांक

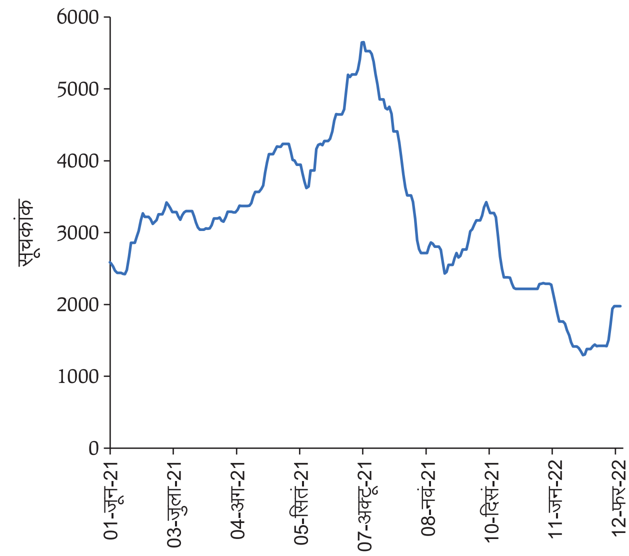

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

लिए फिर से बढ़ना शुरू कर दिया (चार्ट 5 ए)। 2014 के बाद से पहली बार फरवरी की शुरुआत में ब्रेंट के 95 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के रिकॉर्ड उच्च स्तर के साथ अधिकतर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई खासकर कच्चे तेल के लिए कीमतों में तेजी आई। मध्य पूर्व और मध्य एशिया में भू-राजनीतिक कटुता आपूर्ति में व्यवधान की अटकलों को हवा और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को समर्थन दे रही है (चार्ट 5बी)। सोने की कीमतों को मजबूत अमेरिकी डॉलर से सुरक्षित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, हालांकि भू-राजनीतिक तनाव सराफा को समर्थन प्रदान करना जारी रखते हैं (चार्ट 5सी)। एफएओ खाद्य कीमत सूचकांक जनवरी 2022 में औसतन 135.7 अंक रहे, दिसंबर 2021 की तुलना में 1.1 प्रतिशत अधिक और बड़े पैमाने पर वनस्पति तेलों और डेयरी उप-सूचकांक द्वारा संचालित है (चार्ट 5 डी)।

मुद्रास्फीति अधिकांश एई और कुछ ईएमई में बहु-दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गई है (चार्ट 6)। अमेरिका में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति जनवरी 2022 में 7.5 प्रतिशत तक पहुंच गई - 1982 के बाद से इसका उच्चतम स्तर रहा। व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मूल्य सूचकांक द्वारा मापा गया फेड का प्रचलित मुद्रास्फीति अनुमान दिसंबर में बढ़कर 5.8 हो गया। समन्वित रूप से कोर पीसीई मुद्रास्फीति भी उसी महीने 4.9 प्रतिशत करीब 40 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। यूके में सीपीआई मुद्रास्फीति भी दिसंबर में बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई – जो जनवरी 1997 में शुरू हुई डेटा श्रृंखला में सबसे अधिक है। यूरो क्षेत्र की मुद्रास्फीति दिसंबर में 5 प्रतिशत से जनवरी में 5.1 प्रतिशत के नए शिखर पर पहुंच गई। ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में, ब्राजील और रूस में सीपीआई मुद्रास्फीति जनवरी 2022 में बढ़कर क्रमशः 10.38

चार्ट 4 : समुद्री मालभाड़ा कीमतों का विश्लेषण

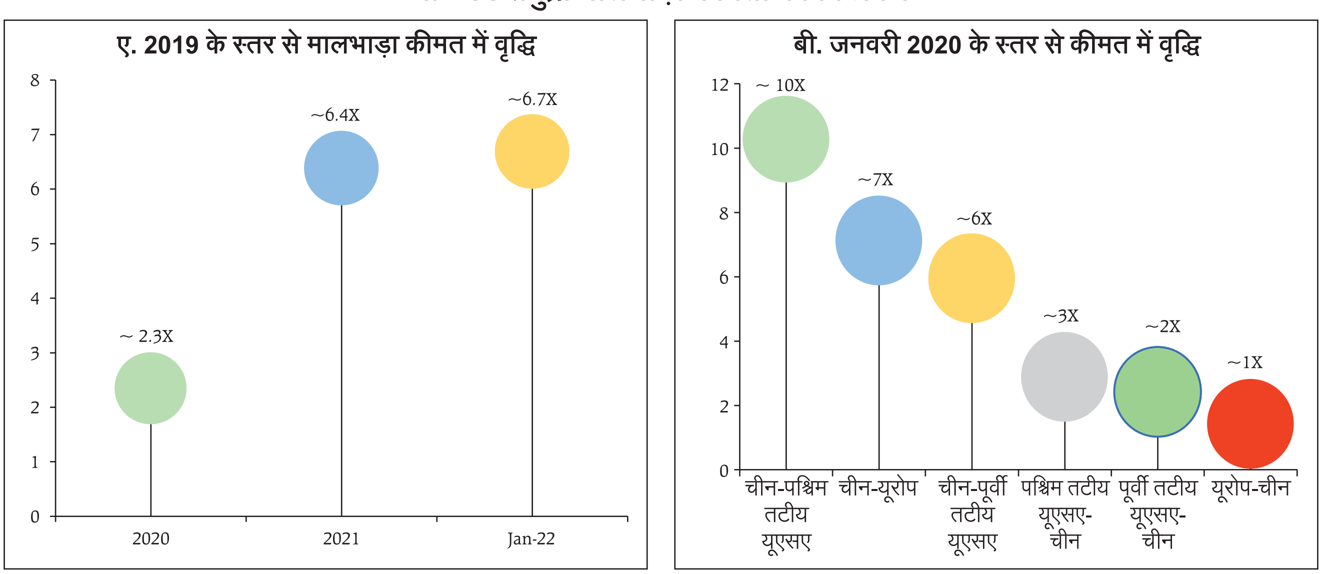

स्रोत: रिउटर्स।

चार्ट 5: कमोडिटी और खाद्य कीमतें

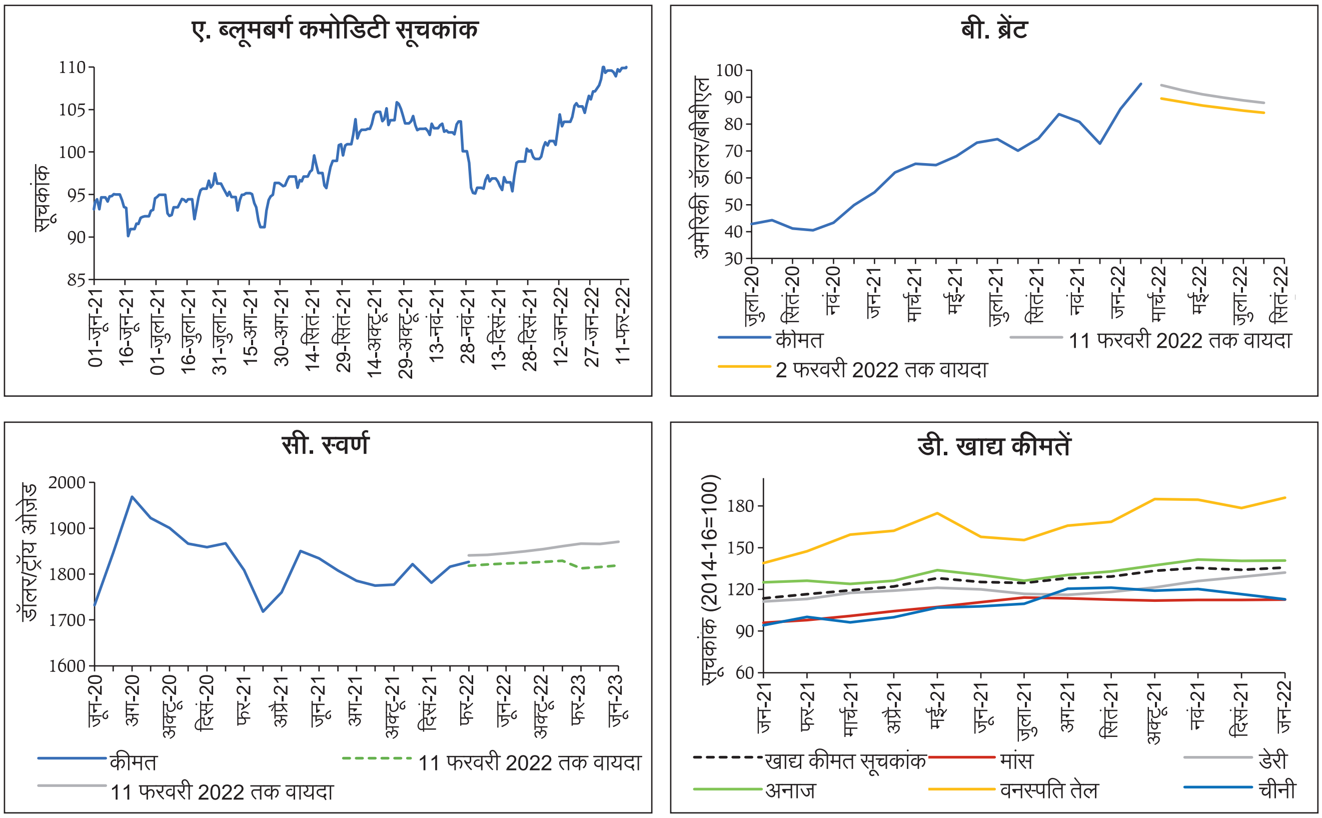

स्रोत: ब्लूमबर्ग; वर्ल्ड बैंक पिंक शीट; और एफ़एओ।

प्रतिशत और 8.7 प्रतिशत हो गई, जो दिसंबर 2021 में क्रमशः 10.06 प्रतिशत और 8.4 प्रतिशत थी।

वैश्विक वित्तीय बाजार जनवरी की शुरुआत से तेज बिकवाली से अस्थिर थे और नीतिगत धुरी, भू-राजनीतिक तनाव और

चार्ट 6: मुद्रास्फीति

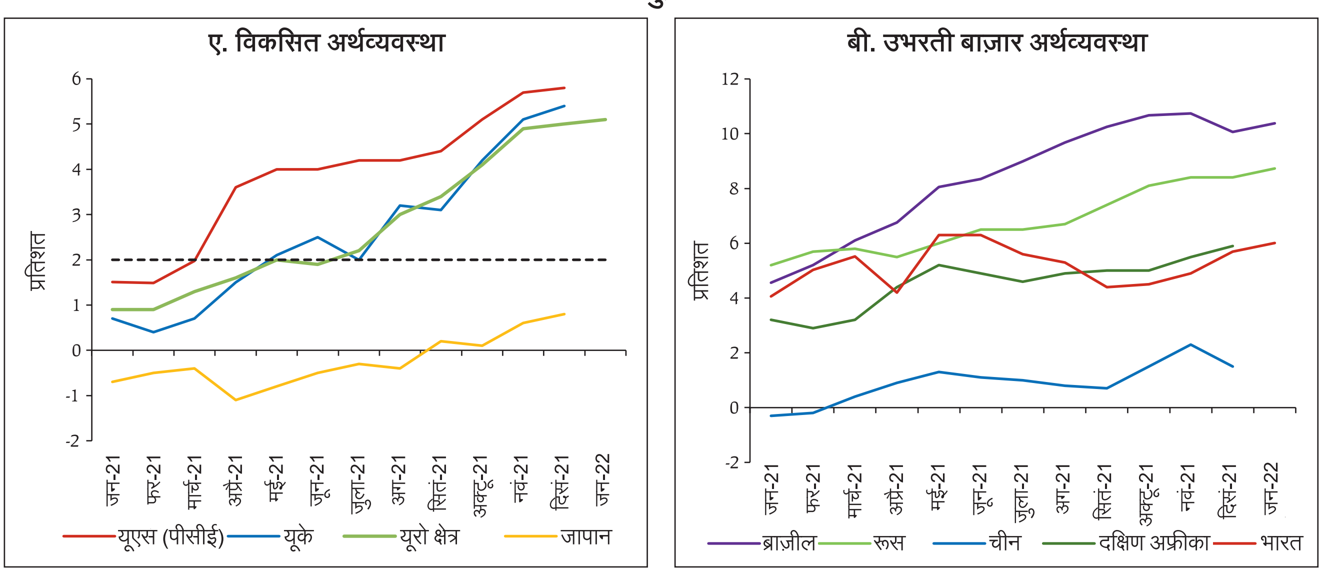

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

वैश्विक वृद्धि की धीमी गति के संयोजन से निवेशकों की भावनाओं को झटका लगा है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में, मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) वर्ल्ड इक्विटी सूचकांक दोनों एई और ईएमई स्टॉक सूचकांक द्वारा संचालित अक्टूबर 2021 के स्तर तक गिर गया (चार्ट 7ए)। बॉन्ड बाजारों में, यूएस 10-वर्षीय ट्रेजरी प्रतिफल वर्ष की शुरुआत के बाद से 25 बीपीएस से अधिक मजबूत हुआ; इन स्तरों को अंतिम बार फरवरी 2020 में देखा गया था। बॉन्ड बाजार सहभागियों को प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों द्वारा पहले की अपेक्षा अधिक आक्रामक रूप में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। इसके अलावा, अल्पकालिक दरों में और भी अधिक वृद्धि के साथ एक चपटा प्रतिफल वक्र उभरा है (चार्ट 7 बी)। मजबूत आर्थिक आंकड़ों की हलचल और फेड के अधिक आक्रामक रुख के बीच जनवरी की दूसरी छमाही में अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ (चार्ट 7सी)। इसके साथ-साथ, अधिकांश ईएमई मुद्राओं का मूल्यह्रास हुआ, निवल पूंजी बहिर्वाह से इन अधोमुखी गति में वृद्धि हुई (चार्ट 7डी)।

अधिकतर एई केंद्रीय बैंकों द्वारा दर वृद्धि के लिए आगे मार्गदर्शन देने या दायित्व लेने के साथ, मौद्रिक नीति कार्रवाइयों और रूखों का देशों में विचलित होना जारी है (चार्ट 8)। अपनी जनवरी की बैठक में, यूएस फेड ने घोषणा की कि वह मार्च की शुरुआत तक मात्रात्मक सहजता को धीरे धीरे समाप्त कर देगा, साथ ही आगे मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा कि यह जल्द ही फेडरल फ़ंड दर के लिए लक्ष्य सीमा बढ़ाने के लिए उपयुक्त होगा। इसने तुलन पत्र में कमी के सिद्धांतों को भी निर्धारित किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) ने फरवरी में लगातार दूसरी बार दरों में बढ़ोतरी की क्योंकि इसने अपनी बेंचमार्क दर को 25 आधार अंक (बीपीएस) बढ़ाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया, जो कि 40 बीपीएस की संचयी वृद्धि थी। रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी

चार्ट 7 : वित्तीय बाज़ार

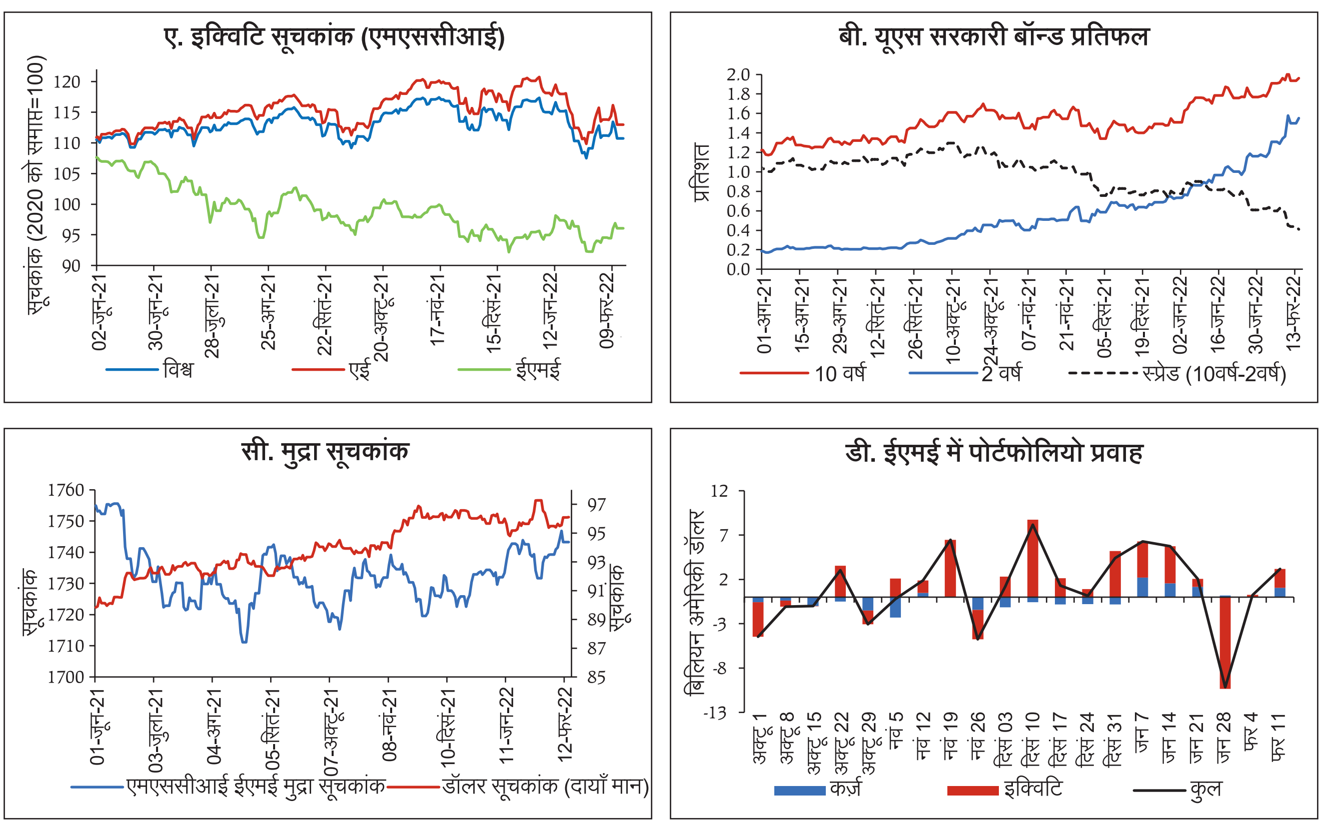

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आईआईएफ़।

चार्ट 8 : चुनिंदा देशों के केंद्रीय बैंकों की दर कार्रवाइयां

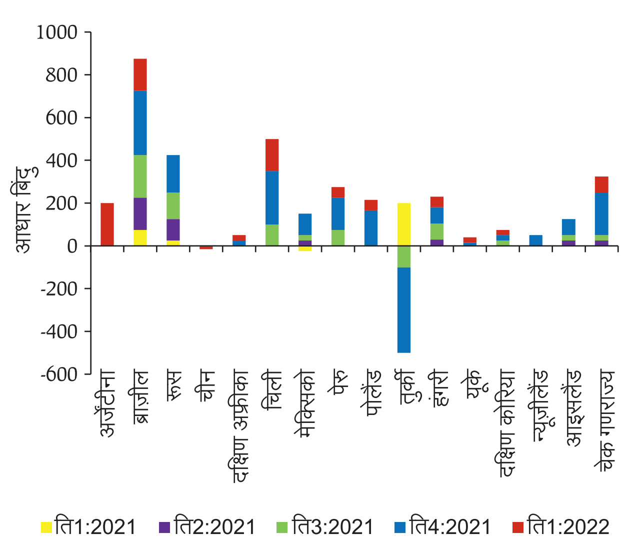

स्रोत: केंद्रीय बैंक वेबसाइट।

नीतिगत दर को बनाए रखा लेकिन फरवरी की शुरुआत में अपने बांड खरीद कार्यक्रम को रोकने की घोषणा की। उच्च मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को स्वीकार करते हुए बैंक ऑफ जापान ने अपनी बेंचमार्क दर अपरिवर्तित रखी। इसी तरह, बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन आर्थिक मंदी अवशोषित होने के कारण इसने अपनी नीतिगत दर पर अपने असाधारण आगे के मार्गदर्शन को वापस ले लिया। सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने अपने एस$एनईईआर पॉलिसी बैंड की मूल्यवृद्धि दर को बढ़ाकर अपने पहले सामान्य से अलग कदम में सात वर्षों में दूसरी बार अपनी मौद्रिक नीति व्यवस्था को कड़ा किया। ईएमई केंद्रीय बैंकों में, चिली और ब्राजील ने क्रमशः जनवरी और फरवरी में अपनी बेंचमार्क दरों में 150 बीपीएस की बढ़ोतरी की। फरवरी 2022 में बैंक ऑफ रशिया ने लगातार आठवीं बैठक के लिए अपनी प्रमुख दरों को 100 बीपीएस से बढ़ाकर 10.5 प्रतिशत कर दिया। इसी तरह, हंगरी, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका ने भी पिछले महीने अपनी नीतिगत दरों में क्रमश: 50 बीपीएस, 25 बीपीएस और 50 बीपीएस की वृद्धि की। इंडोनेशिया ने मार्च से सितंबर 2022 तक तीन चरणों में लागू होने वाले वाणिज्यिक बैंकों के लिए घरेलू मुद्रा आरक्षित आवश्यकता में 300 बीपीएस की वृद्धि की घोषणा करके चलनिधि सामान्यीकरण की दिशा में एक कदम उठाया है। तुर्की ने अपनी जनवरी की बैठक में 500 बीपीएस की संचयी कमी के बाद विराम लिया। सितंबर और दिसंबर 2021 के बीच दरें। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने लगातार दूसरी बार अपनी 1 साल की ऋण मूल दर (एलपीआर) में 10 बीपीएस की कटौती कर 3.7 प्रतिशत की। इसने 5 साल के एलपीआर को भी कम कर दिया -जो बंधक के मूल्य निर्धारण के लिए बेंचमार्क है – जिसमें 5 बीपीएस से 4.6 प्रतिशत तक कमी की, अप्रैल 2020 के बाद इसकी पहली कटौती रही। चीन ने 1-वर्षीय मध्यम अवधि के उधार सुविधा के लिए ऋण और 7-दिवसीय रिवर्स पुनर्खरीद समझौते में 10 बीपीएस दरों की कमी की।

संक्षेप में, वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण को महामारी द्वारा बंधक बना रखा गया है, यहां तक कि भू-राजनीतिक लड़ाई और वित्तीय बाजारों में तेज अस्थिरता अनिश्चितता प्रदान करती है। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, उत्पादन लाइनों में तनाव, ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव और मजदूरी के दबाव में मुद्रास्फीति के बढ़ने का जोखिम होता है, जिससे नीतिगत व्यापार में तेजी आती है। पूंजी बहिर्वाह, मूल्यह्रास मुद्राओं और बिगड़ती राजकोषीय स्थिति के रूप में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए जोखिम ने दृष्टिकोण को बढ़ाया और अंधकारमय किया है।

III. घरेलू विकास

घरेलू समष्टिआर्थिक स्थितियां वैश्विक विन्यास से अलग हो रही हैं। तीसरी लहर में मामूली कमी के बाद आर्थिक गतिविधियां में रिकवरी मजबूती और कर्षण प्राप्त कर रही है। 24 जनवरी, 2022 को भारत में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 22.36 लाख हो गई, जो 28 दिसंबर, 2021 को 84,349 थी। हालांकि, दैनिक संक्रमण 21 जनवरी, 2022 के बाद से कम हो गया और 14 फरवरी, 2022 को 3.47 के शिखर से घटकर 27,409 हो गया। 20 जनवरी, 2022 को लाख (चार्ट 9ए)। टीकाकरण के मोर्चे पर, जनवरी के पहले दस दिनों में दैनिक टीकाकरण दर बढ़कर 90 लाख से अधिक हो गई, लेकिन तब से धीमी हो गई है। वर्तमान में, जबकि दैनिक टीकाकरण लगभग 50 लाख का है, कुल टीकाकरण 173 करोड़ खुराक को पार कर गया है (चार्ट 9बी)।

नए संक्रमणों में गिरावट के साथ, फरवरी 2022 में गतिशीलता में सुधार हुआ, गूगल और एपल गतिशीलता सूचकांक क्रमिक रूप से और साथ ही एक साल पहले के स्तरों को पार कर गए। खुदरा और मनोरंजन गतिविधियों, उद्यानों, ट्रांजिट स्टेशनों

चार्ट 9 : कोविड-19 के मामले और टीकाकरण

ए. कोविड-19 दैनिक मामले और मृत्यु 7-दिवसीय एमए

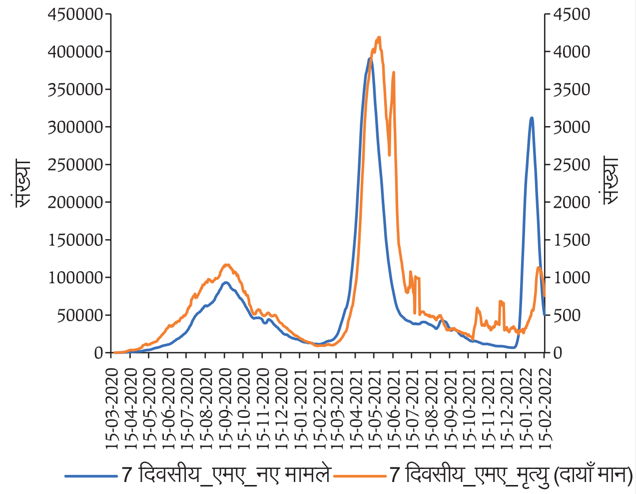

बी. दैनिक टीकाकरण का 7-दिवसीय गतिशील औसत

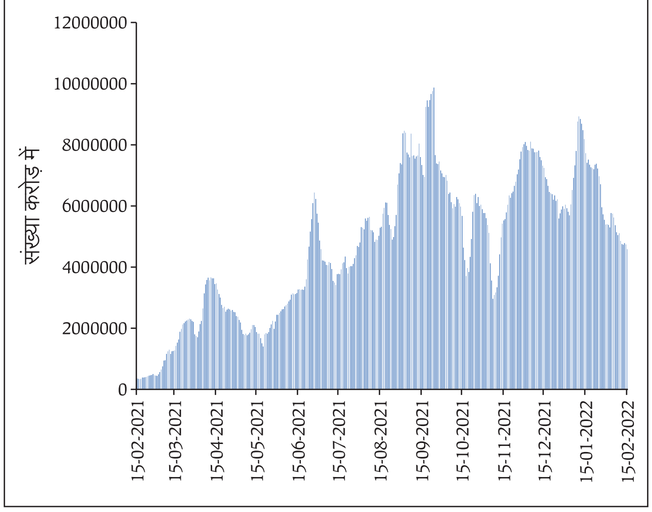

स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफ़डबल्यू)

और कार्यस्थलों के आसपास गतिशीलता के लिए गूगल गतिशीलता सूचकांक पूर्व-महामारी के स्तर पर पहुंच गया, जबकि एपल गतिशीलता सूचकांक सभी प्रमुख शहरों में ऊपर की ओर चला गया (चार्ट 10ए और 10बी)। गतिविधि की बहाली के साथ, बिजली उत्पादन, फरवरी के पहले पखवाड़े में महामारी से पहले के स्तर को पार कर गया (चार्ट 10सी)।

चार्ट 10: आर्थिक गतिविधियों पर कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रभाव

ए. गूगल मोबिलिटी परिवर्तन: भारत

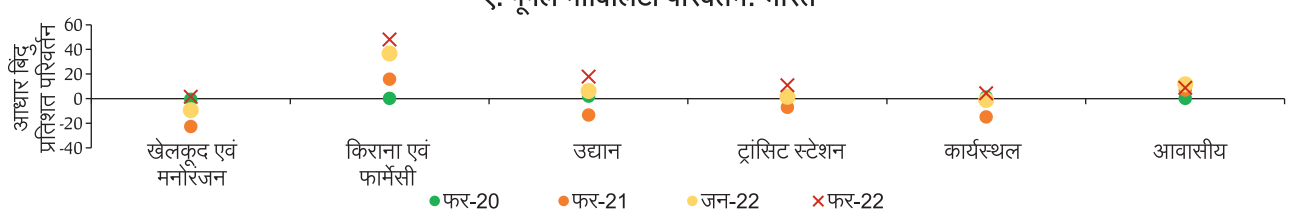

बी. शहर-वार एप्पल मोबिलिटी ड्राइविंग

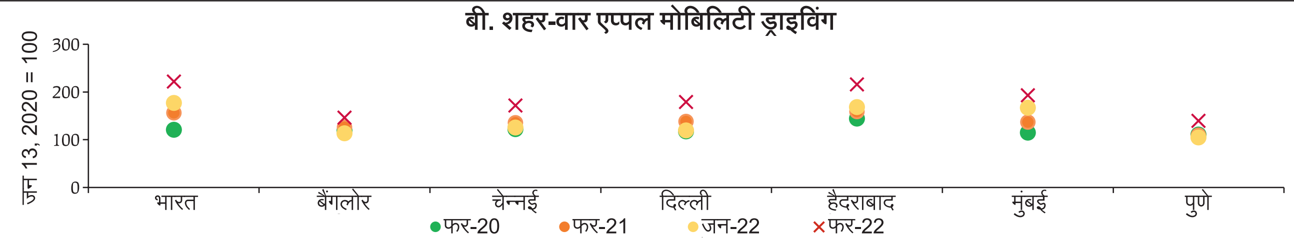

सी. विद्युत उत्पादन

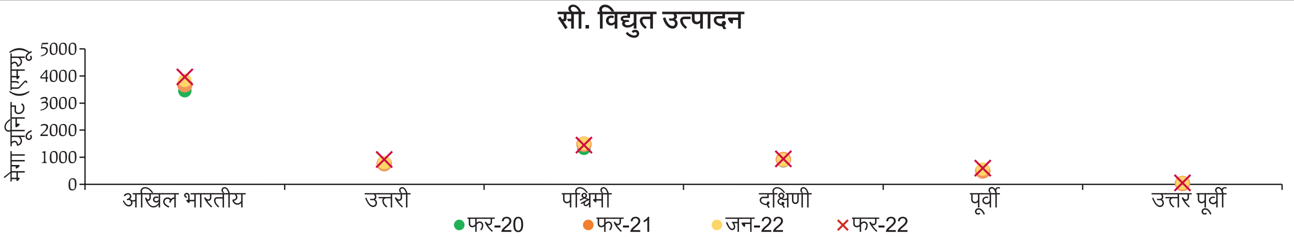

स्रोत: गूगल; सीईआईसी; और पोसोको।

चार्ट 11 : ई-वे बिल और टोल संग्रह

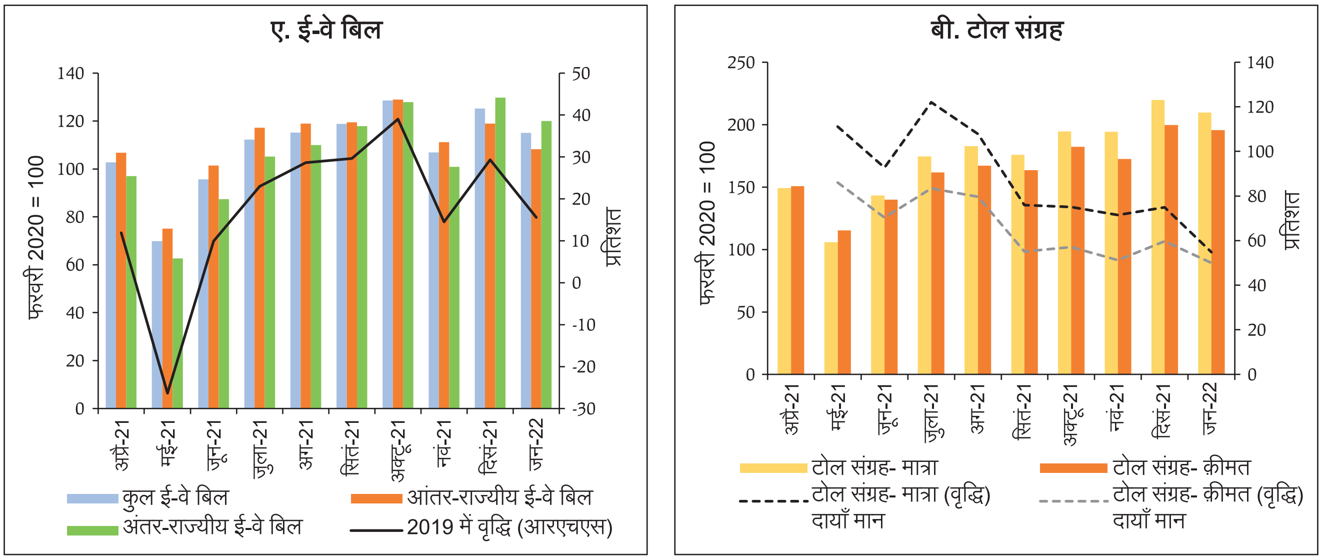

स्रोत: जीएसटीएन; भारतीय रिज़र्व बैंक; और लेखकों की अपनी गणना।

सकल मांग

तीसरी लहर के बावजूद, ई-वे बिल जनरेशन महामारी पूर्व स्तरों से ऊपर रहा (चार्ट 11 ए), हालांकि गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण जनवरी में क्रमिक गिरावट आई थी। टोल संग्रह जनवरी 2022 में आघातसहनीय बना रहा, भले ही आधार प्रभाव के घटने के कारण वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि घटकर 54.8 प्रतिशत हो गई (चार्ट 11 बी)।

गतिशीलता प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के साथ पेट्रोलियम की खपत में कमी आई। जनवरी 2022 में सभी प्रमुख श्रेणियों में कमी दर्ज की गई। डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन की खपत में भी गिरावट आई (चार्ट 12 ए)।

गैर-परिवहन खंड में खिंचाव के कारण वाहन पंजीकरण में गिरावट जारी रही, हालांकि परिवहन खंड ने क्रमिक वृद्धि दर्ज की (चार्ट 12सी)। प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण आंशिक रूप से ट्रैक्टरों की घरेलू बिक्री में 32.6 प्रतिशत की कमी के साथ ग्रामीण मांग में गिरावट आई। देर से मानसून के कारण खरीफ फसलों की कटाई में देरी के कारण ट्रैक्टर की मांग में गिरावट बताई जा रही है। ग्रामीण मांग में कमी के कारण, ईंधन की बढ़ती कीमतों के साथ युग्मित दोपहिया, तिपहिया और मोटरसाइकिलों की बिक्री वर्ष-दर-वर्ष और पूर्व-महामारी दोनों स्तरों पर गिर गई (चार्ट 12डी)। दो पहिया वाहनों के भीतर, इलेक्ट्रिक वाले भाग ने जनवरी 2022 में क्रमिक रूप से 44 प्रतिशत से अधिक की मजबूत वृद्धि जारी रखी क्योंकि ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं ने लॉजिस्टिक परिचालन और अंतिम मील डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक से चलने वाले दोपहिया वाहनों की ओर रुख किया।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, श्रम भागीदारी दर दिसंबर 2021 में 40.9 से गिरकर जनवरी 2022 में 39.9 हो गई, क्योंकि रोकथाम के उपायों में वृद्धि हुई (चार्ट 13)।

चार्ट 12 : परिवहन क्षेत्र संकेतक

ए. पेट्रोलियम खपत

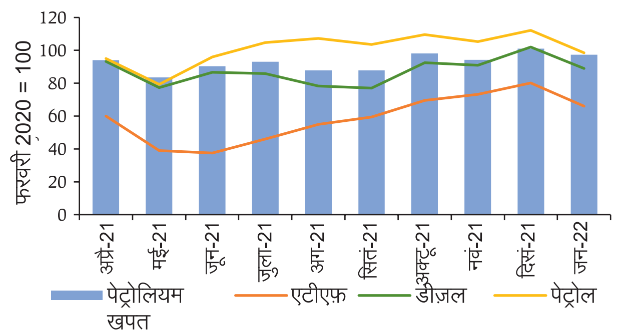

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ; और लेखक की अपनी गणना।

बी. ऑटोमोबाइल बिक्री

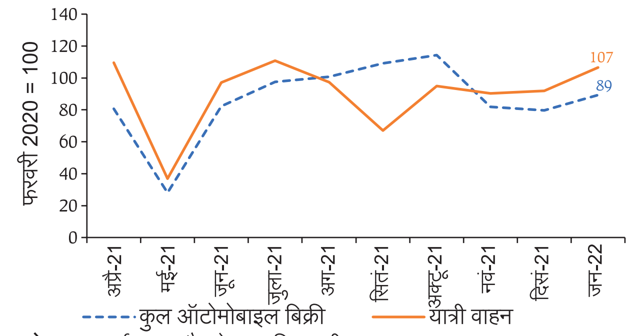

स्रोत: एसआईएएम; और लेखक की अपनी गणना।

सी. वाहन पंजीकरण

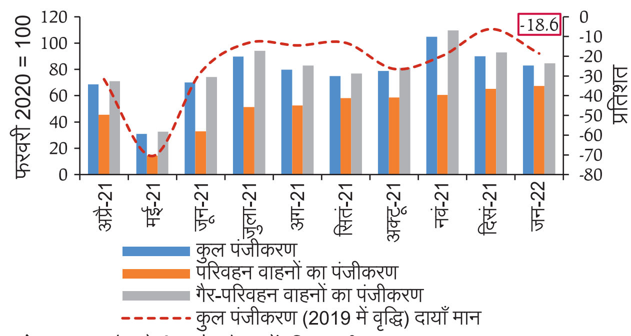

स्रोत: वाहन डैशबोर्ड ; और लेखकों की अपनी गणना।

डी. ग्रामीण मांग

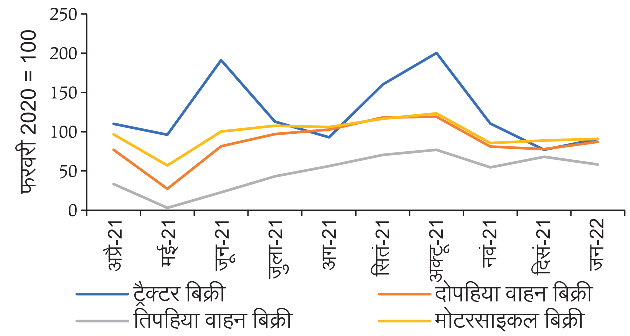

स्रोत: एसआईएएम; और टीएमए; और लेखकों की अपनी गणना।

सीएमआईई के रोजगार आंकड़ों के अनुसार, तीसरी लहर के प्रभाव में जनवरी 2022 में श्रम बाजार को मामूली नुकसान हुआ। यद्यपि नियोजित श्रमिकों की संख्या में क्रमिक रूप से गिरावट आई है, एक वर्ष पहले ही कार्यबल में बढ़ोतरी हुई थी (चार्ट 14)।

चार्ट 13: रोज़गार, बेरोज़गारी, और श्रम भागीदारी दरें

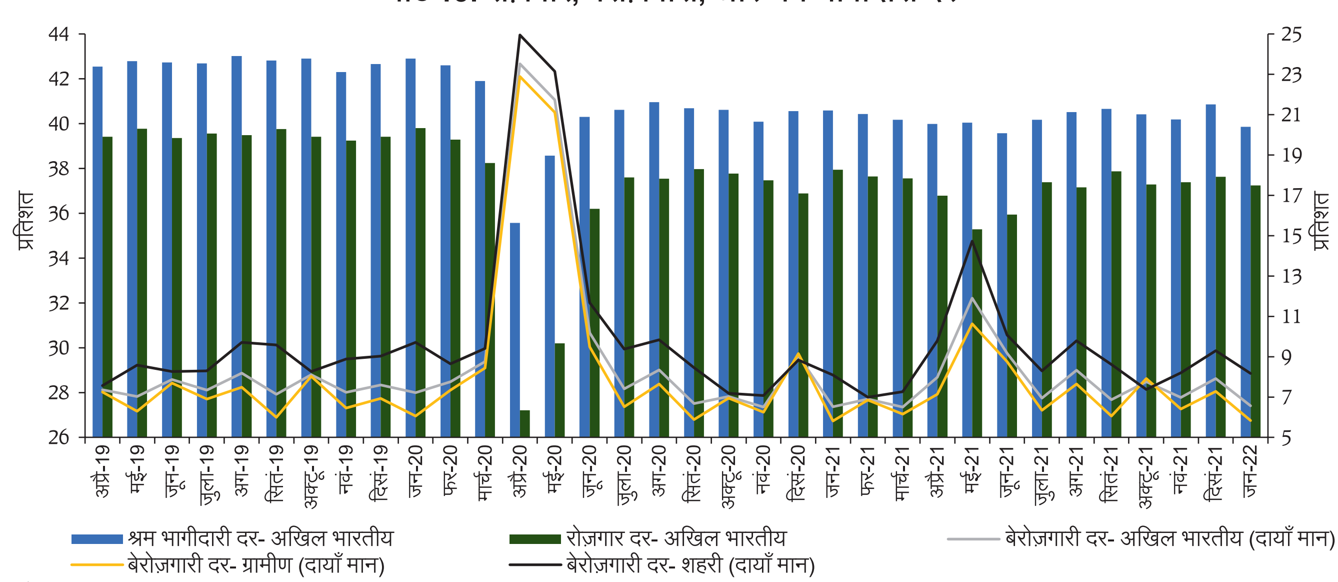

स्रोत: सीएमआईई।

चार्ट 14: रोज़गार में श्रमिकों की संख्या

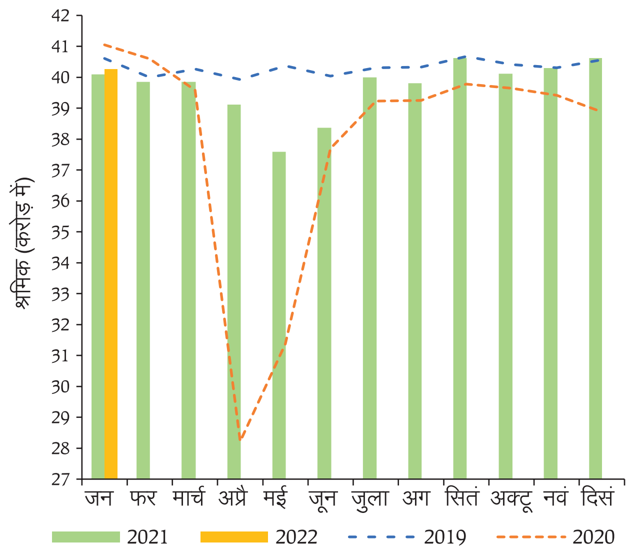

स्रोत: सीएमआईई।

पीएमआई दर्शाता है कि नवंबर 2021 में विस्तार दिखाने के बाद लगातार दूसरे महीने विनिर्माण और सेवाओं दोनों के तहत रोजगार में कमी आई (चार्ट 15)।

जनवरी 2022 में 34.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारत के पण्य वस्तु निर्यात ने 23.7 प्रतिशत व-द-व (महामारी पूर्व स्तर पर 31.8 प्रतिशत) की मजबूत वृद्धि दर्ज की (चार्ट 16 ए और बी)। अप्रैल 2021 - जनवरी 2022 के दौरान, पण्य वस्तु निर्यात 335.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य का 83.9 प्रतिशत है।

निर्यात वृद्धि व्यापक-आधारित थी, जिसमें दस प्रमुख कमोडिटी समूहों ने जो निर्यात के करीब 78 प्रतिशत हैं अधिक निर्यात के लिए अपने पूर्व-महामारी स्तर से भी अधिक वृद्धि दर्ज की (सारणी 2)। हालांकि, निर्यात गति में गिरावट प्रमुख श्रेणियों में दिखाई दे रही थी। निर्यात प्रदर्शन में सुधार इंजीनियरिंग सामान, रसायन और पेट्रोलियम उत्पादों के अधिक मात्रा में शिपमेंट से उपजा है। 309.3 लाख कोविड-19 वैक्सीन खुराक के रिकॉर्ड निर्यात द्वारा समर्थित पूर्व-महामारी के स्तर पर फार्मास्युटिकल निर्यात में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनवरी 2022 में लगातार दूसरे महीने इंजीनियरिंग सामान का निर्यात 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर रहा। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईईपीसी) को उम्मीद है कि हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग

चार्ट 15: पीएमआई रोज़गार सूचकांक

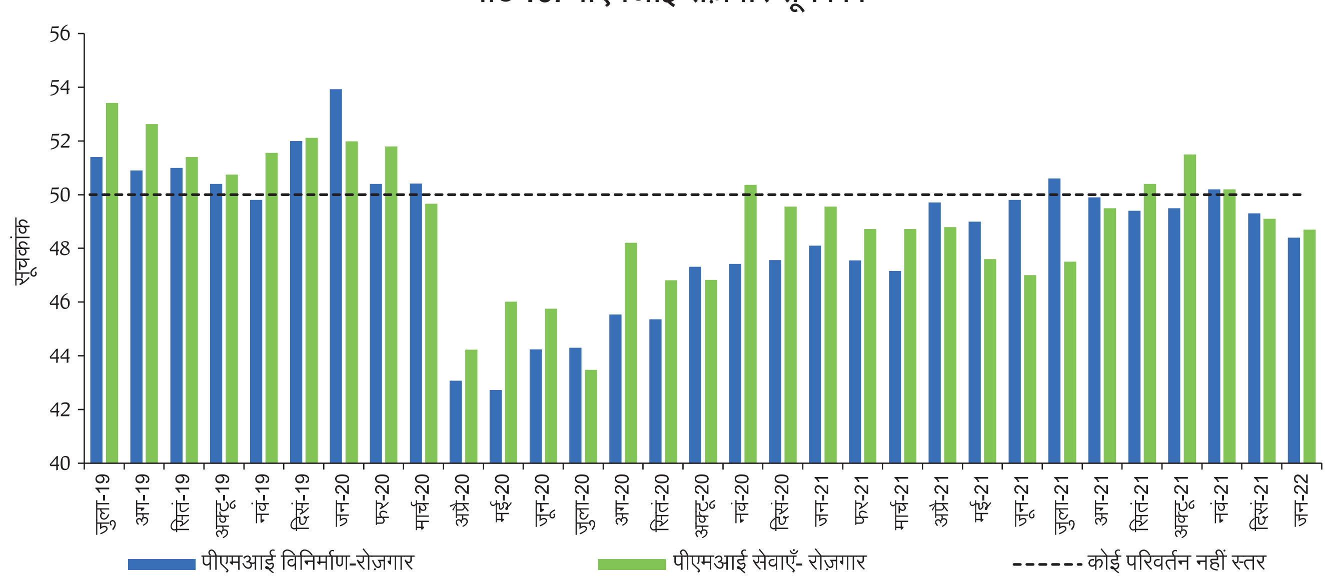

स्रोत: आईएचएस मार्किट।

चार्ट 16: भारत का पण्य वस्तु निर्यात- जनवरी 2022

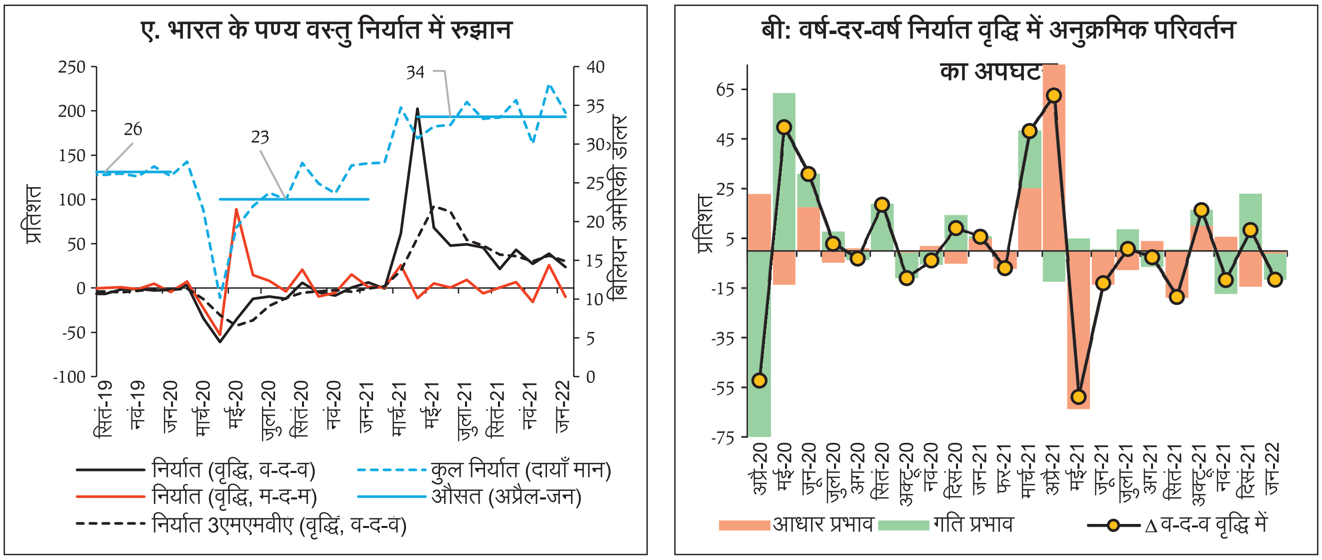

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएस; और लेखकों की अपनी गणना।

और रेफ्रिजरेशन (एचवीएसी) वाले भाग का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। चावल जो कृषि वस्तुओं के निर्यात बास्केट का सबसे बड़ा घटक है उसमें पूर्व-महामारी के स्तर पर 35.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अप्रैल 2021-जनवरी 2022 के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में पूर्व-महामारी के स्तर की तुलना में 26.3 प्रतिशत की तेजी आई। केंद्रीय बजट 2022-23 में हाल ही में घोषित नीतिगत उपायों जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क के अंशांकन से इलेक्ट्रॉनिक निर्यात क्षमता को और बढ़ावा मिलेगा। बजट में घोषित हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क में कमी से इनपुट लागत कम हो सकती है और इस प्रकार हमारे रत्न और आभूषण निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। सीमा शुल्क के युक्तिकरण का उद्देश्य मूल्य वर्धित विनिर्माण को बढ़ाकर और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को मजबूत करके आत्मानिर्भर भारत के लक्ष्यों को सशक्त बनाना है।

सारणी 2 : शीर्ष 10 निर्यातित वस्तुएं

शीर्ष 10 निर्यात वस्तु समूह	जन-22 (%शेयर)	जन-22/जन-20 (वृद्धि)	जन-22/दिस-21 (वृद्धि)	अप्रै 21-जन22/अप्रै 19-जन20 (वृद्धि)
इंजीनियरिंग माल	27.0	47.9	-6.0	37.7
पेट्रोलियम उत्पाद	11.0	17.1	-36.6	32.4
रत्न एवं आभूषण	9.5	12.4	8.0	4.5
जैविक एवं अजैविक रसायन	7.2	29.4	-8.1	28.3
दवा एवं औषधि	6.0	15.3	-11.4	16.2
सभी तरह के कपड़ों के रेडीमेड वस्त्र	4.5	6.7	5.6	-1.7
सूती धागे/कपड़े	4.1	52.8	-3.8	50.2
इलेक्ट्रानिक सामान	4.0	33.8	-18.4	26.3
प्लास्टिक और लिनोलियम	2.5	46.5	-6.2	26.4
चावल	2.4	35.9	-9.1	52.1
कुल 10 प्रमुख वस्तुओं का समूह	78.2	29.8	-11.3	26.9
कुल निर्यात	**100.0**	31.8	-9.9	27

स्रोत: एमओसीआई।

चार्ट 17: भारत की सेवा निर्यात में वृद्धि

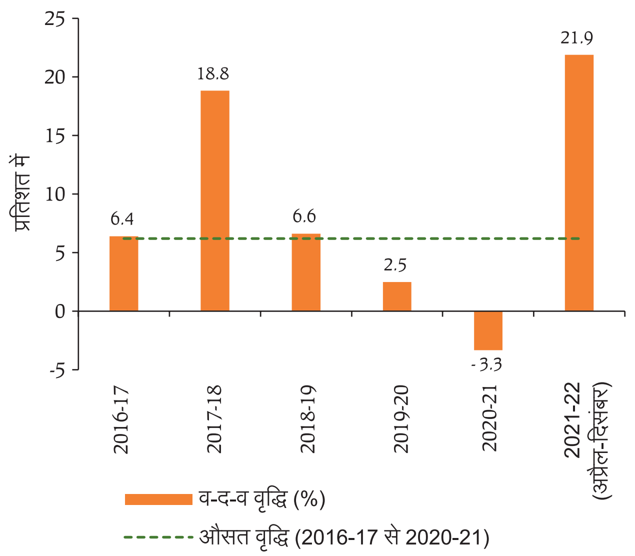

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 18 : वैश्विक आईटी खर्च

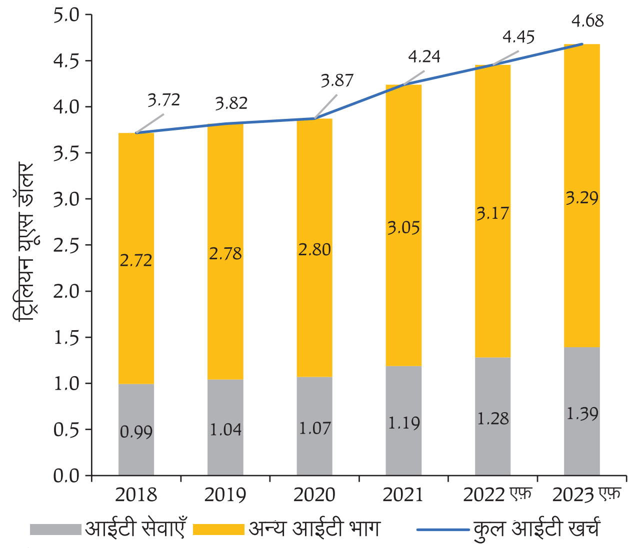

स्रोत: गार्टनर।

सेवा व्यापार पर जारी किए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार (1 फरवरी), भारत के सेवा निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई और 2021-22 की तीसरी तिमाही में लगातार तीन तिमाही में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से आईटी और व्यावसायिक सेवाओं द्वारा बढ़ाया गया था। अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान, सेवाओं के निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि पिछले 5 वर्षों के दौरान दर्ज औसत वृद्धि से काफी अधिक बढ़ गई (चार्ट 17)।

2022 और 2023 के लिए गार्टनर[2] द्वारा वैश्विक आईटी खर्च के नवीनतम पूर्वानुमान एक उत्साही दृष्टिकोण का संकेत देते हैं (चार्ट 18)। इसके अलावा, ओईसीडी का नवीनतम सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक[3] 2020 के सापेक्ष 2021 में उदारीकरण की त्वरित गति को इंगित करता है। भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों, जैसे अमेरिका और यूके द्वारा कंप्यूटर सेवाओं जैसे क्षेत्रों में व्यापार उदारीकरण, भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात को आगे बढ़ा सकता है और उच्च वृद्धि को बनाए रखने में सहायता प्रदान कर सकता है (चार्ट 19)।

जनवरी 2022 में पण्य वस्तु आयात 52.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, हालांकि आयात वृद्धि क्रमिक रूप से कम होने के बावजूद तेजी से बढ़ी। बहरहाल, आयात लगातार पांचवें महीने के लिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्थान से ऊपर रहा (चार्ट 20ए और 20बी)।

आयात वृद्धि व्यापक-आधारित थी, जिसमें नौ प्रमुख कमोडिटी समूहों ने आधे से अधिक आयात के लिए अपने पूर्व-महामारी के स्तर पर वृद्धि दर्ज की (सारणी 3)। इलेक्ट्रॉनिक सामान, विद्युत और गैर-विद्युत मशीनरी, रसायन और कोयले के आयात की उच्च मांग ने इस वृद्धि को प्रेरित किया। दूसरी ओर, तेल आयात, जनवरी 2022 में पूर्व-महामारी के स्तर पर 12.1

चार्ट 19: कंप्यूटर सेवाओं के लिए ओईसीडी का व्यापार प्रतिबंध सूचकांक

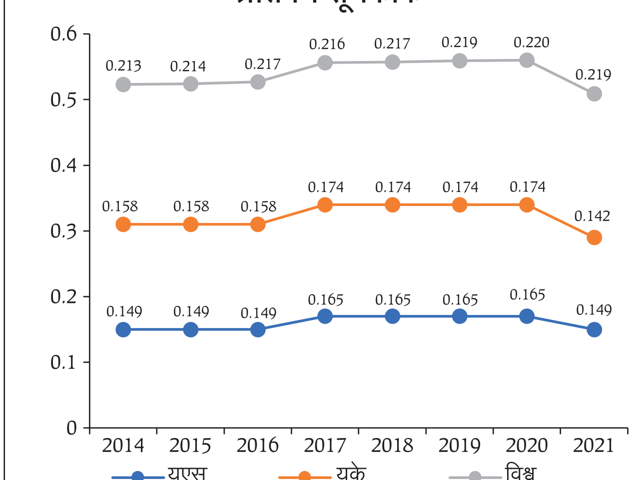

टिप्पणी: एसटीआरआई (सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक) 0 से 1 के बीच मान लेता है। जहां 0 पूरी तरह से खुला है और 1 पूरी तरह से बंद है।
स्रोत: ओईसीडी।

[2] गार्टनर ने 18 जनवरी, 2022 को विश्वव्यापी आईटी खर्च पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की।

[3] 02 फरवरी, 2022 को सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक पर ओसीईडी प्रेस विज्ञप्ति।

चार्ट 20 : भारत का पण्य वस्तु आयात- जनवरी 2022

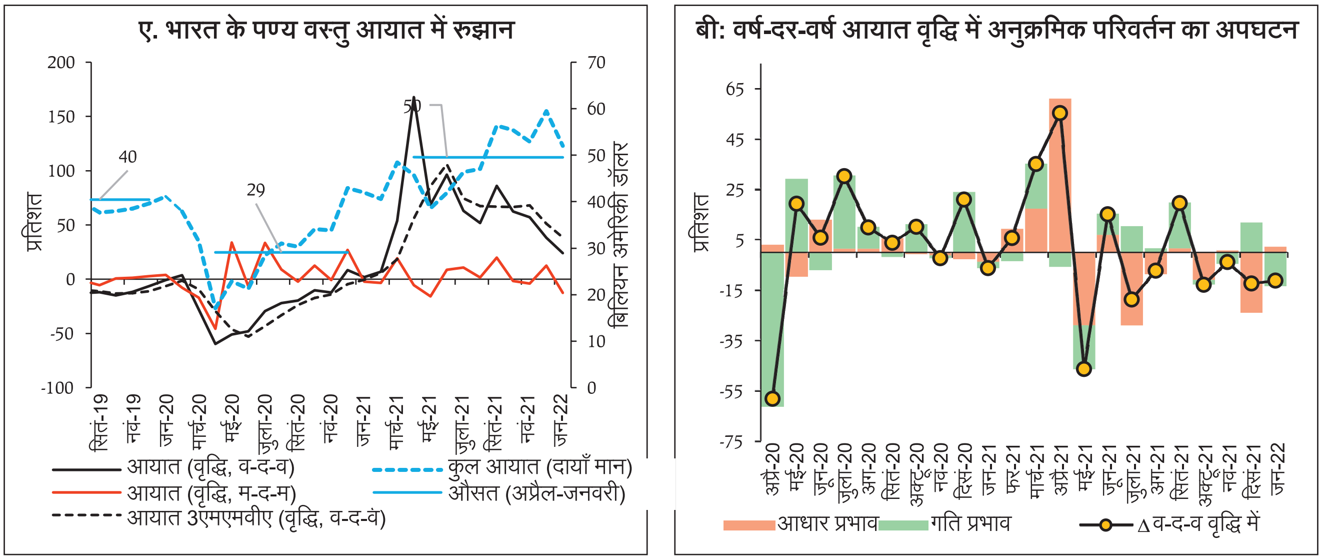

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएस; और लेखकों की अपनी गणना।

प्रतिशत कम हो गया, क्योंकि ओमिक्रॉन ने मांग को प्रभावित किया था। कमजोर मांग के कारण वर्ष-दर-वर्ष और क्रमिक आधार पर सोने के आयात में कमी देखी गई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डबल्यूजीसी) को उम्मीद है कि 2022 में भारत का सोने का आयात 800-850 टन के स्तर तक पहुंच जाएगा।

जनवरी 2022 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात रिकॉर्ड स्तर पर रहा और महामारी से पहले की तुलना में इसमें 82.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 21ए)। कुल मिलाकर गैर-तेल गैर-सोने के आयात ने जनवरी 2022 में लगातार आठवें महीने मजबूत वृद्धि बनाए रखी (चार्ट 21बी)।

भारत का पण्य वस्तु व्यापार घाटा जनवरी 2022 में बढ़कर 17.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और जनवरी 2020 में 15.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

केंद्रीय बजट 2022-23 ने पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित करके वृद्धि पुनरुद्धार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इंफ्रास्ट्रक्चर

सारणी 3 : शीर्ष 10 आयातित वस्तुएं

शीर्ष 10 आयात वस्तु समूह	जन-22 (%शेयर)	जन-22/जन-20 (वृद्धि)	जन-22/दिस-21 (वृद्धि)	अप्रै 21-जन22/अप्रै 19-जन20 (वृद्धि)
पेट्रोलियम, कच्चे तेल और उत्पाद	22.0	-12.1	-29.3	18.9
इलेक्ट्रानिक सामान	15.8	82.6	27.8	24.3
मशीनरी, इलेक्ट्रिकल और गैर-इलेक्ट्रिकल	7.8	18.3	6.4	1.8
जैविक एवं अजैविक रसायन	5.1	56.2	-17.8	40.8
कोयला, कोक एवं ब्रिकेट्स इत्यादि	5.0	53.2	-7.0	27.5
स्वर्ण	4.6	51.7	-49.2	64.1
मोती, बहुमूल्य एवं अर्ध-बहुमूल्य पत्थर	4.5	59.5	-19.3	31.6
वनस्पति तेल	3.6	121.5	1.7	96.6
गैर-लौह धातु	3.5	59.6	7.4	28.6
कृत्रिम राल, प्लास्टिक की वस्तुएँ	3.4	39.3	-10.6	32.1
कुल 10 प्रमुख वस्तुओं का समूह	75.3	27.8	-14.1	27.3
कुल निर्यात	**100.0**	26.4	-12.6	22.3

स्रोत: एमओसीआई।

चार्ट 21 : प्रमुख वस्तुओं के आयात में वृद्धि (पूर्व-कोविड स्तर में वृद्धि)

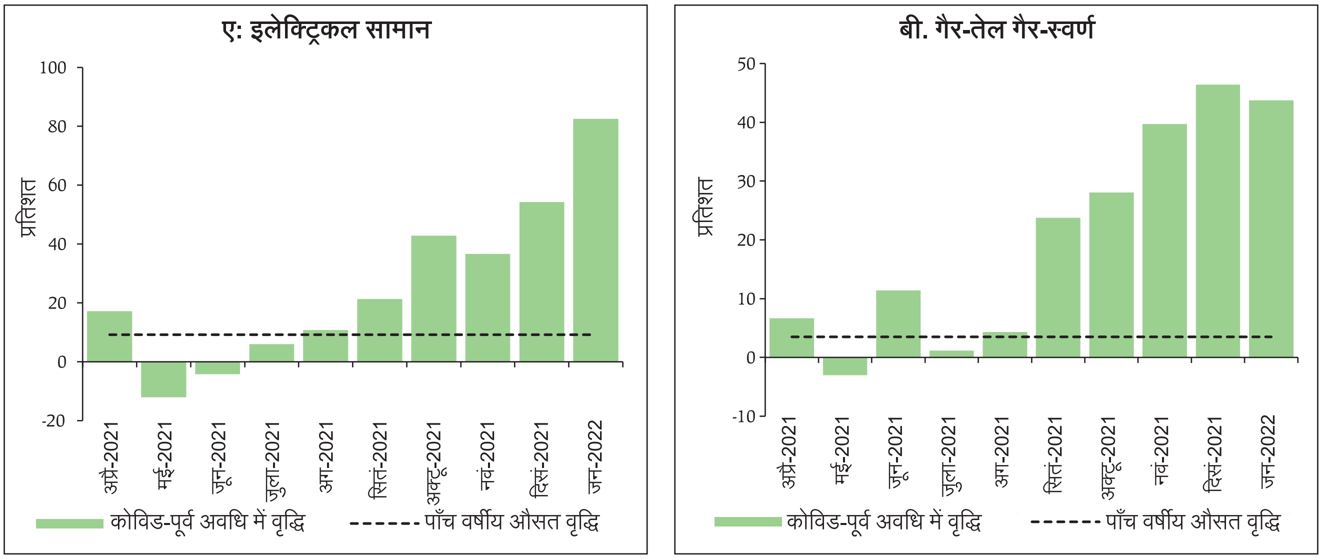

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएस; और लेखक की अपनी गणना।

के विकास के माध्यम से सार्वजनिक निवेश पर इसके जोर से निजी निवेश को आकर्षित करने और 2022-23 और उसके बाद रोजगार सृजन और मांग को मजबूत करने की उम्मीद है।

सकल राजकोषीय घाटा (जीएफ़डी) 2021-22 (आरई) में जीडीपी के 6.9 प्रतिशत पर रखा गया है, जबकि बजट अनुमान (बीई) जीडीपी का 6.8 प्रतिशत है। 0.1 प्रतिशत अंकों के मामूली विचलन के पीछे उनके बजट स्तरों से राजस्व और व्यय में भारी विचलन है। विशेष रूप से, केंद्र सरकार का निवल कर राजस्व बजट अनुमान (बीई) से सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत से अधिक है। गैर-कर राजस्व ने बीई को जीडीपी के 0.3 प्रतिशत से अधिक कर दिया, जो रिज़र्व बैंक द्वारा बजटीय अधिशेष हस्तांतरण से अधिक था। संशोधित अनुमानों (आरई) में विनिवेश प्राप्तियों को सकल घरेलू उत्पाद के 0.4 प्रतिशत तक नीचे लाया गया है। व्यय के मोर्चे पर, राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों ने जीडीपी के क्रमशः 1.0 और 0.2 प्रतिशत के बजट अनुमान को पार कर लिया है।

2022-23 (बीई) में, जीएफडी को जीडीपी के 6.4 प्रतिशत पर रखा गया है, जो 2021-22 (आरई) से 42 आधार अंकों का समेकन है, जो 2024-25 तक जीएफडी को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने के मध्यम अवधि के लक्ष्य के अनुरूप है। 2022-23 (बीई) के लिए राजस्व अनुमान यथार्थवादी मान्यताओं पर आधारित हैं, अर्थात, 0.9 की कर उछाल और ₹65,000 करोड़ की विनिवेश प्राप्तियां (2021-22 (बीई) में ₹1.75 लाख करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले)। खर्च के मोर्चे पर, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च पर बड़ा जोर दिया है। पूंजीगत व्यय 2010-20 के दौरान 1.7 प्रतिशत के औसत से बढ़कर 2.9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। प्रभावी पूंजीगत व्यय, जिसमें केंद्र का पूंजीगत व्यय और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए राज्यों को सहायता अनुदान शामिल है, उसका बजट 2022-23 (बीई) में 4.1 प्रतिशत है। 2022-23 के बजट प्रस्तावों में ₹14.95 लाख करोड़ की सकल बाजार उधारी शामिल है, जो कुछ हद तक बाजार की उम्मीदों से अधिक है, और इसके परिणामस्वरूप 10-वर्षीय जी-सेक बेंचमार्क (6.54 जीएस 2032) को 15 आधार अंकों से सख्त किया गया है, जो इसकी 12 महीनों में सबसे ऊंची उछाल है (सारणी 4)।

2020-21 में लगभग 9 प्रतिशत की कमी के बाद, 2021-22 (आरई) में राज्यों को कर हस्तांतरण में तेजी से सुधार हुआ है, जो 2021-22 के बजट अनुमान से अधिक है। कुल कर हस्तांतरण में एक साल पहले की तुलना में 2021-22 (आरई) में 25.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2022-23 में 9.6 प्रतिशत की

सारणी 4 : प्रमुख संकेतक (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

	2020-21	2021-22		2022-23
	वास्तविक	बीई	आरई	बीई
1	2	3	4	5
1. राजकोषीय घाटा	9.2	6.8	6.9	6.4
2. राजस्व घाटा	7.3	5.1	4.7	3.8
3. प्राथमिक घाटा	5.7	3.1	3.3	2.8
4. सकल कर राजस्व	10.2	9.9	10.8	10.7
5. गैर-कर राजस्व	1.0	1.1	1.4	1.0
6. राजस्व व्यय जिसमें:	15.6	13.1	13.6	12.4
7. पूंजीगत परिव्यय	2.2	2.5	2.6	2.9
जिसमें				
पूंजी की लागत	*1.6*	*2.3*	*2.4*	*2.4*

टिप्पणी: पूंजीगत परिव्यय ऋण और अग्रिम के बगैर पूंजीगत व्यय है।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। राज्यों के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए, बजट ने 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना' के परिव्यय को 2021-22 (आरई) में ₹15,000 करोड़ से बढ़ाकर 2022- 23 (बीई) में ₹1 लाख करोड़ कर दिया है। अप्रैल-नवंबर, 2021 की अवधि के लिए राज्यों के पूंजी परिव्यय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 55.2 प्रतिशत पर मजबूत है, जिसमें कई राज्यों ने वर्ष-दर-वर्ष 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है।

सकल आपूर्ति

04 फरवरी, 2022 तक रबी फसलों के तहत कुल रकबा 700.8 लाख हेक्टेयर के एक नए रिकॉर्ड को छू गया, जो पिछले वर्ष के रकबे से 1.5 प्रतिशत और सामान्य (5 साल के औसत) रकबे (चार्ट 22ए) से 8.2 प्रतिशत अधिक है। बुवाई पर्याप्त जलाशय स्तर (चार्ट 22 बी) और एक स्थानिक और अस्थायी रूप से अच्छी तरह से वितरित पूर्वोत्तर (एनई) मानसून वर्षा से प्रेरित थी। मुख्य रूप से हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में तिलहन और दलहन की ओर विविधीकरण के कारण गेहूं की बुवाई में पिछले साल की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। कुल रकबे में तिलहन,

चार्ट 22: ग्रामीण अर्थव्यवस्था

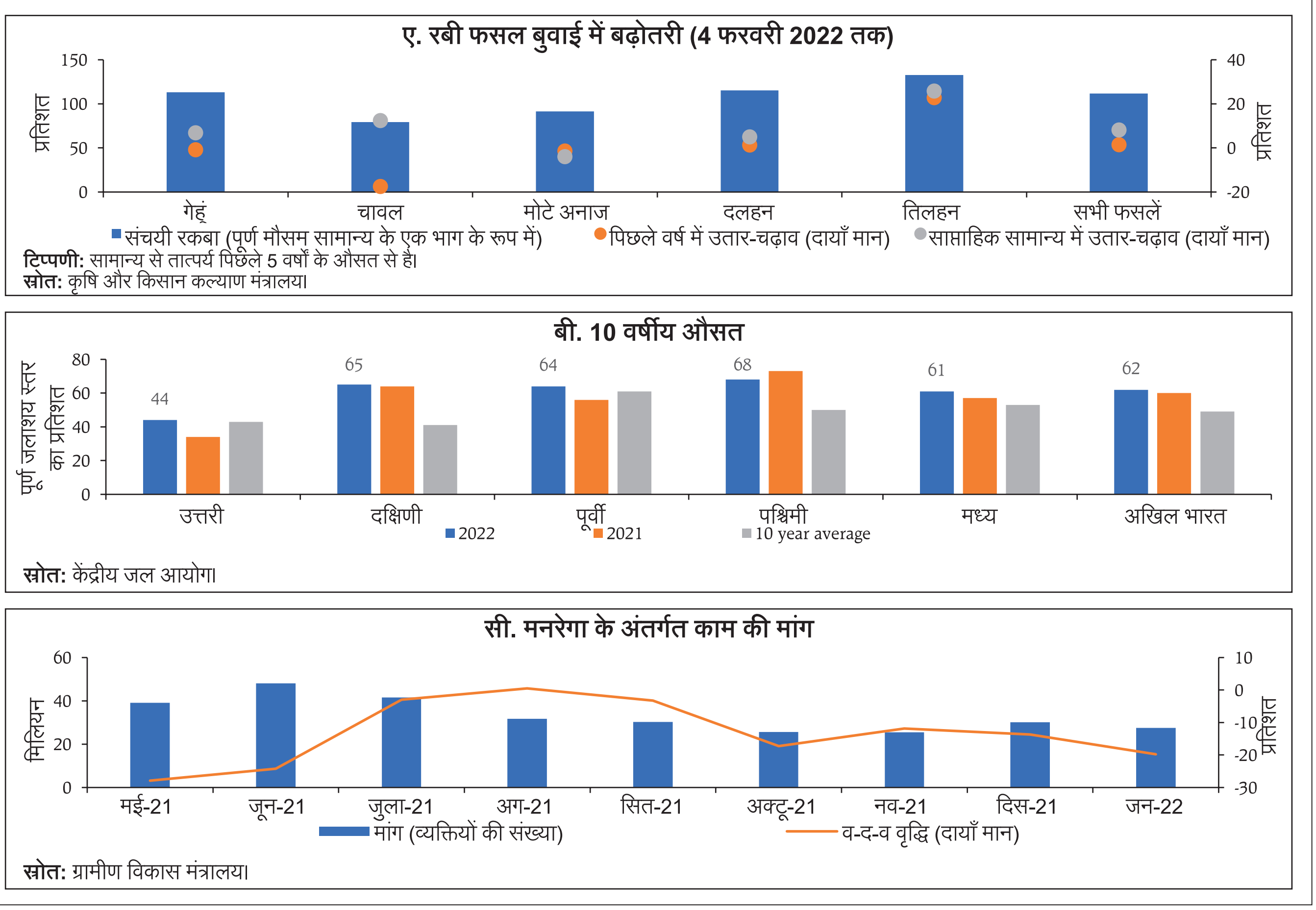

मुख्य रूप से रेपसीड और सरसों का हिस्सा 12.3 प्रतिशत (पूर्ण सीजन सामान्य) से बढ़कर 14.7 प्रतिशत हो गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत काम की मांग पूरे मौसम में (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) घटती रही है, जो आंशिक रूप से ग्रामीण इलाकों में रबी की बुवाई से उत्पन्न रोजगार को दर्शाती है (चार्ट 22सी)।

जायद फसल का मौसम (मार्च से मई), जिसका विस्तार रबी सीजन के अंत से खरीफ सीजन की शुरुआत तक है, जो निवल बोए गए क्षेत्र के 2.9 प्रतिशत से 5.1 प्रतिशत के बीच है। पिछले कुछ वर्षों में जायद के रकबे में वृद्धि ने ध्यान आकर्षित किया है (चार्ट 23)।

14 फरवरी, 2022 तक चावल की खरीद 457.5 लाख टन (खरीफ विपणन सीजन 2021-22) को छू गई, जो एक साल पहले की तुलना में 6.5 अधिक है। तिमाही बफर मानदंडों (जनवरी-मार्च) के अनुसार जनवरी 2022 के अंत तक चावल और गेहूं दोनों के लिए स्टॉक स्तर आरामदायक (क्रमशः 7.8 और 2.0 गुना) रहता है।

औद्योगिक क्षेत्र में, हेडलाइन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जनवरी 2022 में 54.0 पर विस्तार में रहा, जबकि यह एक महीने पहले 55.5 से कम हो गया था। नए ऑर्डर और उत्पादन के उप-सूचकांक धीमी गति से बढ़े और उत्पादन की कीमतों में तेजी आई। पीएमआई सेवाएं भी 51.5 पर विस्तार मोड में रही, हालांकि इसने पिछले छह महीनों में सबसे कम विस्तार दर्ज किया। सेवाओं के लिए व्यापार अपेक्षा सूचकांक (बीईआई) का जनवरी 2022 में लगातार छठे महीने विस्तार हुआ (चार्ट 24)।

चार्ट 23 : जायद मौसम के लिए संभावना को बढ़ाना

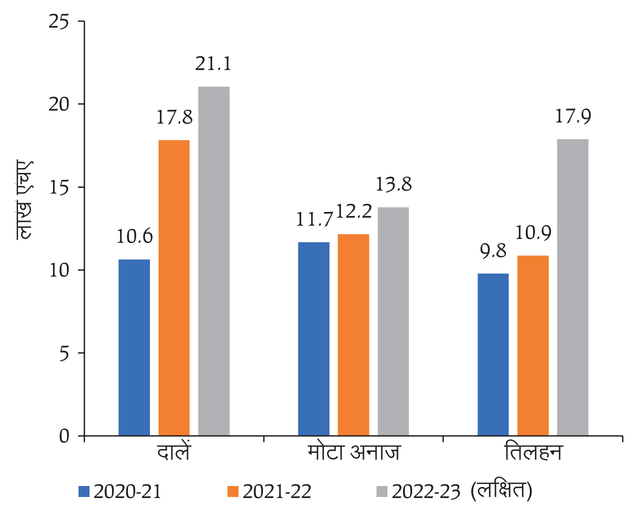

नोट: कुछ राज्य गर्मियों में चावल उगाते हैं (लगभग 20-30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र) जो खरीफ के मौसम का अतिव्यापन करता है। कई राज्यों में गर्मियों की सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं।
स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

चार्ट 24: क्रय प्रबन्धक का सूचकांक

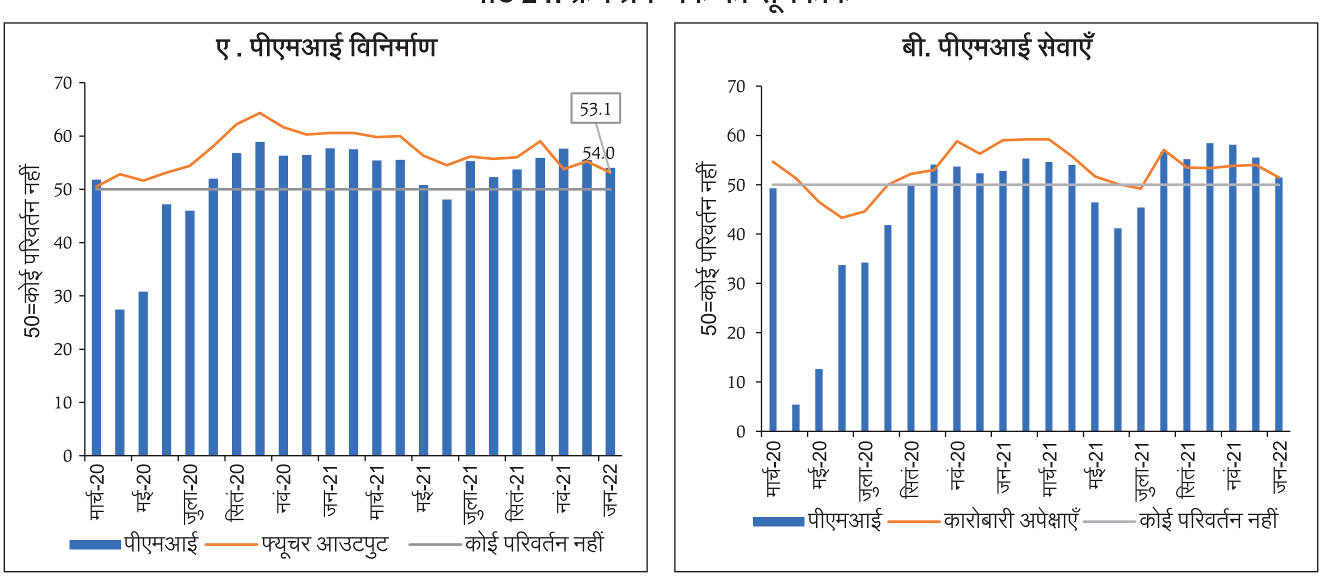

स्रोत: आईएचएस मार्किट

चार्ट 25: रेलवे और एयर ट्राफिक

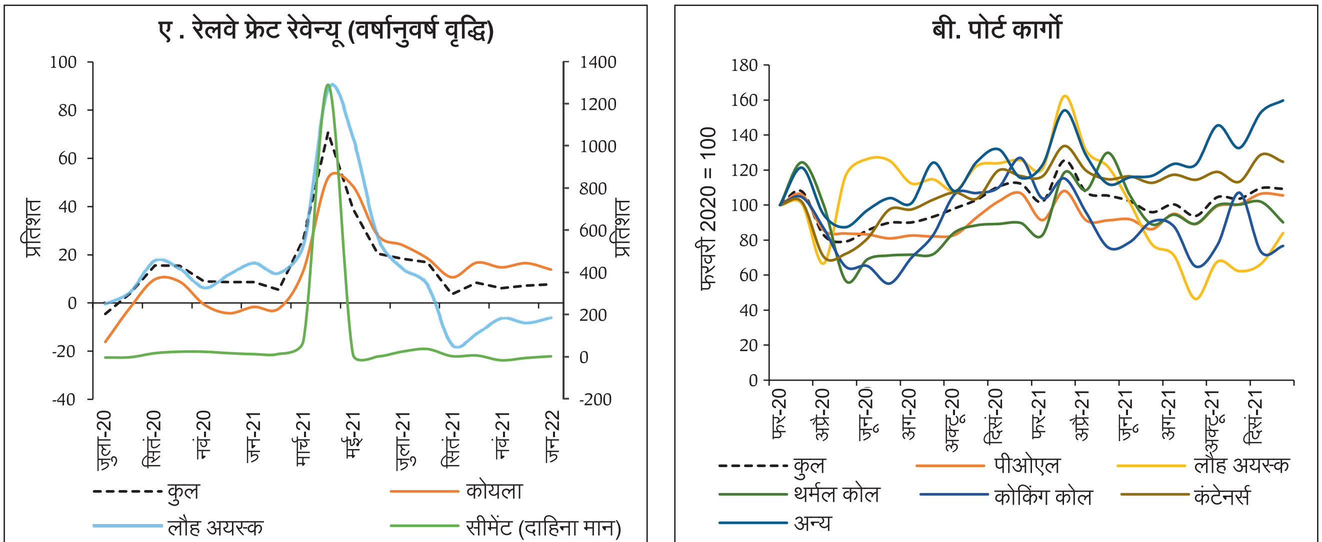

स्रोत: रेल दृष्टि

स्रोत: भारतीय पत्तन संघ

सेवा क्षेत्र में, रेलवे माल ढुलाई ने जनवरी 2022 में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो एक साल पहले 8.7 प्रतिशत थी (चार्ट 25 ए)। कोयले और सीमेंट के लिए माल ढुलाई में वृद्धि दर्ज की गई, यहां तक कि लौह अयस्क में उच्च आधार पर गिरावट दर्ज की गई। दो साल के लिए संकुचन दर्ज करने के बाद, अप्रैल-जनवरी 2021-22 में संचयी रूप से रेलवे माल ढुलाई में 17.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रेलवे क्षेत्र के लिए 'ऑपरेटिंग रेशियो [4] '2021-22 में 95 से ऊपर रहने की उम्मीद है, जो पिछले वर्षों की तुलना में [5] बेहतर है। जैसा कि शिपिंग ने वैश्विक स्तर पर कंटेनर की कमी की बाधाओं को दूर करना शुरू कर दिया है, जनवरी में बंदरगाह यातायात में मामूली क्रमिक सुधार देखा गया (चार्ट 25 बी)।

सीमेंट उत्पादन और इस्पात की खपत दोनों ने महामारी से पहले के स्तर (चार्ट 26) पर वृद्धि दर्ज की। निर्माण के संबंध में एक बेहतर मांग दृष्टिकोण को उद्योग में क्षमता वृद्धि के साथ मिलान किए जाने की उम्मीद है, जिसमें अगले दो वित्तीय वर्षों में 84 मिलियन टन (एमटी) से अधिक नई क्षमता जोड़ने की योजना है।

फरवरी 2022 के पहले पखवाड़े में, दैनिक घरेलू हवाई अड्डे के फुटफॉल का औसत प्रति दिन 4.7 लाख था - जनवरी में इसी अवधि से 5.7 प्रतिशत का संकुचन। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के फुटफॉल में भी क्रमिक रूप से 7.1 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि कार्गो खंड में घरेलू कार्गो के लिए 1.8 प्रतिशत और अंतरराष्ट्रीय कार्गो के लिए 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

चार्ट 26: निर्माण क्षेत्र संकेतक

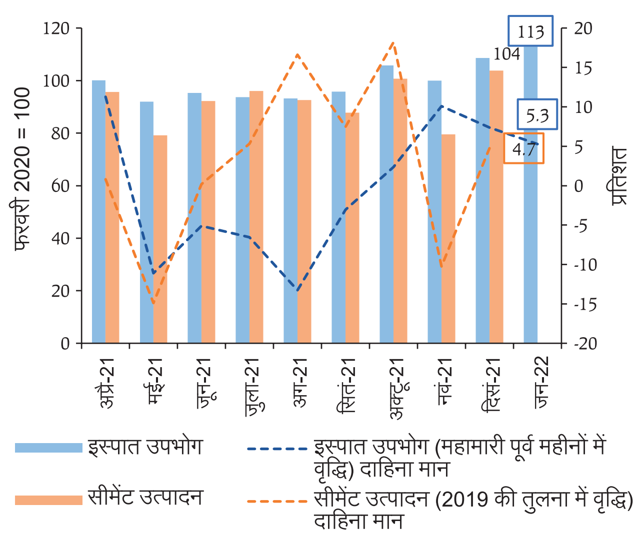

स्रोत: संयुक्त प्लांट समिति ; और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

4 परिचालन अनुपात को कंपनी के राजस्व के प्रतिशत के रूप में परिचालन व्यय में व्यक्त किया जाता है। कम अनुपात का अर्थ है उच्च दक्षता।

5 मिंट, 29 जनवरी 2022।

सारणी 5 : उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाएँ

		उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाओं की वृद्धि (वर्षानुवर्ष प्रतिशत)						2019 की तुलना में वृद्धि			
क्षेत्र	**संकेतक**	**अग-21**	**सितं-21**	**अक्टू-21**	**नवं-21**	**दिसं-21**	**जन-22**	**अक्टू 21/ अक्टू 19**	**नवं 21/ नवं 19**	**दिसं 21/ दिसं 19**	**जन 22/ जन 20**
शहरी मांग	यात्री वाहन बिक्री	7.6	-41.2	-27.1	-18.6	-13.3	-8.1	-16.7	-14.8	-1.5	2.2
ग्रामीण मांग	दुपहिया वाहन बिक्री	-14.6	-17.4	-24.9	-34.4	-10.8	-21.1	-12.3	-25.5	-4.2	-15.9
	तीन पहिया वाहन बिक्री	59.7	53.8	19.1	-6.6	27.0	-8.5	-52.6	-59.7	-47.7	-60.4
	ट्रैक्टर बिक्री	-17.0	-14.8	0.4	-22.5	-27.5	-32.6	8.2	17.2	3.8	-1.2
व्यापार, होटल, यातायात, संचार	वाणिज्यिक वाहन बिक्री		24.5			0.9				-0.3	
	रेलवे माल ढुलाई यातायात	16.9	3.6	8.4	6.1	7.2	7.7	25.1	15.6	16.5	17.1
	पोर्ट कार्गो यातायात	11.5	0.5	6.3	-0.2	-0.4	-2.7	5.2	3.9	4.0	1.3
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात	35.7	10.1	6.7	-1.7	2.0		-10.0	-11.4	-1.1	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात	25.8	18.1	23.8	11.7	10.5		8.4	-5.0	-3.6	
	घरेलू हवाई यात्री यातायात	132.6	76.5	68.7	65.5	53.3		-27.0	-17.6	-12.5	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	119.2	155.9	162.9	140.2	121.7		-61.0	-58.6	-54.5	
	जीएसटी ई-वे बिल्स (कुल)	33.3	18.3	14.5	5.9	11.6	4.7	39.0	14.5	29.3	15.6
	जीएसटी ई-वे बिल्स (आंतर राज्य)	30.8	15.6	14.1	7.3	8.9	2.2	40.7	17.6	33.0	9.2
	जीएसटी ई-वे बिल्स (अंतर राज्य)	37.2	22.3	15.1	3.9	13.4	6.3	36.7	10.1	24.0	20.1
	यात्री आगमन	329.9	278.8	337.0	255.0	235.5		-80.8	-76.9	-75.2	
विनिर्माण	इस्पात उपभोग	-2.2	-3.2	-3.8	-7.7	-8.6	-3.7	2.4	10.1	7.4	5.3
	सीमेंट उत्पादन	36.3	10.8	14.5	-3.6	12.9		18.1	-10.6	4.8	
पीएमआई संकेतक	विनिर्माण	52.3	53.7	55.9	57.6	55.5	54.0				
	सेवाएँ	56.7	55.2	58.4	58.1	55.5	51.5				

स्रोत: सीईआईसी आंकड़े : आईएचएस बाजार ; एसआईएएम ; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और संयुक्त प्लांट समिति

सेवा क्षेत्र के भीतर, ऑटोमोबाइल क्षेत्र और विमानन क्षेत्रों के संपर्क गहन गैर-परिवहन खंड में मंदी का अनुभव जारी है, भले ही व्यापार और परिवहन में कुछ सुधार स्पष्ट हो गया (सारणी 5)।

मुद्रा स्फ़ीति

एनएसओ द्वारा 14 फरवरी, 2022 को जारी आंकड़ों से पता चला है कि जनवरी 2022 के महीने के लिए हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति (साल-दर-साल) एक महीने पहले के 5.7 प्रतिशत (चार्ट 27 ए) से बढ़कर 6.0 प्रतिशत हो गई। सीपीआई में लगभग 30 बीपीएस द्वारा महीने-दर-महीने की गिरावट लगभग 65 बीपीएस के एक बड़े प्रतिकूल आधार प्रभाव (एक साल पहले कीमतों में महीने-दर-महीने परिवर्तन) से ऑफसेट से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर और जनवरी के बीच लगभग 35 बीपीएस की हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई।

खाद्य समूह मुद्रास्फीति मुख्य चालक थी, जो जनवरी में 5.6 प्रतिशत थी, जो दिसंबर में 4.5 प्रतिशत थी। खाद्य कीमतों की गति में लगभग 1.1 प्रतिशत की गिरावट लगभग 2.1 प्रतिशत अंक के प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण कम हुई। सब्जियों की कीमतें जनवरी में अपस्फीति से बाहर निकलीं। अनाज, मांस और मछली, अंडे, दूध, दालें और मसालों के संबंध में कीमतों में साल-दर-साल वृद्धि हुई, जबकि तेल और वसा, फल, चीनी और मिष्ठान्न, गैर-मादक पेय और तैयार भोजन और नाश्ते में मुद्रास्फीति कम हुई।

लगातार आठ महीनों तक दोहरे अंकों में रहने के बाद, ईंधन मुद्रास्फीति जनवरी में घटकर 9.3 प्रतिशत हो गई, जो दिसंबर में 11.0 प्रतिशत थी। एलपीजी और मिट्टी के तेल की मुद्रास्फीति में नरमी आई, और बिजली की कीमतें जनवरी में अपस्फीति में बनी रहीं। सीपीआई ईंधन (सीपीआई बास्केट में 6.84 प्रतिशत का भार) ने जनवरी में हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगभग 10 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट 27बी)।

[6] सीपीआई हेडलाइन से ‹खाद्य और पेय पदार्थ› और ‹ईंधन और प्रकाश› समूहों को हटाकर सीपीआई खाद्य और ईंधन को छोड़कर जो है उस पर काम किया जाता है।

चार्ट 27 : सीपीआई मुद्रास्फीति

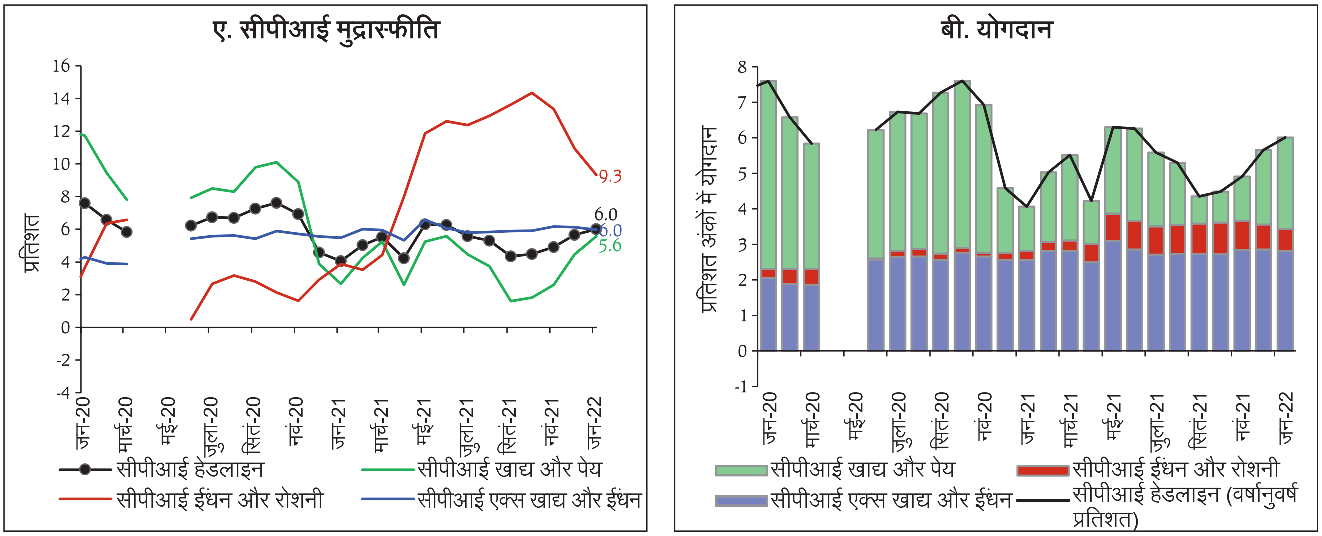

नोट: अप्रैल- मई 2021 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति की गणना अप्रैल- मई 2020 के लिए इम्प्यूटेड सीपीआई सूचकांकों के आधार पर की गई थी।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ के आंकलन

खाद्य और ईंधन 6 या मुख्य मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति जनवरी में 6.0 प्रतिशत पर बनी रही, हालांकि यह दिसंबर में 6.1 प्रतिशत से कम हो गई (चार्ट 27 ए)। जबकि कपड़ों और जूते में मुद्रास्फीति, और घरेलू वस्तुओं और

चार्ट 28 : डीसीए आवश्यक पण्य मूल्य

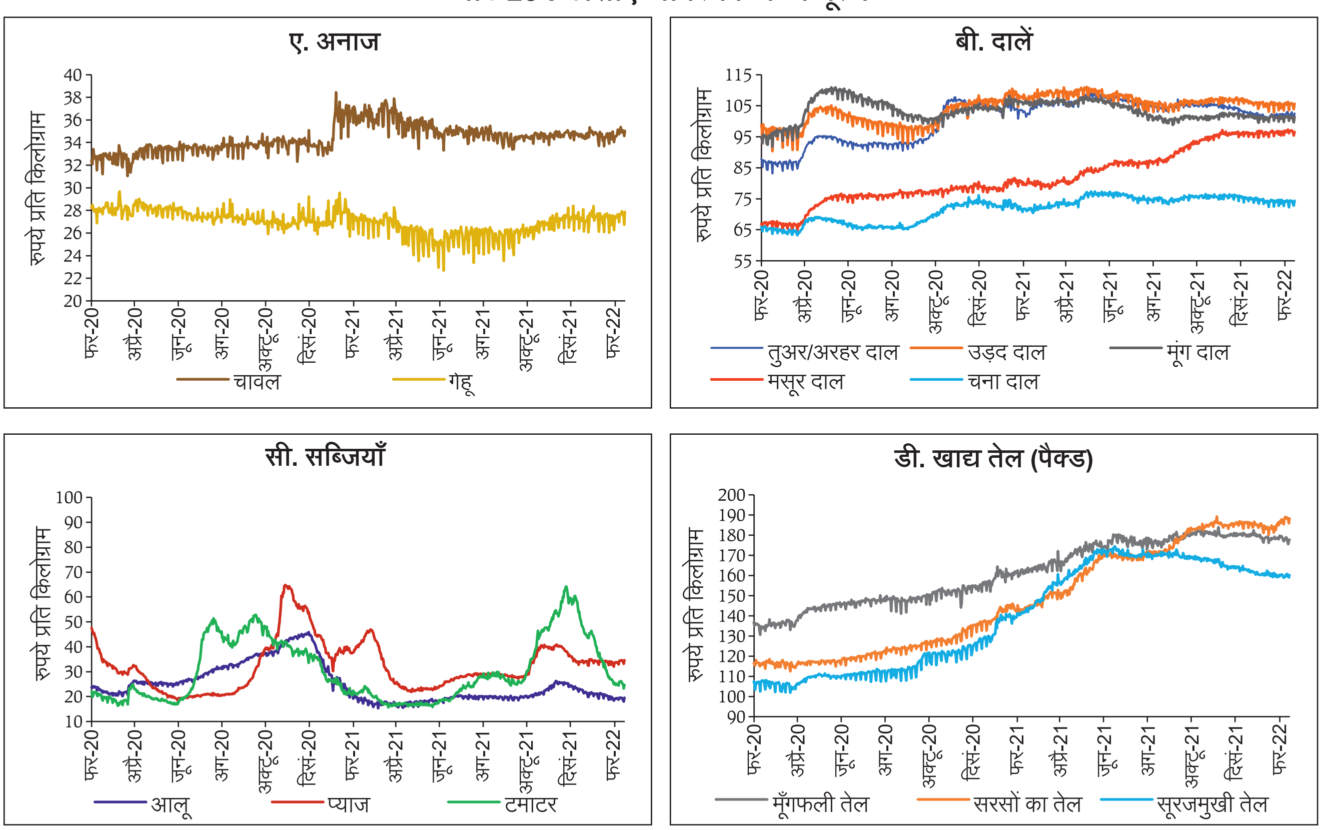

स्रोत: उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार; और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ के आंकलन

सेवाओं में वृद्धि हुई, पैन, तंबाकू और नशीले पदार्थों, आवास, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार, मनोरंजन और मनोरंजन और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभावों में मुद्रास्फीति कम हो गई।

फरवरी (1-14 फरवरी, 2022) के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य डेटा अनाज की कीमतों में कुछ वृद्धि का संकेत देते हैं। दालों की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं। खाद्य तेलों के मामले में, सूरजमुखी के तेल जैसे परिष्कृत खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट जारी रही, दूसरी ओर, सरसों तेल और वनस्पति की कीमतों में तेजी आई। टमाटर और आलू की कीमतों में और अधिक मौसमी मूल्य सुधार देखा गया, जबकि प्याज की कीमतें फरवरी में अब तक स्थिर रही हैं (चार्ट 28)।

फरवरी में अब तक (1-14 फरवरी 2022) चार प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहे। जबकि एलपीजी की कीमतें स्थिर रहीं, फरवरी की पहली छमाही में मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई (सारणी 6)।

जनवरी में विनिर्माण और सेवाओं में इनपुट लागत में और वृद्धि हुई, जैसा कि पीएमआई में परिलक्षित होता है, सेवाओं में वृद्धि की अधिक स्पष्ट दर देखी गई है। हालांकि, बिक्री मूल्य वृद्धि जनवरी में विनिर्माण और सेवाओं में मौन रही।

सारणी 6: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें

वस्तु	इकाई	घरेलू कीमतें			महीने दर महीने (प्रतिशत)	
		फर-21	जन-22	फर-22^	जन-22	फर-22
पेट्रोल	₹/लीटर	91.26	102.87	102.87	-0.1	0.0
डीज़ल	₹/लीटर	82.99	90.51	90.51	0.0	0.0
मिट्टी का तेल (सब्सिडी)	₹/लीटर	27.36	36.56	42.17*	-5.5	15.4
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	771.29#	910.13	910.13	0.0	0.0

^: 1-14 फरवरी, 2022 की अवधि के लिए। *: 2 फरवरी, 2022 तक।
#: फरवरी 2021 में औसत मूल्य।
नोट: मिट्टी के तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई)। मिट्टी के तेल के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रियायती कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।
स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान है।

IV. वित्तीय स्थितियां

घरेलू वित्तीय स्थितियाँ सौम्य बनी हुई हैं, हालाँकि हाल ही में कुछ और सख्त हुई हैं। 10 फरवरी, 2022 को अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में, रिज़र्व बैंक ने संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को और अधिक लचीला और चुस्त बनाने के लिए चार निर्णयों की घोषणा की: (i) नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) रखरखाव चक्र के भीतर विकसित तरलता और वित्तीय स्थितियों द्वारा वारंट किए जाने पर अलग-अलग अवधियों के परिवर्तनीय दर रेपो संचालन के रूप में आयोजित किया जाना है; (ii) मुख्य चलनिधि प्रबंधन उपकरण के रूप में संचालित करने के लिए और सीआरआर रखरखाव चक्र के साथ मेल खाने के लिए संचालित करने के लिए 14-दिवसीय अवधि के परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) और परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर); (iii) आरक्षित रखरखाव अवधि के दौरान किसी भी अप्रत्याशित चलनिधि परिवर्तन से निपटने के लिए फाइन-ट्यूनिंग संचालन द्वारा समर्थित मुख्य संचालन और मांग किए जाने पर आयोजित की जाने वाली लंबी परिपक्वता की नीलामी; और (iv) 1 मार्च, 2022 से, फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) परिचालन सभी दिनों में केवल 17.30-23.59 बजे के दौरान उपलब्ध होंगे, न कि 09.00-23.59 बजे के दौरान, जैसा कि महामारी की स्थिति से निपटने के लिए 30 मार्च 2020 से शुरू किया गया था । ओमीक्रोन से संबंधित संक्रमणों और व्यवधान को देखते हुए, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए क्रमशः ₹50,000 करोड़ और ₹15,000 करोड़ की ऑन-टैप चलनिधि सुविधाओं को 31 मार्च, 2022 से 30 जून, 2022 तक बढ़ा दिया गया था।

जनवरी की दूसरी छमाही से 14 फरवरी, 2022 तक एलएएफ के तहत दैनिक शुद्ध चलनिधि अवशोषण औसत ₹6.4 लाख करोड़ के साथ बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि मॉडरेट हुई, जो दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 के मध्य तक ₹7.0 लाख करोड़ से कम है। चलनिधि पुनर्संतुलन जारी रहा, अधिशेष चलनिधि रातों-रात फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो विंडो से विभिन्न परिपक्वताओं की वीआरआरआर नीलामियों में स्थानांतरित हो रही है, जिसमें मुख्य 14-दिवसीय वीआरआरआर ऑपरेशन

शामिल है, एक निर्बाध और गैर-विघटनकारी तरीके से। नतीजतन, फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो विंडो के तहत औसत दैनिक अवशोषण जनवरी के दूसरे पखवाड़े से 14 फरवरी, 2022 के दौरान दिसंबर 2021 के मध्य से जनवरी 2022 के मध्य तक 1.5 लाख करोड़ रुपये से घटकर ₹1.4 लाख करोड़ हो गया। प्रत्याशित जीएसटी संग्रह से अधिक होने के कारण प्रणालीगत तरलता में क्षणिक जकड़न को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने तीन वीआरआर संचालन आयोजित किए - 20 जनवरी को 50,000 करोड़ रुपये की एक नीलामी, और क्रमशः 21 जनवरी और 24 जनवरी, 2022 को 75,000 करोड़ रुपये की दो नीलामी।

जनवरी 2022 के उत्तरार्ध में जीएसटी के बहिर्वाह ने रातोंरात मुद्रा बाजार दरों को पॉलिसी रेपो दर से ऊपर खींच लिया। गैर-संपार्श्विक खंड में, भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) ने पॉलिसी रेपो दर को छुआ, जबकि संपार्श्विक दरों - त्रि-पक्षीय रेपो और बाजार रेपो दर - ब्याज दर गलियारे (सीमांत स्थायी सुविधा दर) की सीमा तक पहुंच गई। जनवरी के अंत में परिवर्तनीय दर रेपो संचालन और बड़े सरकारी खर्च के माध्यम से चलनिधि इंजेक्शन के साथ यह क्षणिक तंगी कम हो गई (चार्ट 29)। अप्रत्याशित चलनिधि मिसमैच से निपटने के लिए फाइन-ट्यूनिंग परिचालनों के उपयोग ने विकसित चलनिधि आवश्यकताओं का सामना करने में संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे के अंतर्निहित लचीलेपन को प्रदर्शित किया।

बाहरी अवधि के मुद्रा बाजार खंड में ब्याज दरों में वृद्धि हुई। नरम ओवरनाइट दरों के बावजूद 3 महीने की टी-बिल दर और जमा के प्रमाण पत्र (सीडी) दर को नीतिगत रेपो दर की ओर खींच लिया गया था। उसी समय, 3 महीने के वाणिज्यिक पत्र (सीपी) - एनबीएफसी दर ने पॉलिसी रेपो दर से ऊपर कारोबार किया, जो बड़े निर्गमों (चार्ट 30) को दर्शाता है। उच्च कट ऑफ पर वीआरआरआर के माध्यम से अवशोषण के आकार में क्रमिक वृद्धि ने अल्पकालिक दरों को ऊपर की ओर झुका दिया है।

बॉन्ड यील्ड सख्त हो गई, नए जारी किए गए 10-वर्षीय जी-सेक बेंचमार्क (6.54 जीएस 2032) पर यील्ड 14 फरवरी, 2022 (चार्ट 31 ए) को 6.67 प्रतिशत पर बंद हुई। यील्ड वक्र स्थिर रहा, लेकिन 8-10 वर्ष की परिपक्वता (चार्ट 31 बी) में तेज वृद्धि के साथ। जबकि 1.2 लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों और तेल बांडों के लिए स्विच संचालन के संचालन ने अस्थायी राहत प्रदान की, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषणाओं के साथ यील्ड तेजी से बढ़ी, जो 14.95 लाख करोड़ रुपये की उम्मीद से अधिक केंद्र सरकार के बाजार उधार में परिवर्तित हुई, जिसने बाजार की भावना को परेशान किया। परिणामी बिक्री ने 10 साल

चार्ट 29 : रिवर्स रीपो और ओवरनाइट मनी मार्केट दरों के अंतर्गत अवशोषण

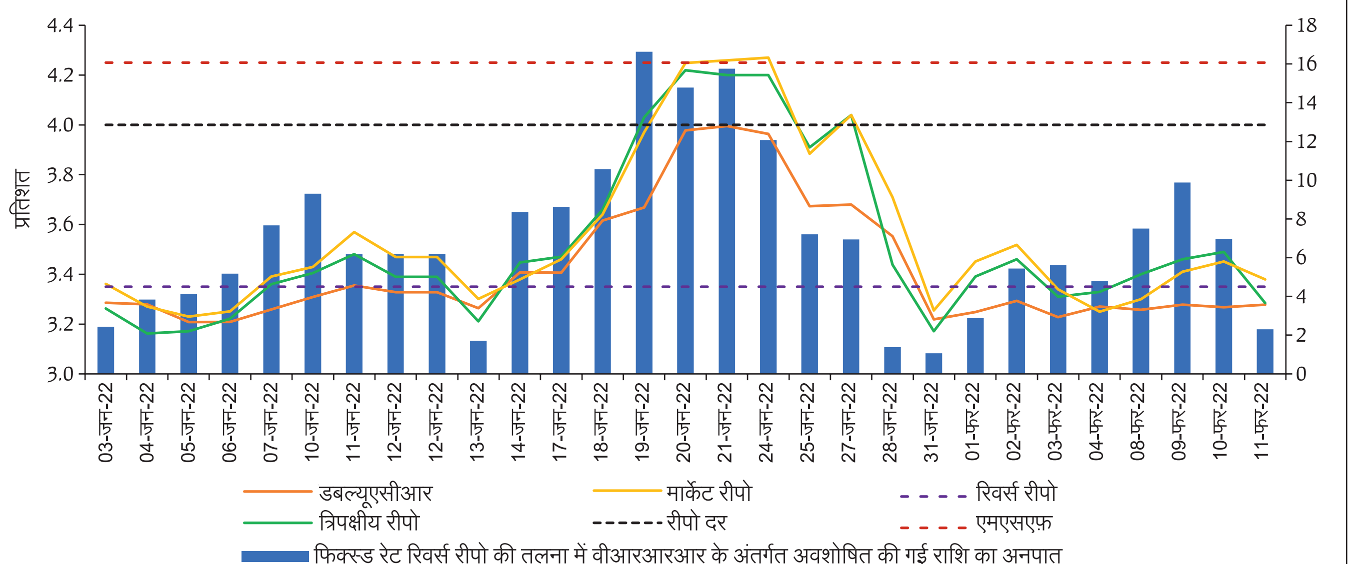

स्रोत: आरबीआई और आरबीआई स्टाफ का अनुमान है।

चार्ट 30 : नीतिगत कॉरीडोर और मुद्रा बाजार दरें

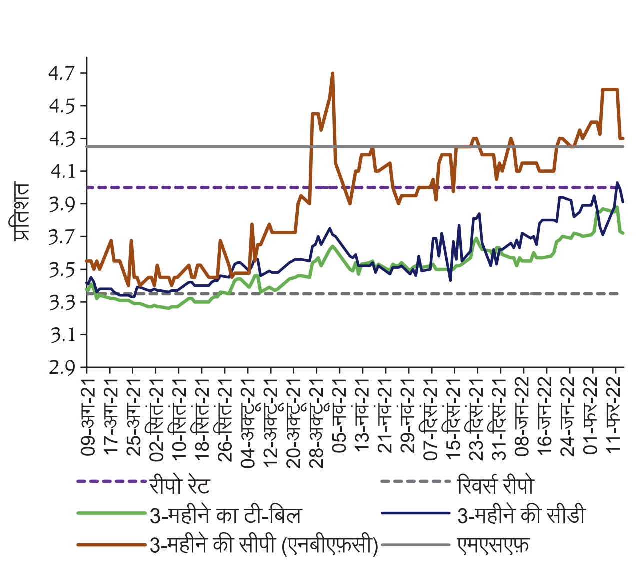

स्रोत: ब्लूमबर्ग

के बेंचमार्क प्रतिफल को लगभग 15 बीपीएस तक बढ़ा दिया और बजट का दिन 6.83 प्रतिशत पर समाप्त हुआ। वैश्विक मोर्चे पर, यूएस फेड द्वारा संकेतित नीतिगत सामान्यीकरण की तेज गति, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और केंद्रीय बजट 2022-23 से पहले बाजार उधार कार्यक्रम के आकार पर घरेलू बांड बाजार की चिंताओं के बीच कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि ने जी-सेक यील्ड को मजबूत करने में योगदान दिया। हालांकि, 10 फरवरी, 2022 को मौद्रिक नीति की घोषणा और 11 फरवरी, 2022 को होने वाली प्रतिभूतियों की नीलामी को रद्द करने और 18 फरवरी, 2022 को होने वाली प्रतिभूतियों की नीलामी को रद्द करने के बाद यील्ड में नरमी आई। प्राथमिक बाजार में, जनवरी 2022 के दौरान आयोजित सभी साप्ताहिक नीलामी में आंशिक रूप से बदलाव देखा गया। इसके बाद, रिजर्व बैंक ने 4 फरवरी, 2022 को आयोजित साप्ताहिक नीलामी में 5 साल और 14 साल की प्रतिभूतियों के लिए कोई बोली स्वीकार नहीं की।

जी-सेक यील्ड के साथ, कॉरपोरेट बॉन्ड पर प्रतिफल एक सख्त पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है, हालांकि, जोखिम-मुक्त (जी-सेक) दर (सारणी 7) की तुलना में कुछ हद तक कम है। नतीजतन, जोखिम प्रीमियम (कॉरपोरेट बांड तुलनीय परिपक्वता के जी-सेक में फैलता है) एक महीने पहले से फरवरी 2022 (10 फरवरी तक) के दौरान अपरिवर्तित रहा या मार्जिन पर बढ़ गया। वर्ष 2021-22 के दौरान कॉरपोरेट बॉन्ड के कम जारी होने से प्रतिफल पर दबाव कम हुआ है।

चार्ट 31 : बॉन्ड यील्ड्स

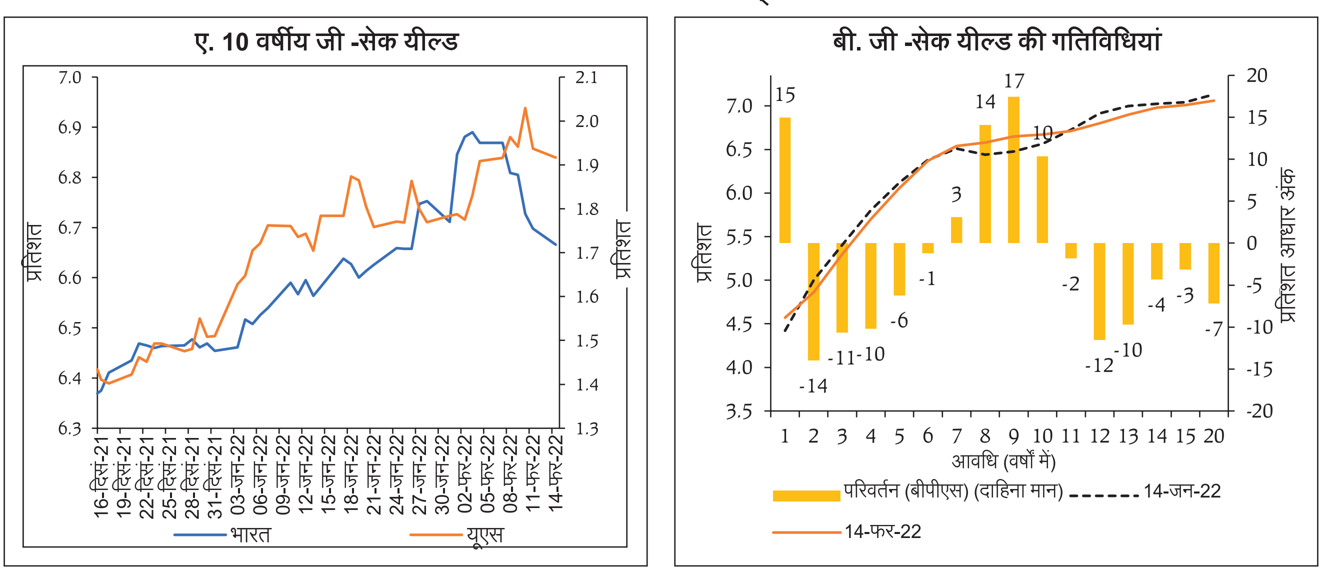

स्रोत: ब्लूमबर्ग

सारणी 7: वित्तीय बाजार - दरें और स्प्रेड

वाद्य यंत्र	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (बीपीएस) (संबंधित जोखिम मुक्त दर से अधिक)		
	जन 2022	फर 2022 (10 वरी तक)	भिन्नता (बीपीएस में)	जन 2022	फर 2022 (10 वरी तक)	भिन्नता (बीपीएस में)
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
व्यापारिक बाध्यता						
(i) एएए (1-वर्ष)	4.65	4.82	17	14	12	-2
(ii) एएए (3 साल)	5.61	5.82	21	12	18	6
(iii) एएए (5-वर्ष)	6.07	6.23	16	-17	-16	1
(iv) एए (3-वर्ष)	6.40	6.57	17	91	93	2
(v) बीबीबी-माइनस (3-वर्ष)	10.41	10.22	8	458	458	0
10 वर्षीय जी-सेक	6.41	6.73	32			

नोट: यील्ड और स्प्रेड की गणना मासिक औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफ़आईएमएमडीए); और ब्लूमबर्ग।

कुल मिलाकर मौद्रिक और ऋण की स्थिति रिजर्व बैंक के अनुकूल नीतिगत रुख के अनुरूप विकसित हुई। आरक्षित धन (आरएम), नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बहाली के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर, 4 फरवरी, 2022 (एक साल पहले 18.9%) पर 8.4% वर्षानुवर्ष की दर से बढ़ा, प्रचलन में मुद्रा के साथ, आरएम का सबसे बड़ा घटक, एक समान गति से बढ़ रहा है (8.2 प्रतिशत; 20.8 प्रतिशत एक साल पहले)। मुद्रा आपूर्ति (एम 3) में भी 28 जनवरी, 2022 (एक साल पहले 12.1 प्रतिशत) तक 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से बैंकों की कुल जमा राशि में 8.3 प्रतिशत (एक साल पहले 10.5 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाता है। वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण में वृद्धि, जो अप्रैल 2020 के बाद पहली बार नवंबर 2021 में 7 प्रतिशत के निशान से ऊपर हो गई, 28 जनवरी, 2022 को 8.2 प्रतिशत थी (एक साल पहले के 5.9 प्रतिशत के स्तर से बहुत ऊपर) [चार्ट 32]।

एससीबी ऐतिहासिक रूप से कम दरों पर नए ऋणों की कीमत जारी रखते हैं, वर्तमान सहजता चरण के दौरान बेहतर संचरण को प्रतिबिंबित करते हैं। रिजर्व बैंक के नीतिगत उपायों की प्रभावशीलता की गवाही देते हुए, एससीबी ने मार्च 2020 से नए रुपये के ऋणों के साथ-साथ बकाया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) के लिए 115 बीपीएस की नीतिगत दर में कटौती के पूर्ण पास-थ्रू को प्रभावित किया है। मार्च 2020 से जनवरी 2022 के दौरान, फंड-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की एक साल की औसत सीमांत लागत में 95 बीपीएस (चार्ट 33) की गिरावट आई। बेहतर मौद्रिक पारेषण के परिणामस्वरूप प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों के लिए उधार की लागत कम हुई है।

अधिशेष तरलता के कारण मार्च 2020 से जनवरी 2022 के दौरान औसत सावधि जमा दर (एमटीडीआर) में 151 बीपीएस की कमी आई है। 178 बीपीएस की प्रत्यक्ष गिरावट विशेष रूप से एक वर्ष तक की परिपक्वता की छोटी अवधि के लिए स्पष्ट है। घरेलू बैंकों में, निजी बैंकों ने मजबूत जमा वृद्धि (चार्ट 34) के

चार्ट 32 : मौद्रिक और ऋण कुल राशियाँ

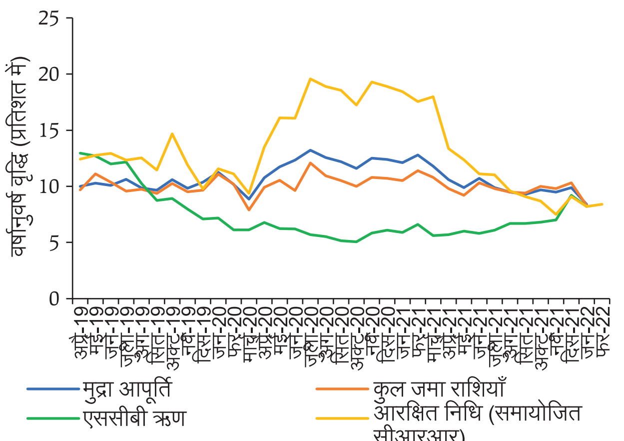

नोट: 1. ये आंकड़े धन आपूर्ति, सकल जमा और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबन्धित हैं; और आरक्षित निधि के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबन्धित हैं।
2. तथापि, फरवरी के लिए आरक्षित निधि से संबन्धित आंकड़े 04 फरवरी 2022 की स्थिति के अनुसार हैं।
स्रोत: आरबीआई

चार्ट 33 : उधार और जमा दरों में प्रसार (मार्च 2020 से जनवरी 2022 तक)

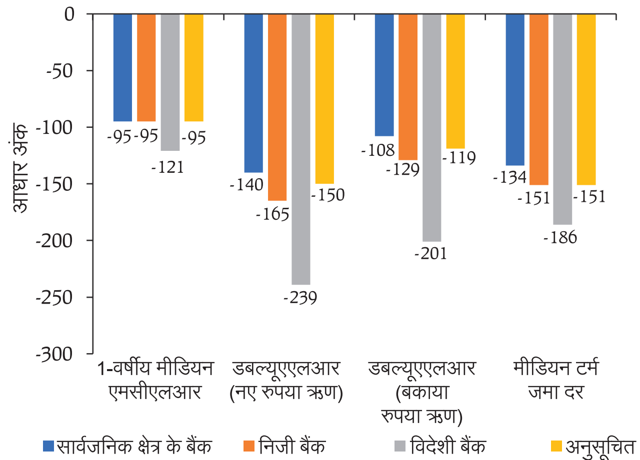

नोट: डबल्यूएलएआर से संबन्धित नवीनतम आंकड़े दिसंबर 2021 से संबन्धित हैं
स्रोत: आरबीआई और आरबीआई स्टाफ का अनुमान है।

चार्ट 34 : मीडियन टर्म जमा दरों में परिपक्वता के आधार पर प्रसार (मार्च 2020 से जनवरी 2022 तक)

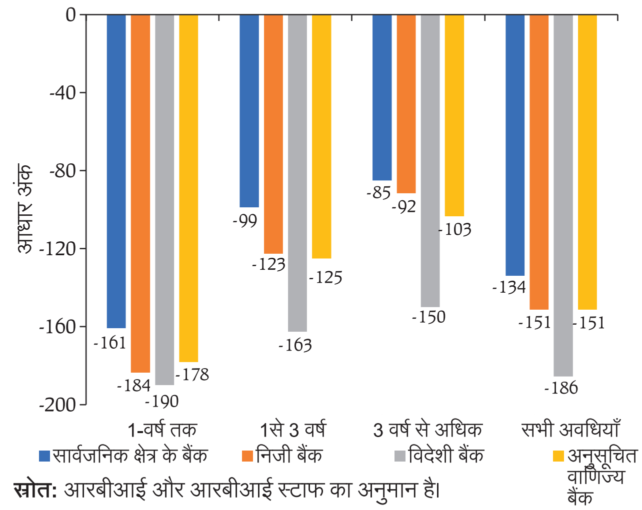

स्रोत: आरबीआई और आरबीआई स्टाफ का अनुमान है।

कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की तुलना में सावधि जमा दरों के लिए उच्च पास-थ्रू प्रभावित किया है। हालांकि, एससीबी एक मोड़ बिंदु पर पहुंच गए हैं। क्रेडिट मांग में वृद्धि और कुल जमा में कम वृद्धि के साथ, बैंकों ने हाल के महीनों में उच्च दरों पर अपनी जमा राशि में मूल्य निर्धारण शुरू कर दिया है। नतीजतन, एमटीडीआर अक्टूबर 2021 के बाद से 5 बीपीएस की मामूली वृद्धि हुई।

यूएस फेड (चार्ट 35ए) द्वारा मौद्रिक नीति को जल्दी सख्त करने की संभावनाओं के कारण जोखिम-बंद भावनाओं के बीच भारतीय इक्विटी बाजारों ने जनवरी 2022 के महीने में उच्च अस्थिरता का अनुभव किया। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी बाजारों में, बड़ी गिरावट दर्ज की गई, निवेशकों ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र (चार्ट 35 बी) के प्रति सतर्क रुख किया। एक सकारात्मक नोट पर महीने की शुरुआत के बाद, बीएसई सेंसेक्स नवीनतम अमेरिकी

चार्ट 35: इक्विटी बाजार

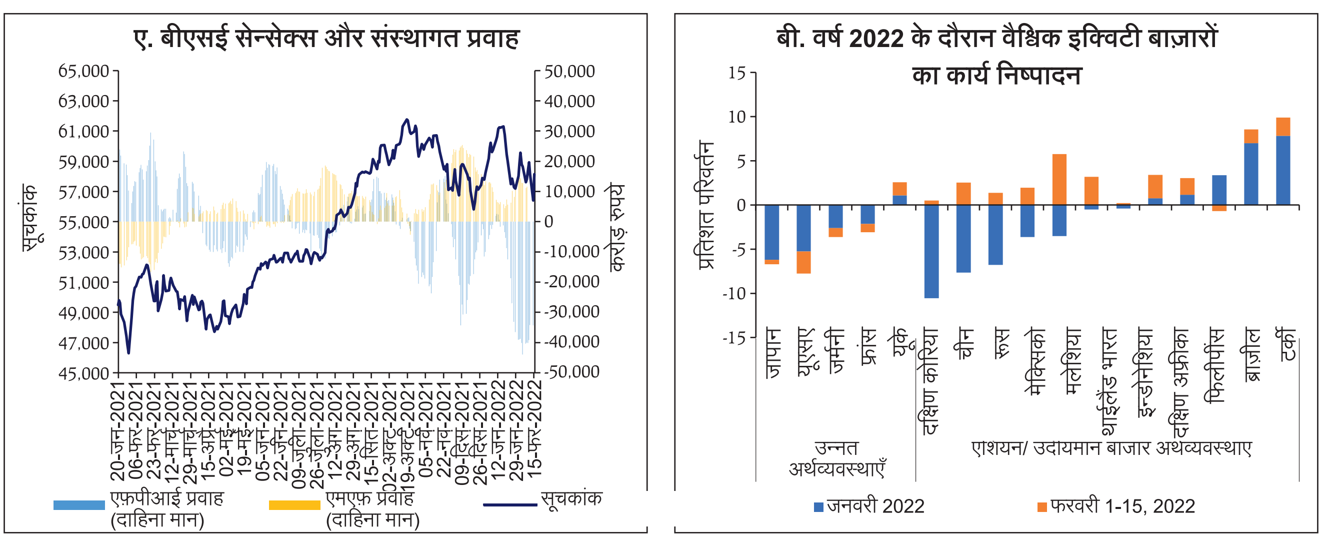

नोट: एफ़पीआई और एमएफ़ निवेश को 15 दिनों के रोलिंग -सम आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग; एनएसडीएल और सेबी

फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक के मिनटों में ओमीक्रोन मामलों की बढ़ती संख्या और हॉकिश टोन पर अस्थिर हो गया। इसके बाद, बाजार ने मजबूत तीसरी तिमाही: 2021-22 कॉर्पोरेट आय परिणामों और ओमीक्रॉन के सीमित आर्थिक प्रभाव की उम्मीदों की उम्मीदों पर वापस उछाल दिया। हालांकि, रैली क्षणिक साबित हुई क्योंकि निवेशकों ने बढ़ती वैश्विक मुद्रास्फीति, अमेरिकी ट्रेजरी पैदावार और कच्चे तेल की कीमतों को रूस और यूक्रेन के बीच भू-राजनीतिक तनाव के साथ जोड़ा। फरवरी की शुरुआत में, इक्विटी बाजारों ने घरेलू भावनाओं को मदद करने वाले सकारात्मक वैश्विक संकेतों के साथ केंद्रीय बजट में घोषणाओं की संभावनाओं पर रिबाउंड किया। इसके बाद तेज झूलों का पालन किया गया, ज्यादातर वैश्विक संकेतों को ट्रैक किया गया। 14 फरवरी, 2022 को बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव पर बाजार ों में गिरावट आई, लेकिन चिंताओं को कम करने के बीच अगले दिन लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया। कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स में 2022 के दौरान अब तक 0.2 प्रतिशत की गिरावट आई है - जनवरी 2022 के दौरान 0.4 प्रतिशत की गिरावट, और फरवरी 2022 (15 फरवरी, 2022 तक) के दौरान 0.2 प्रतिशत की वृद्धि। बीएसई आईपीओ इंडेक्स, जो हाल ही में सूचीबद्ध प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) शेयरों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है, ने बाजार बेंचमार्क को कम कर दिया, 2022 के दौरान अब तक (15 फरवरी, 2022 तक) 13.8 प्रतिशत की गिरावट आई है।

सभी सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियों के बाजार पूंजीकरण के 80 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाली 1,273 सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियों के कॉर्पोरेट आय परिणाम, 2021-22 की तीसरी तिमाही (चार्ट 36) के दौरान दोहरे अंकों की वर्षानुवर्ष बिक्री वृद्धि दिखाते हैं। बिक्री वृद्धि के मामले में उच्च प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में होटल और पर्यटन, तेल और गैस, धातु और खनन, कपड़ा, रसायन, मशीनरी, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) शामिल थे। इनपुट लागत दबाव ने कुछ क्षेत्रों की लाभप्रदता को प्रभावित किया।

अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान, सकल आवक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) एक साल पहले के 68.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से घटकर 60.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट 37)। विनिर्माण, कंप्यूटर सेवाएं, संचार सेवाएं, खुदरा और थोक व्यापार और शिक्षा, अनुसंधान और

चार्ट 36 : सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियों का कार्य निष्पादन

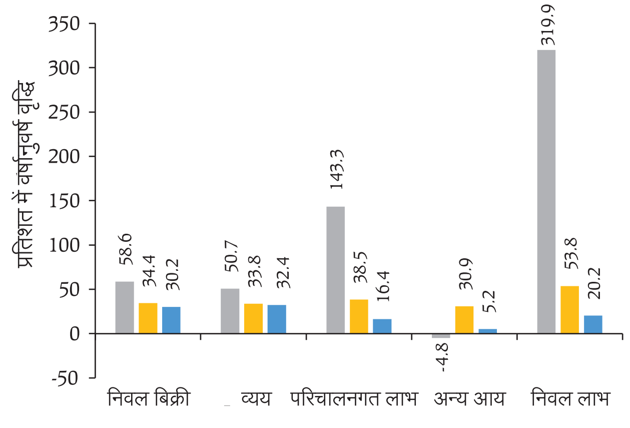

नोट: असाधारण सामानों को शामिल नहीं किया गया है
स्रोत: प्रोवेस और आरबीआई स्टाफ की आकलन।

विकास ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने अधिकांश निवेश को आकर्षित किया। भारत से निवल जावक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्षानुवर्ष आधार पर अधिक निकला।

वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका में आक्रामक नीतिगत सामान्यीकरण पर चिंताओं के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने जनवरी 2022 के दौरान घरेलू इक्विटी बाजार से अपना निवेश निकालना जारी रखा। हालांकि, ऋण खंड ने महीने के दौरान मामूली प्रवाह दर्ज किया (चार्ट 38)।

चार्ट 37 : विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

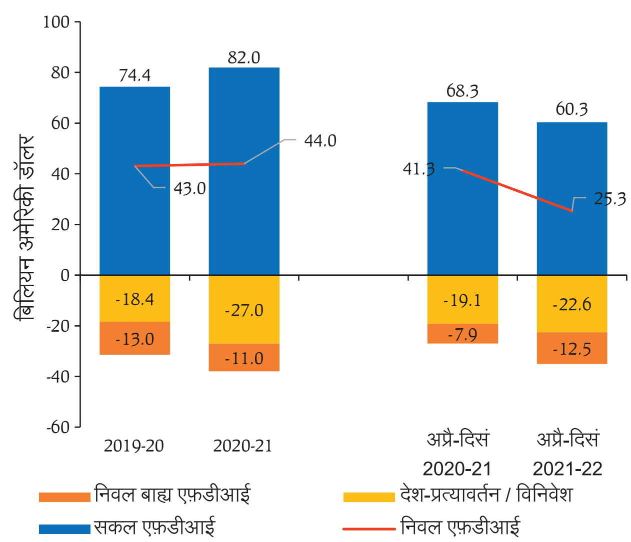

स्रोत: आरबीआई

चार्ट 38 : निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

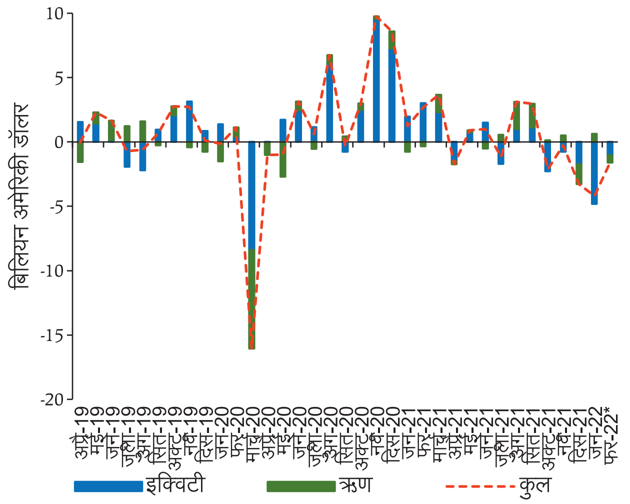

*11 फरवरी तक

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)

चार्ट 39 : विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ

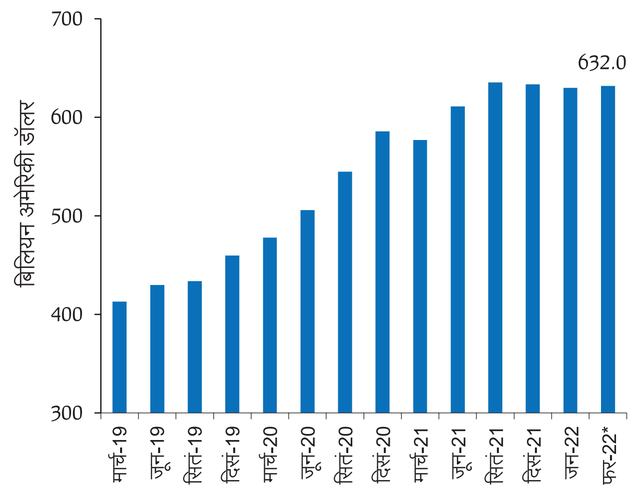

*4 फरवरी की स्थिति के अनुसार

स्रोत: आरबीआई

अंतर-कंपनी उधारसहित भारत को विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) का शुद्ध संवितरण अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जबकि एक साल पहले 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध बहिर्वाह की तुलना में चुकौती और अंतर-कंपनी उधार को छोड़कर शुद्ध वितरण 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जबकि एक साल पहले 5.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध पुनर्भुगतान की तुलना में। दिसम्बर में, उधार/उप-उधार, पहले के ईसीबी के पुनर्वित्त और रुपये के ऋणों के पुनर्वित्त के लिए काफी मात्रा में उधार लिया गया था।

4 फरवरी 2022 को विदेशी मुद्रा भंडार 632.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2021-22 (चार्ट 39) के लिए अनुमानित 12.6 महीने के आयात के बराबर था।

विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपया (आईएनआर) जनवरी 2022 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1.3 प्रतिशत

चार्ट 40 : 40 मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में मासिक गतिविधियां (आधार : 2015-16 = 100)

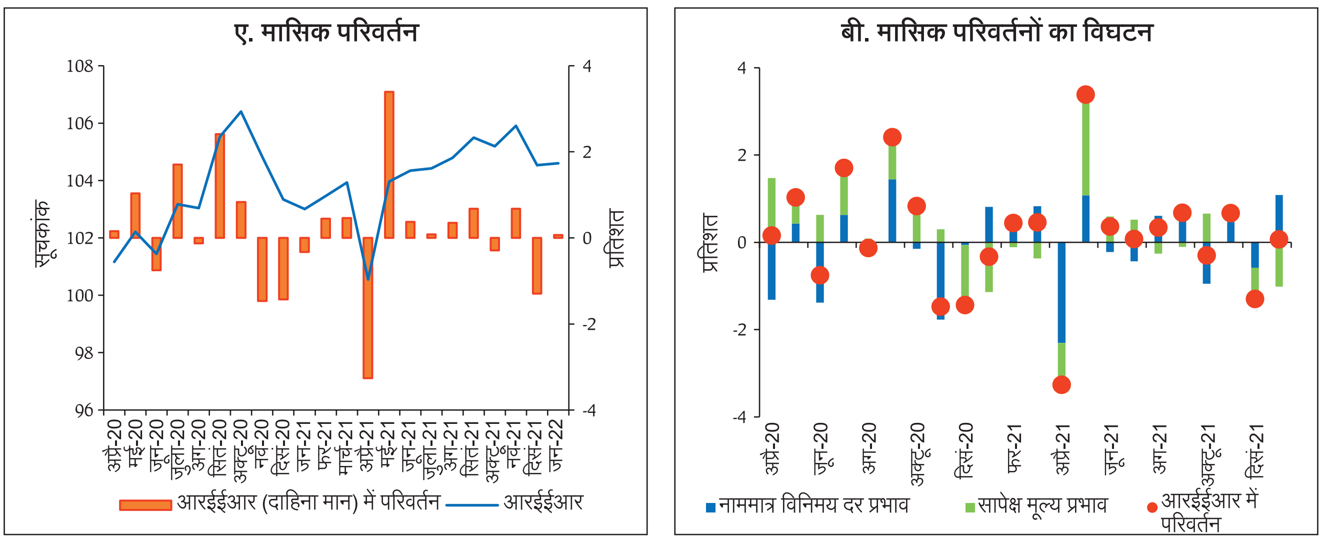

नोट: जनवरी 2022 के आंकड़े अनंतिम हैं

स्रोत: आरबीआई

सारणी 8 : चुनिन्दा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दर

भुगतान प्रणाली	लेनदेन मात्रा वृद्धि (वर्षानुवर्ष प्रतिशत)				लेनदेन मात्रा वृद्धि (वर्षानुवर्ष प्रतिशत)			
	दिसं-2020	दिसं-2021	जन-2021	जन-2022	दिसं-2020	दिसं-2021	जन-2021	जन-2022
आरटीजीएस	20.2	17.9	14.1	15.7	3.3	21.7	-7.2	13.9
एनईएफ़टी	31.6	22.3	10.3	26.2	31.7	6.5	12.3	12.8
यूपीआई	70.8	104.4	76.5	100.5	105.5	98.7	99.4	93.0
आईएमपीएस	38.7	24.5	33.5	27.0	38.6	35.6	33.1	34.1
एनएसीएच	28.0	-2.7	-14.6	28.8	32.2	5.1	11.6	26.4
एनईटीसी	115.2	74.9	60.4	54.8	83.3	59.7	48.1	50.0
बीबीपीएस	86.2	137.0	84.0	130.2	97.9	165.2	106.0	148.8

स्रोत: आरबीआई

(एम-ओ-एम) बढ़ गया। नाममात्र और वास्तविक दोनों प्रभावी शब्दों (40-मुद्रा बास्केट) में, आईएनआर में एक महीने पहले के स्तर से क्रमशः 1.1 और 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 40एऔर 40बी)।

भुगतान प्रणाली

वर्ष 2022 की शुरुआत पहले महीने में डिजिटल भुगतान में एक मजबूत रैली के साथ हुई है, जिसमें थोक और खुदरा लेनदेन पिछले वर्ष हासिल किए गए उल्लेखनीय मील के पत्थर के शीर्ष पर लगातार वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) प्रदर्शित कर रहे हैं। बड़े मूल्य भुगतान के मोर्चे पर, रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के माध्यम से लेन-देन की मात्रा जनवरी 2022 (सारणी 8) में दोहरे अंकों की वृद्धि को बनाए रखती है। खुदरा खंड में, यूपीआई लेनदेन जनवरी 2021 के सापेक्ष मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में लगभग दोगुना हो गया। भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) - आवर्ती बिल भुगतान के लिए एक-स्टॉप पारिस्थितिकी तंत्र, इस प्रवृत्ति को दर्शाता है। फल देने वाले भुगतान स्थान में अब तक पहुंच से बाहर तक पहुंचने के प्रयासों के साथ, आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) ने इस महीने अब तक के सबसे अधिक लेनदेन हासिल किए हैं।

हाल के साक्ष्य से पता चलता है कि 2021 के दौरान निजी भुगतान गेटवे पर टियर 2 और 3 शहरों से ऑनलाइन लेनदेन की मात्रा के साथ भौगोलिक क्षेत्रों, क्षेत्रों और व्यवसायों में डिजिटल डिवाइड कम हो सकता है, क्रमशः 45.6 प्रतिशत और 54.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।[7] कुल मिलाकर, उच्चतम विकास खाद्य और पेय क्षेत्र से उपजा है, इसके बाद वित्तीय सेवाओं का स्थान है। गेम्स, यूटिलिटीज और ई-कॉमर्स भी डिजिटल भुगतान वृद्धि के प्रमुख चालक थे। इसके अलावा, थोक ई-कॉमर्स खंड में वर्ष के दौरान मजबूत वृद्धि दर्ज की गई।

चार्ट 41 : आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक

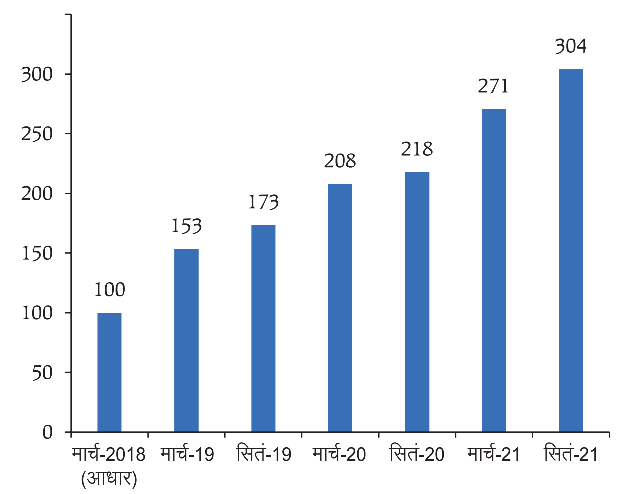

स्रोत: आरबीआई

[7] https://razorpay.com/blog/the-covid-era-of-rising-fintech-razorpay-report-10th-edition/

[8] आरबीआई डीपीआई में 5 व्यापक मानदंड शामिल हैं जो विभिन्न समय अवधि में देश में डिजिटल भुगतान की गहराई और पैठ को मापने में सक्षम बनाते हैं। ये मानदंड हैं - (i) भुगतान सक्षमकर्ता (भार 25 प्रतिशत); (ii) भुगतान अवसंरचना - मांग-पक्ष कारक (10 प्रतिशत); (iii) भुगतान अवसंरचना - आपूर्ति पक्ष कारक (15 प्रतिशत); (iv) भुगतान प्रदर्शन (45 प्रतिशत); और (v) उपभोक्ता केंद्रितता (5 प्रतिशत)।

रिज़र्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक[8] सितंबर 2021 (चार्ट 41) में 304 तक चढ़ गया, जो डिजिटल भुगतान में तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। महामारी के प्रकोप के बाद से वायरलेस इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 77.7 करोड़ [9] तक पहुंच गई है और प्रति भारतीय उपयोगकर्ता द्वारा प्रति दिन मोबाइल पर खर्च किया गया औसत समय 2019 के 3.7 घंटे से बढ़कर 2021 में 4.7 घंटे[10] (विश्लेषण किए गए देशों में पांचवां सबसे अधिक) हो जाने के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन की पैठ तेजी से बढ़ी है। ऐप अर्थव्यवस्था के निरंतर विस्तार से डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर वृद्धि होने की उम्मीद है। नैसकॉम के अनुसार, भारत में डिजिटल भुगतान की मात्रा 2025 तक के पांच वर्षों में 16 गुना बढ़ सकती है। [11]

विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर जारी बयान[12] में, रिज़र्व बैंक ने सरकारों द्वारा जारी ई-रूपी वाउचर पर राशि सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये करने की घोषणा की है, जो सरकारी लाभों और सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी को और अधिक सुविधाजनक बनाएगा। बारंबारी एवं आवधिक भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाले समाधान-व्यापारिक प्राप्य राशि बट्टाकरण प्रणाली (ट्रेड्स) पर निपटान के लिए राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन सदन (एनएसीएच) अधिदेश सीमा को भी 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की बढ़ती चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय बजट 2022-23 में डिजिटल और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना, भुगतान के डिजिटल तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता जारी रखना और स्टार्ट-अप के लिए कर प्रोत्साहन योजना में छूट शामिल है।

[9] *https://www.trai.gov.in/sites/default/files/PR_No.04of2022_1.pdf*

[10] *https://www.appannie.com/en/go/state-of-mobile-2022/*

[11] *https://nasscom.in/knowledge-center/publications/india-digital-payments-40-2025-outlook*

[12] *https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=53248*

निष्कर्ष

आज वैश्विक अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति की एक मोड़ पर खड़ी है। जिंसों की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति शृंखला की बाधाओं की निरंतरता के कारण मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्थाओं में बनी रही है। वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थिति अनिश्चितता की एक बढ़ी हुई स्थिति में उलझी हुई है, जिसमें जोखिम का झुकाव नकारात्मक पक्ष की ओर है। ब्याज दर, इक्विटी मूल्यांकन, ऋण लागत और मुद्रा डेटा सहित एक समग्र सूचकांक -गोल्डमैन सैक्स वित्तीय स्थिति सूचकांक - विशेष रूप से उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं (चार्ट 42) के लिए वित्तीय स्थितियों के महत्वपूर्ण रूप से कठोर होने की ओर इंगित करता है। जोखिम से बचने के दृष्टिकोण से निवेशक का रुख कमजोर हुआ है, जो पूंजी प्रवाह को अस्थिर कर सकता है और भावी रिकवरी को और आगे बढ़ा सकता है।

इस अस्थिर वैश्विक वातावरण के बावजूद, घरेलू आर्थिक स्थिति में सुधार जारी है। केंद्रीय बजट 2022-23 और 10 फरवरी, 2022 की मौद्रिक नीति की घोषणा ने टिकाऊ और व्यापक-आधारित पुनरुद्धार के लिए दशा निर्धारित किया है। बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से सार्वजनिक निवेश पर नए सिरे से जोर देने के कारण 2022-23 में निजी निवेश में वृद्धि होने और रोजगार सृजन एवं मांग को मजबूत करने की उम्मीद है।

चार्ट 42 : वित्तीय स्थिति सूचकांक

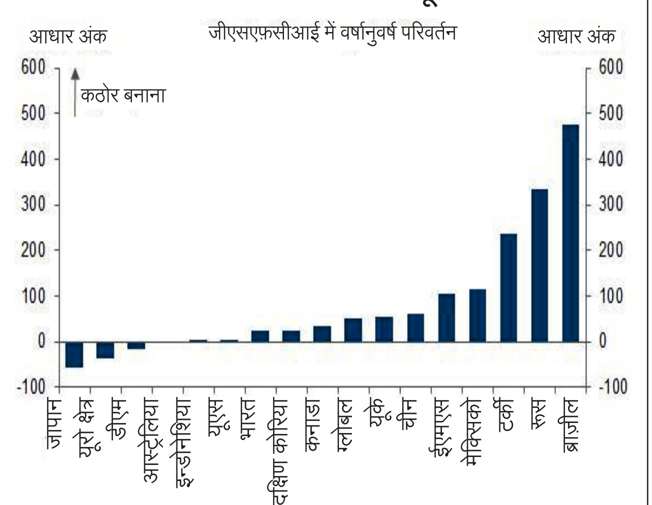

स्रोत: गोल्डमैन सैच्स

बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, जिसका उद्देश्य मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता के माध्यम से समावेशी विकास प्राप्त करना है।

2022-23 में मुद्रास्फीति के उदार सीमा के भीतर रहने के अनुमान को ध्यान में रखते हुए, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने एक अनुकूल नीतिगत रुख के साथ स्थिर होने और दृढ़ रहने का फैसला किया। गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने इस बात पर जोर दिया कि मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरता हासिल करने के अपने प्रयास को जारी रखेगी, साथ ही एक मजबूत और निरंतरआर्थिक सुधार[13] सुनिश्चित करेगी। अधिक व्यय और व्यापार करने में सुगमता ने दृष्टिकोण को उज्ज्वल किया है। आईएमएफ के मुताबिक भारत एक बार फिर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।

[13] 10 फरवरी 2022 को गवर्नर का वक्तव्य

*जॉम्बी फर्म और सृजनात्मक विध्वंस की प्रक्रिया**

शुम्पीटर की सृजनात्मक विध्वंस की प्रक्रिया में कमज़ोर फर्मों से उच्च-संवृद्धि क्षमता वाले सुदृढ फर्मों की ओर संसाधनों का गतिज पुनराबंटन अपेक्षित है। लेकिन, जॉम्बी फर्म, जो प्रतिचक्रीय नीति की बदौलत अपेक्षा से अधिक समय तक बने रहते हैं, इस प्रक्रिया में बाधक बनते हैं। भारत के फर्म-स्तरीय आँकड़ों का उपयोग करते हुए इस आलेख का यह निष्कर्ष है कि मौद्रिक नीति, आर्थिक मंदी के दौरान, जॉम्बी फर्मों को क्रेडिट प्रवाह का त्रुटिपुर्ण आबंटन कर, सृजनात्मक विध्वंस की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालती, बल्कि ऐसा लगता है कि जॉम्बी फर्मों ने, नए निवेश आरंभ करने के वजाय अपना अस्तित्व बचाने हेतु संसाधन उधार ले कर, मौद्रिक नीति के प्रभाव को सीमांत पर कमज़ोर कर दिया है।

परिचय

इस तथ्य को प्रमाणों के साथ महसूस किया जा रहा है कि कारोबारी चक्र की लागत अधिक है और स्थिरीकरण नीतियाँ, जैसा कि अधिकतर मानी जाती हैं, उससे कहीं अधिक लाभकारी हैं (योरदे, शुलारिक और टेलर, 2020)। संवृद्धि पथ पर कमजोर चक्रीय स्थितियों के अंतर्जात प्रभावों के कारण, आक्रामक और सक्रिय प्रतिचक्रीय नीति कार्रवाईयाँ सर्वाधिक उपयुक्त हो सकती हैं (सेरा, फैटस और सक्सेना, 2020)। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद की अवधि में, उत्पादकता वृद्धि में मंदी - एक दीर्घकालिक पूर्व-जीएफसी प्रवृत्ति जो केवल संकट के कारण बढ़ी थी - आंशिक रूप से अति-नरम मौद्रिक नीति का परिणाम भी हो सकती है, जिसने ज़ॉम्बियों को सतत ऋण देने और जीवित रखने हेतु कमजोर बैंकों को सक्षम बनाया (ऑब्स्टफेल्ड और डुवल, 2018)।

शुम्पीटर की सृजनात्मक विध्वंस की प्रक्रिया में कमज़ोर फर्मों से उच्च-संवृद्धि क्षमता वाले सुदृढ फर्मों की ओर संसाधनों का गतिज पुनराबंटन अपेक्षित है, लेकिन, नौकरी छिनने और कमज़ोर फर्मों को बचाने हेतु नीतिगत हस्तक्षेप, मध्यावधिक प्रगति को बाधित कर सकते हैं और तकनीकी “जड़ता” पैदा हो सकती है (कैबलेरो और हैमर,1996)। इस प्रकार, प्रतिचक्रीय नीति प्रतिक्रिया में विकल्प होता है - मौजूदा नौकरियों को संरक्षित करना अथवा सृजनात्मक विध्वंस को प्रोत्साहित करना, नौकरियों और संसाधनों को विफल फर्मों से सफल फर्मों की ओर विस्थापित होने देना (जी 30, 2020)।

वैश्विक स्तर पर, लगातार घाटे में चल रही जॉम्बी फर्मों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो नियमित रूप से ऋण चुकाने के लिए अधिक ऋण/बाहरी वित्त का उपयोग करती हैं, ताकि वे कारोबार में बनी रहें (बनर्जी और हॉफमैन, 2020)। कमजोर बैंक अक्सर ऐसी जॉम्बी फर्मों को उच्च ब्याज दरों पर उधार देते हैं, जिससे वित्तीय प्रणाली में कमजोर बैंकों का अस्तित्व बना रहता है। समायोजनकारी मौद्रिक नीति और कम ब्याज दरें भी जॉम्बी फर्मों - जिसे व्यापक रूप से “सजीव लेकिन मृत” कहा जाता है - को कारोबार में बने रहने में मदद करतीं हैं। जापान में 1990 के दशक में ज़ॉम्बियों से जुड़े कटु अनुभव के बाद, यह उत्तरोत्तर महसूस किया गया है कि उधारजीविता एक वैश्विक परिघटना हो सकती है। इस प्रकार, अनुसंधान इस चुनौती के विभिन्न पक्षों की ओर मुड़ गया है, मसलन - अधिक उत्पादक फर्मों के जॉम्बी क्राउड-आउट वृद्धि के अवसर और अर्थव्यवस्था में उनकी बढ़ती उपस्थिति संभावित वृद्धि को कम कर सकती है (मैकगोवन, एंड्रयूज और मिलोट, 2018); कमजोर बैंकों और कमजोर दिवाला व्यवस्थाओं के साथ काम करने वाले देश जॉम्बी को पनपने देते हैं (एंड्रयूज और पेट्रोलाकिस, 2019); “ज़ॉम्बी क्रेडिट चैनल” एक कमजोर पूंजीकृत बैंकिंग (वित्तीय) प्रणाली में पनपता है, और इस तरह की प्रणाली में समायोजनकारी मौद्रिक नीति से “सतत ऋण” की प्रथा को बल मिलता है जिससे कमजोर बैंक और कमजोर फर्म जीवित रहते हैं। इसमें कमजोर फर्म, कमजोर बैंकों से नए उधार लेकर समय पर ऋण चुकौती करते हैं और इसलिए कमजोर बैंक न्यूनतम विनियामक पूंजी आवश्यकता से ऊपर रहने के लिए दबावग्रस्त आस्तियों का निर्धारण स्थगित करते रहते हैं (आचार्य, 2019); “... शुम्पीटर के सृजनात्मक विध्वंस के सिद्धांत की डेटा में पुष्टि नहीं की गई है” (बोसियो, जानकोव, जोलेव्स्की और रामलहो, 2020); और, जितने लंबे समय तक ज़ॉम्बी के रूप में यह जीवित रहता है, एक कमजोर

* यह आलेख भारतीय रिज़र्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के सितिकंठ पट्टनायक, सिलु मुदुली और जिबिन जोस द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं।

फर्म की मृत्यु का जोखिम कम हो जाता है (नूरमी, वन्हाला और वीरेन, 2020)।

एक अर्थव्यवस्था में काम करने वाली फर्मों की प्रकृति - मजबूत, कमजोर या ज़ॉम्बी - अक्सर मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया के परिणाम और अर्थव्यवस्था पर आघात को प्रभावित कर सकती है। मजबूत फर्में मंदी की स्थिति में अधिशेष नकदी का ढेर लगा सकती हैं, बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए डिलीवरेज कर सकती हैं और चक्रीय पिक-अप का लाभ उठाने के लिए तैयार रह सकती हैं। हालांकि, सीमित तरल संपत्ति और संपार्श्विक और खराब क्रेडिट इतिहास वाले कमजोर फर्मों पर बेहतर की ओर पलायन का असर पड़ सकता है, जिसके कारण, जरूरत पड़ने पर उन्हें कम ऋण मिल सकता है, वह भी ऊँची दरों पर (या बाहरी वित्त प्रीमियम)। प्रतिचक्रीय मौद्रिक नीति कमजोर फर्मों की रक्षा करके आघात के प्रसार को रोकने में मदद कर सकती है।

उधारकर्ताओं की साख प्रतिकूल आघात में पता चलती है, क्योंकि वे ऐसे समय में नकदी-प्रवाह में व्यवधान (या चलनिधि दबाव) का सामना करते हैं, जब उनकी निवल संपत्ति (या संपार्श्विक या स्वयं की इक्विटी पेश करने की क्षमता) कम हो जाती है। जब किसी फर्म का निवल मालियत प्रचक्रीय होता है (अर्थात, मंदी किसी फर्म की उधार लेने की क्षमता को कम करती है), बाहरी वित्त प्रीमियम प्रतिचक्रीय होता है (यानी, मंदी में, सूचना विषमता को देखते हुए, बैंक या तो उच्च ब्याज दर वसूल सकते हैं या सीमित ऋण देते हैं [1]), तब प्रति-चक्रीय मौद्रिक नीति (जो बाहरी वित्त प्रीमियम में अत्यधिक वृद्धि के जोखिम को कम कर सकती है और बैंकों को कमजोर को ऋण आपूर्ति के लिए प्रेरित कर सकती है) आवश्यक हो जाती है। मौद्रिक नीति का बैलेंस शीट चैनल और क्रेडिट चैनल दोनों एक बहिर्जात आघात के बाद अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद कर सकते हैं। बैलेंस शीट चैनल के संबंध में, सबसे पहले, कम ब्याज दरें विपणन योग्य संपार्श्विक (जैसे शेयर और बांड) के मूल्य में वृद्धि कर सकती हैं; दूसरा, ऋण चुकाने का बोझ उस हद तक कम हो सकता है कि ऋण, ब्याज की परिवर्तनीय दरों पर अनुबंधित हों; और तीसरा, फर्मों के नकदी प्रवाह में सुधार हो सकता है जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग की स्थिति मौद्रिक प्रोत्साहन के प्रति प्रतिक्रिया करती है। ये तीनों ताकतें फर्मों के लिए बाहरी वित्त प्रीमियम को कम करने में मदद कर सकती हैं। क्रेडिट चैनल (या क्रेडिट आपूर्ति चैनल) क्रेडिट राशनिंग के जोखिम को भी कम कर सकता है।

जॉम्बी की बढ़ती उपस्थिति वाले माहौल में, हालांकि, स्थिरीकरण नीतियां सृजनात्मक विध्वंस में बाधा डालकर मध्यम अवधि के संवृद्धि पथ को संभावित रूप से खतरे में डाल सकती हैं। इस संदर्भ में यह आलेख इस बात की जांच करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जॉम्बी का प्रभाव समय के साथ कैसे बदल गया है, और कैसे ज़ॉम्बी गैर-जॉम्बी के मुकाबले मौद्रिक नीति के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। खंड II मौद्रिक नीति विश्लेषण के लिए आनुभविक फर्म-स्तरीय अनुसंधान में जॉम्बी और गैर-जॉम्बी के बीच स्पष्ट अंतर की प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। यह जॉम्बी की पहचान के लिए इस पर्चे में अपनाए गए दृष्टिकोण की भी व्याख्या करता है, और फिर यह तथ्यात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है कि भारत में समय के साथ गैर- ज़ॉम्बी के सापेक्ष जॉम्बी ने कैसा कार्य-प्रदर्शन किया है। खंड III आनुभविक रूप से - (ए) बैंकों से उधार, (बी) निवेश, और (सी) गैर-जॉम्बी के सापेक्ष मौद्रिक नीति दर और चलनिधि की स्थिति में बदलाव के लिए जॉम्बी के वित्त की लागत - की संवेदनशीलता की जांच करता है। जहाँ, मौद्रिक नीति को भारित औसत कॉल मनी रेट (डब्ल्यूएसीआर) के माध्यम से कैप्चर किया जाता है - यह भारत में मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य है, तरलता की स्थिति को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत निवल अधिशेष/घाटे की स्थिति के माध्यम से निवल माँग और मियादी देयताएँ के प्रतिशत के रूप में कैप्चर किया जाता है। खंड IV. में समापन टिप्पणियों को प्रस्तुत किया गया है।

II. भारत में ज़ॉम्बी बनने के कुछ साक्ष्य

भारत में, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र की फर्में शामिल हैं। पूर्व में उपलब्ध जानकारी में सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों कंपनियां हैं, जबकि कई छोटे और मध्यम उद्यम असंगठित क्षेत्र में हैं। इस पर्चे में प्रस्तुत विश्लेषण सीएमआईई के प्रॉवेस डेटाबेस पर आधारित है

[1] जब बैंक सूचना विषमता की चुनौती से निपटने का प्रबंध करते हैं (नकदी प्रवाह/तुलन पत्र की स्थिति की निगरानी करके) तो ऋण की लागत बढ़ सकती है (बेरेंके और गर्टलर, 1989), जबकि जब बैंक सूचना विषमता की समस्या को दूर करने में विफल रहते हैं तो वे ऋण राशनिंग का सहारा ले सकते हैं। (स्टिग्लिट्ज़ एंड वीस, 1981)।

और इसलिए संगठित क्षेत्र से संबंधित है। भारत के लिए इस डेटासेट का उपयोग करने वाले पिछले अध्ययनों में पाया गया है कि छोटी फर्में बड़ी फर्मों[2] की तुलना में बाहरी वित्त पर अधिक निर्भर हैं। महत्वपूर्ण रूप से, "बाहरी वित्त" के भीतर "वैकल्पिक वित्त" - अर्थात, मित्रों/रिश्तेदारों/परिवार, कारोबार भागीदारों और कारोबार ऋण से लिया गया वित्त, अक्सर कानूनी अनुबंधों के बिना - छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) और गैर-सूचीबद्ध फर्मों के लिए प्राथमिक स्रोत है, बड़ी और सूचीबद्ध फर्मों के विपरीत, बैंकों और बाजारों से वित्तपोषण उनके लिए पेकिंग क्रम में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा, धारणाओं के विपरीत, बैंकों और बाजारों से वित्त के बजाय वैकल्पिक वित्त पर अधिक निर्भर रहने वाली फर्में अपेक्षाकृत मजबूत वृद्धि प्रदर्शित करती हैं (एलन, चक्रवर्ती, डे और कियान, 2012)[3]।

गैर-ज़ॉम्बी फर्मों (या आंतरिक वित्त के विपरीत बाहरी वित्त के लिए उनका सहारा) के लीवरेज में परिवर्तन, ज़ोम्बी के विपरीत, कारोबार चक्र की स्थिति पर निर्भर हो सकता है, जो न केवल उनके नकदी प्रवाह को प्रभावित कर सकता है बल्कि नए निवेश के समय और आकार के निर्णयों को भी प्रभावित कर सकता है। कई कारकों के आधार पर निवेश चक्र या तो अस्थायी चक्रीय मंदी या लंबी कमजोरी के दौर से गुजर सकता है (पट्टनायक, बेहेरा, कावेडिया और श्रीवास्तव, 2020)। बाद के मामले में, ज़ॉम्बी[4] और कमजोर बैंकों के बीच अपवित्र संबंध (जो कि चूक की स्थिति में न्यूनतम विनियामक पूंजी की आवश्यकता से नीचे गिरने के जोखिम का सामना करते हैं) मजबूत हो सकते हैं। कारोबार चक्रों और प्रति-चक्रीय मौद्रिक नीति के प्रति फर्मों (उनका लीवरेज) की प्रतिक्रिया, जॉम्बी और गैर-जॉम्बी के बीच भिन्न हो सकती है। समग्र गैर-वित्तीय गैर-सरकारी कॉर्पोरेट क्षेत्र में लीवरेज चक्र में जॉम्बी के सापेक्ष महत्व के आधार पर, मौद्रिक नीति के प्रभाव का - कारोबार चक्र को स्थिर करने बनाम जॉम्बी को बढ़ावा देने के संदर्भ में - आकलन किया जा सकता है। भारत में, फर्मों के लीवरेज पर कारोबार चक्र के प्रभाव पर सीमित साहित्य उपलब्ध है (पट्टनायक और सेनगुप्ता, 2018)। जहां तक हमारी जानकारी है, इस बारे में कोई शोध उपलब्ध नहीं है कि प्रति-चक्रीय मौद्रिक नीति, जॉम्बी बनाम गैर-जॉम्बी के लीवरेज प्रोफाइल के माध्यम से कैसे परिचालित होती है, और तदनुसार, क्या मौद्रिक नीति सृजनात्मक विध्वंस में बाधा डालती है और इस तरह संसाधनों के गलत आबंटन में योगदान करती है।

भारत में जॉम्बी की भूमिका पर, कश्यप, महापात्रो और तंत्री (2021) ने भारत में अप्रत्यक्ष सातत्य (अर्थात, कमजोर फर्म कमजोर बैंकों से संबंधित पक्षों के माध्यम से उधार लेकर लीवरेज बढ़ाती हैं, लेकिन वास्तविक निवेश को कम करती हैं) होने के प्रमाण पाए जो अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इस तरह के संसाधन का गलत आबंटन क्राउड आउट प्रभाव को जन्म देता है जिसके लिए जॉम्बी जिम्मेदार हैं। आनुभविक शोध में, जॉम्बी की पहचान करना और उन्हें उन फर्मों से, जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रतिकूल आधात के कारण दबाव का सामना करते हैं अथवा जिन्हें योजना के तहत सब्सिडी और निर्देशित क्रेडिट के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है - अलग करना आसान नहीं है। कुलकर्णी, रिटाधी, विज और वाल्डॉक (2019) ने पर्यवेक्षी डेटा का उपयोग करके भारतीय जॉम्बी को उन फर्मों के रूप में पहचानने के लिए एक नया दृष्टिकोण तैयार किया, जो 60-90 दिन पुराने हैं (लेकिन अभी भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं) और AA क्रेडिट रेटिंग से नीचे हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार, भारत में 11 प्रतिशत कर्जदार जॉम्बी पाए गए।

आनुभविक विश्लेषण (अगले भाग में) के लिए इस आलेख में 2000-01 से 2019-20 की अवधि के लिए गैर-वित्तीय फर्मों के वार्षिक वित्तीय विवरणियों पर विचार किया गया है। यह एक असंतुलित पैनल डेटा है। फर्मों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर जॉम्बी और गैर-जॉम्बी में वर्गीकृत किया गया है: एक

2 फर्मों के लिए उपलब्ध वित्त पोषण के समग्र स्रोत में दो व्यापक घटक हैं - आंतरिक स्रोत (जिसमें लाभांश के भुगतान के बाद निवल आय, मूल्यह्रास, प्लस प्रावधान शामिल हैं) और बाहरी स्रोत (जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों, बाजारों और वैकल्पिक वित्त से प्राप्त निधियाँ शामिल हैं)

3 वैकल्पिक वित्तपोषण की प्रारंभिक लागत अधिक हो सकती है, लेकिन एक बार फर्मों, ग्राहकों, निवेशकों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच संबंध स्थापित हो जाने के बाद, उनके लिए औसत लागत बैंक या बाजार वित्तपोषण की लागत से कम रहती है। इस तरह के कारोबार, संविदाओं की कानूनी प्रवर्तनीयता के बजाय आपसी विश्वास और रिश्तों के ट्रैक रिकॉर्ड पर चलते हैं। कमजोर निवेशक/फर्म संरक्षण वाले अभिशासनों में, बाहरी वित्त के भीतर "वैकल्पिक वित्त" उच्च रह सकता है।

4 ज़ॉम्बी ऐसी फर्में हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए अधिक उधार लेना पड़ता है, और वे अक्सर अपने कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त लाभ नहीं कमा पातीं हैं। समायोजनकारी मौद्रिक नीति शूम्पेटेरियन सृजनात्मक विध्वंस को लगातार विलंबित/स्थगित करते हुए, ज़ॉम्बी बनने की धीमी प्रक्रिया को प्रेरित कर सकती है।

फर्म को समय t पर एक जॉम्बी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि:

1. फर्म का लीवरेज औसत लीवरेज से ऊपर है;
2. ब्याज व्याप्ति अनुपात (आईसीआर) <1;
3. रेटिंग जोखिमपूर्ण श्रेणी में है; तथा
4. ऋण वृद्धि धनात्मक है।

उपर्युक्त वर्गीकरण फ़िल्टरों में से, (1), (2) और (3) एक फर्म के सामने वित्तीय संकट की अवस्था को इंगित करते हैं, जबकि स्थिति (4) बाहरी वित्तपोषण तक इसकी पहुंच को दर्शाती है। अध्ययन के लिए विचार किए गए अन्य चरों की विस्तृत परिभाषाएं परिशिष्ट-1 में दी गई हैं। विश्लेषण में उपयोग किए गए चर के सारांश आंकड़े सारणी 1 में जॉम्बी और गैर-जॉम्बी के लिए अलग-अलग प्रदान किए गए हैं। यह देखा जा सकता है कि उनकी उम्र के संबंध में जॉम्बी और गैर-जॉम्बी के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं हैं (यानी, कारोबार में वर्षों की संख्या) और आकार; हालांकि, लाभप्रदता पर, जॉम्बी ने, गैर- जॉम्बी के विपरीत, अपनी संपत्ति पर औसतन केवल ऋणात्मक प्रतिफल दिया है। गैर- जॉम्बी का औसत ऋण उनकी कुल संपत्ति का 35 प्रतिशत से कम है, जबकि जॉम्बी के पास उनकी कुल संपत्ति का लगभग 65 प्रतिशत का ऋण स्तर है। लीवरेज में इस उच्च अंतर का एक हिस्सा पहले वर्गीकरण फ़िल्टर के चुनाव का परिणाम हो सकता है। निधियों की औसत लागत, जो उनके कुल ब्याज व्यय और औसत ऋण के अनुपात के रूप में परिभाषित है, जॉम्बी के लिए केवल 40 आधार अंक अधिक है। गैर- जॉम्बी की तुलना में जॉम्बी के संबंध औसतन कम बैंकों के साथ होते हैं, लेकिन बैंक के साथ जारी संबंध जॉम्बी की तुलना में गैर- जॉम्बी के लिए अधिक होते हैं। कुल संपत्ति में अचल संपत्तियों के वार्षिक जोड़ के अनुपात से मापा गया निवेश, जॉम्बी के लिए कम है, हालांकि गैर-जॉम्बी के लिए औसत निवेश काफी अधिक नहीं है। रेटिंग के दृष्टिकोण से, चूंकि विभिन्न उपकरणों की औसत रेटिंग के आधार पर जॉम्बी की पहचान की जाती है, वे गैर- जॉम्बी की तुलना में जोखिमपूर्ण श्रेणी में आते हैं।

भारत में, गैर-वित्तीय कॉरपोरेट्स के कुल वित्तपोषण का लगभग दो-तिहाई बाहरी स्रोतों से सुरक्षित है, जो न केवल मौद्रिक नीति के बाहरी वित्त प्रीमियम चैनल, बल्कि मौद्रिक नीति की प्रभावकारिता के लिए जॉम्बी बनने प्रक्रिया की जांच करने के महत्व की पुष्टि करता है। (चार्ट 1)।

पहले से निर्धारित पहचान योजना के अनुसार, भारत में लगभग 10 प्रतिशत गैर-वित्तीय फर्मों को जॉम्बी के रूप में देखा जा सकता है (चार्ट 2)। 2016 तक वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद की अवधि में यह हिस्सेदारी बढ़ी और बाद में, कुछ स्थिरता देखी गई। हालांकि जीएफसी के बाद की वृद्धि बड़े पैमाने पर नीतिगत प्रोत्साहन का परिणाम हो सकती है जो

सारणी 1: आँकड़ों का सारांश

	प्रेक्षण	माध्य	मानक विचलन	माध्यिका	कुर्टोसिस	विषमता
गैर-जॉम्बी						
आयु (वर्ष)	24137	30.90	20.23	26.00	6.31	1.56
आकार	24137	8.25	1.66	8.12	2.48	0.33
आरओए (%)	24137	3.59	6.21	3.22	4.73	-0.35
लीवरेज (%)	24137	33.15	24.77	31.60	638.68	13.12
निधियों की लागत (%)	24137	10.11	5.08	9.79	4.63	0.82
बैंक संबंध	24137	4.87	4.13	4.00	4.76	1.48
बैंक संबंध अवधि	24137	10.81	7.75	9.00	2.28	0.59
निवेश	21198	0.06	0.09	0.03	77.91	5.47
बैंक उधार	16154	2744.98	5283.64	686.35	13.93	3.22
माध्य रेटिंग	24137	6.18	2.12	6.33	2.67	-0.70
जॉम्बी						
आयु (वर्ष)	2046	27.56	18.24	24.00	6.67	1.61
आकार	2046	7.59	1.65	7.43	2.41	0.49
आरओए (%)	2046	-5.08	6.90	-2.86	1.99	-0.56
लीवरेज (%)	2046	66.00	37.81	58.07	59.93	5.60
निधियों की लागत (%)	2046	10.41	4.43	10.73	4.16	0.08
बैंक संबंध	2046	4.43	4.10	3.00	5.60	1.72
बैंक संबंध अवधि	2046	8.77	7.16	7.00	2.85	0.88
निवेश	1726	0.04	0.09	0.01	31.96	4.82
बैंक उधार	1453	3027.63	5462.31	745.50	11.56	2.87
माध्य रेटिंग	2046	1.67	0.66	2.00	1.98	0.41

नोट: कृपया इस सारणी में उपयोग किए गए चर के स्पष्टीकरण के लिए परिशिष्ट -1 देखें।
स्रोत: सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) और लेखकों के अनुमान।

चार्ट 1: आंतरिक बनाम वाह्य वित्तपोषण पैटर्न (भारत में गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र)

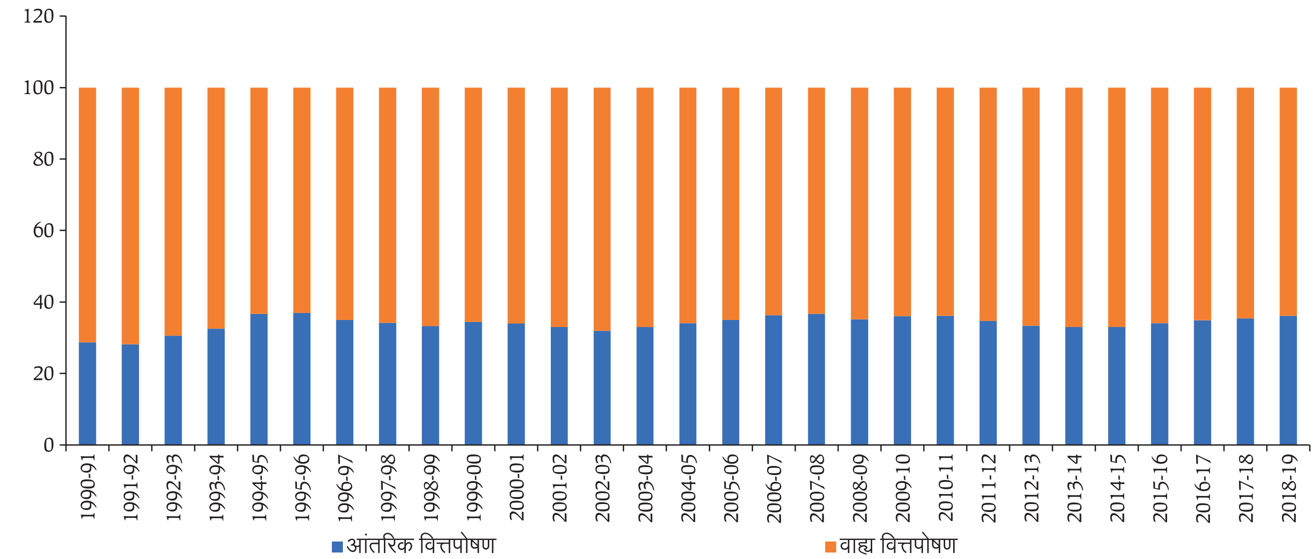

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक और लेखकों के अनुमान।

जीएफसी से वास्तविक अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए निर्देशित की गई थी। हाल ही में स्थिरीकरण, नए दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) वाला अभिशासन जो लंबे समय तक जीवित रहने वाले अनर्जक कारोबारों के प्रति अपेक्षाकृत कम सहिष्णु है, के बाद भारत के क्रेडिट बाजार की स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन के कारण हो सकता है।

एक विशेष रूप से चौंकाने वाली खोज यह है कि भारत में जॉम्बी, जीएफसी के बाद, कुल गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र के ऋण में अपनी हिस्सेदारी को 10 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ा दिया है (चार्ट 3)। आगे का विश्लेषण प्रमुख वित्तीय मापदंडों में जॉम्बी और गैर-जॉम्बी के बीच अपेक्षित अंतर की पुष्टि करता है - भारत में जॉम्बी गैर-जॉम्बी की तुलना में, कुल संपत्ति के लिए कुल ऋण

चार्ट 2: गैर-वित्तीय फर्मों की कुल संख्या में जॉम्बी फर्मों का अंश

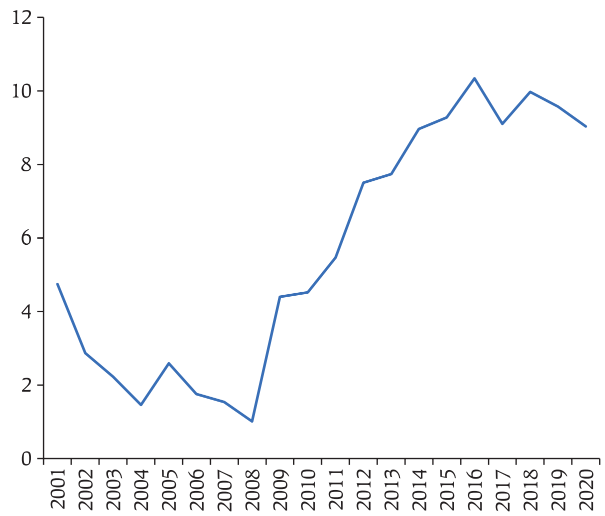

स्रोत: सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) और लेखकों के अनुमान।

चार्ट 3: गैर-जॉम्बी बनाम जोंबी की ऋण भागीदारी

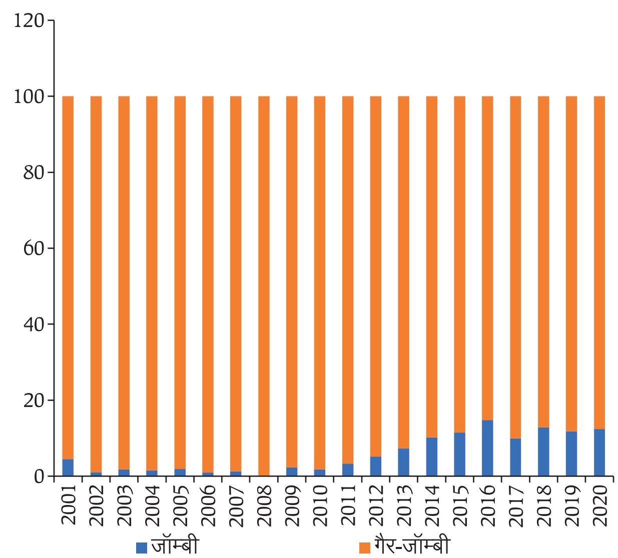

स्रोत: सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) और लेखकों के अनुमान।

चार्ट 4: लीवरेज और जॉम्बी की निधियों की लागत

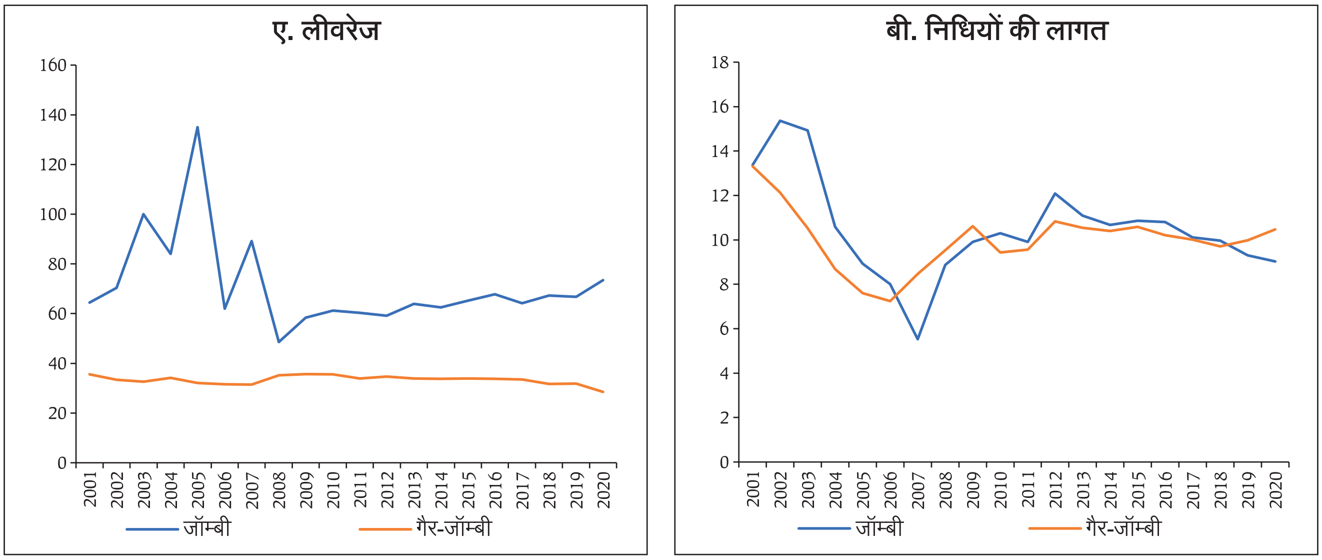

स्रोत: सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) और लेखकों के अनुमान।

द्वारा परिभाषित, उच्च लीवरेज के साथ संचालित होता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे कुछ हद तक, गैर-जॉम्बी के समान भुगतान लागत पर, निधि उधार लेने का प्रबंध कर लेते हैं (चार्ट 4)। उनके अधिक लीवरेज के बावजूद, गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र की कुल बिक्री में जॉम्बी की हिस्सेदारी में हाल के दिनों में गिरावट आई है, जिसे भारत में जॉम्बी के सबूत के रूप में देखा जा सकता है जो संसाधनों के गलत आबंटन में भूमिका निभाता है और अर्थव्यवस्था में सृजनात्मक विध्वंस में बाधा डालता है (चार्ट 5)। इसके अलावा, जहाँ जॉम्बी के कर्ज में साल-दर-साल (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि गैर-ज़ॉम्बी के समान ही रही है, वह लाभ अर्जित करने में लगातार पिछड़ गया, जो संसाधनों के गलत आबंटन का एक और उल्लेखनीय प्रमाण है (चार्ट 6)।

चार्ट 5: निवेश और बिक्री में हिस्सेदारी

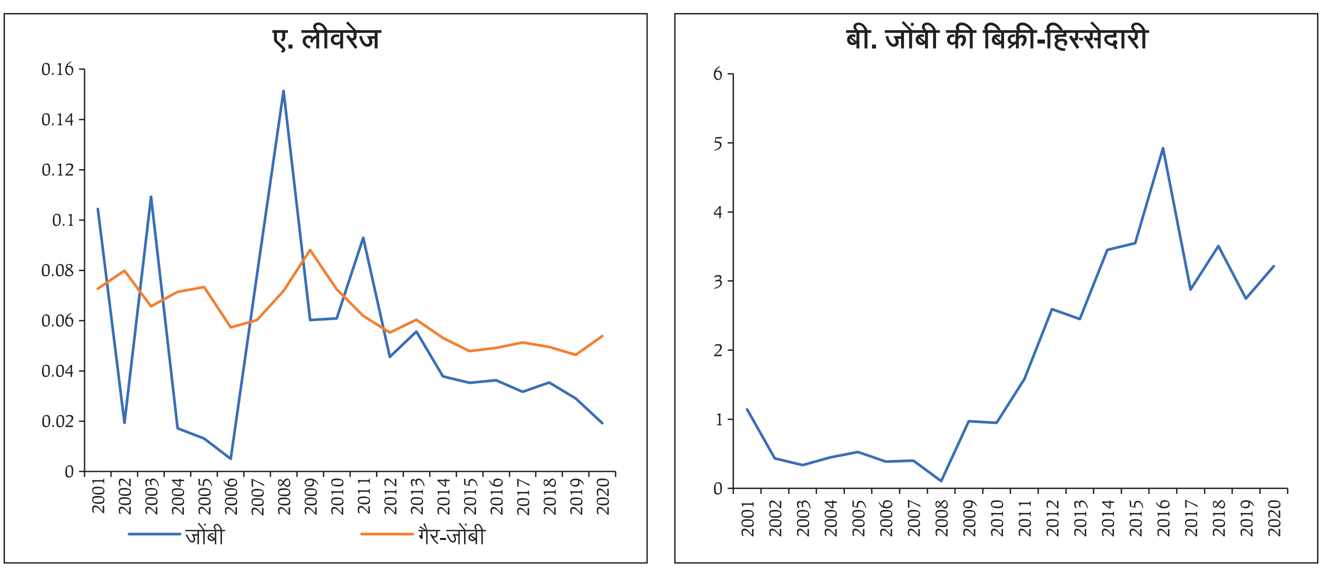

स्रोत: सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) और लेखकों के अनुमान।

चार्ट 6: ऋण वृद्धि और लाभप्रदता - जॉम्बी बनाम गैर-जॉम्बी

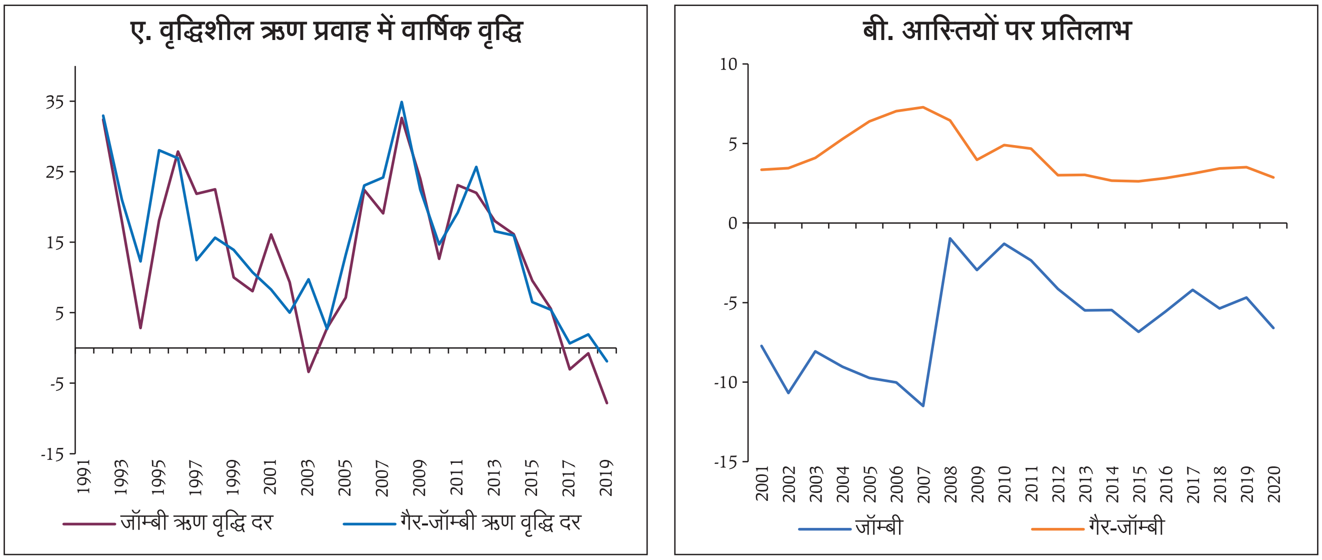

स्रोत: सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) और लेखकों के अनुमान।

III. आनुभविक विश्लेषण

सृजनात्मक विध्वंस और कारोबार चक्र को स्थिर करने में मौद्रिक नीति की प्रभावकारिता का अक्सर आनुभविक अनुसंधान में अलग-अलग अध्ययन किया जाता है, भले ही बाद वाला संभावित रूप से पहले वाले को कमजोर कर सकता है, और पहले वाला संभावित रूप से विस्तारित अवधि में वृद्धि में सहयोग करने के लिए मौद्रिक नीति पर बोझ को कम कर सकता है - जिसका अर्थ है कि दोनों मुद्दे परस्पर जुड़े हो सकते हैं। इस पर्चे का उद्देश्य इस परस्पर संबंध के केवल एक पहलू की जांच करना है, अर्थात, क्या संवृद्धि-सहायक मौद्रिक नीति ज़ॉम्बी की रक्षा करती है और इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में सृजनात्मक विध्वंस प्रक्रिया को रोकती है। मौद्रिक नीति कार्रवाईयाँ फर्मों की निधियों की लागत और उनके नए उधारों की मात्रा (या लीवरेज में परिवर्तन) को प्रभावित करके परिचालित होती हैं, जो बदले में नए निवेश निर्णयों (या अचल संपत्तियों में परिवर्तन) को प्रभावित कर सकती हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि विभिन्न तरलता स्थितियों के तहत, निधियों की लागत, नए उधार और ज़ॉम्बी और गैर-ज़ॉम्बी के नए निवेश, मौद्रिक नीति के झटके के प्रति प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। तदनुसार, इस पत्र में निम्नलिखित तीन आनुभविक मुद्दों पर जोर दिया गया है:

- ज़ॉम्बी बनाम गैर-ज़ॉम्बी के निधियों की लागत पर मौद्रिक नीति का प्रभाव;
- ज़ॉम्बी बनाम गैर-ज़ॉम्बी के निधियों की लागत में बदलाव के प्रति बैंक उधार की संवेदनशीलता; तथा
- ज़ॉम्बी बनाम गैर-ज़ॉम्बी के बैंक उधार में परिवर्तन के प्रति निवेश की संवेदनशीलता।

प्रथम चरण में यह अध्ययन, एक फर्म के ज़ॉम्बी के रूप में वर्गीकरण की संभावनाओं को प्रभावित करने वाले कारकों की भूमिका की जाँच करता है। इस आकलन के लिए, पैनल डीजिट डेटा मॉडल अपनाया गया है। औपचारिक रूप से $\pi(x_{it})$ अथवा फर्म i वेक्टर विशिष्टता x_{it} के साथ t समय पर ज़ॉम्बी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लॉजिस्टिक मॉडल की स्थिति में इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है:

$$\pi(x_{it}) = \Phi(x_{it}^{'}\beta + \mu_i + u_t)$$

यहाँ, $\Phi(.)$ मानक सामान्य विभाजन का संयोजी विभाजन है और, μ_i और u_t क्रमशः इकाई और समय स्थिर प्रभाव हैं। एक फर्म के ज़ॉम्बी बनने की संभावना पर चर विशेषताओं के प्रभाव का आकलन, किसी चर में परिवर्तन के सीमांत प्रभाव, जिसे x_{i_j} पर $\pi(x_{it})$ कहा जाए, की जाँच कर किया जाता है। अतः j^{th} विश्ष्टता

चर में इकाई परिवर्तन का सीमांत प्रभाव, फर्म i के ज़ॉम्बी बनने की संभावना से संबंधित चर विशेषता को इस प्रकार आकलित किया जा सकता है:

$$\frac{d\pi(x_{it})}{dx_{ijt}} = \beta_j \phi\left(x_{it}^{'}\beta + \mu_i + u_t\right)$$

यहाँ, $\phi(.)$ सामान्य संभाव्यता घनत्व फलन है। ये आकलन, किसी फर्म के ज़ॉम्बी के रूप में वर्गीकृत होने की संभावना से संबंधित इन चरों के वृद्धिपरक प्रभाव को दिखाते हैं।

अगले चरण में, निम्नलिखित पैनल प्रतिगमन ढ़ाँचा का उपयोग पूर्व में चर्चा की गई तीन विशिष्ट आनुभविक परिकल्पनाओं की जाँच के लिए किया गया है। मॉडल का सामान्य निर्धारण इस प्रकार है:

$$y_{it} = X_{it}\beta + u_{it}\ , \forall\ i, t$$

$$u_{it} = \mu_i + \lambda_t + v_{it}$$

जहाँ, y_{it} आश्रित चर है, X_{it} एक्सप्लानेटरी चर का वेक्टर है और u_{it} व्यक्तिगत स्थिर प्रभाव μ_i और समय स्थिर प्रभाव λ_t में एरर टर्म है। कतिपय प्रतिगमन विशिष्टताओं जिसमें पैनल-अपरिवर्तनीय एक्सप्लैनेटरी चर शामिल हैं (उदाहरण के तौर पर, एक वर्ष के दौरान सभी फर्म के लिए मौद्रिक नीति दर समान है), केवल फर्म-विशेष स्थिर प्रभाव को आकलन हेतु विचारार्थ लिया गया है।

फर्मों की निधियों की लागत पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, भारत में मौद्रिक नीति को भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) के माध्यम से कैप्चर किया जाता है - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य। डब्ल्यूएसीआर के अलावा, फर्म-विशिष्ट कारकों की भूमिका जैसे कि उनका आकार, लाभप्रदता, और बैंकिंग संबंधों की संख्या और अवधि जो फंड की लागत निर्धारित कर सकते हैं, इस मॉडल में भी शामिल हैं। यह आकलन करने के लिए कि क्या मौद्रिक नीति का क्रेडिट चैनल फर्म स्तर पर काम करता है, उनके निधियों की लागत में बदलाव के जवाब में जॉम्बी और गैर-जॉम्बी के विभेदक बैंक-उधार पैटर्न का भी अनुमान लगाया गया है। अधिशेष और घाटे की चलनिधि चरणों के लिए प्रतिक्रिया पैटर्न का अलग अध्ययन किया जाता है [निवल मांग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) के प्रतिशत के रूप में वार्षिक औसत निवल चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) स्थिति के माध्यम से प्राप्त]। यह जांचने के लिए कि - क्या जॉम्बी नए निवेश करने के लिए बैंकों से उधार लेते हैं या मौजूदा खर्चों को पूरा करके जीवित रहने के लिए - फर्मों के नए उधारों के लिए निवेश की संवेदनशीलता का अध्ययन आगे किया जाता है। बैंक उधार को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: अल्पकालिक उधार और लंबी अवधि के उधार, बाद वाला अक्सर फर्मों द्वारा नए निवेश के इरादे का संकेत देते हैं। इस पर्चे में इस्तेमाल किए गए नमूना-आँकड़ा में कुल बैंक उधार का करीब 40 प्रतिशत, लंबी अवधि का उधार पाया गया है।

तीन आनुभविक मुद्दों की जांच करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, विशिष्ट कारकों, जो एक फर्म को ज़ॉम्बी के रूप में चिह्नित कर सकते हैं (या एक जॉम्बी के रूप में एक फर्म की संभावना को प्रभावित करते हैं), के महत्व का मूल्यांकन पहले किया जाता है (सारणी 2)। एक उच्च आयु प्रोफ़ाइल वाली फर्म (या जो अधिक समय तक जीवित रहती है) के ज़ॉम्बी होने की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है; लेकिन कुल मिलाकर, ऐसे ज़ॉम्बी जो लंबे समय तक जीवित रहने में सफल होते हैं, सृजनात्मक विध्वंस के लिए जोखिम पैदा करते हैं। आस्ति पर अधिक प्रतिफल एक फर्म के जॉम्बी होने की संभावना को कम करता है। बैंकिंग संबंधों पर दो दिलचस्प निष्कर्ष हैं: पहला, कम संख्या में बैंकों के साथ संबंध रखने वाली फर्मों के जॉम्बी होने की संभावना अधिक होती है; दूसरा, छोटे बैंकिंग संबंधों वाली फर्मों के भी जॉम्बी होने की संभावना अधिक होती है। एक लंबा बैंकिंग संबंध बैंकों को फर्मों के बारे में सॉफ्ट जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है, जो बदले में फर्म की साख के वास्तविक मूल्यांकन में योगदान दे सकता है। जॉम्बी के लिए बैंकिंग संबंध संरचना, प्रतिस्पर्धी बैंकिंग प्रणाली में गैर- जॉम्बी से भिन्न होने की उम्मीद है जिसमें, फर्म के साथ पिछले संबंधों के वजाय, जोखिम-प्रतिलाभ प्रोफ़ाइल और फर्मों के दृष्टिकोण को उत्तरोत्तर अधिक महत्व मिल सकता है। जॉम्बी, बैंक उधार (समग्र और दीर्घकालिक ऋणों के लिए स्पष्ट) पर अधिक निर्भर होते हैं क्योंकि बाजार के स्रोत अच्छी और बुरी फर्मों के बीच बेहतर अंतर कर सकते हैं और बाद बुरी फर्मों को इनकार कर सकते हैं।

ब्याज के पहले आनुभविक मुद्दे पर, अनुमान बताते हैं कि डब्ल्यूएसीआर में 100-आधार बिंदु की कमी उसी वर्ष (सारणी 3) में फर्मों की निधियों की लागत को 35 आधार अंकों तक कम कर देती है। हैरानी की बात है कि कुछ मामलों में, जॉम्बी, निधियों की कम औसत लागत का जुगाड़ कर लेते हैं, जो एनपीए के उच्च स्पष्टतापूर्ण निर्धारण से बचने के लिए दीर्घजीविता के प्रभाव और बैंकों द्वारा संबंधित उच्च पूंजी शुल्क का संकेत हो सकता है अथवा यह साधारण संबंध-आधारित बैंकिंग का भी संकेत हो सकता है जो इस समस्या को तब तक जीवित रखना चाहते हों जब तक इससे किसी तरह निपटा जा सकता है। इंटरएक्टिव डमी गुणांक इस बात पर प्रकाश डालता है कि गैर- जॉम्बी की तुलना में, डब्लूएसीआर में परिवर्तन के लिए जॉम्बी के निधियों की लागत अधिक संवेदनशील है। एक ब्याज दर आघात, अपेक्षित रूप से, जॉम्बी के लिए अधिक मायने रखता है, लेकिन मौद्रिक नीति की प्रभावकारिता के दृष्टिकोण से, यह पाया गया है कि सभी फर्मों (जॉम्बी और गैर-जॉम्बी) के फंड की लागत डब्ल्यूएसीआर में बदलाव की प्रतिक्रिया में बदल जाती है। फिर से, अपेक्षित लाइनों के साथ, बड़ी और लाभदायक फर्मों के पास निधियों की औसत लागत कम होती है।

निधियों की निम्न औसत लागत सभी फर्मों के लिए उच्च बैंक उधार को प्रोत्साहित करती है (सारणी 4)। चलनिधि अधिशेष चरणों के दौरान, उधार भी आम तौर पर अधिक होते हैं, जो मौद्रिक नीति की समग्र प्रभावकारिता को प्रमाणित करते हैं। जैसा कि कोई भी उम्मीद करेगा, ज़ॉम्बी का बैंक उधार गैर-ज़ॉम्बी की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक है। हालांकि, महत्वपूर्ण रूप से, अतिरिक्त चलनिधि की स्थिति के दौरान गैर-ज़ॉम्बी की तुलना में ज़ॉम्बी अपेक्षाकृत कम उधार लेती है, जो इस धारणा का समर्थन नहीं करती है कि वृद्धि-उत्प्रेरक प्रति-चक्रीय मौद्रिक नीति कभी-कभी अर्थव्यवस्था में सृजनात्मक विध्वंस प्रक्रिया को रोक सकती है। आम तौर पर, आर्थिक मंदी की अवधि में, अच्छी फर्में नकद अधिशेष जमा कर सकती हैं, जबकि खराब फर्मों को जीवित रहने के लिए अधिक ऋण की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे बैंक जो ऋण वृद्धि लक्ष्य से संचालित होते हैं, वे अभी भी बाद वाले (खराब फर्मों) की ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी तरह से पर्यवेक्षित बैंकिंग प्रणाली में, बैंकों द्वारा सृजित नई आस्तियों की जोखिम संवेदनशीलता पर बढ़ता दबाव उन्हें ऐसा करने से रोक सकता है, इस चुनौती के बावजूद कि वह जोखिम-प्रतिकूल के रूप में देखा जाए। प्रभावी बैंक पर्यवेक्षण और विश्वसनीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता प्रक्रिया, इस प्रकार, किसी अर्थव्यवस्था में सृजनात्मक विध्वंस में बाधा डालने वाली नरम मौद्रिक नीति की संभावना को कम कर सकती हैं।

समायोजनकारी मौद्रिक नीति के झटके की प्रतिक्रिया में बैंक उधार में वृद्धि से फर्मों के निवेश बढ़ जाते हैं, जिसे कुल आस्ति में अचल पूंजी के वृद्धिशील जोड़ के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है (सारणी 5)। हालांकि, जॉम्बी में निवेश के प्रति संवेदनशीलता कम पाई गई है। इंटरैक्टिव डमी गुणांक लंबी अवधि के बैंक उधारों के लिए भी समान परिणामों की पुष्टि करता है। चूँकि, पिछले पांच वर्षों में सभी गैर-वित्तीय फर्मों द्वारा अवशोषित कुल बैंक ऋण का लगभग 10 प्रतिशत जॉम्बी के बैंक-उधार-खाते हैं, वे कुछ हद तक मौद्रिक नीति की प्रभावकारिता को कम कर रहे हैं। यदि बैंकिंग प्रणाली में संसाधन आबंटन में और सुधार से बैंकों से नए ऋण के प्रवाह में जॉम्बी की हिस्सेदारी कम हो जाती है, तो एक समायोजनकारी मौद्रिक नीति के झटके के प्रति वास्तविक निवेश प्रतिक्रिया मजबूत हो सकती है। समायोजनकारी मौद्रिक नीति रुख का उद्देश्य अक्सर अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को बढ़ावा देना होता है और इसलिए, यह सृजनात्मक विध्वंस की प्रक्रिया के खिलाफ काम नहीं करता है, जिसकी पुष्टि इस आलेख के आनुभविक परिणामों से भी होती है।

IV. निष्कर्ष

वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद की अवधि में, एक मजबूत और टिकाऊ संवृद्धि पथ पर वापसी अधिकांश देशों के लिए कठिन रही है, यहां तक कि प्रति-चक्रीय नीतियों ने वृद्धि का समर्थन करने के लिए पारंपरिक और अपरंपरागत उपायों के चरम स्वरूपों के साथ प्रयोग किया है। ऐसा करने की प्रक्रिया में, एक धारणा विकसित हुई है कि ऐसी नीतियां सृजनात्मक विध्वंस में बाधा बन सकती हैं और इस तरह अनजाने में, हालांकि, प्रवृत्ति-निवेश और उत्पादकता वृद्धि को कम सकती हैं। ज़ॉम्बी फर्मों की संख्या के साथ - जो ऋण की चुकौती नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जीवित रहने के लिए और अधिक उधार लेने का

प्रबंधन करते हैं - समय के साथ विश्व स्तर पर बढ़ते हुए, इस धारणा की प्रासंगिकता की आनुभविक जाँच का महत्व बढ़ा है।

भारत में, गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र के कुल ऋण का लगभग 10 प्रतिशत ज़ॉम्बी के खाते में होने का अनुमान है और उन्होंने अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों को दिए गए कुल बैंक ऋण का लगभग 10 प्रतिशत अवशोषित कर लिया है। जैसा कि कोई उम्मीद करेगा, वे सामान्य रूप से अत्यधिक लीवरेज वाले पाए जाते हैं; लगातार वर्षों में संपत्ति पर ऋणात्मक प्रतिफल देते हैं और नए निवेश करने के बजाय जीवित रहने के लिए अधिक उधार लेते हैं। उनकी निधियों की औसत लागत मौद्रिक नीति के झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील है। बैंकों से उनका उधार, हालांकि, गैर-ज़ॉम्बी के उलट, अक्सर उच्च वास्तविक निवेश गतिविधि को जन्म नहीं देती है। यह पुष्टि करता है कि समायोजनकारी मौद्रिक नीति समग्र रूप से निधियों की लागत को कम करने, ऋण के उच्च प्रवाह को प्रोत्साहित करने और नए निवेश को बढ़ाने में प्रभावी है, लेकिन इसका प्रभाव ज़ॉम्बी के कारण सीमांत पर कम हो जाता है, जो (ज़ॉम्बी) उधार संसाधनों, जिसमें दीर्घकालिक बैंक ऋण शामिल हैं, का उपयोग नए निवेश के लिए कम और अपना अस्तित्व बचाने के लिए अधिक करते हैं। महत्वपूर्ण रूप से, अधिशेष चलनिधि की स्थिति के दौरान, जो अक्सर मौद्रिक नीति के समायोजन चरणों के साथ होता है, जॉम्बी के लिए क्रेडिट प्रवाह गैर-ज़ॉम्बी के प्रवाह की तुलना में कमजोर रहता है, जो बड़े पैमाने पर जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण और दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता व्यवस्था के लाभकारी प्रभाव के कारण हो सकता है, जो शायद अब ज़ॉम्बी के सदाबहार रहने में सहयोगी नहीं होगा। अनुभवजन्य निष्कर्ष, अर्थात्, समायोजनकारी मौद्रिक नीति के चरणों के दौरान जॉम्बी में अत्यधिक चलनिधि प्रवाहित होने का कोई सबूत नहीं है, यह पुष्टि करता है कि भारत में मौद्रिक नीति सृजनात्मक विध्वंस प्रक्रिया में बाधा नहीं डाली है और इसलिए, संवृद्धि की प्रवृत्ति के लिए जोखिमपरक नहीं है। हालांकि, बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से संसाधन आबंटन में और सुधार के साथ-साथ, प्रति-चक्रीय मौद्रिक नीति के प्रभाव को बढ़ाने की गुंजाइश है।

संदर्भ:

Acharya, V. V. (2019). Creating zombies and disinflation: A cul de sac for accommodative monetary policy. *VoxEU. Org*, November *11*.

Adalet McGowan, M., Andrews, D., & Millot, V. (2018). The walking dead? Zombie firms and productivity performance in OECD countries. *Economic Policy*, *33*(96), 685–736.

Allen, F., Chakrabarti, R., De, S., & Qian, M. (2012). Financing firms in India. *Journal of Financial Intermediation*, *21*(3), 409–445.

Andrews, D., & Petroulakis, F. (2019). *Breaking the shackles: Zombie firms, weak banks and depressed restructuring in Europe.* ECB Working Paper No 2240 / February.

Banerjee, R., & Hofmann, B. (2020). *Corporate zombies: Anatomy and life cycle.* BIS Working Papers No. 882, September 2.

Beranke, B. S., & Gertler, M. (1989). Agency costs, net worth, and business fluctuations. *American Economic Review*, *79*(1), 14–31.

Bosio, E., Djankov, S., Jolevski, F., & Ramalho, R. (2020). *Survival of Firms during Economic Crisis.* World Bank Policy Research Working Paper No. 9239.

Caballero, R. J., & Hammour, M. L. (1996). On the timing and efficiency of creative destruction. *The Quarterly Journal of Economics*, *111*(3), 805–852.

Cerra, M. V., Fatás, A., & Saxena, M. S. C. (2020). *Hysteresis and business cycles.* International Monetary Fund Working Paper WP/20/73.

G30 (2020). *Reviving and Restructuring the Corporate Sector Post-Covid.* URL: https://group30.org/publications/detail/4820

Jordà, Ò., Schularick, M., & Taylor, A. M. (2020). *Disasters everywhere: The costs of business cycles reconsidered.* Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper 2020-11. https://doi.org/10.24148/wp2020-11

Kashyap, N., Mahapatro, S., & Tantri, P. L. (2021). They Do It Anyway: Detecting Indirect Evergreening. *Available at SSRN 3775286.*

Kulkarni, N., Ritadhi, S. K., Vij, S., & Waldock, K. (2019). Unearthing zombies. *Georgetown McDonough School of Business Research Paper* No. 3495660.

Nurmi, S., Vanhala, J., & Virén, M. (2020). The life and death of zombies--evidence from government subsidies to firms. *Bank of Finland Research Discussion Paper*, (8).

Obstfeld, M., & Duval, R. (2018). Tight monetary policy is not the answer to weak productivity growth. *VoxEU, January 10.*

Pattanaik, A., & Sengupta, R. (2018). *Business cycle effect on leverage: A study of Indian non-financial firms.* IGIDR Working Paper WP-2018-001 Indira Gandhi Institute of Development Research: Mumbai, India.

Pattanaik, S., Behera, H., Kavediya, R., & Shrivastava, A. (2020). Investment slowdown in India--an assessment. *Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies*, 1–16.

Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *The American Economic Review*, *71*(3), 393–410.

परिशिष्ट-1

चर	परिभाषा
आयु	*t* समय पर एक फर्म की आयु को (*t* - निगमन का वर्ष) वर्षों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।
आकार	कुल आस्तियों का लघुगणक।
आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)	कुल आस्तियों (प्रतिशत में) के लिए निवल आय (यानी, कर के बाद लाभ)।
लीवरेज	कुल आस्तियों पर कुल ऋण (प्रतिशत में)।
निधियों की लागत	कुल औसत ऋण के लिए ब्याज व्यय (प्रतिशत में)।
बैंक संबंध (बीआर)	बैंकों की संख्या जिनके साथ एक फर्म का *t* समय पर संबंध है।
बैंक संबंध अवधि (बीआरएल)	बैंक के साथ संबंध का अधिकतम वर्ष (सभी बैंकरों के बीच) (वर्षों में)।
निवेश	एक वर्ष में स्थिर पूंजी (नया निवेश) को कुल आस्तियों (प्रतिशत में) में जोड़ना।
बैंक उधार	एक वर्ष के दौरान बैंक उधार की राशि, जिसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के उधार (मिलियन रुपये में) शामिल हैं।
औसत रेटिंग	औसत रेटिंग समय *t* पर एक फर्म के विभिन्न लिखतों के लिए औसत रेटिंग है। निम्नतम रेटिंग मान 1 है, जो चूक का सूचक है; उच्चतम रेटिंग मान 8 है; 4 से कम का कोई भी रेटिंग मूल्य जोखिमपूर्ण श्रेणी के अंतर्गत आता है।
जॉम्बी डमी	एक डमी चर जो 1 का मान लेता है यदि फर्म को जॉम्बी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, अन्यथा यह 0 है।
एलएएफ डमी	एक डमी चर जो उन वर्षों के लिए 1 का मान लेता है जब शुद्ध एलएएफ अधिशेष में था, अन्यथा यह 0 है।

स्रोत: सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) और लेखकों के अनुमान।

सारणी 2: ऐसे कारक जो एक फर्म के जॉम्बी होने की संभावना निर्धारित करते हैं

	सीमांत प्रभाव			
	पी (जॉम्बी डमी = 1)	पी (जॉम्बी डमी = 1)	पी (जॉम्बी डमी = 1)	पी (जॉम्बी डमी = 1)
आयु	-0.00692***	-0.00403***	-0.00483***	-0.00425***
	(0.00123)	(0.00128)	(0.00155)	(0.00154)
बैंकिंग संबंधों की संख्या	-0.0136**	-0.00287	-0.0177**	-0.00844
	(0.00556)	(0.00572)	(0.00839)	(0.00678)
आस्तियों पर प्रतिलाभ	-0.120***	-0.120***	-0.126***	-0.126***
	(0.00304)	(0.00302)	(0.00392)	(0.00391)
बैंक संबंध अवधि		-0.0205***	-0.0185***	-0.0179***
		(0.00319)	(0.00378)	(0.00375)
बैंक उधार			0.0526**	
			(0.0207)	
लंबी अवधि के बैंक उधार हिस्सेदारी				0.00287***
				(836×10^{-6})
स्थिरांक	-1.620***	-1.563***	-1.833***	-1.665***
	(0.0529)	(0.0520)	(0.132)	(0.0751)
एन	26183	26183	17607	17607
फर्म निश्चित प्रभाव	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
वर्ष निश्चित प्रभाव	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

कोष्ठक में मानक त्रुटियाँ. * पी < 0.1, ** पी < 0.05, *** पी < 0.01.

स्रोत: लेखकों का अनुमान.

सारणी 3: मौद्रिक नीति में परिवर्तन में निधियों की लागत की संवेदनशीलता

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	निधियों की लागत	निधियों की लागत	निधियों की लागत	निधियों की लागत	निधियों की लागत
डब्ल्यूएसीआर	0.356***	0.356***	0.340***	0.356***	0.320***
	(0.0201)	(0.0201)	(0.0207)	(0.0201)	(0.0321)
आकार	-0.262***	-0.260***	-0.258***	-0.259***	-0.261***
	(0.0534)	(0.0535)	(0.0535)	(0.0571)	(0.0571)
आरओए	-0.0261***	-0.0277***	-0.0275***	-0.0277***	-0.0276***
	(0.00559)	(0.00577)	(0.00577)	(0.00579)	(0.00579)
जॉम्बी डमी		-0.139	-2.062***	-0.139	-0.141
		(0.124)	(0.616)	(0.124)	(0.124)
जॉम्बी डमी× डब्ल्यूएसीआर			0.291***		
			(0.0914)		
बीआर				-0.000781	-0.0437
				(0.0166)	(0.0344)
बीआर × डब्ल्यूएसीआर					0.00656
					(0.00460)
स्थिरांक	10.06***	10.06***	10.15***	10.06***	10.31***
	(0.457)	(0.457)	(0.458)	(0.465)	(0.498)
एन	26183	26183	26183	26183	26183
समग्र आर^2	0.00992	0.0101	0.0104	0.0100	0.00993
फर्म निश्चित प्रभाव	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
वर्ष निश्चित प्रभाव	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

कोष्ठक में मानक त्रुटियाँ. * पी < 0.1, ** पी < 0.05, *** पी < 0.01. **स्रोत**: लेखकों का अनुमान।

सारणी 4: निधियों की लागत में परिवर्तन में बैंक उधार की संवेदनशीलता

	(1)	(2)	(3)
	लॉग(बैंक उधार)	लॉग(बैंक उधार)	लॉग(बैंक उधार)
निधियों की लागत	-0.0148***	-0.0149***	-0.0160***
	(0.00188)	(0.00188)	(0.00194)
जॉम्बी डमी	0.367***	0.436***	0.299***
	(0.0250)	(0.0298)	(0.0701)
एलएएफ डमी	0.0259**	0.0387***	0.0384***
	(0.0113)	(0.0117)	(0.0117)
जॉम्बी डमी × एलएएफ डमी		-0.199***	-0.146***
		(0.0470)	(0.0472)
जॉम्बी डमी × निधियों की लागत			0.0125**
			(0.00567)
स्थिरांक	6.735***	6.732***	6.743***
	(0.0208)	(0.0208)	(0.0214)
एन	17607	17607	17607
समग्र *आर*^{2}	0.00340	0.00418	0.00471
फर्म निश्चित प्रभाव	हाँ	हाँ	हाँ
वर्ष निश्चित प्रभाव	नहीं	नहीं	नहीं

कोष्ठक में मानक त्रुटियाँ. * पी < 0.1, ** पी < 0.05, *** पी < 0.01.
स्रोत: लेखकों का अनुमान.

सारणी 5: बैंक उधार में परिवर्तन में निवेश की संवेदनशीलता

	(1)	(2)	(3)
	निवेश	**निवेश**	**निवेश**
लंबी अवधि के बैंक उधार	$162 \times 10^{-8***}$	$181 \times 10^{-8***}$	
	(367×10^{-9})	(379×10^{-9})	
जॉम्बी डमी	-0.0112***	-0.00823**	-0.0108**
	(0.00309)	(0.00343)	(0.00534)
आरओए	$631 \times 10^{-6***}$	$626 \times 10^{-6***}$	$731 \times 10^{-6***}$
	(161×10^{-6})	(161×10^{-6})	(158×10^{-6})
जॉम्बी डमी × लंबी अवधि के बैंक उधार		$-132 \times 10^{-8**}$	
		(662×10^{-9})	
लंबी अवधि के बैंक उधार / कुल बैंक उधार			$423 \times 10^{-6***}$
			(391×10^{-7})
जॉम्बी डमी × लंबी अवधि के बैंक उधार / कुल बैंक उधार			220×10^{-6}
			(102×10^{-6})
स्थिरांक	0.0839***	0.0839***	0.0691***
	(0.0140)	(0.0140)	(0.0135)
एन	17259	17259	15788
समग्र *आर*^{2}	0.0178	0.0176	0.0600
फर्म निश्चित प्रभाव	हाँ	हाँ	हाँ
वर्ष निश्चित प्रभाव	हाँ	हाँ	हाँ

कोष्ठक में मानक त्रुटियाँ. * पी < 0.1, ** पी < 0.05, *** पी < 0.01.

स्रोत: लेखकों का अनुमान.

*मददगार के रूप में बैड बैंक: भारत के लिए विभिन्न देशों के अनुभवों से सीख**

अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के प्रबंधन में बहुराष्ट्रीय क्षेत्र पार के अनुभव बताते हैं कि पर्याप्त सरकारी और विधिक समर्थन प्राप्त होने पर बैड बैंक की स्थापना सबसे प्रभावी सिद्ध होता है। भारत के संदर्भ में, एक स्पष्ट जनादेश और एक स्पष्ट सरकारी गारंटी के साथ, राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) की स्थापना से वाणिज्यिक बैंकों पर से वित्तीय दबाव को कम करने में मदद करेगी। एनएआरसीएल मौजूदा आस्ति प्रबंधन कंपनियों की गतिविधियों के पूरक होने के साथ बड़ी दबाव वाली आस्तियों के समाधान के लिए एक अतिरिक्त तंत्र होगा । इसके साथ ही, निरंतर प्रतिबद्धता, पेशेवर कर्मचारी और संचालन में पारदर्शिता के कारण इस प्रक्रिया के लागत और समय को प्रभावी बनाने में मदद करेगी।

1. परिचय

राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) की 'बैड बैंक' के रूप में स्थापना और सरकार द्वारा हाल ही में इसकी प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) के लिए ₹ 30,600 करोड़ की गारंटी देने की घोषणा को समान मात्रा[1] में उत्साह के साथ-साथ संदेह के दृष्टिकोण से ग्रहण किया गया है। जहां कुछ ने इसे सभी कठिनाइयों के लिए रामबाण माना है, अन्य कम आशावादी विश्लेषकों ने संकटग्रस्त आस्तियों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए उपलब्ध अनेक विकल्पों के पहले से उपलब्ध होने की ओर इशारा किया है।

इस तरह के परस्पर विरोधी विचार बैड बैंकों की स्थापना में निहित ट्रेड-ऑफ को दर्शाते हैं। इस लेख में इस प्रकार के बैंकों की अंतर-देशीय प्रथाओं का विश्लेषण किया गया है ताकि उनकी सफलता में योगदान देने वाली विशेषताओं को समझा जा सके। इसके बाद एनएआरसीएल की विशेषताओं को इसकी सफलता की संभावना का आकलन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुभव से सीखे गए सबक के साथ जोड़ा जाता है। शेष लेख इस प्रकार संरचित है - खंड 2 बैड बैंकों की अवधारणा और विकास की व्याख्या करता है और खंड 3 अंतर-देशीय डिज़ाइन संरचना की व्याख्या करता है। खंड 4 और 5 क्रमशः उनकी स्थापना से होने वाले लाभों और उनके संचालन में आने वाली चुनौतियों की रूपरेखा से संबंधित हैं। अगला खंड अंतर-देशीय सीख के साथ एनएआरसीएल की विशेषताओं का मूल्यांकन करता है, जबकि खंड 7 में निष्कर्ष दिया गया है।

2. बैड बैंकों की अवधारणा और विकास

वैश्विक स्तर पर, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के आधिक्य से निपटने के लिए नीति विकल्पों में ऋण पुनर्रचना, दिवाला और समाधान ढांचे का उपयोग और सुधार तथा बैड बैंकों का संचालन शामिल है। हालांकि इन वैकल्पिक तंत्रों को पूरे देश में एक अवधि में आजमाया और परखा गया है, बैड बैंक विषेशरूप से प्रणाली-स्तरीय दबाव ग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए अधिक लोकप्रिय अवधारणाओं में से एक है।

'बैड बैंक' शब्द का उपयोग किसी भी संरचना का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, जो उसके तुलन पत्र वाली अथवा इससे इतर की अर्जक आस्तियों को अनर्जक आस्तियों से अलग करने में इसे सक्षम बनाता है। तुलन पत्र मॉडल में अनर्जक आस्तियों को एक अलग आंतरिक इकाई में रखा जाता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलती है और यह बाजार के लिए एक संकेत तंत्र के रूप में काम करता है, जो बैंक के तुलन पत्र को स्वच्छ करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर, तुलन पत्र से इतर मॉडल में एक विशेष-उद्देश्य वाली इकाई संरचना का रूप दिया जाता है, जिसमें अनर्जक आस्तियों को ऑफलोड किया जाता है, उसे प्रतिभूतित किया जाता है और अलग-अलग निवेशकों को बेचा जाता है। वैकल्पिक रूप से, अनर्जक आस्तियों को बाह्य आस्ति प्रबंधन या पुनर्संरचना कंपनी (एएमसी/एआरसी) में स्थानांतरित किया जा सकता है। बाद वाला मॉडल, हालांकि जटिल और महंगा है, तथापि अन्य मॉडल की तुलना में अधिकतम जोखिम हस्तांतरण सुनिश्चित करता है (मार्टिनी, एवं अन्य, 2009)।

---

* लेख अशोक साहू, सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के बैंकिंग अनुसंधान प्रभाग से डॉ स्नेहल एस हेरवाडकर, अर्पिता अग्रवाल और संभवी ढींगरा द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] भारतीय प्रेस ब्यूरो, 16 सितंबर, 2021 की प्रेस विज्ञप्ति, https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1755466 पर उपलब्ध है।

सारणी 1: सीएएमसी और उनकी स्थापना की तिथियां

देश	केंद्रीकृत आस्ति प्रबंधन कंपनी का नाम	स्थापना की तिथि
कोरिया	कोरियाई आस्ति प्रबंधन कंपनी (कामको)*	1962
यूएस	समाधान ट्रस्ट निगम (आरटीसी)	1989
स्वीडन	सिक्यूरम	1992
इंडोनेशिया	इंडोनेशियाई बैंक पुनर्रचना एजेंसी (आईबीआरए)	1998
मलेशिया	दानहर्ता	1998
चीन	ओरिएंट, ग्रेट वॉल, सिंडा, हुआरोंग आस्ति प्रबंधन	1999
जापान	समाधान और संग्रह निगम (आरसीसी)	1999
थाईलैंड	थाई आस्ति प्रबंधन कंपनी टीएएमसी	2001
आयरलैंड	राष्ट्रीय आस्ति प्रबंधन कंपनी (नामा)	2009
जर्मनी	एफएमएस वर्ट मैनेजमेंट	2010
यूके	यूके आस्ति समाधान लिमिटेड (यूकेएआर)	2010
स्पेन	सारेब	2012

टिप्पणी: * एशियाई वित्तीय संकट के बाद केएएमसीओ की भूमिका का विस्तार हुआ।

वर्तमान अध्ययन केंद्रीकृत आस्ति प्रबंधन कंपनियों (सीएएमसी) पर केंद्रित है - जो सरकार की भागीदारी की अलग-अलग श्रेणी पर आधारित है और जिसमें कुछ सीएएमसी की दूसरे सीएएमसी की तुलना में अधिक सफलता के लिए सहायक कारकों की रूपरेखा के साथ इनकी डिजाइन विशेषताओं पर चर्चा किया गया है। 1980 के दशक में अमेरिका में अग्रणी रूप में, सीएएमसी के विचार ने उस समय संकर्षण प्राप्त किया जब 1990 के दशक के अंत में कई अन्य देशों ने इसे पूर्वी एशियाई संकट के बाद और हाल ही में, वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफ़सी) (अनुलग्नक I) के बाद अपनाया। इस अध्ययन के लिए समीक्षा में शामिल की गई सीएएमसी की सूची, उनकी स्थापना की तारीखों के साथ सारणी 1 में दी गई है।

3. बैड बैंकों के डिजाइन संबंधी पहलू: अंतर-देशीय प्रमाण

केंद्रीकृत बैड बैंकों को कई मानदंडों जैसे उनकी पूंजीगत निधि, आस्ति के अधिग्रहण के तरीके और इसके लिए भुगतान की गई कीमत, अशोध्य ऋणों के निपटान के लिए प्रणाली और साथ ही उद्देश्य प्राप्ति हेतु बैंक की समापन रणनीति के आधार पर एक-दूसरे से अलग किया जा सकता है। अंतर-देशीय अनुभवों के विश्लेषण से पता चलता है कि राजनीतिक सहमति, कुशल कानूनी प्रक्रियाएं, नई संस्था को पर्याप्त वैधानिक शक्तियां, अच्छी तरह से विकसित वित्तीय बाजार और निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का उपयोग बैड बैंकों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण पहलू हैं (मार्टिनी, एवं अन्य, 2009)। कुछ एशियाई एएमसी के मामले में, एक स्पष्ट जनादेश, बेहतर परिभाषित अवधिकाल, यथार्थवादी मूल्य निर्धारण और स्पष्ट सरकारी वित्तीय सहायता को भी उनकी सफलता के कारणों के रूप में बताया गया है (फंग, जॉर्ज, होहल और मा, 2004)।

3.1 सीएएमसी का वित्तपोषण

किसी बैड बैंक को सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण वित्त पोषण के माध्यम से या तो बांड निर्गम या इक्विटी योगदान के माध्यम से, केंद्रीय बैंक से विशेष ऋण, या शेयरों की सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है। स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका, सिक्यूरम और समाधान ट्रस्ट निगम (आरटीसी) के मामले में क्रमशः उनकी संबंधित सरकारों द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया गया था (भगवती, खान, और बोगाथी , 2017)। कई पूर्वी एशियाई देशों में, सीएएमसी को सरकार द्वारा गारंटीकृत एएमसी बांड जारी करने के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है, जो सरकार को अपने तुलन पत्र से संभावित देयता को दूर रखने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, कोरियाई आस्ति प्रबंधन कंपनी (केएएमसीओ) निधि जुटाने के लिए सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड जारी करती है और अन्य वित्तीय संस्थान अपनी चुकता पूंजी का लगभग एक-चौथाई योगदान करते हैं (एचई, 2004)। स्पष्ट सरकारी गारंटी द्वारा इन बांडों को अक्सर पूंजी पर्याप्तता गणना में शून्य जोखिम भार सुनिश्चित करके बैंकों को उनमें निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

3.2 दबावग्रस्त आस्तियों का अधिग्रहण

सीएएमसी ने ऐतिहासिक रूप से वित्तीय संस्थानों से, ज्यादातर बैंकों और निवेश ट्रस्ट कंपनियों से, 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक की विभिन्न छूट दरों पर दबावग्रस्त आस्तियां खरीदी है। आमतौर पर, विक्रेता को नकद और प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के माध्यम से मुआवजा दिया जाता है, क्रेता को आमतौर पर सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है। एनपीए की भी जांच इस आधार पर की जाती है कि उनके संपार्श्विक और हस्तांतरण अधिकार कानूनी रूप से निष्पादन योग्य हैं या नहीं। अधिग्रहण प्रक्रिया में जिन अन्य कारकों पर विचार किया जाता है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- सरकारी भागीदारी की श्रेणी और बैड बैंक के अधिदेश के आधार पर, दबावग्रस्त आस्तियों का हस्तांतरण स्वैच्छिक या अनिवार्य हो सकता है। उदाहरण के लिए, थाईलैंड में, जबकि टीएएमसी ने आस्तियों का

अधिग्रहण सरकारी और निजी-स्वामित्व वाली दोनों वित्तीय संस्थानों से किया, जहां अर्हक आस्तियों का हस्तांतरण पहले के लिए अनिवार्य था और दूसरे के लिए वैकल्पिक।

- कुछ मामलों में, बैड बैंकों को दबावग्रस्तआस्ति का केवल एक हिस्सा खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया में, आधे ऋणों का निपटान वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वयं किया जाना होता था, और शेष आधे को सीएएमसी द्वारा खरीदा जाना था। मलेशिया में, दानहर्ता ने केवल एमवाईआर 5 मिलियन से ऊपर के अनर्जक ऋणों (एनपीएल) पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि छोटे एनपीएल को वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वयं बेहतर तरीके से संभाला जाएगा। इसके अलावा, छोटे ऋणों से संबंधित खातों की विशाल संख्या ने इसे केंद्रीकृत एएमसी द्वारा निपटाए जाने के लिए लागत और समय के दृष्टिकोण से निष्प्रभावी बना दिया।

- समस्या के पैमाने और अन्य कारकों के साथ-साथ बैड बैंक की क्षमता के आधार पर विभिन्न देशों द्वारा अधिग्रहित आस्तियों की मात्रा में व्यापक भिन्नताएं हैं। दानहर्ता ने कुल एनपीएल का 80 प्रतिशत अधिग्रहण किया, जबकि आयरिश नामा ने 2009 में देश के सकल घरेलू उत्पाद के 44 प्रतिशत मूल्य की आस्तियों का अधिग्रहण किया।

- कुछ मामलों में, आस्तियों के अधिग्रहण पर भौगोलिक प्रतिबंध हैं; उदाहरण के लिए, चीन में, 2013-14 से स्थापित किए जा रहे स्थानीय और प्रांतीय एएमसी केवल उसी क्षेत्र से संबंधित दबावग्रस्त आस्तियों का अधिग्रहण कर सकते हैं, जिसमें वे स्थित हैं, हालांकि उनका निपटान करते समय ऐसा कोई क्षेत्रीय प्रतिबंध लागू नहीं है।

- बैड बैंकों को इस आधार पर भी पहचाना जा सकता है कि उनका अधिदेश क्षेत्र-विशिष्ट है या सामान्य प्रयोजन वाला है। सामान्य प्रयोजन वाले बैड बैंक वे होते हैं जो अपने द्वारा अर्जित की गई दबावग्रस्तआस्तियों की क्षेत्र आधारित संरचना में अंतर नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, चीन में, चार राज्य के स्वामित्व वाली एएमसी ने विनिर्माण क्षेत्र से लेकर कृषि क्षेत्र तक विविध आस्तियों का अधिग्रहण किया। आईबीआरए ने कॉरपोरेट ऋणों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जो इसकी अर्जित आस्तियों का 84 प्रतिशत है। दूसरी ओर, कुछ यूरोपीय एएमसी, जैसे नामा और सरेब, के पास लक्षित आस्तियों के रूप में भूमि और वाणिज्यिक अचल संपत्ति है और इसे वे विभिन्न बैंकों से प्राप्त करते हैं।

3.3 मूल्य निर्धारण और वसूली

बैड बैंक की व्यवहार्यता और सफलता महत्वपूर्ण रूप से मूल्य निर्धारण पर निर्भर करती है, जो कि मूल बैंक के साथ-साथ सीएएमसी दोनों के लिए उचित है, भले ही हस्तांतरण की विधि कुछ भी हो। अधिक कीमत वाले एनपीए संकटग्रस्त वित्तीय संस्थानों को उबारने के लिए सरकार के भेष में काम करने के अलावा, सीएएमसी की लाभप्रदता और जनादेश हासिल करने की क्षमता को कम कर देते हैं। वैकल्पिक रूप से, बहुत कम कीमतों पर एनपीए प्राप्त करने से पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य विफल हो जाता है, जिससे बैंकों को होने वाले वित्तीय लाभ पर असर पड़ता है। डेटा की उपलब्धता, अधिग्रहीत आस्तियों की प्रकृति और गुणवत्ता, तथा दबावग्रस्त आस्तियों के लिए बाजार (तालिका 2) जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर अंतरण मूल्य पर निर्णय लेने के लिए देश अलग-अलग प्रक्रिया अपनाते हैं। यूरोपीय देशों में, हस्तांतरण मूल्य आमतौर पर अनुमानित (वर्तमान) बाजार मूल्य और अनुमानित वास्तविक (दीर्घकालिक) आर्थिक मूल्य के बीच निर्धारित किया जाता है, जो कि अनुमानित भावी नकदी प्रवाह, बही मूल्य, बाजार मूल्य, संपार्श्विक मूल्य और अन्य पहलुओं के साथ-साथ वसूली की संभाव्यता पर आधारित होता है।

3.4 आस्तियों का प्रबंधन और निपटान

किसी केंद्रीकृत एजेंसी द्वारा आस्तियों का अधिग्रहण और एकत्रीकरण अपने आप में उनके प्रभावी या लाभदायक संचालन की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि उक्त दोनों कार्यों के लिए कौशल और विशेषज्ञता के अलग-अलग सेट की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, मलेशिया में, समाधान प्रक्रिया को पूरा करने में सहायता के लिए दानहर्ता के साथ एक कॉरपोरेट ऋण पुनर्संरचना समिति के साथ-साथ एक बैंकिंग पुनर्पूंजीकरण एजेंसी, दानामोडल भी थी। आस्ति प्रबंधन पर विशेष ज्ञान तक पहुंच बनाने और सरकारी स्वामित्व वाली एएमसी में विशेषज्ञता की

सारणी 2: मूल्य निर्धारण, अधिग्रहण और वसूली

बैड बैंक	खरीद या स्थानांतरण मूल्य	अर्जित आस्ति (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)	वसूली की औसत दर (प्रतिशत)
दानहर्ता	अचल संपत्ति ऋण के लिए नए मूल्यांकन के आधार पर बाजार मूल्य; गैर-जमानती ऋण के लिए बकाया मूलधन का 10 प्रतिशत।	5	58
इंडोनेशियाई बैंक पुनर्रचना एजेंसी (आईबीआरए)	शून्य मूल्य पर हस्तांतरित आस्तियां।	27	22
कामको	बट्टागत अनुमानित नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य के आधार पर; गैर-जमानती ऋण के लिए अंकित मूल्य का 3 प्रतिशत।	20	47
ओरिएंट, ग्रेट वॉल, सिंडा, हुआरोंग	संबंधित बैंकों से बही मूल्य पर खरीदे गए एनपीएल।	18	34
समाधान ट्रस्ट निगम (आरटीसी)	आस्ति क्रय नहीं किया।	एनए	87
एसएआरईबी	केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर परिकलित वास्तविक आर्थिक मूल्य के आधार पर।	10	एनए
सिक्यूरम	आस्ति क्रय नहीं किया। ऋण और संबंधित आरक्षित निधियों का हस्तांतरण किया गया, जबकि सरकार ने बैंकों का सीधे पुनर्पूंजीकरण किया।	4	एनए
एनएएमए	बही मूल्य से नीचे हस्तांतरण किया गया और मूल्यांकन के आधार पर आयरिश सरकारी बॉन्ड के माध्यम से भुगतान किया गया।	44	33

एनए: लागू नहीं/उपलब्ध नहीं है।
स्रोत: संदर्भित शोध पत्रों के आधार पर।

कमी को दूर करने के लिए भी संयुक्त उद्यम भागीदारी का उपयोग किया जाता है।

आस्ति निपटान के लिए सीएएमसी द्वारा अपनाए गए तकनीकों को निपटान में शामिल आस्ति के प्रकार के अनुरूप बनाया गया है। व्यवहार्य ऋणों का पुनर्संरचना किया जा सकता है, जबकि गैर-व्यवहार्य व्यवसाय, आस्ति, या अंतर्निहित संपार्श्विक आस्तियां, बेच दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, समरूप आस्तियों को अस्ति-समर्थित प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से जमा और प्रतिभूतित किया जा सकता है। जिन मामलों में व्यक्तिगत आस्तियों के परिसमापन की आवश्यकता होती है, मूल्य निर्धारण के लिए पुरोबंध और संपार्श्विक की सार्वजनिक नीलामी की जाती है।

3.5 विंड-डाउन रणनीति

एएमसी के आदर्श जीवनकाल पर दो विचार सामने आए हैं। 'यूरोपीय दृष्टिकोण' नैतिक खतरे की चिंताओं का प्रभुत्व है और एएमसी के स्पष्ट रूप से परिभाषित, यथार्थवादी अवधिकाल का समर्थन करता है, जिसमें बैंकों से संपत्ति हस्तांतरण अधिमानतः एक ही बार में पूरा किया जाता है। एसएआरईबी, यूकेएआर और एफ़एमएस सभी को लाभ कमाने या अपनी बहियों में दर्शाई गई सभी ऋणों को बेचने या पूर्व-निर्दिष्ट समय अवधि के बाद निपटान करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था। एसएआरईबी का लक्ष्य अपने 15 साल के जीवन में 15 प्रतिशत का लाभ कमाना है, जबकि यूकेएआर की स्थापना संकटग्रस्त संस्थानों में सरकार की हिस्सेदारी को बेचने के लिए की गई थी। दूसरी ओर, 'एशियाई दृष्टिकोण', नैतिक खतरों की समस्याओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की पूर्ति करते हुए आमतौर पर एएमसी को अपने वित्तीय संकट टूलकिट का एक हिस्सा बनाने, बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता को बनाए रखने में विश्वास करता है (मार्टिन, 2020)। चीनी और कोरियाई एएमसी की जहां कोई स्पष्ट समाप्ति तिथि नहीं थी, दानहर्ता को एक सीमित समय-सीमा के साथ स्थापित किया गया था और 2005 में इसके संचालन को बंद कर दिया गया था।

3.6 सुपर विधिक शक्तियाँ

ऐसे देशों में जहां मौजूदा विधिक व्यवस्था ने ऋण के कामकाज, पुनर्संरचना वार्ता या पुरोबंध में बाधा या देरी का कारण बनी, वहाँ सीएएमसी को इन बाधाओं को दूर करने के लिए सुपर विधिक शक्तियां प्रदान की गईं। उदाहरण के लिए, दानहर्ता को दो विशेष शक्तियां प्रदान की गई: स्वत्वाधिकार की निश्चितता के साथ वैधानिक निहित के माध्यम से एनपीएल हासिल करने की क्षमता; और वित्तीय रूप से संकटग्रस्त कंपनी उधारकर्ताओं के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र विशेष प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति। इसी तरह, एसएआरईबी को अन्य लेनदारों पर अधीनस्थ ऋण के लिए एक तरजीही लेनदार के रूप में एक विशेष दर्जा और सभी स्पेनिश सीमित देयता कंपनियों पर लागू नहीं होने वाले अन्य विधिक लाभ प्राप्त हैं। एनएएमए को उसके अधिनियम के तहत, अपने दिवालिया देनदारों से वाणिज्यिक अचल संपत्ति संपार्श्विक के

अधिग्रहण की अनुमति दी गई है, जो आयरलैंड में अन्य उधारदाताओं को प्राप्त नहीं है।

4. केंद्रीकृत बैड बैंक के लाभ

दुनिया भर में साक्ष्य बताते हैं कि एक केंद्रीकृत बैड बैंक पर्याप्त दबाव कम करने में मदद कर सकता है और इसके विभिन्न प्रणालीगत लाभ हैं, जो पहले से मौजूद दबावग्रस्त आस्ति समाधान प्रणाली की सहायता करते हैं और उन्हें सक्षम बनाते हैं।

- बिक्री करने वाले बैंकों को कमजोर आस्तियों का बाकी हिस्सों से स्पष्ट अलगाव इसके तुलन पत्र को पुनर्संरचित करने और व्यवसाय मॉडल को फिर से आकार देने के लिए एक अवसर और तर्क उपलब्ध करवाता है, जबकि ग्राहकों और निवेशकों को बैंक के मूल प्रदर्शन में पारदर्शी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्रावधानों को मुक्त करके और इस प्रकार, उधार देने के लिए पूंजी को बढ़ाकर, सीएएमसी बैंकों को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सक्षम बनाता है। संकटग्रस्त आस्तियों और कॉरपोरेट पुनर्गठन के प्रबंधन के बजाय दुर्लभ मानव संसाधन नए उधार जैसे अधिक महत्वपूर्ण बैंकिंग कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- बैंकों के पास बैंकों के भीतर अलग-अलग विभागों या सहायक कंपनियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में एनपीए का समाधान करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होने की स्थिति में सीएएमसी मॉडल पर भरोसा किया जा सकता है। आंतरिक पुनर्संरचना के विपरीत, कोई सीएएमसी, बैंक के तुलन पत्र से दबावग्रस्त आस्तियों को निकालने के लिए एक त्वरित साधन उपलब्ध करता है और सरकार या बाजारों से नए पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता को कम करता है।
- इस प्रणाली का लाभ उठाते हुए, बैंक आस्तियों की ऐसी बाध्यकारी तत्काल बिक्री से बच सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम वसूली मूल्य प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने के कारण सीएएमसी के माध्यम से धीरे-धीरे बिक्री से इष्टतम वसूली दरों की प्राप्ति हो सकती है।
- सीएएमसी आमतौर पर मूल्य अधिकतमीकरण के अलावा आस्तियों के आर्थिक मूल्य को संरक्षित रखने जैसी अन्य चिंताओं से प्रेरित होते हैं । उदाहरण के लिए, आरटीसी ने अपनी अचल संपत्ति की बिक्री को समयबद्ध किया ताकि कीमतों में और गिरावट न हो।
- बैड बैंकों में दबावग्रस्त ऋणों का समेकन और संपार्श्विक का केंद्रीकृत स्वामित्व इन आस्तियों के लिए निवेशकों को आकर्षित करने में व्यक्तिगत बैंकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकता है। उदाहरण के लिए, एशिया में सार्वजनिक एएमसी ने बैंकों को अपने एनपीएल बेचने या समस्याग्रस्त आस्तियों को बेचने के लिए मजबूर करने का विकल्प देकर एनपीएल के लिए एक बाजार प्रदान किया (ली, 2020)।
- केंद्रीयकृत एएमसी और सार्वजनिक या निजी एआरसी थाईलैंड की तरह एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, और दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन में उन्हें प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। बैड बैंक ऐसी आस्तियों को रख सकते हैं, जो उत्पादन पूर्व लंबी अवधि के कारण निजी एएमसी नहीं रख सकती हैं, या ऐसी आस्तियां जो मध्यम अवधि में पर्याप्त रूप से लाभदायक नहीं हो सकती हैं लेकिन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और निकटस्थ क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव रखते हैं (आचार्य, 2017)।
- सीएएमसी आमतौर पर विधि के विशेष अधिनियमों या सरकारी आदेशों के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं। जैसे, उन्हें ऋण वसूली में तेजी लाने के लिए विशेष विधिक शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं, जैसा कि कुछ सफल अनुभवों जैसे कि दानहर्ता में देखा गया है ।
- निजी एआरसी द्वारा जारी एसआर की तुलना में अधिक आकर्षक होने के अलावा, एनपीए खरीदने के लिए नकद और/या कूपन-भुगतान करने वाली सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूतियों का उपयोग, बैंकों के तुलन पत्र में सुधार करता है और वित्तीय संस्थानों की आय में वृद्धि करता है। यह संकटग्रस्त आस्तियों के लिए एक जीवंत बाजार और अलगाव में काम कर रहे निजी संस्थाओं की तुलना में एक समान मूल्यांकन मानदंड के निर्माण द्वारा अधिक सकारात्मक मूल्य निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है।

5. केंद्रीकृत बैड बैंक की चुनौतियाँ

अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं ने लंबे समय से स्वीकार किया है कि एक बैड बैंक की स्थापना कई ट्रेड-ऑफ से युक्त है। इनमें शामिल हैं - नैतिक जोखिम को प्रोत्साहित किए बिना बैंकिंग दबाव को कैसे दूर किया जाए; सरकारी खजाने की लागत को कैसे कम किया जाए और एक ऐसा मूल्य निर्धारण कैसे किया जाए जो अधिग्रहण करने वाली इकाई और विक्रेता दोनों के लिए उचित हो। निम्नलिखित गंभीर चुनौतियों को देखते हुए, उनके डिजाइन और संरचना में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

- अनिवार्य रूप से बैंकों के तुलन पत्र से बोझ को कम करने के लिए बनाए गए बैड बैंक, जोखिम भरी आस्तियों के और अधिक निर्माण को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह जानते हुए कि उनके पास अशोध्यता की स्थिति में बैड बैंक का विकल्प है, बैंक ऋण देने में कम सतर्क हो सकते हैं, जिससे नैतिक खतरे की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
- सीएएमसी के डिजाइन को देश-विशिष्ट और/या क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सावधानीपूर्वक तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, प्राथमिक उद्देश्य से भटकने की प्रवृत्ति भी है, जैसा कि चीन के चार बड़े बैड बैंकों के मामले में है, जिसमें अशोध्य ऋणों के बजाय वित्तीय संस्थानों जैसे कि बैंक और बीमा कंपनियों में निवेश अब उनके व्यापार का एक प्रमुख हिस्सा है (इंग्वेस, सेलिग, और एचई, 2004)। उनके अधिशासी निकायों और कर्मचारियों को उचित प्रोत्साहन प्रदान करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कर्मचारियों की भर्ती और प्रतिधारण ऐसी समस्याएं हैं जो अक्सर उत्पन्न होती हैं।
- केंद्रीय बैड बैंक के लिए वित्त पोषण एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। जब तक सावधानीपूर्वक डिजाइन और कुशलतापूर्वक निष्पादित नहीं किया जाता है, सीएएमसी की स्थापना की लागत अनिवार्य रूप से संसाधन-विवश सरकार पर और अंततः करदाताओं पर पड़ती है। यहां तक कि उन देशों में जहां सीएएमसी एनपीएल को कम करने में सफल रही है, यह सरकारी खजाने की कीमत पर प्राप्त हुआ है (फंग, जॉर्ज, हॉल, और मा, 2004)।
- एक और चुनौती जो सामने आती है, वह है एनपीएल के एक बड़े हिस्से के निपटान के लिए बैड बैंक को पर्याप्त वित्तपोषित रखना। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि कुछ मामलों में, बैड बैंक के संसाधन दबावग्रस्त आस्तियों के एक छोटे से हिस्से के लिए जिम्मेदार होते हैं, इस प्रकार पूरी प्रक्रिया को निष्प्रभावी बना देते हैं।
- संकटग्रस्त आस्तियों के लिए बाजार निर्माण और खरीद और बिक्री दोनों चरणों में उनका उचित मूल्य निर्धारण एक अन्य परिचालनगत चुनौती है जो उत्पन्न होती है, क्योंकि यह समाधान की व्यवहार्यता और स्थिरता को निर्धारित करती है। राज्य के स्वामित्व वाली एएमसी द्वारा आस्ति के निपटान को कुछ आस्तियों की बिक्री के विरुद्ध राजनीतिक दबाव और बिकवाली से संबंधित ऑडिट जांच के डर जैसी चुनौतियों से हतोत्साहित किया जा सकता है (फंग, जॉर्ज, होहल , और मा, 2004)।
- सरकार द्वारा वित्तपोषित होने के कारण सीएएमसी को आस्ति मूल्य अधिकतमीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक व्यापक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, आस्ति को बेचने या बनाए रखने से संबंधित उनके निर्णय आस्ति बाजारों को स्थिर करने में मदद करने की आवश्यकता से विवश हो सकते हैं।
- संचालन में पारदर्शिता की कमी और विश्वसनीय आंकड़ों की कमी के कारण आस्तियों के निष्पक्ष मूल्य निर्धारण और पुनर्विक्रय के लिए इष्टतम पोर्टफोलियो के निर्माण में बाधा उत्पन्न हो सकती है (डेलोइट, 2020)। आयरलैंड और स्पेन जैसे देशों में, अपर्याप्त या अनुपलब्ध दस्तावेज़ीकरण ने उनके सीएएमसी (कैस & पेरेसा, 2016) के सुचारू कामकाज में बाधा उत्पन्न की।

6. भारत में दबावग्रस्त आस्तियों का प्रबंधन

2012 के बाद से बढ़ते एनपीए के कारण भारतीय बैंकिंग प्रणाली कमजोर हुई है। बैंकों के लिए दबाव से निपटने के लिए विभिन्न तंत्र जैसे लोक अदालत, ऋण वसूली न्यायाधिकरण,

सरफेसी अधिनियम और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) उपलब्ध हैं, फिर भी समाधान तक इन आस्तियों को अपनी बहियों में बनाए रखते हैं। भारत में एक आंतरिक पुनर्संरचना इकाई जैसे मॉडल का भी प्रयोग किया गया है, किन्तु इसमें केवल आंशिक सफलता ही मिली। स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एसयूयूटीआई) को एक विशेष प्रयोजन इकाई के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका प्राथमिक कार्य यूटीआई के अशोध्य ऋणों के प्रबंधन और मोचन को प्रशासित करना था, किन्तु इसे अभी तक बंद नहीं किया गया है। एसयूयूटीआई को हस्तांतरित अन्य आस्तियों के मूल्य में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है, उनके निपटान को हतोत्साहित किया गया है और एसयूयूटीआई को समय के साथ उसे बनाए रखने और जारी रखने से लाभ हुआ है।

वैकल्पिक रूप से, बैंक एसआर जारी करके एक मार्जिन पर निजी एआरसी को अशोध्य ऋणों की एकमुश्त बिक्री के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। एआरसी मॉडल कई कारकों से बाधित साबित हुआ है, जैसे कि पुराने एनपीए उन पर पारित किए जा रहे हैं, ऋण एकत्रीकरण की कमी, दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए अतिरिक्त वित्तीयन की अनुपलब्धता, एआरसी द्वारा धन जुटाने में कठिनाई आदि। इसके अलावा संकटग्रस्त उधारकर्ताओं के समग्र समाधान के लिए वसूली और आवश्यक कौशल प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना भी शामिल है (आरबीआई, 2021)। इसके अलावा, वसूली की अनिश्चितता एसआर के लिए द्वितीयक बाजार को अतरल बना देती है, जिससे ये एसआर अभिदाता संस्था की बहियों में ही बने रहते हैं, जो अक्सर मूल बिक्री करने वाले बैंक स्वयं होते हैं (यादव और चव्हाण, 2021)।

भारतीय मामले में, अधिकांश दबावग्रस्त आस्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पास हैं और उनके शीर्ष प्रबंधन को हमेशा दबावग्रस्त आस्तियों पर निर्णायक कार्रवाई करते समय एक दुविधा का सामना करना पड़ता है: वर्तमान में भौंहें चढ़ाने और भविष्य में सतर्कता कार्रवाई की संभावना के डर के बिना मार्जिन की सही मात्रा क्या होनी चाहिए, जिसे अनुमानित किया जा सकता है? [2] दबावग्रस्त आस्तियों के लिए सही कीमत तय करना मुश्किल हो सकता है और ये वाणिज्यिक निर्णय बदलती परिस्थितियों के साथ गलत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में, अभी समाधान के लिए साहसिक कदम नहीं उठाना और इसे कुछ समय के लिए रास्ते से हटाना हमेशा एक बेहतर विकल्प के रूप में माना जा सकता है।

अब तक का अनुभव बताता है कि बार-बार मुकदमों के कारण, समाधान प्रक्रिया में देरी होती है, जिससे आस्तियों के मूल्य में गिरावट आती है, जो इस बीच बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इन तंत्रों के अप्रभावित रहने से इन्हें दबावग्रस्त आस्तियों के बड़े बकाया स्टॉक का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा (सितंबर 2021 के अंत में 72.1 प्रतिशत) पीएसबी के तुलन पत्र में है, जिसके परिणामस्वरूप पुनर्पूंजीकरण का बोझ जनता को उठाना पड़ता है। इसके अलावा, अशोध्य ऋण की समस्या ने बैंकों की जोखिम लेने की क्षमता को कम कर दिया है, जिससे उनकी ऋण वृद्धि प्रभावित हुई है।

एनएआरसीएल की डिजाइन संबंधी विशेषताएं

एनएआरसीएल की कुछ विशेषताएं कहीं और अपनाए गए सफल मॉडल के समान हैं और ये एनपीए दबाव को कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं।

- संरचना: बाजार के पेशेवरों और परिवर्तनकारी विशेषज्ञों को शामिल करके इन आस्तियों के प्रबंधन के लिए इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (आईडीआरसीएल) के साथ-साथ दबावग्रस्त आस्तियों को अधिगृहीत करने और समेकित करने के लिए एनएआरसीएल की स्थापना मलेशिया में अपनाई जाने वाली व्यवस्था के समान है, जो अपनी दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में अत्यधिक सफल साबित हुई है।
- स्वामित्व: एनएआरसीएल का प्रारंभिक पूंजी आधार ₹6,000 करोड़ है, जिसमें से पीएसबी के पास बहुमत (51 प्रतिशत) हिस्सेदारी है, जबकि शेष शेयरधारिता निजी क्षेत्र के बैंकों और गैर-बैंक वित्त कंपनियों[3] में निहित है। इस प्रकार, यह संरचना सरकार के सीमित संसाधनों पर तत्काल दबाव नहीं डालती है। आईडीआरसीएल की अधिकांश निजी शेयरधारिता

[2] 'सीवीसी को बैंकों द्वारा अशोध्य ऋण की बिक्री में कई त्रुटियाँ मिली हैं', दिनांक 18 मार्च, 2019 के टाइम्स ऑफ इंडिया। https://timesofindia.indiatimes.com पर उपलब्ध, 15 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया।

[3] दिनांक 5 अक्टूबर, 2021 के https://www.moneycontrol.com/ लेख से 14 फरवरी, 2022 को एक्सेस किया गया।

और दबावग्रस्त आस्तियों के परिणामी पेशेवर और विशेषज्ञ प्रबंधन से अधिकतम और समय पर वसूली सुनिश्चित किए जाने की उम्मीद है।

- अधिग्रहण: कोरिया और मलेशिया जैसे सफल मॉडल का अनुसरण करते हुए, नकद में ऋण के सहमत या रियायती मूल्य के 15 प्रतिशत तक का भुगतान करके शेष के लिए सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर जारी करते हुए, बैंकों से एनपीए का अधिग्रहण किया जाएगा। यह देखते हुए कि पहले चरण में, पहले से ही पूरी तरह से प्रदान की जा चुकी ₹ 90,000 करोड़ की आस्ति (₹ 2,00,000 करोड़ के कुल नियोजित अधिग्रहण में से) के कारण अधिग्रहण की उम्मीद है, जिससे वसूली तुरंत बैंकों के तुलन पत्र को मजबूत करेगी। इसके अलावा, ₹500 करोड़ से अधिक के पुराने बड़े मूल्य खातों पर ध्यान केंद्रित करके, एनएआरसीएल समग्र दबाव[4] का तेजी से समाधान कर सकता है।
- सरकारी गारंटी: एसआर के अंकित मूल्य और वास्तविक प्राप्ति के बीच की कमी को पूरा करने के लिए ₹30,600 करोड़ तक की गारंटी लागू की जा सकती है। गारंटी की समयबद्ध प्रकृति, समाधान या परिसमापन पर सशर्त 5 साल के लिए वैध, और एनएआरसीएल द्वारा सरकार को देय गारंटी शुल्क में क्रमिक वृद्धि के कारण समाधान में किसी भी देरी को हतोत्साहित करने की उम्मीद है। संरचना, स्वामित्व पैटर्न और एसआर का समर्थन करने वाली सरकारी गारंटी से संस्था को विश्वसनीयता प्रदान करने और विभिन्न नियामकों द्वारा उनके बिकवाली के निर्णयों के बारे में बैंकों के डर को दूर करने की उम्मीद है।
- प्रतिभूति रसीदें: बैड बैंक की प्रारंभिक पूंजीकरण आवश्यकताओं को कम करने के अलावा, सरकार द्वारा गारंटी एसआर की तरलता और पारंपरिकता में सुधार करने के लिए बाध्य है, जिससे उनके लिए एक द्वितीयक बाजार के विकास में मदद मिलती है।
- मौजूदा एआरसी के साथ पूरकता: प्रस्तावित तंत्र के तहत, एनएआरसीएल को "स्विस चैलेंज पद्धति" के अनुसार रहने की आवश्यकता है, जहां भारत में 28 मौजूदा एआरसी को दबावग्रस्त आस्तियों के लिए बेहतर प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। दबावग्रस्त आस्तियों के बाजार में खरीदार के रूप में विकल्प या प्रतिद्वंद्वी होने के बजाय, राष्ट्रीयकृत संस्था मौजूदा कंपनियों के पूरक के रूप में कार्य करेगी। वे ऋण समेकन में मदद करेंगे, अशोध्य ऋणों को एकत्र करने में लगने वाले समय को कम करेंगे और अंतर-ऋणदाता मुकदमों से बचेंगे।

[4] इस लेख के प्रकाशन के समय, मार्च 2022 के अंत तक 50,000 करोड़ रुपये की आस्ति को एनएआरसीएल को हस्तांतरित किया जाना निर्धारित है। 28 जनवरी, 2022 को https://www.thehindubusinessline.com/ लेख से प्राप्त किया जा सकता है।

7. निष्कर्ष

मौजूदा समय में एक बैड बैंक का निर्माण बैंकिंग दबाव को कम करने और ऋण चक्र को किक-स्टार्ट करने में मददगार साबित हो सकता है। अंतर देशीय प्रमाण बताते हैं कि अगर लॉजिस्टिक और वित्तीय चुनौतियों को सावधानी से प्रबंधन किया जाता है, तो केंद्रीकृत बैड बैंक के प्रयोगों में चूक की तुलना में अधिक सफल हो सकते हैं। हालांकि वित्तीय दबाव से निपटने के लिए एक सार्वभौमिक निवारक के रूप में उनका स्वागत करना अनुचित हो सकता है, लेकिन अनुकूल संस्थागत ढांचे से सुसज्जित होने पर वे एक सार्थक विकल्प साबित हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुभव से पता चलता है कि भारत में एनएआरसीएल के एक समय-कुशल तंत्र के रूप में काम करने की संभावना है, जबकि प्राथमिक और साथ ही माध्यमिक बाजारों में क्रमशः दबावग्रस्त आस्तियों और एसआर के लिए निवेशकों की रुचि को यह पुनर्जीवित भी करता है। इसमें आगे चलकर, निरंतर प्रतिबद्धता, पेशेवर कर्मचारी और संचालन में पारदर्शिता के कारण लागत और समय को प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि ताजा नुकसान को कम किया जाए, और भविष्य में दबाव के निर्माण से बचने के लिए बैंक के तुलन पत्र को मजबूत किया जाए।

References

Acharya, V. (2017). Some Ways to Decisively Resolve Bank Stressed Assets. *Indian Banks' Association Banking Technology Conference.* Mumbai.

Bhagwati, J., Khan, M. S., & Bogathi, R. R. (2017). *Can Asset Reconstruction Companies (ARCs) be Part*

Solution to the Indian Debt Problem? Working Paper No. 338, ICRIER.

Cas, S. M., & Peresa, I. (2016). What Makes a Good 'Bad Bank'? The Irish, Spanish and German Experience. *European Commission Discussion Paper No. 036.*

Deloitte. (2020). *Bad Banks in India.*

European Commission. (2018). AMC Blueprint. Brussels.

Fung, B., George, J., Hohl, S., & Ma, G. (2004). Public asset management companies in East Asia- A comparative study. *Occasional paper, Financial Stability Institute.*

He, D. (2004). The Role of KAMCO in Resolving Nonperforming Loans in the Republic of Korea. *IMF Working Paper.*

Ingves, S., Seelig, S. A., & He, D. (2004). Issues in the Establishment of Asset Management Companies. *IMF Policy Discussion paper*, PDP/04/3.

Klingebiel, D. (2000). The Use of Asset Management Companies in the Resolution of Banking Crises: Cross-Country Experience. *World Bank Policy Research Working Paper No. 2284.*

Lee, J. (2020). Country Case Studies on Resolving Problem Loans in Asia. *SEACEN Centre Seminar.* Manila: Asian Development Bank.

Martin, R. (2020). Asset Management Companies and NPL Resolution. *SEACEN Webinar.* Joint Vienna Institute.

Martini, L., Stegemann, U., Windhagen, E., Heuser, M., Schneider, S., Poppensieker, T., . . . Brenna, G. (2009). *Bad Banks: Finding the Right Exit from the Financial Crisis.* McKinsey Working Papers on Risk.

McCauley, R. (2003). Unifying government bond markets in East Asia. *paper presented at the Hong Kong Institute of Monetary Research, Hong Kong SAR.*

Reserve Bank of India (2021): Report of the Committee to Review the Working of Asset Reconstruction Companies (Chairman: Shri Sudarshan Sen).

Terada-Hagiwara, A., & Pasadilla, G. (2004). Experience of Asian Asset Management Companies: Do They Increase Moral Hazard?- Evidence from Thailand. *ERD Working Paper No. 55, Asian Development Bank.*

Yadav, A., & Chavan, P. (2021, April). ARCs in India: A Study of their Business Operations and Role in NPA Resolution. *RBI Bulletin.*

अनुलग्नक I: अंतर देशीय अनुभव

देश	पृष्ठभूमि	बैड बैंक का नाम	साल	संरचना	टिप्पणियाँ
स्वीडन	1991-92 में हाउसिंग बबल में अपस्फीति के परिणामस्वरूप व्यापक रूप से बैंक दिवालियापन हुआ।	नॉर्डबैंकन और गोटा के लिए सिक्यूरम	1992-1997	• सिक्यूरम ने एसईके 67 बिलियन (जीडीपी के 4 प्रतिशत से थोड़ा अधिक) की आस्ति नॉर्डबैंकन से एसईके 50 बिलियन और एसईके 45 बिलियन की गोटा से खरीदी, (बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति का 3 प्रतिशत)। • दबावग्रस्त आस्तियों की कीमत सलाहकारों और सरकारी परीक्षकों द्वारा, जहां तक संभव हो, निवल बाजार मूल्य के करीब निर्धारित की गई थी।	• पुनर्पूंजीकरण, सरकारी गारंटी, कुछ बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ एक बैड बैंक के निर्माण का मॉडल, बैंकिंग संकट को समाप्त करने में अत्यधिक सफल रहा। • संपूर्ण सिक्योरम अभ्यास की लागत करदाता एसईके 35 बिलियन है, जो प्रारंभिक अनुमानों से लगभग 15 बिलियन एसईके कम है, जो 1997 की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का 2.1 प्रतिशत था।
दक्षिण कोरिया	एशियाई संकट	कोरिया एसेट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन (केएएमसीओ)	1997	• केएएमसीओ एक केंद्रीकृत सार्वजनिक स्वामित्व वाली आस्ति प्रबंधन कंपनी है (1962 में स्थापित), कॉर्पोरेट पुनर्संरचना में भी शामिल है। • इसके प्रमुख शेयरधारक सरकार (42.8 प्रतिशत), कोरियाई विकास बैंक (28.6 प्रतिशत), और अन्य वित्तीय संस्थान (28.6 प्रतिशत) हैं। • केएएमसीओ ने 110 ट्रिलियन वॉन (लगभग US$92 बिलियन) के अंकित मूल्य के साथ 300,000 से अधिक एनपीएल खरीदे, जो वित्तीय क्षेत्र की आस्ति का 9 प्रतिशत या बैंकों और गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों से लगभग 20 प्रतिशत जीडीपी के तुल्य हैं।	• आधे ऋणों को वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वयं या तो संपार्श्विक बेचकर या ऋणों में मांग के आधार खरीदा गया था, जबकि कामको ने अन्य आधे को खरीदा था। • एनपीएल को कम करने में सफल लेकिन उच्च निवल लागत पर।
मलेशिया	एशियाई मुद्रा संकट	दानहर्ता	1998-2005	• दानहर्ता एक सार्वजनिक कंपनी थी, जिसका पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास था, जिसे वैधानिक समर्थन प्राप्त था। • दानहर्ता ने एमवाईआर 5 मिलियन से अधिक के एनपीएल का अधिग्रहण किया, जो कि छूट पर बैंकिंग प्रणाली के एनपीएल का लगभग 70 प्रतिशत है।	• आगे की हानि को सफलतापूर्वक रोक दिया, मार्च 2005 तक अपने सभी बांड चुका दिए, दिसंबर 2005 में सात साल बाद बंद हो गया। • संचयी आधार पर सरकार के लिए एक छोटा सा नुकसान हुआ।

(जारी)

देश	पृष्ठभूमि	बैड बैंक का नाम	साल	संरचना	टिप्पणियाँ
				• व्यवहार्य ऋण वाले उधारकर्ताओं को अपने ऋणों के पुनर्संरचना और पुनस्थापन की अनुमति दी गई थी, जबकि गैर-व्यवहार्य ऋणों की वसूली उधारकर्ता के व्यवसाय, संपत्ति या अंतर्निहित संपार्श्विक की बिक्री के माध्यम से की गई थी।	
चीन	इसके चार बड़े सरकारी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों से 1.4 ट्रिलियन आरएमबी के दबावग्रस्त ऋण प्राप्त करने के लिए एक-एक एएमसी का गठन किया गया था।	बिग फोर एएमसी (सिंडा, हुआरोंग, चाइना ओरिएंट और ग्रेट वॉल)	1999	• मूल प्रक्रिया के दौरान, सरकार ने एएमसी को क्रेडिट प्रदर्शन के आधार पर उचित मूल्य के बजाय अंकित मूल्य पर आस्ति खरीदने की आवश्यकता थी। • सरकार ने प्रत्येक एएमसी को 10 अरब आरएमबी (1.2 अरब अमेरिकी डॉलर) का प्रारंभिक इक्विटी पूंजी निवेश प्रदान किया। • बड़े चार बैंकों ने अपने एनपीएल को अपने संबंधित लिंक्ड लेकिन स्वतंत्र एएमसी में स्थानांतरित कर दिया।	• बैड बैंक, प्रारंभिक योजना के अनुसार बंद होने के बजाय, वित्तीय समूह में बदल गए, दलाली और अचल संपत्ति के संचालन और यहां तक कि अधिग्रहण के लिए उधार देने लगे।
आयरलैंड	आयरिश वित्तीय संकट और आयरिश आस्ति बबल	राष्ट्रीय संपत्ति प्रबंधन एजेंसी (नामा)	2009	• एनएएमए विधेयक उन छह वित्तीय संस्थानों पर लागू हुआ जो आयरिश सरकार की जमा गारंटी योजना के अंतर्गत आते थे। • एनएएमए ने आयरलैंड में योग्य वित्तीय संस्थानों की बहियों से आस्ति-समर्थित ऋणों की पहचान और मूल्य निर्धारण की व्यवस्था और पर्यवेक्षण किया, लेकिन इन ऋणों की खरीद और प्रबंधन एक एसपीवी के माध्यम से करवाया। • निजी रूप से वित्त पोषित एसपीवी ने वित्तीय संस्थानों से प्रतिभूतियां जारी करके आस्ति खरीदी, जिनमें से अधिकांश सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित थीं।	• सरकारी बांडों का उपयोग करके आस्ति खरीदी गई, जिससे आयरलैंड के सकल राष्ट्रीय ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

(जारी)

देश	पृष्ठभूमि	बैड बैंक का नाम	साल	संरचना	टिप्पणियाँ
जर्मनी	2008 का वैश्विक वित्तीय संकट	वेस्ट एलबी के लिए मोचन संस्थान	2009	• बैंक को वेस्टएलबी से पूंजी में तीन अरब यूरो और पोर्टफोलियो से संभावित नुकसान को कवर करने के लिए शेयरधारकों से एक अरब यूरो की गारंटी मिली। • नॉर्थ राइन-वेस्टफेलिया के बचत और ऋण संस्थानों ने एक अरब यूरो की गारंटी प्रदान की, जबकि बर्लिन ने चार अरब यूरो तक की गारंटी दी।	• वेस्टएलबी को तीन भागों में विभाजित किया गया था, जिनमें से एक बैड बैंक था, Erste Abwicklungsanstalt (EAA), जो 2011 के अंत तक लगभग 51 बिलियन यूरो की दबावग्रस्त आस्ति को मोचित कर रहा था। ईएए को वेस्टएलबी के अंतिम विश्लेषण से लगभग 100 बिलियन यूरो की अतिरिक्त संपत्ति को मोचित करने का भी काम सौंपा गया था।
यूनाइटेड किंगडम	2008 का वैश्विक वित्तीय संकट	यूके आस्ति समाधान (यूकेएआर)	2010	• एनआरएएम लिमिटेड और ब्रैडफोर्ड एंड बिंगले पीएलसी (बीएंडबी) के सरकारी स्वामित्व वाले व्यवसायों को व्यवस्थित रूप से बंद करने की सुविधा के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें यूके सरकार द्वारा प्रबंधित इसकी सहायक बंधक एक्सप्रेस शामिल है • एचएम ट्रेजरी की ओर से निवेश (यूकेजीआई)।	• फरवरी 2021 में अपनी अंतिम आस्तियों को बेच दिया।
स्पेन	एक अचल संपत्ति बबल के फटने के साथ प्रणालीगत वित्तीय संकट के कारण गठित।	सारेब	2012	• निजी शेयरधारकों के पास एसएआरईबी का 55 प्रतिशत हिस्सा है और शेष 45 प्रतिशत फंड फॉर ऑर्डरली बैंक रिस्ट्रक्चरिंग (एफओबीआर) के पास है। • इसे यूरोपीय संघ से धन प्राप्त हुआ 1) यूरोपीय बेलआउट फंड से एफओबीआर में पूंजी इंजेक्शन और 2) ईसीबी द्वारा कथित रूप से बिगड़ा संपत्ति के भुगतान के रूप में जारी किए गए बांड की स्वीकृति। • सरेब सरकारी बांडों के बदले में स्पेनिश बैंकों से आस्ति विकास ऋण प्राप्त करके कार्य करता है। आस्ति मूल्य निर्धारण के लिए स्पेनिश केंद्रीय बैंक जिम्मेदार है।	• सरेब का लक्ष्य अपने 15 साल के जीवन में 15 प्रतिशत का लाभ कमाना है। • हालांकि, एसएआरईबी संघर्ष कर रहा है, क्योंकि स्पेनिश अचल संपत्ति की कीमतों में गिरावट ने ऋणों के मूल्य को कम कर दिया है और उन्हें उस समय पर्याप्त छूट पर खरीदने के बावजूद पुरोबंधित संपत्तियां ले लीं।

स्रोत: संदर्भित शोध पत्रों के आधार पर।

*भारतीय विनिर्माताओं के रुख पर कोविड-19 का प्रभाव**

यह आलेख 2019-21 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के लिए किए गए औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण (आईओएस) के प्रमुख निष्कर्षों को सूचीबद्ध करता है। उत्तरदाताओं के रुख से पता चलता है कि वृद्धि संवेग में मंदी मुख्य रूप से 2017-18 से शुरू होने वाले लगातार तीन वर्षों तक मांग के कमजोर होने के कारण थी। जैसे ही विनिर्माताओं का दृष्टिकोण प्रबल होने लगा, कोविड-19-प्रेरित लॉकडाउन उपायों ने पुनरुद्धार प्रक्रिया को मंद कर दिया। महामारी ने सर्वेक्षण मापदंडों को ऐतिहासिक निम्न स्तर पर लाकर उत्पादकों के रुख को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। पूर्व की तुलना में जबकि दूसरी लहर का प्रभाव कमतर रहा है और विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समष्टि मापदंड शीघ्र ही कोविड-पूर्व अपने स्तरों को प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें अपने दीर्घकालिक प्रवृत्ति स्तरों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है।

भूमिका

2020 की शुरुआत में कोविड-19 महामारी लाखों लोगों को संक्रमित करते हुए खतरनाक गति से प्रसारित हुई और इसने आर्थिक गतिविधियों को लगभग ठप कर दिया। आर्थिक क्षति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी और यह दशकों में दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक आघात साबित हुआ। इसने नीति निर्माताओं के समक्ष कठिन चुनौतियां रखीं। चूंकि भविष्योन्मुखी सर्वेक्षण नीतिगत निर्णयों का समर्थन करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, इनका उपयोग अधिकांश केंद्रीय बैंकों द्वारा उद्यमों के रुख को भांपने के लिए किया जाता था। सर्वेक्षणों ने महामारी के प्रभाव के साथ-साथ उद्यमों द्वारा प्रत्याशित वसूली प्रक्रिया के समय और गति का मूल्यांकन करने में सहायता की।

रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण (आईओएस) मौद्रिक नीति निर्णय का समर्थन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक दूरंदेशी सर्वेक्षण की भूमिका में आईओएस, विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न उद्यमों के रुख को भांपता है। धारणा में वर्तमान तिमाही का मूल्यांकन और अगली तिमाही के लिए प्रत्याशाएं शामिल हैं। 2020 की शुरुआत में कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर, अन्य क्षेत्रों के साथ, विनिर्माण उद्योग भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। पहली लहर का सामना करने के बाद, अर्थव्यवस्था ने 2020-21 की तीसरी तिमाही से समुत्थान (रिकवरी) के कुछ संकेत दिखाए। हालांकि महामारी की दूसरी लहर ने आर्थिक स्थिति को पुनः खराब कर दिया, विनिर्माण क्षेत्र तेजी से पटरी पर आ गया। हालांकि दिसंबर 2021 के अंत में महामारी के ओमीक्रॉन प्रकार के अचानक बढ़ने से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुईं, लेकिन प्रभाव के बहुत कम होने की संभावना है।

इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान आलेख का उद्देश्य 2019 के बाद से किए गए सर्वेक्षण के विभिन्न दौरों से उत्पन्न होने वाले शोधपरक तथ्यों का निष्कर्ष निकालना है। साथ ही, विनिर्माताओं द्वारा कथित रिकवरी प्रक्रिया पर दृष्टिकोण भी इस आलेख में प्रस्तुत किया गया है। इस दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा सर्वेक्षण के कुल 11 दौर आयोजित किए गए *यानी* दौर 86 (अप्रैल-जून 2019) से लेकर दौर 96 (अक्टूबर-दिसंबर 2021) तक।

यह आलेख सर्वेक्षण दृष्टिकोण से उपलब्ध जानकारी के आधार पर विशिष्ट अनुमानित परिदृश्यों के तहत एक विश्लेषणात्मक ढांचे का उपयोग करके विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रमुख समष्टि आर्थिक चरों, *यथा* औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) और योजित सकल मूल्य (जीवीए) का रिकवरी पथ तैयार करने का भी प्रयास करता है।

शेष आलेख चार खंडों में प्रस्तुत किया गया है। खंड II में, विनिर्माण इकाइयों के अंतर्निहित रुख को प्रस्तुत किया गया है। खंड III, जैसा कि विनिर्माताओं द्वारा माना जाता है, महामारी के आघात के बाद प्रत्याशित रिकवरी प्रक्रिया पर केंद्रित है। खंड IV एक विश्लेषणात्मक ढांचे का उपयोग करके समष्टि चरों के साथ-

* यह आलेख निवेदिता बनर्जी और एस. मजूमदार, उद्यम सर्वेक्षण विभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) द्वारा तैयार किया गया है। आलेख में व्यक्त विचार केवल लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों। सर्वेक्षण डेटा का नवीनतम दौर 10 फरवरी, 2022 को आरबीआई की वेबसाइट *https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=21001* पर जारी किया गया था। पिछला आलेख आरबीआई बुलेटिन के फरवरी 2020 अंक में प्रकाशित हुआ था और इसे *https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=18765* पर देखा जा सकता है।

साथ बाद की रिकवरी पर महामारी के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास करता है और खंड V कुछ नीतिगत निहितार्थों के साथ समाप्त होता है।

II: शोधपरक तथ्य 2019-21

II.1 नमूना फ्रेम, सर्वेक्षण प्रश्नावली और सर्वेक्षण पद्धति

सर्वेक्षण प्रश्नावली[1] को विनिर्माण कंपनियों के एक पैनल के पास भेजा जाता है, जो नई कंपनियों को जोड़ने और बंद/ विलय की गई कंपनियों को हटाने के साथ आवधिक संशोधन से गुजरता है। सर्वेक्षण वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों या विनिर्माण इकाइयों के वित्त प्रमुखों से गुणात्मक प्रतिक्रिया चाहता है। प्रश्नावली को पांच ब्लॉकों में संरचित किया गया है जिसमें प्रतिवादी कंपनियों के बारे में सामान्य जानकारी शामिल है; बिक्री के क्रम में उत्पाद विवरण; कतिपय निष्पादन संकेतकों के आकार की जानकारी; और वर्तमान तिमाही के लिए मूल्यांकन और अगली तिमाही के लिए प्रत्याशाएं। लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अनिश्चितता के कारण, प्रत्याशित रिकवरी प्रक्रिया पर उद्यमों का दृष्टिकोण भांपने के लिए आगामी दो और तीन तिमाहियों के लिए प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए अप्रैल-जून 2020 तिमाही से एक अतिरिक्त ब्लॉक शामिल किया गया था। प्रतिक्रियाओं को तीन-बिंदु स्केल पर एकत्र किया जाता है, *अर्थात* वृद्धि, कोई परिवर्तन नहीं और कमी और सर्वेक्षण परिणामों को सारांशित करने के लिए एकल मात्रात्मक माप *अर्थात* निवल प्रतिक्रिया (एनआर)[2] में परिवर्तित किया जाता है। निर्माण के द्वारा, एनआर का मान -100 से +100 के मध्य हो सकता है, जहां एक ऋणात्मक मान संकुचन/ निराशावाद का प्रतिनिधित्व करता है और एक सकारात्मक एनआर विकास/ आशावाद को दर्शाता है।

II.2 2019-21 के दौरान प्रमुख निष्कर्ष

सर्वेक्षण के परिणाम 'मांग शर्तों', 'वित्तपोषण की स्थिति', 'मूल्य की स्थिति' और 'समग्र व्यावसायिक स्थिति' पर कंपनियों के मूल्यांकन (ए) और प्रत्याशाओं (ई) के संदर्भ में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस आलेख में, आकलन तिमाही के लिए निवल प्रतिक्रियाओं (एनआर) को मूल्यांकन एनआर (एनआरए) की संज्ञा सी गई है और प्रत्याशा तिमाही के लिए एनआर को प्रत्याशा एनआर (एनआरई) के रूप में वर्णित किया गया है।

ए. मांग की शर्तें

उत्पादन (पीआर), क्रयादेश पुस्तक (ओबी), क्षमता उपयोग (सीयू), कच्चे माल की सूची (आईआरएम), निर्यात (ईएक्सपी), आयात (आईएमपी) और रोजगार (ईएमपी) के माध्यम से मांग की स्थिति पर रुख में गिरावट आयी है। पिछली तिमाहियों की तुलना में 2019-20 की दूसरी और तीसरी तिमाही में एनआर आकलन कम थे। हालाँकि, मांग के बढ़ने के साथ 2019-20 की चौथी तिमाही में सुधार के कुछ संकेत दिखे। मार्च 2020 में मौद्रिक नीति समिति के संकल्प में यह भी उल्लेख किया गया है कि जनवरी 2020 में विनिर्माण में तेजी ने पिछले पांच महीनों में संकुचन के बाद औद्योगिक उत्पादन में सकारात्मक प्रभाव आया। लेकिन कोविड-जन्य लॉकडाउन ने आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और एनआर को 2020-21 की पहली तिमाही में ऐतिहासिक निम्न स्तर पर ला दिया।

चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन में ढील दिए जाने से मांग में तेजी देखी गई, जिसका संकेत सर्वेक्षण मापदंडों में ऊर्ध्वगामी वृद्धि से मिलता है। 2020-21 की पहली तिमाही में भारी गिरावट के बाद विनिर्माताओं के रुख में सुधार होने लगा। लेकिन महामारी की दूसरी लहर के कारण 2021-22 की पहली तिमाही में मांग की स्थिति फिर से खराब हो गई, लेकिन इससे उत्पादन में तुलनात्मक रूप से निम्नतर कमी आयी, जो वास्तव में 2021-22 की दूसरी तिमाही में तेजी से उलट गई।

[1] प्रश्नावली को लिंक पर देखा जा सकता है: *https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewForms.aspx?FCId=40*

[2] यदि आई, एन और डी किसी विशेष मापदंड पर प्रश्न के उत्तर के लिए क्रमशः 'वृद्धि', 'नो चेंज' और 'कमी' के अनुपात के अनुरूप हैं, तो एनआर की गणना एनआर=100*(आईडी) के रूप में की जाती है और नो चेंज (एनसी) या यथास्थिति को एनसी=100*एन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आमतौर पर एनआर की गणना आशावादी प्रतिक्रियाओं के अनुपात में निराशावादी प्रतिक्रियाओं के अनुपात को घटाकर की जाती है; लागत संबंधी मापदंडों को छोड़कर, सभी मापदंडों के लिए एक आशावादी प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि पर विचार करना; जैसे कच्चे माल की लागत, वित्त की लागत आदि, जहां, कमी का विकल्प प्रतिवादी कंपनी के दृष्टिकोण से आशावाद को दर्शाता है। हालांकि, इस आलेख में सभी मापदंडों के लिए एनआर की गणना 100* (आईडी) के रूप में की गई है, ताकि एकरूपता बनाए रखी जा सके और समष्टि चरों के साथ सीधे लिंक किया जा सके।

मूल्यांकन तिमाही (एनआरए_पीआर) और प्रत्याशा तिमाही (एनआरई_पीआर) के लिए उत्पादन पर दोनों एनआर ने अध्ययन की अवधि के दौरान विनिर्माण में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपीएम) के तिमाही-दर-तिमाही (क्यू-ओ-क्यू) अभियान को व्यापक रूप से ट्रैक किया। हालाँकि, एनआरए_पीआर, एनआरई_पीआर से कोविड संबंधित लॉकडाउन की गंभीरता को बेहतर तरीके से दर्शाता है, क्योंकि विनिर्माता महामारी की पहली और दूसरी लहर की अचानक शुरुआत के कारण मांग में गिरावट का अनुमान नहीं लगा सके (चार्ट 1ए)। एनसीए_पीआर और एनसीई_पीआर द्वारा मापी गई प्रतिक्रियाओं में नो चेंज (एनसी) का अनुपात, जो अध्ययन अवधि के दौरान लगभग 50 प्रतिशत था, उसमें महामारी के दौरान तेज गिरावट देखी गई। उत्पादन पर विनिर्माताओं की धारणा इस सर्वेक्षण में शामिल अन्य मांग मापदंडों से भी परिलक्षित होती है, जैसे मूल्यांकन (एनआरए_ओबी) और अपेक्षाओं (एनआरई_ओबी), दोनों के संदर्भ में क्रयादेश पुस्तक (चार्ट 1बी)। हालांकि आकलन एनआर 2020-

चार्ट 1: मांग के मापदंड

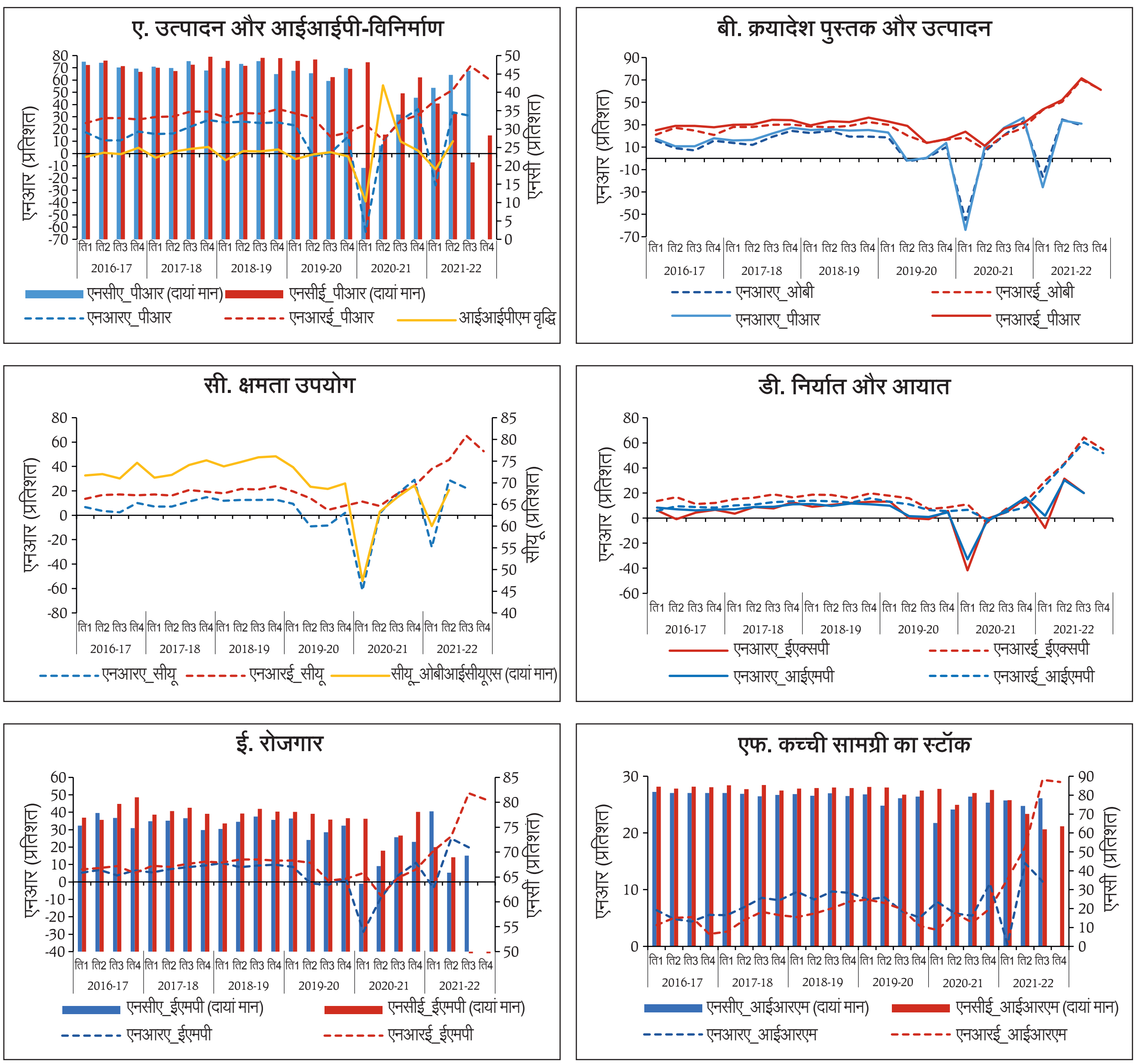

स्रोत: आरबीआई, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ)

21 की पहली तिमाही में अचानक लॉकडाउन के कारण (-) 50 प्रतिशत से नीचे पहुंच गया, वहीं दूसरी लहर में प्रभाव बहुत कम था। तथापि, अध्ययनाधीन अवधि के दौरान प्रत्याशा एनआर सकारात्मक बना रहा।

क्षमता उपयोग (सीयू), आईओएस में सम्मिलित एक वैकल्पिक मांग मापदंड है जिसे एक विनिर्माण कंपनी द्वारा अपनी स्थापित क्षमता के लिए उपयोग की जाने वाली वास्तविक क्षमता के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। सीयू (क्रमशः एनआरए_सीयू और एनआरई_सीयू) के लिए मूल्यांकन और प्रत्याशा एनआर, जैसा कि आईओएस में कैप्चर किया गया है, ने सीयू के संचलन में एक प्रारंभिक संकेत प्रदान किया, जिसका बाद में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए एक अन्य सर्वेक्षण के आधार पर अनुमान लगाया गया था, *यथा* क्रयादेश पुस्तक, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोगिता सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस)[3] जो विनिर्माण सीयू पर वास्तविक मात्रात्मक जानकारी एकत्र करता है। कोविड-19 अवधि के दौरान जब अर्थव्यवस्था ने एक अभूतपूर्व मांग आघात का अनुभव किया, तब एनआरए_सीयू ने भी वास्तविक सीयू (सीयू_ओबीआईसीयूएस) को बेहतर तरीके से ट्रैक किया (चार्ट 1सी)। 2020-21 की पहली तिमाही में तीव्र गिरावट देखने के बाद, निर्यात और आयात पर उत्तरदाताओं के रुख ठीक होने लगे, जिनमें महामारी की दूसरी लहर के दौरान 2021-22 की पहली तिमाही में फिर से कमी आयी। यह भी स्पष्ट है कि मांग की स्थिति मजबूत होने के साथ, वर्ष 2020-21 के दूसरे अर्धांश के बाद से निर्यात और आयात पर प्रत्याशाओं में काफी सुधार हुआ है।

नो चेंज दर्शाने वाला उत्तरदाताओं का अनुपात (एनसीए_ईएमपी और एनसीई_ईएमपी दोनों) आमतौर पर मंद रोजगार मापदंड[4] पर प्रतिक्रियाओं पर हावी है। हालांकि पिछले एक साल में धीरे-धीरे गिरावट के बाद 2019-20 की चौथी तिमाही में नौकरी का परिदृश्य ठीक होने लगा, लेकिन यह महामारी के कारण 2020-21 की पहली तिमाही में ढह गया। महामारी के कम प्रभाव के साथ बाद की तिमाहियों में आशावाद सुदृढ़ होना शुरू हुआ (चार्ट 1ई), लेकिन दूसरी लहर के दौरान एक और आघात लगा। आईआरएम को एक और धीमी गति से चलने वाला मांग मापदंड माना जाता है क्योंकि कंपनियां आईआरएम के एक निश्चित स्तर को बनाए रखने का लक्ष्य रखती हैं, सिवाय इसके कि जब मांग या कीमत में बड़े बदलाव की आशंका हो। आईआरएम पर प्रतिक्रियाओं पर एनसी का वर्चस्व है जो अध्ययन की अवधि के दौरान लगभग 80 प्रतिशत रहा, लेकिन पिछले डेढ़ साल में महामारी से रुख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा (चार्ट 1एफ)।

बी. वित्तीय स्थितियां

अच्छी वित्तीय स्थितियां कंपनियों को अपने कारोबार को मजबूत बनाने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। उत्तरदाताओं ने 2019-20 की दूसरी तिमाही को छोड़कर कोविड-पूर्व अवधि में समग्र वित्तीय स्थिति (ओएफएस) पर सकारात्मक भावनाएं व्यक्त कीं। 2019-20 की तीसरी तिमाही के लिए रुख भी सकारात्मक, लेकिन बहुत कम थे। हालांकि 2020-21 की पहली तिमाही में विनिर्माताओं के रुख में गिरावट आयी, लेकिन कारोबारी माहौल को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा घोषित कई राहत उपायों से इसे तुरंत बढ़ावा मिला (चार्ट 2ए)। हालांकि, दूसरी लहर ने फिर से विनिर्माताओं के रुख को धूमिल कर दिया। बाह्य वित्त की लागत (सीओएफ) ने 2019-20 के बाद से कुछ राहत दिखाना शुरू कर दिया है, जो विनिर्माताओं के लिए अपने कारोबार को चलाने के लिए बेहतर रास्ते को दर्शाता है, जो कि 2020-21 की चतुर्थ तिमाही के बाद से फिर से बढ़ना शुरू हो गया (चार्ट 2बी)।

सी. कीमत की स्थिति

कीमत की स्थिति का आकलन आईओएस में एकत्रित कच्चे माल की लागत (सीआरएम), वेतन व्यय और उद्यमों के बिक्री मूल्य (एसपी) जैसे मापदंडों के आधार पर किया जाता है। यह मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान निविष्टि लागत दबाव और बाजार की अनिश्चितता के तहत कंपनियों की लाभप्रदता तय करने के लिए वित्तीय स्थिति के साथ मांग की स्थिति को कारोबार में कैसे सम्मिलित किया जाता है।

सीआरएम, जो औद्योगिक कच्चे माल[5] की डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में गति को भांपता है, 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान विनिर्माताओं के लिए एक स्थायी चिंता का विषय बना रहा और उसके बाद इसमें कमी आयी। फिर भी, आपूर्ति श्रृंखला

[3] ओबीआईसीयूएस डेटा आरबीआई की वेबसाइट पर त्रैमासिक रूप से जारी किया जाता है और इस तरह के नवीनतम डेटा को लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है: *https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=21000*

[4] रोज़गार मापदंड में अनियत मजदूरों सहित पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों तरह के कर्मचारी शामिल हैं।

[5] डब्ल्यूपीआई से विशिष्ट मदों को शामिल करता है जिनका कुल भार 18.1 प्रतिशत है।

चार्ट 2: वित्तीय स्थिति

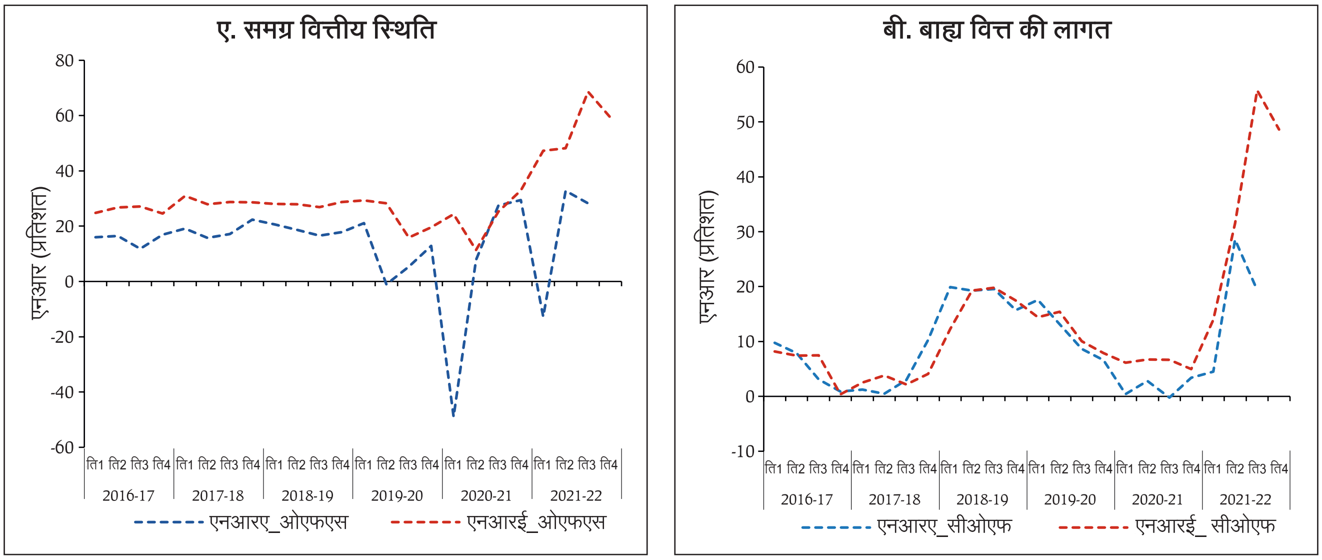

स्रोत: आरबीआई।

व्यवधान और परिवहन विलंब के कारण 2020-21 की दूसरी तिमाही में लागत में पुनः बढ़ोतरी हुई (चार्ट 3ए)। परिणामस्वरूप, 2020-21 की दूसरी तिमाही से बिक्री कीमत में भी वृद्धि होने लगी, जिससे उपभोक्ताओं पर लागत का दबाव बढ़ गया (चार्ट 3बी)। यद्यपि अध्ययनाधीन पूरी अवधि के दौरान विनिर्मित उत्पादों (भार: 64.2 प्रतिशत) में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के साथ बिक्री कीमत में वृद्धि हुई, 2020-21 की शुरुआत में थोक मुद्रास्फीति में अभूतपूर्व आपूर्ति आघात ने सर्वेक्षण रुख को वास्तव में दर्शाए गए संचलन की तुलना में बहुत अधिक प्रभावित किया। 2019-20 की तीसरी तिमाही के बाद से लगातार निविष्टि लागत दबावों के कारण लाभ मार्जिन[6] (एनआरई_पीएम) पर दृष्टिकोण निष्क्रिय बना रहा, जिसमें 2021-22 की पहली तिमाही में सकारात्मकता आयी (चार्ट 3सी)।

डी. समग्र कारोबारी स्थिति

समग्र कारोबारी स्थिति (ओबीएस) के लिए एनसी प्रतिक्रिया, जो 2019-20 तक लगभग 50 प्रतिशत रही, वस्तुतः 2020-21 में काफी कम हो गई क्योंकि महामारी के कारण धारणा बदल गई, जैसा कि 2020-21 की पहली तिमाही में एनआर में 60 प्रतिशत नकारात्मक रूखों से संकेत मिलता है। यह अभिमत तदनंदर तिमाहियों में मजबूत होने लगा, जो 2021-22 की पहली तिमाही में दूसरी लहर के दौरान फिर से निष्क्रिय हो गया (चार्ट 4ए)। विभिन्न सर्वेक्षण मापदंडों के लिए गणना किए गए एनआर के आधार पर, कारोबार मूल्यांकन (बीएआई) और प्रत्याशाएं (बीईआई) के लिए एक समग्र सूचकांक की गणना अलग से की जाती है[7]। 2019-20 की दूसरी और तीसरी तिमाही में बीएआई संकुचन क्षेत्र में रहा क्योंकि अधिकांश मांग मापदंड अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत दे रहे थे। सारांश सूचकांक में सुधार होना शुरू हुआ और 2019-20 की चतुर्थ तिमाही में विस्तार क्षेत्र में प्रवेश किया। हालाँकि, कोविड संबंधी लॉकडाउन ने 2020-21 की पहली तिमाही में बीएआई को ऐतिहासिक रूप से सबसे कम मूल्य 56.5 प्रतिशत (2008-09 की चतुर्थ तिमाही में वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के दौरान दूसरा सबसे कम मूल्य 82.6 प्रतिशत के रूप में) पर नीचे ला दिया। बीईआई में भी 2020-21 की दूसरी तिमाही में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आयी, हालांकि यह विस्तार क्षेत्र में बना रहा। हालाँकि, बीएआई और बीईआई दोनों में, 2020-21 की तीसरी तिमाही में तुरंत सुधार हुआ और बाद की

---

6 निवल बिक्री के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ के रूप में परिभाषित।

7 बीएआई और बीईआई समग्र संकेतक हैं जिनकी गणना क्रमशः मूल्यांकन और प्रत्याशा के लिए नौ कारोबारी मापदंडों के साधारण औसत के रूप में की जाती है, जहां प्रत्येक मापदंड को भारित निवल प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त किया जाता है, भार सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में उद्योग समूहों का हिस्सा होता है। जिन नौ मापदंडों पर विचार किया गया है, वे हैं: (1) समग्र व्यावसायिक स्थिति; (2) उत्पादन; (3) क्रयादेश पुस्तक; (4) कच्चे माल की सूची; (5) तैयार माल की सूची; (6) लाभ मार्जिन; (7) रोजगार; (8) निर्यात; और (9) क्षमता उपयोग। निर्माण के हिसाब से, सूचकांक 0 से 200 के बीच होते हैं, जिसमें 100 अंक विस्तार (>100) को संकुचन (<100) से अलग करते हैं।

चार्ट 3: कीमत की स्थिति

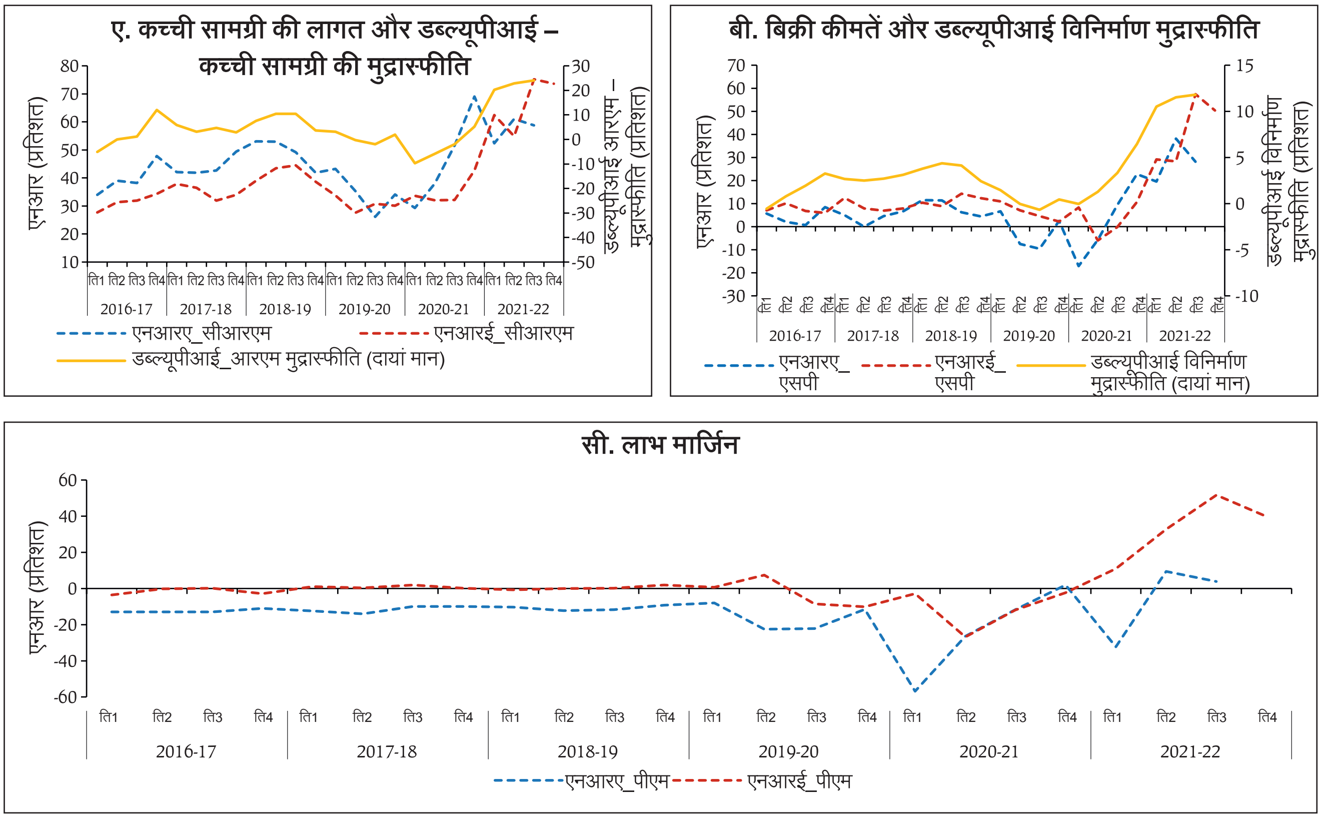

स्रोत: आरबीआई, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

तिमाहियों में ये और भी सुदृढ़ हुए। हालांकि, दूसरी लहर के मद्देनजर, 2021-22 की पहली तिमाही में बीएआई में फिर से संकुचन हुआ, इसने अगली तिमाही में शीघ्र रिकवरी की। बीईआई का विस्तार जारी रहा (चार्ट 4बी)।

चार्ट 4: समग्र कारोबार स्थिति

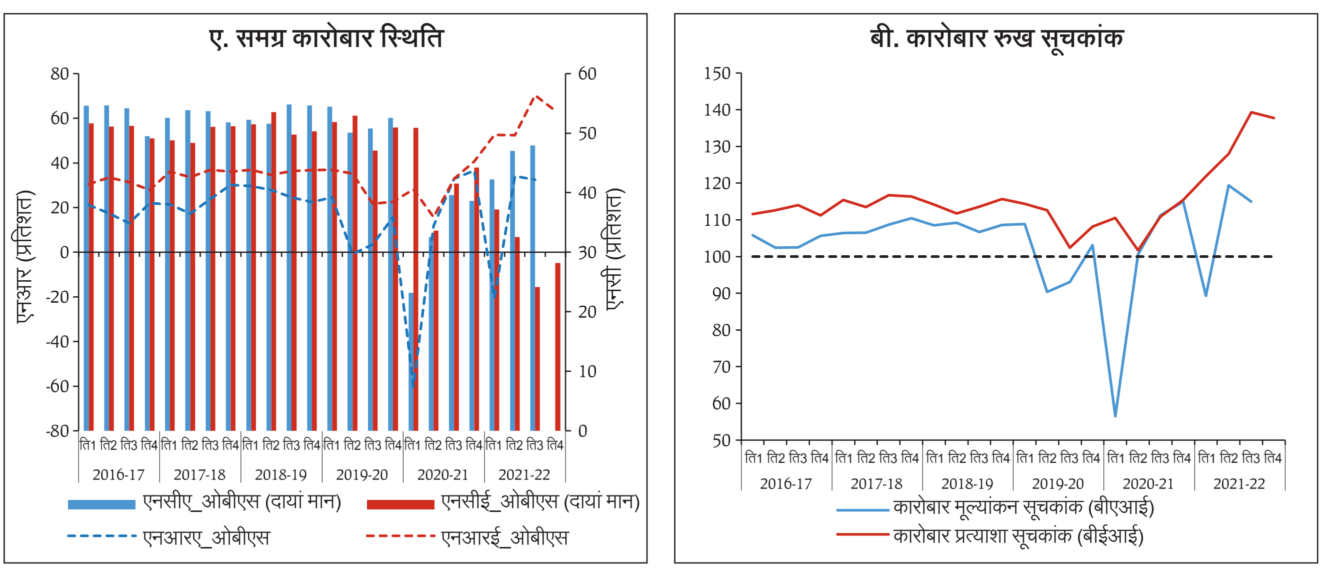

स्रोत: आरबीआई

III: कोविड के बाद रिकवरी प्रक्रिया पर निर्माताओं की धारणा

चूंकि दुनिया भर में अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं कोविड-19 के प्रकोप से गंभीर रूप से प्रभावित थीं, इसलिए अधिकांश केंद्रीय बैंकों ने उनके द्वारा किए गए परिदृश्य सर्वेक्षणों के प्रतिक्रिया स्वरूप पर इसके प्रभाव और उसके बाद प्रत्याशित समुत्थान प्रक्रिया का अध्ययन करना महत्वपूर्ण समझा।

III.1 बहुराष्ट्रीय क्षेत्र-पार अनुभव

चूंकि दूरंदेशी सर्वेक्षण नीतिगत निर्णयों का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं[8] ने इन सर्वेक्षणों का उपयोग कोविड-19 प्रभाव पर उद्यमों के दृष्टिकोण को भांपने के लिए लिखतों के रूप में किया। फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा 2 से 10 मार्च, 2020 के दौरान आयोजित किए गए एडहॉक सर्वेक्षण में केवल कुछ विशिष्ट प्रश्नों ने विनिर्माण और साथ ही सेवा फर्मों के रुख में गिरावट का संकेत दिया। न्यूयॉर्क के फेडरल रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग सर्वे के मार्च दौर ने न्यूयॉर्क राज्य में कारोबार गतिविधि में गिरावट का संकेत दिया। इसके अलावा, छह महीने के दृष्टिकोण के बारे में आशावाद में भी तेजी से कमी आयी, फर्में 2009 के बाद जितनी आशावादी थीं, अब उस से कम थीं। इस प्रभाव को बेहतर तरीके से भांपने के लिए, मार्च 2020 के एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग सर्वे और बिजनेस लीडर्स सर्वे में पूरक प्रश्न शामिल किए गए थे, जो कारोबार के विभिन्न पहलुओं पर नोवेल कोरोना वायरस के देखे गए प्रभावों पर केंद्रित थे।

कोविड-19 के दुष्प्रभाव और प्रत्याशित समुत्थान पथ को समझने के लिए, कन्सास राज्य एफईडी ने 2020 में विनिर्माण पर अपने मासिक सर्वेक्षण में विशिष्ट प्रासंगिक प्रश्नों को शामिल किया। बैंक ऑफ कनाडा ने 2020 में अपने कारोबार परिदृश्य सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में, आर्थिक प्रभावों और महामारी के बाद की रिकवरी को बेहतर ढंग से समझने के लिए कनाडाई व्यवसायों और संघों के लघु और लक्षित खंड से सलाह भी ली। फेड रिज़र्व फिलाडेल्फिया के मासिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आउटलुक सर्वे ने अपने अक्टूबर 2020 के सर्वेक्षण दौर में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वर्तमान क्षमता उपयोग दरों पर विशेष प्रश्न पूछे। विनिर्माताओं से आर्थिक नीति अनिश्चितता के प्रभाव और अगले वर्ष के लिए उनकी कुल पूंजीगत व्यय योजनाओं पर कोविड-19 के प्रभावों के बारे में भी पूछा गया। फर्मों की वर्तमान क्षमता उपयोग के बारे में विशेष प्रश्न महामारी के बड़े प्रभाव को दर्शाते हैं, जहां अधिकांश फर्मों ने एक साल पहले की तुलना में काफी निम्नतर स्तर की क्षमता पर काम करने की सूचना दी थी।

III.2 भारतीय संदर्भ

चूंकि सामान्य सर्वेक्षण, लॉकडाउन लागू होने से बहुत पहले आयोजित किए गए थे, उत्तरदाताओं ने पहले से संकुचन का अनुमान नहीं लगाया था क्योंकि वे महामारी की गंभीर और अचानक प्रकृति के पूर्ण प्रभाव को नहीं देख नहीं पाये, जो बाद में देखी गई थी[9]। इसलिए 2019-20 की चौथी तिमाही में जब भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ने लगे, 18-20 मार्च 2020 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों पर एक त्वरित सर्वेक्षण आयोजित किया गया[10]। त्वरित सर्वेक्षण ने गंभीर निराशावादी रुख का संकेत दिया। आगे, इसके अलावा, सामान्य प्रश्नावली के माध्यम से भविष्य की उम्मीदों को भांपने के लिए, 2020-21 की पहली तिमाही के बाद से दो और तिमाहियों के लिए महत्वपूर्ण मापदंडों पर कॉर्पोरेट क्षेत्र के व्यावसायिक दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए एक ब्लॉक पेश किया गया था।

सर्वेक्षण के परिणामों ने कंपनियों के रुख में शुरुआती दृढ़ता के संकेत दिये, जो आमतौर पर भविष्य के बारे में आशावादी रहती हैं। उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदलने से पहले प्रतीक्षा करके पता लगाना चाहा। लेकिन जैसे-जैसे प्रतिकूल स्थिति का समय बढ़ता गया, रुख काफी प्रभावित हुआ। अत्यधिक अनिश्चित समय के दौरान नीतिगत निर्णय लेने के लिए ऐसी सभी अतिरिक्त जानकारी उपयोगी थी। अतिरिक्त ब्लॉक के सर्वेक्षण के परिणाम भी रिज़र्व

[8] विवरण संदर्भ सूची में प्रस्तुत किए गए हैं।

[9] जनवरी-मार्च 2020 सर्वेक्षण का सामान्य दौर 30 जनवरी 2020 को शुरू किया गया था और परिणाम 18 मार्च, 2020 तक प्राप्त आंकड़ों के साथ संकलित किए गए थे।

[10] परिणाम भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर लिंक में उपलब्ध हैं: *https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=19437*

बैंक द्वारा अप्रैल 2020 से अपने तिमाही डेटा रिलीज़ में प्रसारित किए गए थे।

दो अतिरिक्त तिमाहियों को शामिल करते हुए, 2020-21 के बाद से सर्वेक्षण दौर[11] में कुल तीन प्रत्याशा तिमाहियों को शामिल किया गया था। इसलिए कुछ सामान्य तिमाहियों के लिए, विभिन्न सर्वेक्षण दौरों के माध्यम से प्रत्याशा लगाई जाती है। अतिरिक्त ब्लॉक में मांग पक्ष से शामिल मापदंडों में पीआर, ओबी, सीयू और रोजगार, मूल्य गतिशीलता पर सीआरएम और एसपी और ओबीएस शामिल हैं।

मांग की स्थिति

सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित विभिन्न प्रोत्साहन पैकेजों और उपायों के कारण विनिर्माताओं का व्यावसायिक विश्वास कुछ हद तक सामान्य हो गया है। हालांकि, पहली लहर के बाद प्रत्याशाएं मजबूत होने लगीं, दूसरी लहर के कारण रुख पर फिर से बादल छा गए, हालांकि यह शीघ्र प्रत्यावर्तित हो गई (चार्ट 5ए और 5बी)[12]। सीयू और रोजगार के लिए समान पैटर्न देखा गया (चार्ट 5सी और 5डी)। कारखाने के स्तर पर सामाजिक दूरी और परिवहन के मुद्दों के कारण नौकरी के परिदृश्य में धीमी गति से

चार्ट 5: समुत्थान प्रक्रिया संबंधी रुख: मांग मापदंड

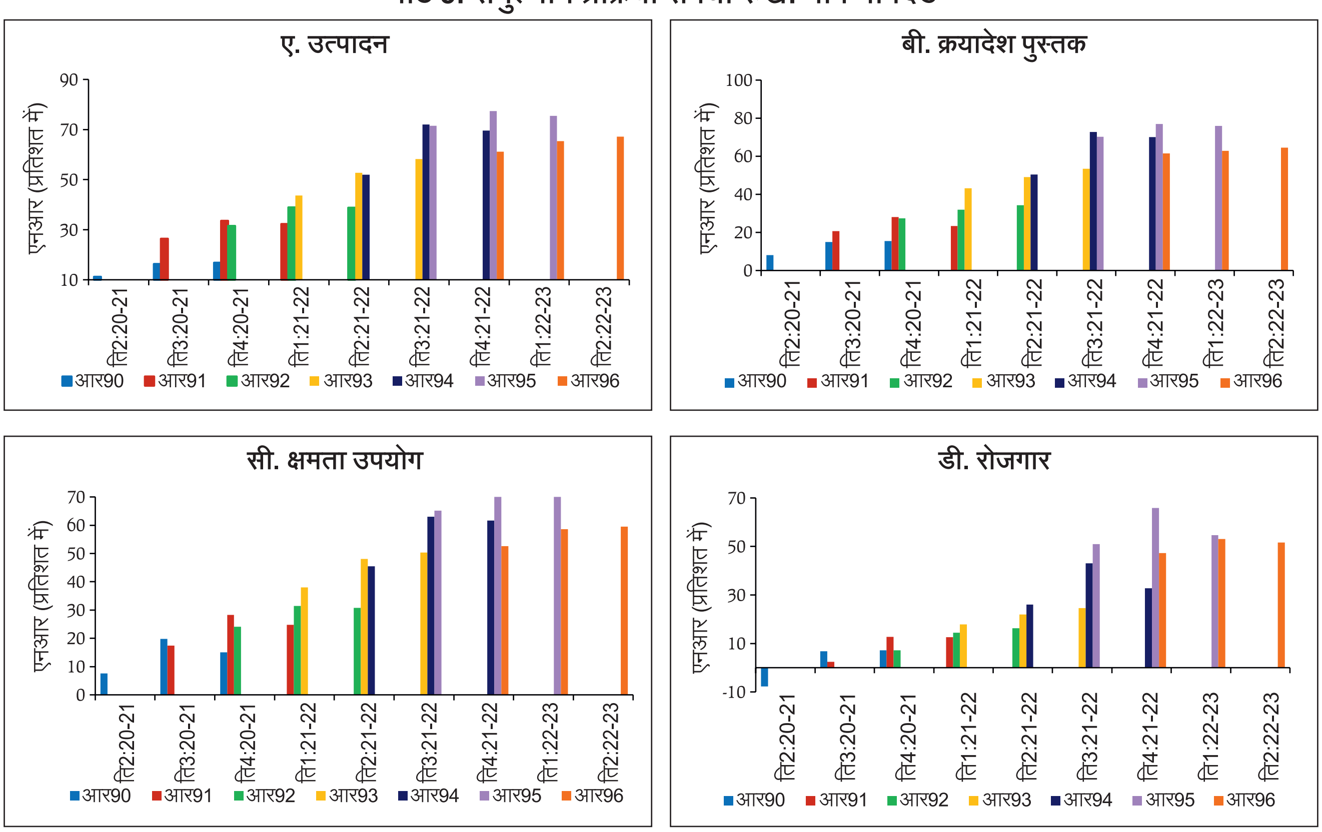

स्रोत: आरबीआई।

[11] ति1:2020-21 से ति3:2021-22 के दौरान किए गए सर्वेक्षण आईओएस के 90-96 दौर के अनुरूप हैं। इन्हें क्रमशः आर90, आर91, आर92, आर93, आर94, आर95 और आर96 के रूप में दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए, अप्रैल-जून 2020 दौर के सर्वेक्षण (आर90) में, ति1: 2020-21 के आकलन के साथ, उत्तरदाताओं ने ति2-ति4: 2020-21 के लिए अपनी प्रत्याशा से अवगत कराया।

[12] चार्ट 5 से 7 केवल प्रत्याशाओं को दर्शाते हैं।

चार्ट 6: समुत्थान प्रक्रिया संबंधी रुख: कीमत की स्थिति

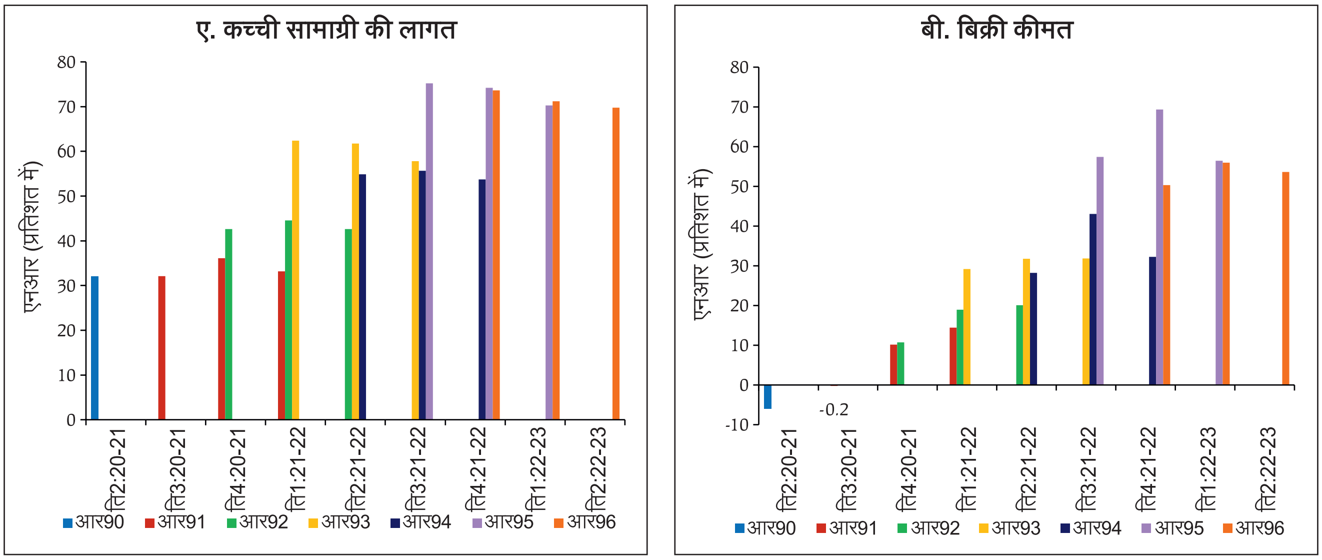

स्रोत: आरबीआई।

सुधार आने लगा, लेकिन नवीनतम सर्वेक्षण दौर में सुधार हुआ जो टीकाकरण अभियान पर विश्वास को दर्शाता है।

कीमत की स्थिति[13]

विनिर्माताओं की प्रत्याशा के अनुसार तिमाहियों में निविष्टि लागत पर अधिक दबाव बना। मांग में धीमी रिकवरी के बाद, विनिर्माताओं ने उपभोक्ताओं पर लागत का दबाव डाला, जिससे बिक्री कीमत (एसपी) में वृद्धि हुई। उत्तरदाताओं को प्रत्याशा थी कि निविष्टि लागत पर दबाव बना रहेगा और बिक्री कीमत धीरे-धीरे सख्त होगा (चार्ट 6)।

समग्र कारोबार स्थिति

विनिर्माताओं को भविष्य के बारे में आशावादी देखा गया जैसा कि उनकी प्रत्याशाओं से परिलक्षित होता था। हालांकि वे महामारी की पहली लहर के शुरुआती प्रभाव के कारण, 90वें दौर में भविष्य के बारे में आशावादी थे, लेकिन सक्रिय नीति समर्थन के साथ आत्मविश्वास वापस आ गया। उद्यमों को अपना कारोबार चलाने के लिए बेहतर अवसर सृजित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों से उच्च कारोबारी आशावाद का मार्ग प्रशस्त हुआ जैसा कि सर्वेक्षण परिणामों में दर्शाया गया है (चार्ट 7)।

चार्ट 7: समुत्थान प्रक्रिया संबंधी रुख: समग्र कारोबार स्थिति

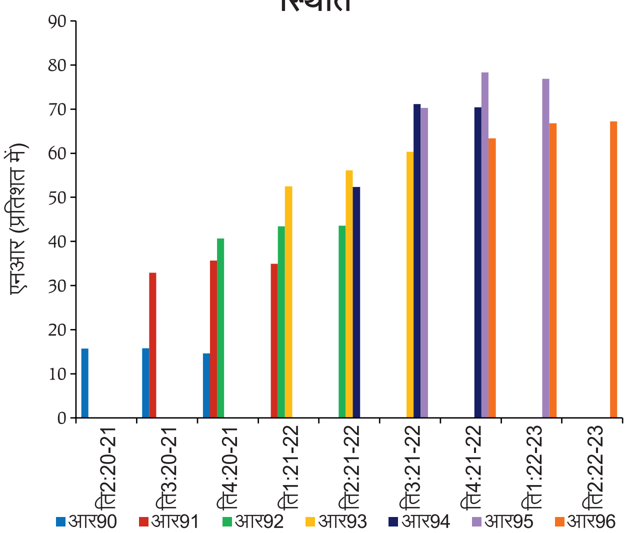

स्रोत: आरबीआई।

[13] कीमतों पर प्रश्न आर91 में अतिरिक्त ब्लॉक में शामिल किए गए थे; हालांकि, चार्ट में एकरूपता बनाए रखने के लिए, आर90 के लिए केवल एक प्रत्याशा तिमाही के लिए कीमत की स्थिति पर प्रतिक्रिया को सामान्य सर्वेक्षण दौर में पूछे गए अनुसार शामिल किया गया है।

III.3 कोविड अवधि के दौरान निर्माताओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

विनिर्माताओं से प्राप्त टिप्पणियों/ सुझावों ने अप्रैल-जून 2020 के सर्वेक्षण (आर90) के दौर में उनके कारोबार में संकट दर्शाया क्योंकि अधिकांश कारखाने बंद थे। कच्चे माल की कमी, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और परिवहन में देरी के कारण आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माताओं को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चूंकि उपभोक्ता केवल आवश्यक वस्तुओं की खरीद कर रहे थे, इसलिए तैयार माल की उच्च सूची निर्माताओं के लिए चिंता का विषय बन गई। बाद के सर्वेक्षण दौरों में रुख में सुधार आया, लेकिन कंपनियों ने कच्चे माल की अनुपलब्धता, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के साथ-साथ श्रम की कमी को प्रमुख बाधाओं के रूप में बताया। हालांकि रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित स्थगन से निर्माताओं को कुछ राहत मिली, लेकिन दूसरी लहर ने उनकी आशावाद को फिर से धूमिल कर दिया, जिससे उनकी पुनर्भुगतान क्षमता बाधित हो गई। उन्होंने एक्सप्रेस टीकाकरण की भी मांग की ताकि फर्म पूरी क्षमता से चल सकें।

हालांकि घरेलू और विदेशी मांग की कमी, आर्थिक अनिश्चितता और उच्च निविष्टि लागत प्रमुख चिंताएं थीं, विनिर्माताओं को निकट भविष्य में अपने कारोबार को महामारी-पूर्व स्तर पर बहाल करने के बारे में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षेत्र-विशिष्ट त्वरित राहत, रिज़र्व बैंक द्वारा सक्रिय मौद्रिक नीति उपाय और तेजी से हो रहे टीकाकरण के कारण आशावादी देखा जाता है।

IV: समुत्थान (रिकवरी) पर दृष्टिकोण

इस खंड में, सर्वेक्षण के रुख के आधार पर कोविड के बाद के समुत्थान (रिकवरी) का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। 2000-01 की पहली तिमाही से विश्लेषण के लिए 20 साल की अवधि को कवर करने वाली लंबी अवधि की श्रृंखला पर विचार किया गया है। यह आलेख आईओएस (मुख्य रूप से एनआरए_पीआर और बीएआई) और संबंधित समष्टि-आर्थिक श्रृंखला में देखे गए मांग मापदंडों पर केंद्रित है। यह देखा गया है कि एनआरए_पीआर और बीएआई का आईआईपीएम (आईआईपीएम व-द-व) और जीवीए निर्माण (जीवीए व-द-व) में क्रमशः वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ एक मजबूत समसामयिक संबंध है। हालांकि, समष्टि चरों के इस तरह के सहसंबंध, प्रत्याशा मापदंडों, यानी, एनआरई और बीईआई के साथ मूल्यांकन मापदंडों *यानी* एनआरए और बीएआई की तुलना में बहुत कम हैं (अनुबंध सारणी 1)। इसके अलावा, प्रत्याशा मापदंडों की तुलना में मूल्यांकन मापदंड अधिक कुशलता से समष्टि चर के संकेतों का पता लगाते हैं (अनुबंध सारणी 2)। महामारी से प्रभावित वर्षों में चालू तिमाही में विनिर्माताओं के रुख में कमी आने का कारण एनआरई को अधिक देखा जा रहा है। हालांकि, केवल एक तिमाही के लिए उपलब्ध होने के कारण, मूल्यांकन केवल वर्तमान तिमाही के लिए पूर्व सूचना प्रदान करने के लिए उपयोगी है। यह बाद की तीन तिमाहियों के लिए प्रत्याशा के बारे में जानकारी द्वारा पूरक है, जो विशेष रूप से सर्वेक्षण की चरण संख्या 90 के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। कुछ और तिमाहियों के लिए प्रत्याशा की जानकारी विनिर्माताओं द्वारा प्रत्याशित रिकवरी प्रक्रिया के बारे में बेहतर विचार दे सकती है।

पहली जांच इस बात से संबंधित है कि क्या कोविड-19 ने आर्थिक गतिविधियों में स्थायी बदलाव के लिए एक नया सामान्य या अल्पकालिक आघात अपनाया है, जहां से अर्थव्यवस्था शीघ्र पटरी पर आ जाएगी। स्ट्रक्चरल ब्रेक पॉइंट और उसके बाद के चाउ टेस्ट के लिए बाई-पेरॉन टेस्ट ने 2008-09 में आईआईपीएम वर्ष में एक स्ट्रक्चरल ब्रेक का सुझाव दिया, लेकिन एनआरए_पीआर, बीएआई और जीवीएम_व-द-व के लिए ब्रेक पॉइंट अलग-अलग टाइम पॉइंट पर हैं (अनुबंध सारणी 3, 4, 5, 6)। 2008 में जीएफसी के साक्ष्य 2008 में आईआईपीएम में एक स्ट्रक्चरल ब्रेक का सुझाव देते हैं, जैसा कि रोलिंग मीन और मानक विचलन में स्थायी बदलाव से देखा गया है, लेकिन एनआरए_पीआर के लिए एक विशुद्ध आघात है क्योंकि श्रृंखला कुछ तिमाहियों के बाद अपनी सामान्य गति पर लौट आई है। जीवीएम_व-द-व और बीएआई के लिए समान अंतर दिखाई देता है। चार्ट 8ए से 8डी, संबंधित श्रृंखला को इसके रोलिंग मीन[14] और रोलिंग मानक विचलन के साथ प्रस्तुत करते हैं।

उपरोक्त चार्ट बताते हैं कि वैश्विक वित्तीय संकट की तुलना में कोविड महामारी ने अर्थव्यवस्था को अधिक गंभीर रूप से प्रभावित किया। अर्थव्यवस्था के पूरी तरह से ठीक होने और स्थिर होने के बाद कोविड-19 प्रकरण के कारण पूर्ण प्रभाव और संरचनात्मक परिवर्तनों के बारे में आगे की जांच बेहतर ढंग से देखी जाएगी।

[14] चार तिमाहियों के लिए रोलिंग विंडो पर विचार किया जाता है *अर्थात* किसी विशेष तिमाही के लिए, 'माध्य' और 'एसडी' उस तिमाही और पिछली तीन तिमाहियों का औसत और मानक विचलन हैं।

चार्ट 8: समष्टि चरों *की तुलना में* आवर्ती माध्य और सर्वेक्षण मापदंडों का मानक विचलन

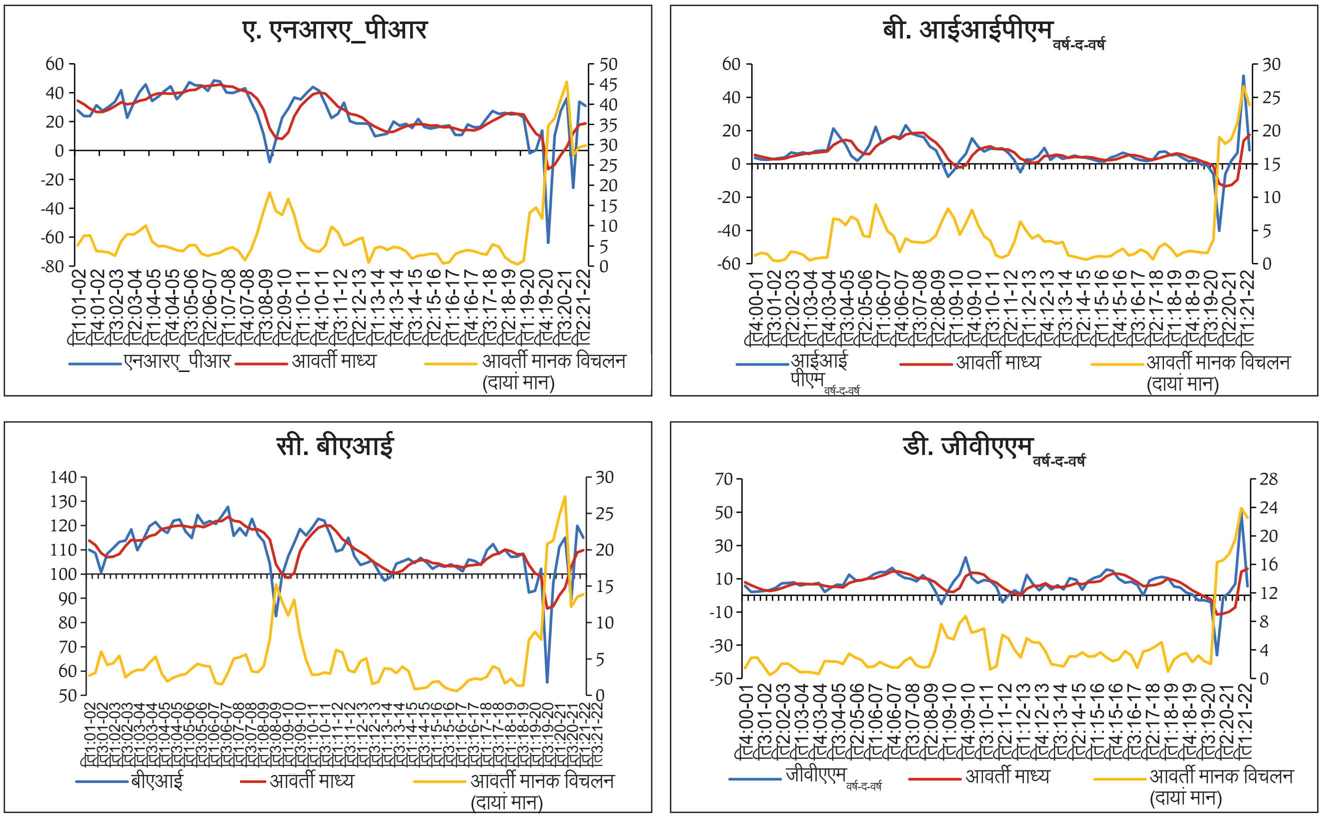

स्रोत: आरबीआई, एनएसओ, लेखकों की गणना।

कोविड-19 आघात से रिकवरी: परिदृश्य का एक विश्लेषण

सर्वेक्षण से एकत्र किए गए विनिर्माता के दृष्टिकोण के आधार पर आईआईपीएम और जीवीएएम के लिए प्रत्याशित रिकवरी पथ की रूपरेखा तैयार करने का प्रयास किया गया है। चूंकि आईओएस वर्तमान तिमाही मूल्यांकन और बाद की तीन तिमाहियों की प्रत्याशा को भांप लेता है, इसका उपयोग अगले एक साल के हॉरीजॉन में समष्टि चरों की परिकल्पना के लिए किया जा सकता है। हिडन मार्कोव मॉडल रिग्रेशन (एचएमएमआर) तकनीक को मौजूदा साहित्य के बाद समष्टि चरों के रिकवरी पथ का अनुमान लगाने के लिए नियोजित किया गया था (गोल्डफेल्ड और क्वांट, 1973; हैमिल्टन, 1989; डाइबॉल्ड *और अन्य*, 1994; डाइबॉल्ड और रुडबुश, 1996; फिलार्डो और गॉर्डन, 1998; बेलोन सेंट मार्टिन, 2003; बर्दाजी, 2009; कैमाचो *और अन्य*, 2012; बर्नार्डेली, 2015; भौमिक और मजूमदार, 2020; और सामंत और भौमिक, 2022)। अनुमानित मॉडल इस प्रकार हैं:

आईआईपीएम के लिए अनुमानित मॉडल हैं:

1. $IIPM_{yoy_t} = \alpha_{0s} + \beta_{1s}IIPMyoy_{(-1)} + \beta_{2s}APR(I)_t + \beta_{3s}APR(D)_t + \beta_{4s}D_t + \varepsilon_t \quad s \in S = \{1,2\}$

2. $IIPM_{yoy_t} = \alpha_{0s} + \beta_{1s}IIPMyoy_{(-1)} + \beta_{2s}NRA_PR_t + \beta_{4s}D_t + \varepsilon_t \quad s \in S = \{1,2\}$

3. $IIPM_{yoy_t} = \alpha_{0s} + \beta_{1s}IIPMyoy_{(-1)} + \beta_{2s}EPR(I)_t + \beta_{3s}EPR(D)_t + \beta_{4s}D_t + \varepsilon_t \quad s \in S = \{1,2\}$

4. $IIPM_{yoy_t} = \alpha_{0s} + \beta_{1s}IIPMyoy_{(-1)} + \beta_{2s}NRE_PR_t + \beta_{4s}D_t + \varepsilon_t \quad s \in S = \{1,2\}$

और इसी तरह जीवीएएम के लिए अनुमानित समीकरण हैं:

5. $GVAM_{yoy_t} = \alpha_{0s} + \beta_{1s}GVAMyoy_{(-1)} + \beta_{2s}BAI_t + \beta_{4s}D_t + \varepsilon_t \quad s \in S = \{1,2\}$

6. $GVAM_{yoy_t} = \alpha_{0s} + \beta_{1s}GVAMyoy_{(-1)} + \beta_{2s}BEI_t + \beta_{4s}D_t + \varepsilon_t \quad s \in S = \{1,2\}$

चार्ट 9: विनिर्मान क्षेत्र से संबंधित समष्टि चरों के लिए अनुमानित समुत्थान पथ

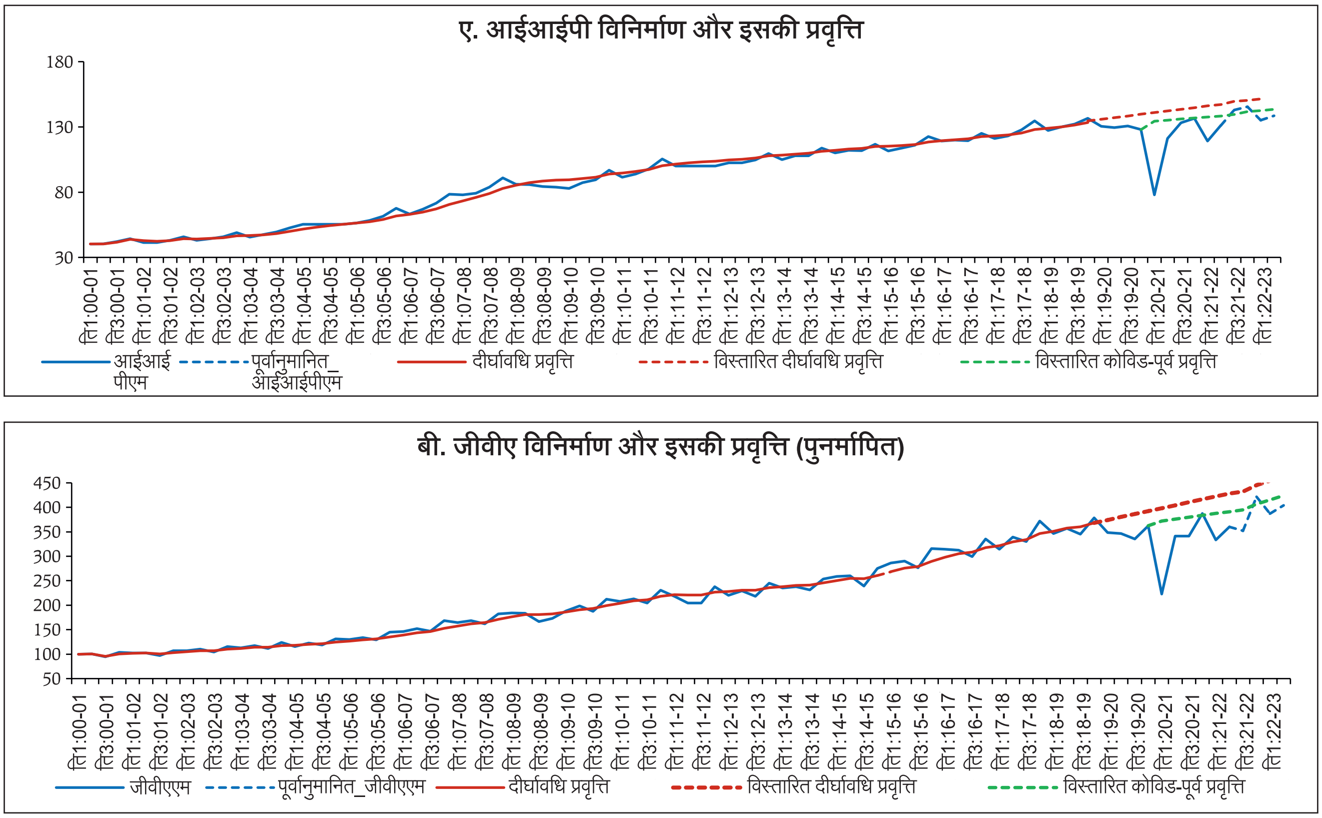

स्रोत: आरबीआई, एनएसओ, लेखकों की गणना।

जहां, एपीआर (आई) और एपीआर (डी) उत्पादन मापदंड के आकलन में वृद्धि और कमी दर्शाते हैं; ईपीआर(आई) और ईपीआर(डी) का अर्थ है उत्पादन के लिए प्रत्याशा में वृद्धि और कमी; और डी एक डमी है जिसका उपयोग कोविड आघात से उबरने के लिए किया जाता है। मॉडल अनुमान के परिणाम अनुबंध सारणी 7 और 8 में प्रस्तुत किए गए हैं।

साहित्य के बाद, आईआईपीएम और जीवीएएम के लिए दीर्घकालिक रुझानों की गणना एक तरफा हॉड्रिक-प्रेस्कॉट (एचपी) फ़िल्टर का उपयोग करके की जाती है, पहला 2000-01 की पहली तिमाही से 2018-19 की चतुर्थ तिमाही की अवधि के लिए और दूसरा कोविड-पूर्व अवधि हेतु 2000-01 की पहली तिमाही से 2019-20 की चतुर्थ तिमाही के लिए गणना की गई प्रवृत्ति। पिछले पांच वर्षों के त्रैमासिक औसत के आधार पर दोनों प्रवृत्तियों को दो अलग-अलग परिदृश्यों में विस्तारित किया गया है; लंबी अवधि के रुझान के बाद पहला परिदृश्य, जबकि दूसरा 2019-20 से पहले अर्थव्यवस्था में मंदी के साथ, लेकिन कोविड-19 प्रभाव को मानदंड के रूप में छोड़कर। बाद की चार तिमाहियों (2021-22 की तीसरी तिमाही से 2022-23 की दूसरी तिमाही) में समष्टि चर के अनुमानों का अनुमान आईओएस रुख का उपयोग करके लगाया गया है (चार्ट 9)[15]।

परिणामों को विभिन्न परिदृश्यों के तहत मान्यताओं के साथ काल्पनिक निर्माण के रूप में देखा जा सकता है, न कि पारंपरिक पूर्वानुमान के रूप में। उपरोक्त चार्ट प्रदर्शित करते हैं कि हालांकि आईआईपीएम और जीवीएएम, दोनों ति4: 2020-21 में कोविड-पूर्व रुझान के पथ पर पहुंच गए, दूसरी लहर ने विकास की गति को बाधित करके रिकवरी प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। हालाँकि, दोनों को निकट-अवधि में महामारी-पूर्व प्रवृत्ति पथ तक पहुँचने का अनुमान है, लेकिन दीर्घकालिक रुझान के पथ को प्राप्त करने में कुछ और समय लगने की संभावना है।

V. निष्कर्ष

आईओएस के 11वें चरण ति1: 2019-20 से ति3: 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन अलग-अलग चरणों

[15] जीवीएएम को सरल प्रतिनिधित्व के लिए ति1: 2000-01 को 100 के रूप में लेकर पुनर्मापित किया गया है।

की ओर इशारा करते हैं। 2019-20 में सर्वेक्षण मापदंडों ने विनिर्माताओं के रुख के संदर्भ में समग्र अर्थव्यवस्था में मंदी को दर्शाया। महामारी की पहली और दूसरी लहर ने आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर दिया, और विनिर्माताओं की धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। धीरे-धीरे सामान्य स्थिति बहाल होने के साथ स्थितियों में सुधार हुआ। आगे चलकर, इस विश्लेषण को समष्टि चरों में संरचनात्मक परिवर्तनों को समझने के लिए विस्तारित किया जा सकता है, जब एक बार रिकवरी पूरी तरह से हो जाती है। साथ ही, हालांकि प्रमुख समष्टि-आर्थिक चरों को मांग की स्थिति में सुधार के साथ निकट-अवधि में अपने कोविड-पूर्व रुझान को प्राप्त करने के लिए माना जाता है, उन्हें अपने दीर्घकालिक रुझान के पथ पर लौटने में समय लगने की उम्मीद है। समवर्ती रूप से, महामारी की बाद की लहरें और वायरस रोकथाम उपायों को फिर से लागू करने से विनिर्माताओं के रुख में कमी आ सकती है और यह रिकवरी प्रक्रिया को मंद कर सकता है। हालांकि, टीकों का त्वरित रोलआउट, राजकोषीय और अन्य सुधारों के साथ एक समावेशी विकास-उन्मुख केंद्रीय बजट 2022-23 और इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च और क्षेत्र-विशिष्ट समर्थन में वृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के विभिन्न चरणों के तहत निवेश-उन्मुख प्रोत्साहन, आसान वित्तीय स्थिति, *आदि* से अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करने की उम्मीद है और मध्यम अवधि में विकास क्षमता को फिर से हासिल करने की सुविधा प्रदान करेगा। भविष्य में निरंतर नीतिगत समर्थन वसूली को आसान और तेज बना सकता है।

संदर्भ

Bank of Canada (2020), 'Business Outlook Survey', Spring, Summer and Autumn issue, *https://www.bankofcanada.ca/2020/04/business-outlook-survey .*

Bhowmick, S. and Majumdar, S. (2020). 'Sentiments of Indian Manufacturers in 2018-19', RBI Bulletin, February.

Dana E. Goin and Jennifer Ahern (2018). 'Identification of Spikes in Time Series', Division of Epidemiology, School of Public Health, University of California, Berkeley, California, January.

Federal Reserve Bank of Kansas City (2020), 'Manufacturing Survey', February issue, *https://www.kansascityfed.org/surveys/manufacturing-survey/202002-tenth-district-manufacturing-activity-increased-modestly-february/*.

Federal Reserve Bank of Kansas City (2020), 'Manufacturing Survey', various monthly survey reports, *https://www.kansascityfed.org/research/indicatorsdata/mfg*.

Federal Reserve Bank of New York (2020) , 'Business Leaders Survey', March issue, *https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/survey/business_leaders/2020/2020_03blsreport.pdf?la=en* .

Federal Reserve Bank of New York (2020), 'Empire State Manufacturing Survey', various issues *https://www.newyorkfed.org/survey/empire/empiresurvey_archives* .

Federal Reserve Bank of Philadelphia (2020), 'Manufacturing Business Outlook Survey', October issue, *https://www.philadelphiafed.org/-/media/frbp/assets/surveys-and-data/mbos/2020/bos1020.pdf?la=en* .

Morten O. Ravn and Harald Uhlig (2002). 'On Adjusting the Hodrick-Prescott Filter for the Frequency of Observations', The Review of Economics and Statistics, May 2002, 84(2): 371–380.

Piet de Jong; Jeremy Penzer (1998). 'Diagnosing Shocks in Time Series', Journal of the American Statistical Association, Vol. 93, No. 442. (Jun., 1998), pp. 796-806.

Reserve Bank of India (2020), 'Industrial Outlook Survey', April, August, October issues *https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=19437/19717/19984*.

Reserve Bank of India (2020), Monetary policy resolution March 27, 2020, *https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=49581* .

Samanta, G. P. and Bhowmick, S. (2022). 'Quantifying Survey-based Qualitative Responses on Capacity Utilisation-An Analysis for India', RBI Working Paper No. 05/2022.

अनुबंध

सारणी 1: सर्वेक्षण मापदंडों और समष्टि चरों के बीच समसामयिक सहसंबंध

	एनआरए_पीआर	एनआरई_पीआर	बीएआई	बीईआई
आईआईपीएम$_{वर्ष-दर-वर्ष}$	0.70	0.64		
जीवीएएम$_{वर्ष-दर-वर्ष}$			0.49	0.38

टिप्पणी: सहसंबंध की गणना कोविड-19 महामारी अवधि को छोड़कर की गई है।

सारणी 2: समष्टि चरों के लिए मूल्यांकन और प्रत्याशा मापदंड द्वारा पता लगाया गया सिग्नल

प्रतिशत में	एनआरए_पीआर/ आईआईपीएम	एनआरई_पीआर/ आईआईपीएम	बाई/ जीवीएएम	बीईआई/ जीवीएएम
सही	64	59	52	49
गलत	36	41	48	51

सारणी 3: एनआरए_पीआर में स्ट्रक्चरल ब्रेक का पता लगाना

ब्रेक का प्रकार: एल+1 बनाम एल के **बाई-पेरॉन टेस्ट** क्रमिक रूप से निर्धारित ब्रेक ब्रेक: 2012 की दूसरी तिमाही चयन: 0.15 ट्रिमिंग, सिग. स्तर 0.05		
	टी-सांख्यिकी	**संभाव्यता**
2000:ति2 - 2012:ति1 - 48 ऑबजर्वेशन	17.94709	0.0000
2012:ति2 - 2021:ति1 - 36 ऑबजर्वेशन	7.031145	0.0000
चाउ ब्रेकपॉइंट टेस्ट: 2012 की दूसरी तिमाही	**एफ-आंकड़े**	**संभाव्यता**
शून्य परिकल्पना: निर्दिष्ट ब्रेकपॉइंट्स पर कोई ब्रेक नहीं	42.89050	0.0000

सारणी 4: आईआईपीएम$_{वर्ष-दर-वर्ष}$ में स्ट्रक्चरल ब्रेक का पता लगाना

ब्रेक का प्रकार: एल+1 बनाम एल के **बाई-पेरॉन टेस्ट** क्रमिक रूप से निर्धारित ब्रेक ब्रेक: 2005:ति4, 2008:ति4 चयन: 0.15 ट्रिमिंग, सिग. स्तर 0.05		
	टी-सांख्यिकी	**संभाव्यता**
2000:ति2 - 2005:ति3 - 22 ऑबजर्वेशन	4.787717	0.0000
2005:ति4 - 2008:ति3 - 12 ऑबजर्वेशन	8.166848	0.0000
2008:ति4 - 2020:ति4 - 49 ऑबजर्वेशन	2.667591	0.0000
चाउ ब्रेकप्वाइंट टेस्ट:	**एफ-आंकड़े**	**संभाव्यता**
2005:ति4 के लिए: शून्य परिकल्पना: निर्दिष्ट ब्रेकपॉइंट्स पर कोई ब्रेक नहीं	0.644799	0.4244
2008:ति4 के लिए: शून्य परिकल्पना: निर्दिष्ट ब्रेकपॉइंट्स पर कोई ब्रेक नहीं	20.84616	0.0000

सारणी 5: बीएआई में स्ट्रक्चरल ब्रेक का पता लगाना

ब्रेक का प्रकार: एल+1 बनाम एल के **बाई-पेरॉन टेस्ट** क्रमिक रूप से निर्धारित ब्रेक ब्रेक: 2012:ति2 चयन: 0.15 ट्रिमिंग, सिग. स्तर 0.05		
	टी-सांख्यिकी	**संभाव्यता**
2000:ति2 - 2012:ति1 - 48 ऑबजर्वेशन	94.34883	0.0000
2012:ति2 - 2021:ति1 - 36 ऑबजर्वेशन	73.16671	0.0000
चाउ ब्रेकप्वाइंट टेस्ट: 2012:ति2	**एफ-आंकड़े**	**संभाव्यता**
शून्य परिकल्पना: निर्दिष्ट ब्रेकपॉइंट्स पर कोई ब्रेक नहीं	40.88216	0.0000

सारणी 6: जीवीएएम$_{वर्ष-दर-वर्ष}$ में स्ट्रक्चरल ब्रेक का पता लगाना

ब्रेक का प्रकार: एल+1 बनाम एल के **बाई-पेरॉन टेस्ट** क्रमिक रूप से निर्धारित ब्रेक ब्रेक: 2017:ति2 चयन: 0.15 ट्रिमिंग, सिग. स्तर 0.05		
	टी-सांख्यिकी	**संभाव्यता**
2000:ति2 - 2017:ति1 - 68 ऑबजर्वेशन	9.546114	0.0000
2017:ति2 - 2020:ति4 - 15 ऑबजर्वेशन	0.465348	0.6429
चाउ ब्रेकप्वाइंट टेस्ट: 2017:ति2	**एफ-आंकड़े**	**संभाव्यता**
शून्य परिकल्पना: निर्दिष्ट ब्रेकपॉइंट्स पर कोई ब्रेक नहीं	12.39505	0.0007

सारणी 7: एचएमएम के लिए प्रतिगमन परिणाम

समीकरण 1	अवरोधन	आईआईपीएम$_{वर्ष-दर-वर्ष}$ (-1)	एपीआर (आई)	एपीआर (डी)	डी	एसडी
एसटी1	-3.269	0.932	0.062	0.006	2.046	0.734
एसटी2	-3.763	0.878	0.059	-0.173	10.498	2.608
समीकरण 2	अवरोधन	आईआईपीएम$_{वर्ष-दर-वर्ष}$(-1)	एनआरए_पीआर		डी	एसडी
एसटी1	-5.774	0.904	0.042		1.98	0.751
एसटी2	-18.256	0.869	0.113		10.46	2.632
समीकरण 3	अवरोधन	आईआईपीएम$_{वर्ष-दर-वर्ष}$(-1)	ईपीआर (आई)	ईपीआर (डी)	डी	एसडी
एसटी1	-8.055	0.485	0.238	-0.138	3.159	1.345
एसटी2	47.952	1.014	-0.822	-1.41	12.32	2.590
समीकरण 4	अवरोधन	आईआईपीएम$_{वर्ष-दर-वर्ष}$(-1)	एनआरई_पीआर		डी	एसडी
एसटी1	-4.751	0.933	0.03		2.202	0.827
एसटी2	-23.732	0.934	0.136		12.114	2.695
समीकरण 5	अवरोधन	जीवीएएम$_{वर्ष-दर-वर्ष}$ (-1)	बीएआई		डी	एसडी
एसटी1	-11.808	0.866	0.099		2.648	0.918
एसटी2	-16.888	0.773	0.133		8.656	2.823
समीकरण 6	अवरोधन	जीवीएएम$_{वर्ष-दर-वर्ष}$ (-1)	बीईआई		डी	एसडी
एसटी1	-7.417	0.946	0.049		3.531	1.284
एसटी2	-6.534	0.848	0.014		11.902	2.863

सारणी 8: आईआईपीएम और जीवीएएम के लिए संक्रमण संभावना मैट्रिक्स

आईआईपीएम			जीवीएएम		
समीकरण 1	एसटी 1 तक	एसटी2 तक	समीकरण 5	एसटी 1 तक	एसटी2 तक
एसटी1 से एसटी2 से	0.823 0.197	0.177 0.803	एसटी1 तक एसटी2 तक	0.791 0.183	0.209 0.817
समीकरण 2	एसटी 1 तक	एसटी2 तक	समीकरण 6	एसटी 1 तक	एसटी2 तक
एसटी1 से एसटी2 से	0.823 0.196	0.177 0.804	एसटी1 तक एसटी2 तक	0.826 0.337	0.174 0.663
समीकरण 3	एसटी 1 तक	एसटी2 तक			
एसटी1 से एसटी2 से	0.820 0.445	0.180 0.555			
समीकरण 4	एसटी 1 तक	एसटी2 तक			
एसटी1 से एसटी2 से	0.825 0.213	0.175 0.787			

टिप्पणी: राज्य 1 निम्नतर वृद्धि की अवधि से जुड़ा है और राज्य 2 उच्च विकास की अवधि को दर्शाता है।

प्रारंभिक राज्य संभावनाओं ने राज्य 1 को निश्चित माना, *यानी*, संभावना = 1।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

अवसरिक शृंखला

विषय-वस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	97
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	98
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	99
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय/विक्रय	100
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	101
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	101
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	102
7	मुद्रा स्टॉक (एम$_3$) के स्रोत	103
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	104
9	कुल चलनिधि राशियां	104
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	105
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	105
12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	106
13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश	106
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	107
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	108
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	109
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	110
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)	111
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	111
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	111
21	थोक मूल्य सूचकांक	112
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)	116
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	116
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	117
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	117
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	118
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	119
28	वाणिज्यिक पत्र	119
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	119
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	120

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	121
32	विदेशी मुद्रा भंडार	121
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	121
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	122
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	122
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	123
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- पंजीकरण	124
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमरीकी डॉलर)	125
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	126
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	127
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	128
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	129
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	130
	अवसरिक श्रृंखला	
44	लघु बचत	132
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	133
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	134
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	135
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	136
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	137

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।
– = शून्य/नगण्य
प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम   आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2020-21	2020-21		2021-22	
		ति1	ति2	ति1	ति2
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	-4.8	-22.4	-7.3	18.8	8.5
1.1.1 कृषि	3.3	3.5	3.0	4.5	4.5
1.1.2 उद्योग	-1.8	-31.0	-1.6	40.4	6.7
1.1.3 सेवाएं	-7.8	-24.9	-11.0	16.1	9.9
1.1क अंतिम खपत व्यय	-4.5	-19.9	-13.4	13.8	8.6
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	-10.4	-46.6	-8.6	55.3	11.0
	2020-21	2020		2021	
		नवं.	दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	-8.4	-1.6	2.2	1.3	0.4
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	11.4	10.7	10.8	8.9	10.3
2.1.2 ऋण	5.6	5.9	6.2	6.9	9.1
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	5.5	5.9	6.2	7.1	9.3
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	19.3	19.3	17.3	3.6	2.8
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	18.8	15.3	14.9	12.8	14.7
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	12.2	12.5	12.4	9.5	11.4
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	3.50	3.00	3.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.2	3.8	3.7	4.8	5.0
3.4 ऋण-जमा अनुपात	72.4	72.2	73.1	71.0	71.9
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	37.4	11.0	23.5	37.3	64.8
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.5	30.5	30.4	29.0	28.4
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	46.8	73.6	72.0	17.7	12.9
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
4.2 रिवर्स रिपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
4.4 बैंक दर	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
4.5 आधार दर	7.40/8.80	7.40/8.80	7.30/8.80	7.30/8.80	7.25/8.80
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	6.55/7.05	6.60/7.10	6.55/7.10	6.50/7.00	6.50/7.00
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.60
4.8 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	3.25	3.10	3.24	3.35	3.32
4.10 91-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	3.32	2.93	3.08	3.53	3.66
4.11 182-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	3.47	3.26	3.34	3.83	3.97
4.12 364-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	3.83	3.39	3.46	4.13	4.27
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	6.34	5.84	5.89	6.33	6.47
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिआ					
5.1 भा.रु.-अमरीकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	72.40	73.80	73.58	74.71	74.30
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	85.31	88.02	89.81	83.85	84.05
5.3 फारवर्ड प्रीमिआ अमरीकी डॉलर 1-माह (%)	6.80	3.36	3.84	3.69	3.96
3-माह (%)	5.64	3.52	3.75	3.80	4.15
6-माह (%)	5.47	4.23	4.35	4.71	4.71
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	6.18	6.9	4.6	4.9	5.6
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.03	5.3	3.7	4.8	5.6
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	1.29	2.3	2.0	14.9	13.6
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	1.71	3.8	-0.6	10.2	13.4
6.3.2 ईंधन और पावर	-7.99	-7.0	-6.1	44.4	32.3
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	2.75	3.2	4.5	12.3	10.6
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	-16.91	-12.2	8.4	56.4	38.5
7.2 निर्यात	-6.88	-8.3	0.4	34.4	38.9

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिज़र्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2020-21	2021		2022			
		जन.	दिसं. 31	जन. 7	जन. 14	जन. 21	जन. 28
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	2831727	2780045	2959237	2989898	3006151	3008989	3004604
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	13	13	16	14	16	16
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	**2831738**	**2780058**	**2959250**	**2989914**	**3006165**	**3009004**	**3004619**
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	106555	114391	113486	112475	114143	116293	114864
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2724437	2664788	2845196	2876892	2891494	2892200	2889257
1.2.3 रुपया सिक्का	746	879	567	546	528	512	498
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	–	–	–	–	–	–	–
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	1504697	1512883	1991453	1969320	1914602	1985921	1929291
2.1.1.1 केंद्र सरकार	100	101	100	100	101	101	100
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	542693	476349	716432	644326	683105	658094	681336
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6529	6536	7631	7036	7400	6939	7560
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3204	2619	3416	3788	4002	3696	3766
2.1.1.7 अन्य बैंक	31820	26397	37349	37240	36699	37648	36681
2.1.1.8 अन्य	895440	987112	1180276	1215308	1147216	1232104	1139410
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	24868	13726	46206	61480	36038	47297	60395
2.1.2 अन्य देयताएं	1343670	1440272	1313545	1289986	1308879	1306804	1300073
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	**2848367**	**2953154**	**3304998**	**3259306**	**3223482**	**3292725**	**3229365**
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	13	13	17	14	16	16
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1204135	1357052	1412900	1378487	1366456	1372901	1387051
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.2 राज्य सरकारें	1674	4769	6677	13016	13975	2899	716
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	90275	84597	102489	94323	94732	169843	94286
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.6 नाबार्ड	26422	26181	24770	24770	24770	24770	24770
2.2.3.7 एक्जिम बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.8 अन्य	6678	6643	77	77	3077	1459	811
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	24858	6521	46227	49829	20966	22993	30404
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.4.2 सरकारी खज़ाना बिल	–	–	–	–	–	–	–
2.2.5 निवेश	1331671	1308808	1521572	1510000	1507414	1502486	1497144
2.2.6 अन्य आस्तियां	162643	158570	190274	188789	192078	195359	194167
2.2.6.1 सोना	146572	150412	179293	177696	180696	183856	181597

*: डेटा अनंतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाज़ार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		दीर्घावधि रिपो परिचालन&	लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन#	लघु वित्त बैंकों के लिए विशेष दीर्घावधि रिपो परिचालन	विशेष पुनः क्रय रिपो £	निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9+10+ 11+12-2-4-7-8-13)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर				विक्रय	क्रय					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
दिसं. 1, 2021	-	242239	-	-	2	–	-	835	-	-	-	-	-	-243072
दिसं. 2, 2021	-	268334	-	-	100	–	-	100	-	-	-	-	-	-268334
दिसं. 3, 2021	-	227557	-	469737	0	–	-	115	-	-	-	-	-	-697409
दिसं. 4, 2021	-	34814	-	-	129	–	-	-	-	-	-	-	-	-34685
दिसं. 5, 2021	-	4998	-	-	8	–	-	-	-	-	-	-	-	-4990
दिसं. 6, 2021	-	220915	-	-	1	–	-	10	-	-	-	-	-	-220924
दिसं. 7, 2021	-	229680	-	200012	10	–	-	365	-	-	-	-	-	-430047
दिसं. 8, 2021	-	212608	-	-	8	–	-	150	-	-	-	-	-	-212750
दिसं. 9, 2021	-	219375	-	-	255	–	-	485	-	-	-	-	-	-219605
दिसं. 10, 2021	-	205465	-	-	0	–	-	370	-	-	-	-	-	-205835
दिसं. 11, 2021	-	3489	-	-	207	–	-	-	-	-	-	-	-	-3282
दिसं. 12, 2021	-	2455	-	-	13	–	-	-	-	-	-	-	-	-2442
दिसं. 13, 2021	-	211943	-	-	56	–	-	160	-	-	-	150	-	-211897
दिसं. 14, 2021	-	210008	-	200010	0	–	-	200	-	-	-	-	-	-410218
दिसं. 15, 2021	-	168446	-	-	1259	–	-	815	-	-	-	-	-	-168002
दिसं. 16, 2021	-	87551	-	-	263	1000	-	155	-	-	-	-	-	-86443
दिसं. 17, 2021	-	167019	-	312876	122	-1000	-	705	-	-	-	-	-	-481478
दिसं. 18, 2021	-	49249	-	-	116	–	-	-	-	-	-	-	-	-49133
दिसं. 19, 2021	-	2807	-	-	368	–	-	-	-	-	-	-	-	-2439
दिसं. 20, 2021	-	97266	-	81160	104	–	-	330	-	-	-	100	-	-178552
दिसं. 21, 2021	-	116282	-	155438	304	4399	-	225	-	-	-1281	-	-	-268523
दिसं. 22, 2021	-	113494	-	-	570	–	-	255	-	-	-1153	-	-	-114332
दिसं. 23, 2021	-	93518	-	133332	272	–	-	765	-	-	-	-	-	-227343
दिसं. 24, 2021	-	93955	-	-	6508	–	-	570	-	-	-	-	-	-88017
दिसं. 25, 2021	-	3829	-	-	55	–	-	-	-	-	-	-	-	-3774
दिसं. 26, 2021	-	1981	-	-	199	–	-	-	-	-	-	-	-	-1782
दिसं. 27, 2021	-	95412	-	129567	501	–	-	230	-	-	2275	255	-	-222178
दिसं. 28, 2021	-	135747	-	174412	0	–	-	340	-	-	-	-	-	-310499
दिसं. 29, 2021	-	162196	-	-	15	–	-	540	-	-	-	-	-	-162721
दिसं. 30, 2021	-	184315	-	142729	3913	–	-	1995	-	-	-	-	-	-325126
दिसं. 31, 2021	-	208070	-	267022	8176	–	-	1415	-	-	-	-	-	-468331

टिप्पणी: # लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ), लक्षित दीर्घावधि रिपोपरिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) और मांग के अनुसार लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन। ऋणात्मक(-) चिन्ह बैंकों द्वारा लिए गए पुर्नभुगतान को दर्शाता है।

& ऋणात्मक (-) चिन्ह बैंकों द्वारा किए गए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।

£ 07 मई 2021 की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2021-2022/177 के अनुसार। 18 जून 2021 से, 4 जून 2021 के प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2021-2022/323 के अनुसार डाटा में राशि शामिल है।

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेन्ट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2020-21	2020	2021	
		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	68315	3991	0	-2917
1.1 क्रय (+)	162479	10014	8489	7475
1.2 विक्रय (-)	94164	6023	8489	10392
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	510516	29439	1669	-20809
3 संचयी (मार्च के के अंत से) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	68315	72379	40330	37413
(करोड़ ₹)	510516	538628	306805	285996
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	72751	39792	49106	49106

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेन्ट में परिचालन

मद	2020-21	2020	2021	
		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	12118	3985	0	0
1.2 विक्रय (-)	12118	3985	0	0
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	690	1962	0	0

सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	31 दिसंबर 2021 की स्थिति		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	6548	5849	699
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	9011	7816	1195
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	52212	5000	47212
4. 1 वर्ष से अधिक	0	0	0
कुल (1+2+3+4)	**67771**	**18665**	**49106**

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2020-21	2021						2022
		जन. 29	अग. 27	सितं. 24	अक्टू. 22	नवं. 19	दिसं. 31	जन. 28
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	182	0	2	152	461	7201	8176	38
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुर्नवित्त								
2.1 सीमा	–	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	–	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
3.2 बकाया	–	0	0	0	0	0	0	734
4. अन्य								
4.1 सीमा	75000	75000	76000	76000	76000	76000	76000	76000
4.2 बकाया	32387	32205	23296	25396	21696	24196	24401	24401
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	32569	32205	23298	25548	22157	31397	32577	25173

टिप्पणीः 1. अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा अर्थात एक्ज़िम बैंक को 22 मई 2020 से पुनः शुरू कर दिया।

2. अन्य के लिए पुनर्वित सुविधा, अर्थात भारिबैंक अधिनियम 1934 के नाबार्ड/ सिड़बी/एनएचबी यू /एस 17 (4 एच), 17 अप्रैल 2020 से।

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा भंडार की मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2020-21	2020	2021		
		दिसं. 18	नवं. 19	दिसं. 17	दिसं. 31
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2751828	2681512	2878246	2894325	2881115
1.1 संचलन में नोट	2826851	2749859	2961030	2970938	2959237
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	26170	25875	26698	26796	26921
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	101935	94965	110225	104152	105786
2 जनता की जमाराशियां	2042471	1728417	2005116	2042731	2257098
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	1995120	1686628	1957254	1994275	2206052
2.2 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	41788	47861	48456	51045
3 एम$_1$ (1 + 2)	**4794299**	**4409929**	**4883362**	**4937057**	**5138213**
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	170025	164567	170025	170025	170025
5 एम$_2$ (3 + 4)	**4964324**	**4574496**	**5053387**	**5107082**	**5308238**
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	14050278	13645443	14762272	14804346	14975823
7 एम$_3$ (3 + 6)	**18844578**	**18055372**	**19645634**	**19741403**	**20114036**
8 कुल डाकघर जमाराशियां	509544	489323	509544	509544	509544
9 एम$_4$ (7 + 8)	**19354122**	**18544695**	**20155178**	**20250947**	**20623580**

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम$_3$) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020	2021		
		दिसं. 18	नवं. 19	दिसं. 17	दिसं. 31
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	**5850374**	**5637236**	**6075285**	**6024478**	**6100716**
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1099686	980473	1193964	1127230	1194335
1.1.1 सरकार पर दावे	1337300	1290946	1555163	1546804	1526753
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1333917	1284643	1546532	1533230	1520076
1.1.1.2 राज्य सरकारें	3383	6303	8631	13574	6677
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियां	237615	310473	361199	419574	332418
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	237572	310431	361156	419531	332375
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	4750689	4656763	4881321	4897248	4906381
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	**11668466**	**11204826**	**11869926**	**12022917**	**12389335**
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	8709	11205	4634	1945	2094
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	11659757	11193621	11865291	12020972	12387240
2.2.1 वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	10949509	10547037	11162194	11313933	11680480
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	694758	636368	684429	688730	688991
2.2.3 वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	15490	10216	18669	18308	17769
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	**4578846**	**4597615**	**4960354**	**5038744**	**4924971**
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	4199400	4267681	4586034	4664425	4550652
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	4199637	4267926	4586275	4664665	4550897
3.1.2 विदेशी देयताएं	237	245	241	241	245
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	379446	329934	374319	374319	374319
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	**26913**	**26618**	**27441**	**27539**	**27664**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	**3280021**	**3410924**	**3287371**	**3372275**	**3328650**
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1356660	1478577	1327908	1417697	1307042
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1923362	1932347	1959464	1954578	2021608
एम$_3$ (1+2+3+4-5)	**18844578**	**18055372**	**19645634**	**19741403**	**20114036**

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020	2021		
		दिसं. 18	नवं. 19	दिसं. 17	दिसं. 31
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	4794299	4409929	4883362	4937057	5138213
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	11048277	10476477	11461215	11532850	11814892
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	18936051	18142693	19761139	19864680	20245248
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2751828	2681512	2878246	2894325	2881115
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	15892848	15167847	16574706	16651595	17043116
1.2.1 मांग जमाराशियां	1995121	1686628	1957254	1994275	2206052
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	13897727	13481219	14617452	14657319	14837063
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	6253977	6066549	6577853	6595794	6676679
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	78702	67260	56026	73916	84894
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	7643750	7414671	8039598	8061526	8160385
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	41788	47861	48456	51045
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	244025	251545	260325	270304	269971
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	18518950	17794755	18949988	19042687	19479623
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	5850374	5637236	6075285	6024478	6100716
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1099686	980473	1193964	1127230	1194335
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	4750689	4656763	4881321	4897248	4906381
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	12668575	12157519	12874703	13018209	13378907
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	34134	37338	26610	22242	26864
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	12634441	12120181	12848093	12995967	13352043
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	951313	917177	973791	967331	958477
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26618	27441	27539	27664
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4438202	4461072	4825536	4878329	4755068
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4199400	4267681	4586034	4664425	4550652
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	238802	193391	239502	213904	204416
2.4 पूंजी खाता	2775245	2872234	2994318	3077536	2976588
2.5 अन्य मदें (निवल)	1272767	1267519	1047508	1006339	1040519

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2020-21	2020	2021		
		दिसं.	अक्टू.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
1 एन एम$_3$	**18936051**	**18142693**	**19634678**	**19761139**	**20245248**
2 डाकघर जमाराशियां	509544	489323	509544	509544	509544
3 एल$_1$ (1 + 2)	**19445595**	**18632016**	**20144222**	**20270683**	**20754792**
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	33179	34795	26662	26861	24644
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2645	2645	3627	3631	1984
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	25550	28865	18175	18175	15360
4.3 सावधि जमाराशियां	4984	3285	4860	5054	7299
5 एल$_2$ (3 + 4)	**19478774**	**18666811**	**20170884**	**20297544**	**20779435**
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	31905	..	..	31905
7 एल$_3$ (5 + 6)	**19510679**	**18698716**	..	..	**20811340**

टिप्पणी : संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020	2021		
		दिसं. 18	नवं. 19	दिसं. 17	दिसं. 31
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	2853763	2776477	2988471	2998477	2986901
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां	698867	522176	731562	741305	764828
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	651748	488262	683604	693730	716432
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	41788	47861	48456	51045
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	3599981	3340442	3767894	3788238	3802775
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	730328	524719	482327	513971	531501
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	1099686	980473	1193964	1127230	1194335
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1096345	974212	1185376	1113698	1187700
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	–	–	–	–	–
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	–	–	–	–	–
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1333174	1283889	1545839	1532614	1519509
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1333174	1283889	1545839	1532614	1519509
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	743	754	693	616	567
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	237572	310431	361156	419531	332375
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	3340	6261	8588	13532	6634
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-403492	-493092	-738247	-635502	-689698
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण और अग्रिम	-378066	-466959	-716272	-615205	-664928
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	34134	37338	26610	22242	26864
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	–	–	–	–	–
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	25426	26133	21976	20297	24770
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26618	27441	27539	27664
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4199400	4267681	4586034	4664425	4550652
2.3.1 सोना	247723	272328	300065	298092	292779
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3951694	3995371	4285987	4366350	4257890
2.4 पूंजी खाता	1173033	1292910	1235252	1319795	1221533
2.5 अन्य मदें (निवल)	183626	185667	92656	97901	85509

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	2020-21	मार्च 31 /माह के अंतिम शुक्रवारों/शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया						
		2021						
		जन. 1	नवं. 26	दिसं. 3	दिसं. 10	दिसं. 17	दिसं. 24	दिसं. 31
	1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	3599981	3322152	3736107	3764934	3742918	3788238	3744266	3802775
1 घटक								
1.1 संचलन में मुद्रा	2853763	2770377	2983295	2984193	3000647	2998477	2996038	2986901
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां	698867	509365	704368	732507	693849	741305	697251	764828
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	42410	48443	48235	48423	48456	50977	51045
2 स्रोत								
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1099686	1102053	1177312	1309946	1266149	1127230	1091480	1194335
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-378066	-630217	-726053	-832999	-810981	-615205	-622634	-664928
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	8709	11496	2135	2067	2140	1945	2130	2094
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4199400	4269569	4597067	4605630	4642680	4664425	4595536	4550652
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26681	27539	27539	27539	27539	27539	27664
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1356660	1457429	1341893	1347249	1384610	1417697	1349785	1307042

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवारों/ माह के रिपोर्टिंग शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020	2021		
		दिसं. 18	नवं. 19	दिसं. 17	दिसं. 31
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	14960961	14314736	15634295	15720406	16103094
1.1.1 मांग जमाराशियां	1861193	1564598	1820862	1857984	2066651
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	13099768	12750138	13813433	13862422	14036443
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5894896	5737562	6216045	6238090	6316400
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	78702	67260	56026	73916	84894
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	7204873	7012576	7597388	7624332	7720044
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	244025	251545	260325	270304	269971
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	16378019	15878502	16720791	16880922	17244818
2.1.1 सरकार को ऋण	4461632	4411845	4582873	4599330	4607365
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11916387	11466657	12137918	12281592	12637453
2.1.2.1 बैंक ऋण	10949509	10547037	11162194	11313933	11680480
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	10888255	10453884	11079778	11228353	11591800
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	23633	9647	9273	7927	6589
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	894	1759	1622	1363	869
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	942351	908214	964828	958369	949514
2.2 वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	238802	193391	239502	213904	204416
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	454866	418715	456666	436485	418116
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	152552	164224	144821	147027	138760
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	63512	61101	72344	75554	74940
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	1010202	1040155	1498308	1401403	1475543
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	542693	488262	683604	693730	716432
2.3.2 उपलब्ध नकदी	90748	84934	98432	92469	94182
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-376761	-466959	-716272	-615205	-664928
2.4 पूंजी खाता	1578041	1555153	1734895	1733570	1730885
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	843995	990613	829084	771949	820827
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	593095	553551	536420	547007	559684
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	80681	69404	32065	34218	29767

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	26 मार्च 2021 की स्थिति	2020	2021		
		दिसं. 18	नवं. 19	दिसं. 17	दिसं. 31
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	4462526	4413605	4584495	4600693	4608235
2 वाणिज्यिक पत्र	82584	75341	67080	57649	53140
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	9840	11241	9778	8711	8397
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	64035	70834	70047	71928	73058
3.3 अन्य	5210	5409	5111	5007	5007
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	121008	127646	116887	116484	115486
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	308904	313097	332529	334142	341692
4.3 अन्य	149325	142431	148190	146064	147470
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	31142	29618	52558	50667	38177
5.2 वित्तीय संस्थाएं	167130	132419	162752	167716	167086

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक			
	2020-21	2020	2021		2020-21	2020	2021	
		दिसं.	नवं.	दिसं.		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6	7	8
सूचना देने वाले बेंकों की संख्या	209	208	211	212	133	132	135	136
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	**259530**	**269495**	**240488**	**254662**	**254589**	**264487**	**235957**	**250071**
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	200585	208104	180927	190557	195866	203319	176748	186316
1.2 बैंकों से उधार राशि	40886	44060	37571	37900	40880	44058	37564	37883
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	18059	17331	21989	26204	17843	17110	21645	25873
2 अन्य के प्रति देयताएं	**16457782**	**15805240**	**17096687**	**17592142**	**16014145**	**15372567**	**16654491**	**17146449**
2.1 कुल जमाराशियां	15540152	14904791	16212125	16670206	15113512	14488370	15784717	16241854
2.1.1 मांग	1899343	1601779	1880478	2109729	1861193	1565783	1840383	2066651
2.1.2 मीयादी	13640809	13303012	14331647	14560478	13252320	12922587	13944334	14175203
2.2 उधार	248271	257321	267747	274394	244025	252891	263467	269971
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	669359	643127	616815	647542	656607	631306	606307	634624
3 रिज़र्व बैंक से उधार	**90275**	**77318**	**93677**	**102489**	**90275**	**77318**	**93677**	**102489**
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अन्य	90275	77318	93677	102489	90275	77318	93677	102489
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	650745	557529	777305	830773	633440	542590	757991	810615
4.1 उपलब्ध नकदी	92793	86836	103870	96489	90748	84872	101328	94182
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	557951	470693	673435	734284	542693	457719	656663	716432
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	**265729**	**264863**	**268815**	**288252**	**197541**	**204254**	**213515**	**226894**
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	179430	180945	185698	192589	143294	147352	151303	156132
5.1.1 चालू खाते में	16796	17423	15520	19253	14226	15174	12961	16055
5.1.2 अन्य खातों में	162634	163522	170178	173336	129068	132178	138342	140077
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	36716	31389	27208	32082	10654	8512	9590	12048
5.3 बैंकों को अग्रिम	19908	21271	24033	30207	16764	20573	23599	28574
5.4 अन्य आस्तियां	29675	31259	31876	33373	26829	27817	29024	30139
6 निवेश	**4598924**	**4537040**	**4728243**	**4752753**	**4462526**	**4403341**	**4582167**	**4608235**
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	4591896	4528809	4720370	4745686	4461632	4401696	4580669	4607365
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7029	8231	7873	7067	894	1645	1499	869
7 बैंक ऋण	**11297014**	**10926301**	**11548488**	**12037369**	**10949509**	**10587475**	**11199939**	**11680480**
7क खाद्यान्न ऋण	91653	126156	121828	124497	61254	95754	86011	88680
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	11081668	10752941	11337403	11812259	10736491	10416107	10990885	11457609
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	30896	22894	31807	34268	30531	22629	31793	34255
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	128831	101639	127812	136359	127883	100728	126685	135027
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	20762	18020	18228	20865	20394	17727	17978	20446
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	34857	30808	33240	33619	34210	30285	32598	33143

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

क्षेत्र	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 26, 2021	2020	2021		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		दिसं. 18	नवं. 19	दिसं. 31	2021-22	2021
	1	2	3	4	%	%
I. सकल बैंक ऋण (II+III)	**10949509**	**10702596**	**11162247**	**11683413**	**6.7**	**9.2**
II. खाद्यान्न ऋण	**61254**	**92545**	**82415**	**88680**	**44.8**	**-4.2**
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	**10888255**	**10610052**	**11079831**	**11594733**	**6.5**	**9.3**
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	**1280240**	**1237957**	**1344129**	**1417969**	**10.8**	**14.5**
2. उद्योग	**2899531**	**2774549**	**2865403**	**2985278**	**3.0**	**7.6**
2.1 सूक्ष्म और लघु[1]	387220	371463	410646	447566	15.6	20.5
2.2 मझौले	136108	120242	183668	224255	64.8	86.5
2.3 बड़े	2376203	2282844	2271089	2313458	-2.6	1.3
3. सेवाएं	**2673753**	**2569512**	**2626577**	**2848108**	**6.5**	**10.8**
3.1 परिवहन परिचालक	137405	134191	132364	141056	2.7	5.1
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	19219	17594	18720	19712	2.6	12.0
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	49085	49614	50282	52760	7.5	6.3
3.4 शिपिंग	7188	7217	7469	7026	-2.3	-2.6
3.5 नौवहन	25643	23436	26771	12229	-52.3	-47.8
3.6 पेशेवर सेवाएं	105333	103760	101363	105280	-0.1	1.5
3.7 व्यापार	599158	561052	588738	644771	7.6	14.9
3.7.1 थोक व्यापार	310377	269945	303758	329918	6.3	22.2
3.7.2 खुदरा व्यापार	288780	291108	284979	314853	9.0	8.2
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	264889	260768	260262	270860	2.3	3.9
3.9 गैर -बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)[2] जिसमें से	940205	883392	920630	1002081	6.6	13.4
3.9.1 आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	215617	179730	220855	229942	6.6	27.9
3.9.2 सरकारी वित्तीय संस्थाएं (पीएफआई)	78442	57491	90751	108035	37.7	87.9
3.10 अन्य सेवाएं [3]	525628	528488	519979	592334	12.7	12.1
4 व्यक्तिगत ऋण	**2857789**	**2701738**	**2985430**	**3087845**	**8.1**	**14.3**
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	8812	8435	12313	13115	48.8	55.5
4.2 आवास	1460091	1392259	1490157	1521439	4.2	9.3
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	63676	58829	64797	73011	14.7	24.1
4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	4419	4705	4714	4820	9.1	2.5
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	116549	110350	122111	124743	7.0	13.0
4.6 शिक्षा	63969	64843	63452	63213	-1.2	-2.5
4.7 वाहन ऋण	269706	258062	275249	279485	3.6	8.3
4.8 सोने के आभूषण पर ऋण	60849	48859	65630	70871	16.5	45.1
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	809718	755397	887007	937148	15.7	24.1
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र *(मेमो)*						
5.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां[4]	1244276	1201642	1283063	1346408	8.2	12.0
5.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम[5]	1134976	1148883	1099438	1253505	10.4	9.1
5.3 मध्यम उद्यम [6]	207870	183825	242069	276485	33.0	50.4
5.4 आवास	470325	468365	444762	468623	-0.4	0.1
5.5 शिक्षा ऋण	48201	50574	47039	46884	-2.7	-7.3
5.6 नवीकरणीय ऊर्जा	1171	1481	1244	1764	50.7	19.2
5.7 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर	2448	1909	2331	2333	-4.7	22.2
5.8 निर्यात ऋण [7]	19028	15322	16969	31545	65.8	105.9
5.9 अन्य	10726	9627	17303	19273	79.7	100.2
5.10 नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	816816	794582	862276	897351	9.9	12.9

टिप्पणी : 1. डाटा अनंतिम हैं। सकल बैंक ऋण और गैर -खाद्य ऋण का डाटा धारा -42 रिटर्न पर आधारित है, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (एससीबी) शामिल किया गया है, जब कि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण डाटा क्षेत्र-वार पर और उद्योग-वार बैंक ऋण(एसआईबीसी) रिटर्न, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कुल गैर खादय ऋण के लगभग 90 प्रतिशत के चुनिंदा बैंकों को समाविष्ट किया गया है। टिप्पणी 2: जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं। 3: क्रमांक I, II और III के लिए, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर की गणना 1 जनवरी 2021 की तुलना में 31 दिसंबर 2021 को बकाया ऋण के आधार पर की गई थी। हालांकि, चूंकि एसआईबीसी डेटा केवल 18 दिसंबर 2020 के पखवाड़े के लिए उपलब्ध है, क्षेत्रीय ऋण की वृद्धि दर की गणना को 18 दिसंबर 2020 की तुलना में 31 दिसंबर 2021को की गई है।

1. सूक्ष्म और लघु में विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. अन्य सेवाओं के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
4. कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यकलापों के अंतर्गत प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल है।
5. सूक्ष्म और लघु उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋणऔर पीएसएलसी भी शामिल हैं।
6. मध्यम उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल हैं।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	26 मार्च, 2021	2020	2021		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		दिसं. 18	नवं. 19	दिसं. 31	2021-22	2021
	1	2	3	4	%	%
1 उद्योग (2.1 से 2.19)	2899531	2774549	2865403	2985278	3.0	7.6
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	46185	44820	51080	52100	12.8	16.2
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	153382	155377	143214	164290	7.1	5.7
1.2.1 चीनी	25519	26816	16763	20748	–18.7	–22.6
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	18972	18194	17251	19369	2.1	6.5
1.2.3 चाय	4273	4375	4933	5155	20.6	17.8
1.2.4 अन्य	104619	105993	104267	119017	13.8	12.3
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	15978	14518	15760	15794	–1.1	8.8
1.4 वस्त्र	200810	190465	200578	212884	6.0	11.8
1.4.1 सूती वस्त्र	90549	86597	85002	91792	1.4	6.0
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	2726	2541	2769	2995	9.9	17.9
1.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	38861	35282	41555	42667	9.8	20.9
1.4.4 अन्य वस्त्र	68674	66046	71252	75430	9.8	14.2
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	10467	10364	10330	10868	3.8	4.9
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	13533	13110	13363	14259	5.4	8.8
1.7 काग़ज़ और काग़ज़ से बने उत्पाद	35507	34397	36849	38234	7.7	11.2
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	66909	56502	67963	86527	29.3	53.1
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	192444	175873	191240	198293	3.0	12.7
1.9.1 उवर्रक	32241	37885	29327	30236	–6.2	–20.2
1.9.2 औषधि और दवाइयां	51754	49261	52133	54700	5.7	11.0
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	45621	34977	43178	42497	–6.8	21.5
1.9.4 अन्य	62827	53749	66602	70860	12.8	31.8
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	54483	51302	61748	65349	19.9	27.4
1.11 कांच और कांच के सामान	6344	6802	5714	5810	–8.4	–14.6
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	54291	58864	44765	46586	–14.2	–20.9
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	329047	329824	277870	286405	–13.0	–13.2
1.13.1 लोहा और स्टील	232988	242265	186191	187331	–19.6	–22.7
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	96059	87558	91678	99074	3.1	13.2
1.14 सभी अभियांत्रिकी	148152	144210	149368	155875	5.2	8.1
1.14.1 इलेक्ट्रानिक्स	34013	33532	36359	37587	10.5	12.1
1.14.2 अन्य	114138	110677	113009	118289	3.6	6.9
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	83188	84260	84872	84887	2.0	0.7
1.16 रत्न और आभूषण	63448	70108	70141	67881	7.0	–3.2
1.17 निर्माण	94565	101230	95881	95644	1.1	–5.5
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1092611	1023831	1115313	1135536	3.9	10.9
1.18.1 पावर	567584	553919	576805	591639	4.2	6.8
1.18.2 दूरसंचार	112120	101195	110269	114040	1.7	12.7
1.18.3 सड़क	237095	201322	246836	248869	5.0	23.6
1.18.4 हवाई अड्डा	7327	6179	7570	7510	2.5	21.5
1.18.5 बंदरगाह	7363	8461	7546	7268	–1.3	–14.1
1.18.6 रेलवे	11261	12287	13790	10079	–10.5	–18.0
1.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	149861	140466	152497	156131	4.2	11.2
1.19 अन्य उद्योग	238189	208691	229353	248056	4.1	18.9

टिप्पणी : जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2020-21	2020	2021						
		नवं. 27	सितं. 24	अक्टू. 08	अक्टू. 22	अक्टू. 29	नवं. 05	नवं. 19	नवं. 26
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	32	33	33	33	33	33	33	33
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	**125859.6**	**124549.5**	**125238.2**	**126845.4**	**127303.3**	**128013.9**	**127248.2**	**126843.4**	**126631.3**
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	**23736.9**	**22922.9**	**26961.0**	**25556.0**	**25393.8**	**25243.2**	**26361.0**	**24421.0**	**23568.9**
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	4896.9	3926.9	5734.8	5387.3	5285.9	5539.9	6114.8	5879.7	5294.8
2.1.1.2 अन्य	13,899.4	13488.9	14619.8	14657.9	14799.4	14672.8	14884.2	13527.1	13473.5
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	0.0	999.7	749.8	279.9	80.0	309.8	174.9	150.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	4940.6	5507.1	5606.6	4761.0	5028.6	4950.5	5052.1	4839.4	4650.6
2.2 मीयादी देयताएं	**179957.5**	**170541.9**	**168977.8**	**170167.9**	**171836.3**	**171867.5**	**172989.1**	**174852.8**	**175629.1**
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	65333.7	57870.7	56505.0	56018.2	57474.2	56659.6	58734.0	58455.0	59386.8
2.2.1.2 अन्य	111960.2	111060.7	110618.4	112187.5	112503.9	113341.1	112364.0	113316.3	113157.7
2.2.2 बैंकों से उधार	630.0	629.9	911.0	985.1	910.1	927.5	910.1	910.1	910.1
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	2033.7	980.6	943.3	977.1	948.0	939.3	980.9	2171.4	2174.4
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	63559.8	58609.1	54926.2	55750.0	57812.6	58096.5	57950.6	60487.7	62398.8
4.1 मांग	15691.8	14440.6	12031.5	12308.4	12150.6	12222.9	11745.3	12210.4	12380.4
4.2 मीयादी	47868.0	44168.5	42894.6	43441.6	45661.9	45873.6	46205.3	48277.2	50018.4
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	**8151.1**	**7139.8**	**8940.2**	**9036.9**	**8911.0**	**9282.9**	**9058.6**	**9268.7**	**9075.7**
5.1 उपलब्ध नकदी	570.3	554.2	640.7	633.1	672.7	722.8	631.3	722.6	691.6
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	7580.8	6585.6	8299.5	8403.8	8238.2	8560.1	8427.3	8546.1	8384.1
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	**1148.1**	**947.3**	**1223.7**	**1165.1**	**1217.3**	**1299.6**	**1283.3**	**1280.3**	**1215.4**
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**64455.2**	**60795.8**	**70603.5**	**70631.0**	**70288.0**	**71010.3**	**71104.6**	**71886.2**	**73814.2**
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	**28835.7**	**24696.5**	**20170.1**	**19721.6**	**20940.3**	**20265.8**	**20550.8**	**22786.2**	**21853.7**
9 बैंक ऋण (10.1+11)	**114631.6**	**110586.0**	**106670.5**	**107983.1**	**107964.4**	**107241.8**	**107467.1**	**107529.9**	**107879.4**
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	**114612.1**	**110566.8**	**106650.9**	**107962.5**	**107943.9**	**107221.4**	**107446.6**	**107509.4**	**107858.5**
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	89429.1	84270.3	88508.1	91408.2	94217.9	95223.9	95541.5	97554.3	99264.9
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	19.5	19.1	19.6	20.6	20.5	20.4	20.5	20.5	20.8

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)

समूह/उप समूह	2020-21			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	दिसं. '20	नवं.'21	दिसं.'21(अ)	दिसं.'20	नवं.'21	दिसं.'21(अ)	दिसं.'20	नवं.'21	दिसं.'21(अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	**156.7**	**161.1**	**158.3**	**159.6**	**167.5**	**165.8**	**163.4**	**173.5**	**172.2**	**161.0**	**169.7**	**168.2**
1.1 अनाज और उत्पाद	145.4	149.9	146.8	143.4	146.9	147.4	148.0	151.0	151.6	144.9	148.2	148.7
1.2 मांस और मछली	185.2	192.4	187.7	187.5	199.8	197.0	194.8	204.9	202.2	190.1	201.6	198.8
1.3 अंडा	160.3	164.8	162.0	173.4	171.5	176.5	178.4	175.4	180.0	175.3	173.0	177.9
1.4 दूध और उत्पाद	154.1	154.4	154.2	154.0	159.1	159.8	154.4	159.6	160.0	154.1	159.3	159.9
1.5 तेल और चर्बी	148.2	139.9	145.2	154.8	198.4	195.8	144.1	175.8	173.5	150.9	190.1	187.6
1.6 फल	146.9	153.4	149.9	147.0	153.2	152.0	152.6	160.3	158.3	149.6	156.5	154.9
1.7 सब्जी	174.2	196.2	181.7	187.8	183.9	172.4	206.8	229.1	219.5	194.2	199.2	188.4
1.8 दाल और उत्पाद	154.4	156.0	154.9	159.5	165.4	164.4	162.1	165.1	164.2	160.4	165.3	164.3
1.9 चीनी और उत्पाद	114.4	117.0	115.3	113.8	122.1	120.6	116.3	123.1	121.9	114.6	122.4	121.0
1.10 मसाले	161.9	160.4	161.4	164.5	170.8	171.7	163.0	167.2	168.2	164.0	169.6	170.5
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	149.8	141.3	146.3	156.1	169.1	169.7	145.9	156.1	156.5	151.8	163.7	164.2
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	163.2	165.5	164.3	164.3	174.3	175.1	167.2	176.8	178.1	165.6	175.5	176.5
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	**181.8**	**188.7**	**183.6**	**184.6**	**191.4**	**190.9**	**191.8**	**197.0**	**196.8**	**186.5**	**192.9**	**192.5**
3 कपड़ा और जूते	**155.6**	**149.7**	**153.3**	**156.8**	**169.8**	**171.2**	**150.2**	**159.7**	**160.7**	**154.2**	**165.8**	**167.0**
3.1 कपड़ा	156.4	152.0	154.7	157.5	170.4	171.9	152.5	162.3	163.3	155.5	167.2	168.5
3.2 जूते	151.1	137.2	145.3	152.4	166.0	167.3	137.3	145.3	146.7	146.1	157.4	158.7
4 आवास	-	**157.2**	**157.2**	-	-	-	**157.7**	**164.2**	**163.4**	**157.7**	**164.2**	**163.4**
5 ईंधन और लाइट	**149.1**	**140.9**	**146.0**	**150.9**	**165.3**	**165.6**	**142.9**	**161.6**	**161.7**	**147.9**	**163.9**	**164.1**
6 विविध	**153.9**	**146.1**	**150.2**	**155.9**	**165.2**	**166.0**	**147.6**	**157.3**	**157.8**	**151.9**	**161.4**	**162.0**
6.1 घरेलू सामान और सेवा	152.9	145.2	149.3	153.9	162.9	163.9	145.7	155.2	156.0	150.0	159.3	160.2
6.2 स्वास्थ्य	160.3	151.3	156.9	162.5	173.4	174.0	154.1	164.2	165.1	159.3	169.9	170.6
6.3 परिवहन और संचार	144.9	135.0	139.7	147.5	158.9	160.1	136.9	151.2	151.6	141.9	154.8	155.6
6.4 मनोरंजन	154.0	144.3	148.5	155.1	163.8	164.5	145.4	156.7	157.6	149.6	159.8	160.6
6.5 शिक्षा	162.5	156.2	158.9	163.5	169.3	169.7	156.1	160.8	160.6	159.2	164.3	164.4
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	153.7	155.8	154.5	156.2	162.4	162.8	157.7	161.8	162.4	156.8	162.2	162.6
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**156.1**	**154.4**	**155.3**	**158.5**	**167.6**	**167.0**	**156.0**	**165.6**	**165.1**	**157.3**	**166.7**	**166.1**

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।
अ: अनंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2020-21	2020	2021	
				दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	-	118.8	125.7	125.4
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1034	1047	1092	1097
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	–	1040	1053	1101	1106

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2020-21	2020	2021	
		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	48723	49444	48193	47890
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	59283	64757	64667	61280

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
			दिसं.	अक्टू.	नवं. (अ)	दिसं. (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	**100.000**	**123.4**	**125.4**	**140.7**	**142.9**	**142.4**
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	**22.618**	**145.7**	**148.0**	**163.0**	**168.6**	**167.8**
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	**15.256**	**160.7**	**161.1**	**171.6**	**178.4**	**176.5**
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	159.3	157.4	163.7	164.8	165.1
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	179.2	180.7	208.2	235.1	227.0
1.1.1.3 दूध	4.440	153.4	154.1	157.3	157.5	157.3
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	151.2	151.2	161.4	163.4	161.3
1.1.1.5 मसाले	0.529	149.5	153.2	161.6	161.6	165.8
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	162.0	164.4	164.5	166.1	167.0
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	**4.119**	**130.5**	**138.0**	**153.7**	**157.0**	**164.2**
1.1.2.1 फाइबर	0.839	119.8	123.5	156.1	164.2	166.8
1.1.2.2 तिलहन	1.115	161.7	164.4	199.7	202.3	210.1
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	109.0	113.8	119.9	120.7	121.9
1.1.2.4 फूल	0.204	210.0	285.0	217.9	228.7	309.8
1.1.3 खनिज	**0.833**	**164.9**	**172.2**	**178.7**	**190.3**	**178.7**
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	159.8	168.2	169.4	183.8	169.4
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	183.1	186.3	211.2	213.0	211.2
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	**2.410**	**70.4**	**74.1**	**118.9**	**119.2**	**115.4**
1.2 ईंधन और बिजली	**13.152**	**94.0**	**96.9**	**126.0**	**131.7**	**128.2**
1.2.1 कोल	**2.138**	**126.6**	**127.0**	**128.9**	**130.4**	**130.9**
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	141.8	141.9	143.4	143.4	143.4
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.3	119.8	119.8	119.8	119.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	130.9	131.1	166.0	200.5	212.6
1.2.2 खनिज तेल	**7.950**	**79.2**	**81.1**	**128.9**	**137.8**	**131.9**
1.2.3 बिजली	**3.064**	**109.6**	**116.9**	**116.7**	**116.7**	**116.7**
1.3 विनिर्मित उत्पाद	**64.231**	**121.5**	**123.3**	**135.9**	**136.1**	**136.4**
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	**9.122**	**141.4**	**144.0**	**158.5**	**157.0**	**156.6**
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	137.2	137.6	142.4	142.4	143.8
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस,मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	139.0	135.4	146.5	144.9	143.6
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	120.2	121.8	122.1	121.9	121.7
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	143.5	155.0	187.3	182.4	181.1
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	146.9	146.6	148.8	147.9	147.8
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	143.5	141.6	146.0	147.3	146.6
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	115.9	119.1	130.3	135.1	138.1
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	138.1	138.9	145.6	147.2	149.2
1.3.1.9 चीनी,गुड़ और शहद	1.163	118.4	118.2	127.9	125.7	125.2
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	128.0	128.1	131.3	130.1	133.0
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	132.3	131.6	139.0	133.4	131.4
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	166.5	161.1	168.4	170.3	172.8
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	147.0	149.1	155.9	154.8	157.7
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	132.2	133.2	135.4	135.3	136.4
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	142.9	137.9	154.6	154.3	153.1
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	170.5	171.4	201.0	198.6	197.6
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	**0.909**	**124.5**	**123.0**	**127.4**	**127.5**	**127.2**
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	120.2	119.3	123.7	124.0	123.8
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	126.5	124.3	131.6	131.4	131.7
1.3.2.3 शीतल पेय,मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	129.4	127.6	129.4	129.4	128.5
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	**0.514**	**157.2**	**157.2**	**160.2**	**160.7**	**161.5**
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	157.2	157.2	160.2	160.7	161.5

सं. 21ः थोक मूल्य सूचकांक *(जारी)*

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
			दिसं.	अक्टू.	नवं. (अ)	दिसं. (अ)
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	**4.881**	**117.6**	**119.1**	**134.8**	**137.1**	**139.1**
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	106.6	108.5	127.1	130.8	133.4
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	131.7	133.3	147.0	147.7	149.6
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	115.2	114.2	124.1	126.8	127.0
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	132.3	132.5	138.9	139.8	141.1
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	155.6	159.4	169.9	170.5	167.1
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	116.3	115.1	127.8	127.9	128.2
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	**0.814**	**138.6**	**139.2**	**144.2**	**144.6**	**144.0**
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	138.1	138.0	142.9	143.3	142.4
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉस्चिटेड वस्त्र	0.221	139.8	142.2	147.8	147.9	148.5
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	**0.535**	**117.9**	**118.6**	**119.0**	**118.7**	**119.3**
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	101.1	100.9	104.4	103.1	102.5
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	138.6	138.6	140.0	141.9	142.5
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	120.6	121.8	120.5	120.2	121.3
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	**0.772**	**134.6**	**135.3**	**141.4**	**142.6**	**143.0**
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	120.7	121.1	130.8	131.4	131.6
1.3.7.2 विनियर शीट,प्लायवुड का विनिर्माण,लॅमिन बोर्ड,पार्टिकल बोर्डऔर अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	136.6	137.1	141.9	142.5	144.1
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	185.8	188.5	194.5	194.4	194.5
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	125.7	126.6	134.2	139.0	134.4
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	**1.113**	**121.7**	**121.3**	**137.2**	**139.0**	**140.8**
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	124.1	123.1	141.4	143.8	145.3
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	122.2	124.1	139.5	137.9	138.2
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	117.4	115.5	128.0	132.4	136.2
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	**0.676**	**153.8**	**155.5**	**157.0**	**156.4**	**161.5**
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	153.8	155.5	157.0	156.4	161.5
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	**6.465**	**118.2**	**119.7**	**134.3**	**135.6**	**136.9**
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	118.6	119.8	146.5	148.5	149.5
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	123.6	123.7	128.3	129.6	131.1
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिथेंटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	116.7	121.7	141.9	143.0	142.3
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	124.4	125.8	131.6	132.4	133.9
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	114.9	115.7	131.0	132.4	137.0
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट,सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	120.6	121.7	129.0	129.7	130.8
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	115.1	115.1	131.0	132.5	134.0
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	93.7	95.7	108.3	108.8	109.2
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	**1.993**	**130.9**	**131.9**	**136.0**	**136.0**	**137.3**
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	130.9	131.9	136.0	136.0	137.3
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	**2.299**	**111.3**	**114.4**	**126.7**	**127.0**	**127.0**
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब,रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.3	98.7	104.1	104.8	106.5
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	93.3	93.3	102.2	102.0	104.8
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	120.3	125.2	141.2	141.4	140.0
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	**3.202**	**117.6**	**117.4**	**123.8**	**124.6**	**125.1**
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	127.2	127.8	137.2	136.5	141.1
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	109.5	109.7	115.4	116.2	118.8
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	109.3	110.8	124.3	117.5	120.9
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	109.5	109.7	111.6	112.2	114.3
1.3.13.5 सीमेन्ट,चूना और प्लास्टर	1.645	120.9	119.7	126.5	128.7	127.7

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(जारी)*

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
			दिसं.	अक्टू.	नवं. (अ)	दिसं. (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट,सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	125.3	127.1	128.4	129.3	129.5
1.3.13.7 पत्थरों को काटना,आकार देना और संवारना	0.234	121.1	121.0	123.4	123.3	120.4
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	78.9	81.3	92.4	89.2	96.6
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	**9.646**	**111.4**	**115.8**	**143.9**	**143.9**	**141.5**
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	109.2	116.2	161.6	162.6	153.3
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	113.3	120.8	151.2	150.4	145.2
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	99.8	103.2	120.9	119.4	118.3
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	112.0	118.2	140.8	140.0	139.1
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	117.2	123.5	159.7	163.4	160.6
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	108.3	113.5	136.1	133.6	131.1
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	108.7	107.7	147.2	147.8	142.7
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	127.9	129.8	159.9	159.7	161.8
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	112.3	117.7	142.9	141.3	142.8
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	109.1	109.2	119.0	118.5	119.2
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	145.7	146.5	157.6	160.2	160.6
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	**3.155**	**115.9**	**117.9**	**130.9**	**131.6**	**133.6**
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	114.1	116.3	123.5	123.9	126.9
1.3.15.2 धातु से बने टैंक,जलाशय और डिब्बे	0.660	127.8	132.8	157.6	158.6	161.4
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	98.9	97.2	97.1	97.5	97.6
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	96.7	95.1	117.9	120.1	120.0
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	102.9	103.6	108.7	109.7	109.7
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	125.0	126.8	136.9	137.0	139.2
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	**2.009**	**109.8**	**109.7**	**113.4**	**113.6**	**113.2**
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	99.1	99.9	105.7	106.2	106.7
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	134.8	134.4	134.7	134.9	134.9
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	114.9	114.6	119.3	119.8	119.8
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स	0.641	98.5	97.5	102.8	103.3	100.9
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	107.7	109.6	107.1	107.1	108.5
1.3.16.6 हाथ घडी और दीवार घडी	0.076	141.8	141.7	145.4	145.9	146.5
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	102.8	102.8	108.6	102.9	107.1
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	102.7	95.2	98.5	98.5	98.4
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	**2.930**	**113.6**	**115.1**	**123.2**	**121.9**	**123.5**
1.3.17.1 विद्युतमोटर्स,जनरेटर,ट्रांसफार्मरऔरबिजलीवितरणऔरनियंत्रणसंबंधीउपकरण	1.298	113.2	114.9	120.6	117.7	121.0
1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्युलेटर	0.236	117.1	115.4	123.8	123.7	124.1
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	98.1	100.2	103.7	102.4	100.6
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रानिक और बिज़ली के वायर और केबल	0.428	115.9	119.5	141.9	141.8	141.7
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	111.1	111.6	114.9	114.6	115.5
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	119.7	120.4	128.7	129.4	130.4
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	109.5	111.6	113.2	113.2	113.4
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	**4.789**	**114.0**	**114.6**	**120.4**	**120.7**	**120.8**
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन,एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	106.3	107.4	120.6	120.5	121.5
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	119.4	120.8	121.4	121.7	122.1
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	111.6	111.5	115.0	116.0	116.0
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	111.8	113.5	118.3	118.7	118.0
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	80.2	83.6	73.2	73.1	73.0
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने –उतारने वाले उपकरण	0.285	113.4	114.4	120.0	119.9	121.3

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(समाप्त)*

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
			दिसं.	अक्टू.	नवं. (अ)	दिसं. (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	128.7	127.3	133.0	132.9	130.6
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	121.6	121.3	129.4	129.7	130.1
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	108.4	107.6	116.0	116.0	115.8
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.7	75.8	78.3	78.7	78.7
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	128.0	131.9	131.9	132.6	131.0
1.3.18.13 कपड़ा,परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	121.9	123.4	123.7	124.0	126.2
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	128.7	130.4	134.2	134.6	135.7
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	65.2	65.7	66.7	66.3	66.8
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	**4.969**	**117.8**	**118.4**	**122.9**	**123.2**	**123.9**
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	119.4	120.6	122.3	123.2	123.8
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	116.1	116.1	123.6	123.1	124.1
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	**1.648**	**126.2**	**127.5**	**132.4**	**132.6**	**133.0**
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली –वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.9	158.9	158.9
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टाक	0.110	105.0	104.8	105.1	104.5	103.8
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	124.7	126.1	131.8	132.2	132.6
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाडी	0.117	130.3	132.7	137.3	137.9	138.0
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	128.5	129.3	136.9	136.6	137.4
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	**0.727**	**133.2**	**135.1**	**151.0**	**150.6**	**151.4**
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	133.2	135.1	151.0	150.6	151.4
1.3.22 अन्य विनिर्माण	**1.064**	**132.4**	**134.4**	**138.1**	**136.6**	**137.1**
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	130.5	132.7	136.2	134.6	135.2
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	173.7	164.3	190.5	192.6	195.7
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	132.0	131.9	141.1	142.1	142.6
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	142.4	143.1	149.6	151.6	151.1
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	167.4	168.1	172.9	172.9	171.1
2 खाद्य सूचकांक	**24.378**	**153.4**	**154.7**	**166.7**	**170.4**	**169.0**

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)

उद्योग	भारांक	2019-20	2020-21	अप्रैल- नवंबर		नवंबर	
				2020-21	2021-22	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	129.0	118.1	108.5	127.4	126.7	128.5
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	109.6	101.0	89.5	105.8	106.6	111.9
1.2 विनिर्माण	77.63	129.6	117.2	107.2	127.0	128.5	129.6
1.3 बिजली	7.99	158.4	157.6	154.4	170.2	144.8	147.9
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	127.0	118.1	110.4	125.0	122.2	126.5
2.2 पूंजीगत माल	8.22	93.3	75.9	64.9	83.7	84.3	81.2
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	137.7	124.7	113.0	139.8	138.4	141.8
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	136.6	124.7	112.1	142.9	137.3	142.5
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	119.0	101.2	88.5	109.7	113.0	106.7
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	145.3	142.1	136.3	145.0	149.1	150.3

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(करोड़ ₹)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल - दिसंबर			
	2021-22 (बजट आकलन)	2021-22 (वास्तविक)	2020-21 (वास्तविक)	बजट आकलनों का प्रतिशत	
				2021-22	2020-21
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	**2078936**	**1733223**	**1088580**	**83.4**	**70.0**
1.1 कर राजस्व (निवल)	1765145	1473809	962399	83.5	71.6
1.2 करेतर राजस्व	313791	259414	126181	82.7	59.9
2 गैरेतर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	**99975**	**28469**	**33098**	**28.5**	**71.2**
2.1 ऋण की वसूली	21975	19105	14202	86.9	98.0
2.2 अन्य प्राप्तियां	78000	9364	18896	12.0	59.1
3 कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	**2178911**	**1761692**	**1121678**	**80.9**	**70.0**
4 राजस्व व्यय	3167289	2129414	1971173	67.2	65.5
4.1 ब्याज भुगतान	813791	564414	472171	69.4	68.1
5 पूंजी व्यय	602711	391644	308974	65.0	70.4
6 कुल व्यय (4+5)	**3770000**	**2521058**	**2280147**	**66.9**	**66.1**
7 राजस्व घाटा (4-1)	**1088352**	**396191**	**882593**	**36.4**	**60.6**
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	**1591089**	**759366**	**1158469**	**47.7**	**62.7**
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	**777298**	**194952**	**686298**	**25.1**	**59.4**

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय बजट 2022-23।

सं. 24: ख़ज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2020-21	2021						
		जन. 1	नवं. 26	दिसं. 3	दिसं. 10	दिसं. 17	दिसं. 24	दिसं. 31
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	5676	2499	11133	11166	11984	12039	12767	9354
1.2 प्राथमिक व्यापारी	16740	15783	31737	29783	26984	33326	29687	26882
1.3 राज्य सरकारें	13347	90891	86665	91665	95565	98315	102016	103016
1.4 अन्य	52802	116333	100079	103154	102100	96703	100679	106541
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	67473	101471	63455	61466	59320	57654	58141	56154
2.2 प्राथमिक व्यापारी	30966	27744	47832	44432	40691	39262	34421	32988
2.3 राज्य सरकारें	9436	4271	8318	6318	6318	6318	6318	6458
2.4 अन्य	31800	67852	57109	49895	43067	34218	27631	19711
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	119024	150120	110185	117220	119024	115639	119885	115964
3.2 प्राथमिक व्यापारी	154197	122449	107891	104078	105426	110194	111859	117965
3.3 राज्य सरकारें	18510	16302	19553	21643	21643	21643	17843	21643
3.4 अन्य	174501	127373	97489	97258	97677	100389	97357	99125
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	220351	131696	200002	142369	113524	103528	156242	139739
4.4 अन्य	747	183	726	851	444	754	60	761
कुल ख़ज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती ख़ज़ाना बिल को छोड़कर)#	694471	843088	741446	738079	729798	725698	718603	715802

14 दिवसीय मध्यवर्ती ख़ज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय ख़ज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: ख़ज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ			स्वीकृत बोलियां			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91-दिवसीय ख़ज़ाना बिल										
2021-22										
दिसं. 1	10000	108	46007	9501	38	9999	9501	19500	99.13	3.5243
दिसं. 8	10000	103	51182	6801	15	9999	6801	16800	99.14	3.4945
दिसं. 15	10000	84	26541	11202	48	9998	11202	21200	99.13	3.5296
दिसं. 22	10000	131	36123	13737	52	9999	13737	23736	99.09	3.7023
दिसं. 29	10000	149	66767	5051	32	9949	5051	15000	99.10	3.6570
182-दिवसीय ख़ज़ाना बिल										
2021-22										
दिसं. 1	3000	75	12006	0	22	3000	0	3000	98.13	3.8217
दिसं. 8	3000	86	12209	0	35	3000	0	3000	98.13	3.8197
दिसं. 15	3000	65	7797	0	39	3000	0	3000	98.11	3.8738
दिसं. 22	3000	90	11891	0	15	3000	0	3000	98.05	3.9795
दिसं. 29	3000	100	12645	1029	29	3000	1029	4028	98.06	3.9699
364-दिवसीय ख़ज़ाना बिल										
2021-22										
दिसं. 1	7000	124	16184	2092	88	6998	2092	9090	96.03	4.1482
दिसं. 8	7000	117	16737	0	60	7000	0	7000	96.03	4.1490
दिसं. 15	7000	106	19050	0	56	7000	0	7000	96.00	4.1750
दिसं. 22	7000	123	21735	1	49	6999	1	7000	95.93	4.2598
दिसं. 29	7000	116	22770	3800	46	7000	3800	10800	95.92	4.2650

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार		दरों का दायरा	भारित औसत दरें
		उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
		1	2
दिसंबर	1, 2021	2.00-3.50	3.27
दिसंबर	2, 2021	2.20-3.50	3.26
दिसंबर	3, 2021	2.00-3.60	3.28
दिसंबर	4, 2021	2.70-3.25	2.99
दिसंबर	6, 2021	2.00-3.45	3.26
दिसंबर	7, 2021	2.00-3.50	3.29
दिसंबर	8, 2021	2.00-3.55	3.26
दिसंबर	9, 2021	2.00-3.45	3.28
दिसंबर	10, 2021	2.00-3.45	3.28
दिसंबर	13, 2021	2.00-3.50	3.28
दिसंबर	14, 2021	2.00-3.45	3.29
दिसंबर	15, 2021	2.00-3.60	3.33
दिसंबर	16, 2021	2.00-4.50	3.53
दिसंबर	17, 2021	2.00-4.25	3.61
दिसंबर	18, 2021	2.70-3.50	3.31
दिसंबर	20, 2021	2.00-3.99	3.38
दिसंबर	21, 2021	1.50-4.00	3.52
दिसंबर	22, 2021	2.00-3.75	3.38
दिसंबर	23, 2021	2.00-3.90	3.43
दिसंबर	24, 2021	2.00-3.80	3.41
दिसंबर	27, 2021	2.00-3.95	3.26
दिसंबर	28, 2021	2.00-4.15	3.27
दिसंबर	29, 2021	2.00-3.55	3.28
दिसंबर	30, 2021	2.00-3.60	3.33
दिसंबर	31, 2021	2.00-3.80	3.45
जनवरी	1, 2022	2.70-3.70	3.27
जनवरी	3, 2022	2.00-3.50	3.29
जनवरी	4, 2022	2.00-3.50	3.28
जनवरी	5, 2022	2.00-3.45	3.21
जनवरी	6, 2022	2.00-3.45	3.21
जनवरी	7, 2022	2.10-3.65	3.26
जनवरी	10, 2022	2.10-3.60	3.31
जनवरी	11, 2022	2.10-3.65	3.36
जनवरी	12, 2022	2.10-3.55	3.33
जनवरी	13, 2022	2.10-3.45	3.27
जनवरी	14, 2022	2.10-4.10	3.41
जनवरी	15, 2022	2.65-3.60	3.07

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2020	2021			
	दिसं. 18	नवं. 19	दिसं. 3	दिसं. 17	दिसं. 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	67960.05	55596.33	63365.56	73298.30	84702.40
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	8003.34	2272.75	13977.84	12506.20	17497.20
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.08-4.44	3.59-4.22	3.59-4.83	3.53-4.72	3.74-5.31

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2020	2021			
	दिसं. 31	नवं. 15	नवं. 30	दिसं. 15	दिसं. 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	365185.05	450890.70	388363.05	446975.40	350068.65
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	87488.25	172504.00	115234.25	161701.60	87182.55
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.06-12.73	3.38-10.44	3.38-12.76	3.38-12.34	3.50-12.31

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	2020-21	2021						
		जन. 1	नवं. 26	दिसं. 3	दिसं. 10	दिसं. 17	दिसं. 24	दिसं. 31
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	17461	18634	15488	14651	16764	15776	17695	13822
2 नोटिस मुद्रा	2604	4281	912	3983	539	3653	616	3125
3 मीयादी मुद्रा	757	370	358	437	277	1003	735	640
4 त्रिपक्षीय रिपो	421118	648949	652602	829105	624321	741834	665034	834645
5 बाजार रिपो	337341	376407	402681	507154	370923	459449	337263	402671
6 कार्पोरेट बांड में रिपो	2990	1090	6203	2953	5502	1057	234	0
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	62266	73584	91112	65486	72374	70064	75085
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	62490	38420	51839	58113	50991	33208	48074	37640
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5080	7724	5137	3846	3926	4692	5237	6397
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	4970	5734	4211	2872	4649	3810	5688	4503
10.2 182-दिवसीय	4870	5985	2282	676	1778	1418	1149	1706
10.3 364-दिवसीय	4010	4851	2083	1986	1869	1884	2815	2120
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	1490							
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	82910	62714	65552	67494	63213	45012	62963	52366
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	–	4053	873	633	458	702	892	1662

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2020-21		2020-21 (अप्रै-दिसं.)		2021-22 (अप्रै-दिसं.)*		दिसं. 2020		दिसं. 2021*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	**74**	**102062**	**47**	**89390**	**124**	**130083**	**4**	**1652**	**30**	**18258**
1ए प्रीमियम	73	97648	47	85708	117	128289	4	1487	28	17906
1.1 पब्लिक	53	38004	31	28483	96	104870	3	1353	20	15681
1.1.1 प्रीमियम	53	34848	31	25576	95	103725	3	1199	20	15444
1.2 राइट्स	21	64059	16	60907	28	25212	1	299	10	2577
1.2.1 प्रीमियम	20	62800	16	60132	22	24563	1	288	8	2462
2 अधिमान शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3 बांड और डिबेंचर	**16**	**5806**	**10**	**3871**	**21**	**9589**	**–**	**–**	**1**	**456**
3.1 परिवर्तनीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अपरिवर्तनीय	16	5806	10	3871	21	9589	–	–	1	456
3.1.1 पब्लिक	16	5806	10	3871	21	9589	–	–	1	456
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 कुल (1+2+3)	**90**	**107868**	**57**	**93261**	**145**	**139671**	**4**	**1652**	**31**	**18714**
4.1 पब्लिक	69	43809	41	32354	117	114459	3	1353	21	16137
4.2 राइट्स	21	64059	16	60907	28	25212	1	299	10	2577

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कालम के आंकडे कुल में नहीं जुड़ सकते।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम है।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2020-21	2020	2021				
			दिसं.	अग.	सितं.	अक्टू.	नवं.	दिसं.
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड ₹	2159043	200295	247603	248767	267667	236501	284961
	मिलियन अमरीकी डॉलर	291808	27216	33377	33817	35729	31747	37807
1.1 तेल	करोड ₹	190896	17196	34535	38219	40219	41272	44377
	मिलियन अमरीकी डॉलर	25804	2337	4655	5195	5369	5540	5888
1.2 तेल से इतर	करोड ₹	1968147	183098	213068	210548	227447	195229	240584
	मिलियन अमरीकी डॉलर	266004	24880	28721	28621	30361	26206	31919
2 आयात	करोड ₹	2915958	315971	336112	415494	400640	394020	448353
	मिलियन अमरीकी डॉलर	394436	42935	45307	56481	53479	52891	59485
2.1 तेल	करोड ₹	611353	70863	71805	125101	93949	109327	121847
	मिलियन अमरीकी डॉलर	82684	9629	9679	17006	12541	14675	16166
2.2 तेल से इतर	करोड ₹	2304605	245107	264307	290394	306691	284693	326506
	मिलियन अमरीकी डॉलर	311752	33306	35628	39475	40938	38216	43319
3 व्यापार शेष	करोड ₹	-756914	-115676	-88509	-166727	-132973	-157519	-163392
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-102627	-15718	-11931	-22664	-17750	-21144	-21678
3.1 तेल	करोड ₹	-420457	-53667	-37270	-86881	-53729	-68055	-77470
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-56880	-7292	-5024	-11810	-7172	-9135	-10278
3.2 तेल से इतर	करोड ₹	-336458	-62009	-51238	-79846	-79244	-89464	-85922
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-45748	-8426	-6907	-10854	-10578	-12009	-11400

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2021			2022			
		जन. 29	दिसं. 24	दिसं. 31	जन. 7	जन. 14	जन. 21	जन. 28
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	**करोड ₹**	**4306005**	**4765329**	**4707812**	**4702360**	**4707359**	**4719835**	**4727298**
	मिलियन अमरीकी डॉलर	**590185**	**635080**	**633614**	**632736**	**634965**	**634287**	**629755**
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	3992516	4287220	4234327	4231613	4231207	4238297	4249350
	मिलियन अमरीकी डॉलर	547218	571369	569889	569392	570737	569582	566077
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	264803	295562	292779	290171	294839	300149	296461
	मिलियन अमरीकी डॉलर	36294	39390	39405	39044	39770	40337	39493
	मात्रा (मैट्रिक टन)	676.65	754.1	754.1	754.1	755.03	755.42	755.42
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1049	13657	13657	13657	13657	13657	13657
	करोड ₹	11006	143418	142017	141930	142491	142511	142706
	मिलियन अमरीकी डॉलर	1508	19114	19114	19098	19220	19152	19011
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	37679	39129	38690	38646	38822	38878	38780
	मिलियन अमरीकी डॉलर	5165	5207	5207	5202	5238	5216	5174

* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से हैं।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2020-21	2020	2021		2020-21	2021-22
		दिसं.	नवं.	दिसं.	अप्रै.-दिसं.	अप्रै.-दिसं.
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	**141,895**	**140,496**	**140,745**	**142,797**	**7,903**	**3,951**
1.1 एफसीएनआर (बी)	20,473	22,128	18,673	18,155	–2,116	–2,318
1.2 एनआर (ई) आरए	102,579	100,849	101,794	103,062	8,759	3,069
1.3 एनआरओ	18,842	17,520	20,279	21,581	1,260	3,200

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2020-21	2020-21	2021-22	2020	2021	
		अप्रै.-दिसं.	अप्रै.-दिसं.	दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	**43,955**	**41,277**	**25,298**	**6,239**	**1,604**	**625**
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1. 1.1.2)	**54,927**	**49,177**	**37,774**	**7,130**	**2,675**	**1,839**
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	**81,973**	**68,294**	**60,338**	**9,441**	**6,107**	**6,260**
1.1.1.1.1 इक्विटी	61,088	52,535	44,239	7,747	4,515	4,037
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	948	320	1,574	55	112	25
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	51,597	45,638	30,646	7,039	3,894	3,044
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7,091	5,512	10,953	527	384	842
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	1,452	1,065	1,065	126	126	126
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	16,935	12,417	13,129	1,464	1,464	1,464
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	3,950	3,343	2,970	230	128	759
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	**27,046**	**19,117**	**22,564**	**2,311**	**3,432**	**4,421**
1.1.1.2.1 इक्विटी	26,983	19,089	22,003	2,306	3,326	4,314
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	63	28	561	4	106	107
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	**10,972**	**7,900**	**12,476**	**891**	**1,072**	**1,215**
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	5,583	4,386	6,544	642	772	755
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3,013	2,260	2,316	251	251	251
1.1.2.3 अन्य पूंजी	6,688	3,853	5,900	491	201	381
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	4,313	2,598	2,285	493	153	172
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	**36,137**	**28,857**	**–2,039**	**8,551**	**–42**	**–3,613**
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	–	–	–	–	–	–
1.2.2 एफआईआई	38,725	30,536	–737	8,713	–255	–3,275
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	–	–	–	–	–	–
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	2,589	1,679	1,302	162	–213	338
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	**80,092**	**70,133**	**23,259**	**14,791**	**1,561**	**–2,989**

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2020-21	2020	2021		
		दिसं.	अक्टू.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	**12684.40**	**1149.17**	**1564.90**	**1547.41**	**1773.56**
1.1 जमाराशियां	680.37	35.33	46.58	50.40	56.64
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	62.75	5.05	7.43	11.01	10.77
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	471.80	38.76	55.20	57.68	54.30
1.4 उपहार	1586.24	145.15	172.06	206.21	214.59
1.5 दान	12.59	0.67	0.83	0.94	2.69
1.6 यात्रा	3239.67	322.25	464.59	456.31	884.10
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2680.10	217.30	221.56	267.22	281.46
1.8 चिकित्सा उपचार	29.75	2.82	3.11	3.30	3.33
1.9 विदेश में शिक्षा	3836.12	373.32	579.84	482.35	253.69
1.10 अन्य	85.03	8.54	13.71	11.99	11.99

सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

मद	2019-20	2020-21	2021		2022
			जनवरी	दिसंबर	जनवरी
	1	2	3	4	5
40- मुद्रा बास्केट (आधार: 2015-16=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	98.00	93.92	93.71	93.49	94.51
1.2 रीर	103.20	103.46	103.00	104.53	104.61
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	97.38	93.59	93.30	93.69	94.67
2.2 रीर	102.88	102.96	102.57	104.15	104.15
6- मुद्रा बास्केट (व्यापार-भारित)					
1 आधार : 2015-16=100					
1.1 नीर	94.92	88.47	87.34	86.64	87.58
1.2 रीर	103.62	101.88	100.74	102.70	103.42
2 आधार : 2018-19 =100					
2.1 नीर	100.78	93.93	92.73	91.98	92.99
2.2 रीर	103.32	101.59	100.45	102.41	103.12

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण

(राशि अमरीकी मिलियन डॉलर में)

मद	2020-21	2020	2021	2021
		दिसं.-20	नवं.-21	दिसं.-21
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1063	95	90	139
1.2 राशि	26799	2994	1694	4374
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	13	0	3	1
2.2 राशि	8456	0	705	1175
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1076	95	93	140
3.2 राशि	35255	2994	2399	5549
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	6.03	4.59	4.37	5.30
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारित औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.93	1.65	2.79	1.01
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-13.00	0.00-13.00	0.00-10.60	0.00-10.25
उधारकर्ता श्रेणियाँ				
I. कॉर्पोरेट विनिर्माण	12827	1868	401	442
II. कॉर्पोरेट -बुनियादी संरचना	9985	916	1110	2584
ए) परिवहन	636	338	0	109
बी) ऊर्जा	2713	219	1106	959
सी) पानी और सफ़ाई व्यवस्था	151	0	0	0
डी) संचार	757	1	1	5
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	1761	0	0	0
एफ)अन्वेषण खनन और रिफाइनरी	1346	17	0	1100
जी) अन्य उप -क्षेत्र	2622	342	3	411
III. कॉर्पोरेट सेवा क्षेत्र	1894	122	48	291
IV. अन्य संस्थाएं	1026	0	100	500
ए) एसई जेड़ में इकाई	26	0	0	0
बी) सिडबी	0			
सी) एक्जिम बैंक	1000	0	100	500
V. बैंक	0	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबी एफ सी के अलावा)	2110	0	4	0
VII. एनबीएफसी	6934	80	724	1690
ए) एनबीएफसी -आई एफ सी/ए एफ सी	6024	10	550	1275
बी) एनबी एफ सी -एमएफआई	84	15	1	17
सी) एनबीफसी - अन्य	827	55	173	398
VIII. गैर -सरकारी संगठन	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था	8	0	0	0
X. अन्य	470	8	12	42

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	जुला.-सितं. 2020			जुला.-सितं. 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**296176**	**264608**	**31568**	**404597**	**373408**	**31189**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**150791**	**135541**	**15250**	**194275**	**203886**	**-9611**
1.1 पण्य	**75591**	**90407**	**-14816**	**104842**	**149265**	**-44423**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**75200**	**45134**	**30066**	**89434**	**54621**	**34813**
1.2.1 सेवाएं	49793	28707	21086	61421	35836	25585
1.2.1.1 यात्रा	2138	2764	-626	2147	3919	-1772
1.2.1.2 परिवहन	5368	4759	609	7584	8181	-597
1.2.1.3 बीमा	590	537	53	796	575	220
1.2.1.4 जीएनआईई	144	190	-46	217	198	19
1.2.1.5 विविध	41554	20458	21096	50678	22962	27716
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	24791	2769	22021	29965	3184	26781
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	11624	12354	-730	13858	12457	1401
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1003	1107	-104	1303	1463	-160
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	661	355	306	766	275	491
1.2.2 अंतरण	20421	2035	18386	21154	2239	18915
1.2.2.1 आधिकारिक	36	270	-233	18	315	-297
1.2.2.2 निजी	20385	1766	18619	21135	1924	19212
1.2.3 आय	4986	14391	-9405	6859	16546	-9688
1.2.3.1 निवेश आय	3541	13695	-10154	5362	15792	-10430
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1445	696	749	1497	754	743
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**145010**	**129067**	**15943**	**209579**	**169522**	**40057**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**97296**	**65874**	**31422**	**132378**	**119040**	**13338**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	30502	6077	24424	20447	10987	9461
2.1.1.1 भारत में	29527	2450	27078	19281	6475	12806
2.1.1.1.1 इक्विटी	23794	2445	21350	13940	6259	7681
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	4117		4117	4482	0	4482
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1617	5	1611	859	216	643
2.1.1.2 विदेश में	974	3627	-2653	1167	4512	-3345
2.1.1.2.1 इक्विटी	974	1202	-228	1167	2060	-894
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	753	-753	0	781	-781
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1672	-1672	0	1670	-1670
2.1.2 संविभाग निवेश	66794	59796	6998	111931	108054	3877
2.1.2.1 भारत में	66420	58684	7736	110448	105904	4544
2.1.2.1.1 एफआईआई	66420	58684	7736	110448	105904	4544
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	55007	48183	6824	95335	94718	618
2.1.2.1.1.2 ऋण	11413	10501	912	15112	11186	3926
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	375	1113	-738	1483	2150	-666
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**20645**	**24532**	**-3887**	**25555**	**17965**	**7590**
2.2.1 बाह्य सहायता	3209	1323	1886	2420	1303	1117
2.2.1.1 भारत द्वारा	10	21	-11	14	30	-15
2.2.1.2 भारत को	3199	1302	1897	2406	1273	1132
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	8775	12731	-3956	9114	5004	4110
2.2.2.1 भारत द्वारा	769	1005	-235	282	249	33
2.2.2.2 भारत को	8005	11726	-3721	8832	4755	4077
2.2.3 भारत को अल्पावधि	8662	10479	-1817	14021	11658	2364
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	8662	9770	-1108	9615	11658	-2043
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	709	-709	4407	0	4407
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**18762**	**30025**	**-11263**	**20817**	**20457**	**360**
2.3.1 वाणिज्य बैंक	18749	30025	-11276	20473	20457	17
2.3.1.1 आस्तियां	7207	16747	-9539	10097	9858	239
2.3.1.2 देयताएं	11541	13279	-1737	10376	10598	-222
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	10311	8377	1934	8574	9357	-783
2.3.2 अन्य	13	0	13	344	0	344
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	2	-2	0	2	-2
2.5 अन्य पूंजी	8307	8633	-327	30829	12059	18770
3 भूल-चूक	**375**		**375**	**742**	0	**742**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**31568**	**-31568**	0	**31189**	**-31189**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)		31568	-31568	0	31189	-31189

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	जुला.-सितं. 2020			जुला.-सितं. 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**2203029**	**1968215**	**234814**	**2997726**	**2766643**	**231083**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**1121622**	**1008187**	**113435**	**1439417**	**1510625**	**-71208**
1.1 पण्य	**562264**	**672468**	**-110205**	**776788**	**1105928**	**-329140**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**559358**	**335719**	**223639**	**662629**	**404696**	**257932**
1.2.1 सेवाएं	370373	213533	156840	455079	265514	189566
1.2.1.1 यात्रा	15903	20559	-4657	15905	29037	-13132
1.2.1.2 परिवहन	39926	35397	4528	56188	60613	-4425
1.2.1.3 बीमा	4385	3994	391	5896	4263	1633
1.2.1.4 जीएनआईई	1074	1414	-339	1607	1467	141
1.2.1.5 विविध	309085	152168	156917	375483	170133	205350
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	184399	20598	163801	222016	23589	198426
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	86464	91890	-5426	102675	92295	10380
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	7462	8233	-771	9652	10836	-1184
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	4914	2638	2275	5676	2035	3641
1.2.2 अंतरण	151896	15140	136756	156732	16588	140144
1.2.2.1 आधिकारिक	269	2006	-1737	137	2334	-2198
1.2.2.2 निजी	151627	13134	138492	156596	14254	142342
1.2.3 आय	37089	107046	-69956	50817	122594	-71777
1.2.3.1 निवेश आय	26339	101868	-75528	39725	117005	-77280
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	10750	5178	5572	11092	5589	5503
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**1078616**	**960028**	**118588**	**1552809**	**1256019**	**296790**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**723708**	**489983**	**233725**	**980814**	**881990**	**98824**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	226877	45202	181675	151499	81403	70095
2.1.1.1 भारत में	219632	18223	201410	142854	47973	94880
2.1.1.1.1 इक्विटी	176987	18184	158803	103281	46371	56909
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	30620	0	30620	33210	0	33210
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	12025	39	11987	6364	1602	4761
2.1.1.2 विदेश में	7245	26980	-19735	8645	33430	-24785
2.1.1.2.1 इक्विटी	7245	8940	-1695	8645	15265	-6620
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5603	-5603	0	5789	-5789
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	12437	-12437	0	12375	-12375
2.1.2 संविभाग निवेश	496831	444780	52050	829315	800587	28729
2.1.2.1 भारत में	494044	436504	57540	818325	784660	33664
2.1.2.1.1 एफआईआई	494044	436504	57540	818325	784660	33664
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	409153	358396	50757	706356	701779	4577
2.1.2.1.1.2 ऋण	84891	78108	6783	111968	82881	29087
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	2786	8276	-5490	10991	15927	-4936
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**153564**	**182478**	**-28914**	**189343**	**133104**	**56239**
2.2.1 बाह्य सहायता	23866	9840	14026	17930	9654	8276
2.2.1.1 भारत द्वारा	71	153	-82	106	220	-114
2.2.1.2 भारत को	23795	9687	14108	17824	9434	8390
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	65268	94694	-29426	67525	37075	30451
2.2.2.1 भारत द्वारा	5722	7473	-1751	2087	1844	242
2.2.2.2 भारत को	59545	87221	-27675	65439	35231	30208
2.2.3 भारत को अल्पावधि	64430	77945	-13515	103887	86375	17512
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	64430	72671	-8241	71239	86375	-15136
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	5273	-5273	32649	0	32649
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**139558**	**223336**	**-83778**	**154236**	**151566**	**2670**
2.3.1 वाणिज्य बैंक	139459	223336	-83877	151690	151566	124
2.3.1.1 आस्तियां	53611	124564	-70953	74810	73041	1769
2.3.1.2 देयताएं	85848	98771	-12923	76881	78525	-1645
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	76699	62311	14387	63530	69328	-5798
2.3.2 अन्य	99	0	99	2545	0	2545
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	15	-15	0	15	-15
2.5 अन्य पूंजी	61787	64217	-2430	228416	89344	139073
3 भूल-चूक	**2791**	0	**2791**	**5500**	0	**5500**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**234814**	**-234814**	0	**231083**	**-231083**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	234814	-234814	0	231083	-231083

टिप्पणी: पीः प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	जुला.-सितं. 2020			जुला.-सितं. 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**150790**	**135515**	**15275**	**194275**	**203856**	**-9581**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**125384**	**119114**	**6270**	**166263**	**185101**	**-18838**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**75591**	**90407**	**-14816**	**104842**	**149265**	**-44423**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	75243	84319	-9076	104327	133243	-28916
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	348	0	348	515	0	515
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		6088	-6088		16022	-16022
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**49793**	**28707**	**21086**	**61421**	**35836**	**25585**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	68	11	56	75	16	59
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	35	204	-169	74	418	-345
1.अ.ख.3 परिवहन	5368	4759	609	7584	8181	-597
1.अ.ख.4 यात्रा	2138	2764	-626	2147	3919	-1772
1.अ.ख.5 निर्माण	589	563	26	716	715	0
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	590	537	53	796	575	220
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1003	1107	-104	1303	1463	-160
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	313	1456	-1143	202	2189	-1987
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	25515	3290	22225	30823	3651	27172
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	11624	12354	-730	13858	12457	1401
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	530	817	-287	713	1243	-530
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	144	190	-46	217	198	19
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	1875	655	1220	2915	811	2105
1.आप्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**4986**	**14391**	**-9405**	**6859**	**16546**	**-9688**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1445	696	749	1497	754	743
1.आ.2 निवेश आय	2753	13394	-10641	4349	15572	-11223
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1272	8131	-6859	1983	9630	-7647
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	49	2126	-2076	111	2859	-2748
1.आ.2.3 अन्य निवेश	78	3137	-3059	62	3082	-3020
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	1354	1	1353	2193	1	2193
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	788	301	487	1012	220	792
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**20419**	**2009**	**18410**	**21153**	**2209**	**18944**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	20385	1766	18619	21135	1924	19212
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण) 1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	19711	1287	18424	20237	1356	18881
1.इ.2 सामान्य सरकार	674	479	195	899	568	331
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	35	243	-209	18	285	-267
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	**109**	**198**	**-88**	**189**	**210**	**-20**
2.2 पूँजी अंतरण	8	100	-92	62	132	-71
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	101	97	4	128	77	50
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**144902**	**160464**	**-15562**	**209391**	**200531**	**8859**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	**30502**	**6077**	**24424**	**20447**	**10987**	**9461**
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	29527	2450	27078	19281	6475	12806
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	27911	2445	25466	18422	6259	12163
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	23794	2445	21350	13940	6259	7681
3.1.अ.2 ऋण लिखत	4117		4117	4482		4482
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1617	5	1611	859	216	643
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	1617	5	1611	859	216	643
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	974	3627	-2653	1167	4512	-3345
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	974	1955	-981	1167	2842	-1675
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	974	1202	-228	1167	2060	-894
3.1.आ.2 ऋण लिखत		753	-753		781	-781
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	1672	-1672		1670	-1670
3.2 संविभाग निवेश		1672	-1672		1670	-1670
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	**66794**	**59796**	**6998**	**111931**	**108054**	**3877**
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	66420	58684	7736	110448	105904	4544
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	55007	48183	6824	95335	94718	618
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	11413	10501	912	15112	11186	3926
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	375	1113	-738	1483	2150	-666
3.4 अन्य निवेश	**2858**	**3936**	**-1078**	**5367**	**5806**	**-439**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	**44749**	**59086**	**-14337**	**71646**	**44496**	**27150**
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	0	0	0	0	0	0
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	10325	8377	1948	8918	9357	-439
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	13	0	13	344	0	344
3.4.2.3 सामान्य सरकार	10311	8377	1934	8574	9357	-783
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र			0			
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)			0			
3.4.3अ भारत को ऋण	20421	35702	-15281	23433	17406	6026
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	19642	34677	-15035	23137	17128	6009
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	779	1025	-246	296	279	17
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	78	62	16	55	13	42
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	8662	10479	-1817	14021	11658	2364
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	5263	4466	797	7356	6062	1295
3.5 आरक्षित आस्तियां			0	17862		17862
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	**31568**	**-31568**	0	**31189**	**-31189**
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए			0			
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए			0		17862	-17862
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)			0			
4. कुल आस्तियां / देयताएं	0	31568	-31568	0	13326	-13326
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	**144902**	**160464**	**-15562**	**209391**	**200531**	**8859**
4.2 ऋण लिखत	87202	57694	29508	121829	111787	10042
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	52437	66736	-14299	62343	51494	10849
5. निवल भूल-चूक	5263	36034	-30771	25219	37251	-12032
6 Net errors and omissions	**375**		**375**	**742**		**742**

टिप्पणी: पीः प्रारंभिक

Note : P : Preliminary

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(करोड़ ₹)

मद	जुला.-सितं. 2020			जुला.-सितं. 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**1121609**	**1007991**	**113618**	**1439413**	**1510403**	**-70990**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**932637**	**886001**	**46635**	**1231868**	**1371442**	**-139574**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**562264**	**672468**	**-110205**	**776788**	**1105928**	**-329140**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	559675	627181	-67506	772976	987218	-214242
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	2588	0	2588	3812	0	3812
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	45287	-45287	0	118711	-118711
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**370373**	**213533**	**156840**	**455079**	**265514**	**189566**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	505	85	420	558	118	440
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	263	1519	-1256	546	3100	-2554
1.अ.ख.3 परिवहन	39926	35397	4528	56188	60613	-4425
1.अ.ख.4 यात्रा	15903	20559	-4657	15905	29037	-13132
1.अ.ख.5 निर्माण	4383	4186	197	5302	5299	3
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4385	3994	391	5896	4263	1633
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	7462	8233	-771	9652	10836	-1184
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	2330	10833	-8503	1499	16220	-14721
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	189787	24472	165315	228370	27051	201318
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	86464	91890	-5426	102675	92295	10380
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	3944	6078	-2135	5279	9207	-3928
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1074	1414	-339	1607	1467	141
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	13948	4871	9077	21601	6006	15595
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**37089**	**107046**	**-69956**	**50817**	**122594**	**-71777**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	10750	5178	5572	11092	5589	5503
1.आ.2 निवेश आय	20478	99630	-79152	32225	115376	-83151
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	9463	60481	-51018	14692	71350	-56658
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	366	15810	-15445	820	21184	-20364
1.आ.2.3 अन्य निवेश	579	23331	-22752	461	22836	-22375
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	10070	7	10063	16251	5	16246
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	5861	2238	3623	7500	1629	5871
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**151883**	**14944**	**136939**	**156729**	**16367**	**140361**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	151627	13134	138492	156596	14254	142342
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	146616	9573	137043	149936	10045	139891
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	5011	3561	1450	6659	4209	2451
1.इ.2 सामान्य सरकार	257	1810	-1553	133	2113	-1980
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**813**	**1471**	**-658**	**1402**	**1553**	**-151**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	62	747	-685	457	981	-524
2.2 पूँजी अंतरण	751	725	27	946	572	374
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**1077815**	**1193566**	**-115751**	**1551410**	**1485770**	**65641**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**226877**	**45202**	**181675**	**151499**	**81403**	**70095**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	219632	18223	201410	142854	47973	94880
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	207607	18184	189423	136490	46371	90119
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	176987	18184	158803	103281	46371	56909
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	30620	0	30620	33210	0	33210
3.1.अ.2 ऋण लिखत	12025	39	11987	6364	1602	4761
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	12025	39	11987	6364	1602	4761
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	7245	26980	-19735	8645	33430	-24785
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	7245	14543	-7298	8645	21055	-12410
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	7245	8940	-1695	8645	15265	-6620
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5603	-5603	0	5789	-5789
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	12437	-12437	0	12375	-12375
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	12437	-12437	0	12375	-12375
3.2 संविभाग निवेश	**496831**	**444780**	**52050**	**829315**	**800587**	**28729**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	494044	436504	57540	818325	784660	33664
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	409153	358396	50757	706356	701779	4577
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	84891	78108	6783	111968	82881	29087
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	2786	8276	-5490	10991	15927	-4936
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**21257**	**29276**	**-8019**	**39762**	**43017**	**-3256**
3.4 अन्य निवेश	**332850**	**439493**	**-106643**	**530835**	**329679**	**201155**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	76798	62311	14486	66075	69328	-3253
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	99	0	99	2545	0	2545
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	76699	62311	14387	63530	69328	-5798
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0			
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0			
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	151894	265558	-113664	173616	128967	44649
3.4.3अ भारत को ऋण	146100	257932	-111832	171423	126903	44520
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	5793	7626	-1833	2193	2064	128
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	580	462	117	405	97	308
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	64430	77945	-13515	103887	86375	17512
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	39149	33218	5932	54505	44912	9592
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	132346	0	132346
3.5 आरक्षित आस्तियां	**0**	**234814**	**-234814**	**0**	**231083**	**-231083**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0			
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	132346	-132346
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0			
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	234814	-234814	0	98737	-98737
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**1077815**	**1193566**	**-115751**	**1551410**	**1485770**	**65641**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	648628	429138	219490	902649	828246	74403
4.2 ऋण लिखत	390038	496397	-106359	461910	381529	80382
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	39149	268031	-228882	186851	275995	-89145
5. निवल भूल-चूक	**2791**	**0**	**2791**	**5500**	**0**	**5500**

टिप्पणी: पीः प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2020-21		2020		2021			
			सितं.		जून		सितं.	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	193929	482226	188243	455981	199440	493763	202785	506723
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	122726	456947	121267	430714	125397	467990	127072	480697
1.2 अन्य पूंजी	71203	25278	66976	25267	74043	25773	75713	26026
2 संविभाग निवेश	7936	274104	5041	244308	7912	272859	8578	276375
2.1 इक्विटी	2340	177278	1906	149095	3146	176203	4590	177034
2.2 ऋण	5596	96826	3136	95213	4766	96657	3988	99341
3 अन्य निवेश	80606	454253	64785	440252	76828	455000	80317	475775
3.1 व्यापार ऋण	5644	100337	2792	102187	7875	102117	11879	100267
3.2 ऋण	13335	197773	9038	189705	13622	197443	10131	201213
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	42436	143760	34864	138822	35904	143096	41102	142904
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	19191	12384	18092	9538	19427	12344	17205	31391
4 रिज़र्व्स	576984		544687		611075		635363	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	859454	1210583	802757	1140541	895254	1221622	927043	1258873
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-351129		-337784		-326368		-331830

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व 2020-21	2020	2021		विव 2020-21	2020	2021	
		दिसं.	नवं.	दिसं.		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)	27.97	2.62	2.56	3.13	161943141	15757032	17364381	20703988
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	11.55	1.00	0.97	1.10	110634315	10816866	12229072	14801512
1.1.1 आउटराईट	6.28	0.51	0.46	0.48	10032187	772886	617831	651103
1.1.2 रेपो	2.84	0.25	0.26	0.30	43751173	4089804	4273958	5075401
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	2.43	0.24	0.25	0.31	56850956	5954176	7337283	9075009
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	16.04	1.58	1.53	1.96	48903961	4651382	4816873	5516604
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	0.38	0.04	0.06	0.07	2404865	288785	318437	385873
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार आधार-संरचना (एफएमआई)	–	–	–	–	–	–	–	–
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	1591.92	163.48	172.14	192.78	105599849	10659120	10981778	12966991
1.1 ग्राहक लेनदेन	1573.47	161.72	170.95	191.50	91008367	9058136	9589985	11418233
1.2 इंटरबैंक लेनदेन	18.45	1.75	1.19	1.29	14591482	1600984	1391793	1548758
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	317867.59	31735.79	51855.52	56422.79	33504168	3393355	3552986	4076395
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	11.31	1.03	0.62	0.65	623	61	35	36
2.2 एपीबीएस $	14372.99	1018.90	1119.16	1082.20	111001	8180	9750	14987
2.3 आईएमपीएस	32783.47	3556.93	4120.29	–	2941500	292325	364672	–
2.4 एनएसीएच जमा $	16465.29	1741.20	1356.65	1483.71	1216477	118309	95602	113132
2.5 एनईएफटी	30927.89	3076.15	3394.00	3763.38	25130910	2558304	2314490	2724980
2.6 यूपीआई @	223306.64	22341.58	41864.80	45662.99	4103658	416176	768436	826848
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	10.45	0.88	1.00	1.12	172	14	15	16
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	10456.54	922.53	1031.91	1064.54	865520	81871	87212	91163
3.1 भीम आधार पे @	160.84	8.90	19.78	19.59	2580	187	536	611
3.2 एनएसीएच नामे $	9645.75	840.43	900.10	937.92	862027	81576	86517	90426
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	649.96	73.21	112.03	107.03	913	108	158	126
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	57786.60	5502.88	5418.21	5701.80	1291799	128665	156325	161498
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	17641.06	1737.79	2011.16	2112.59	630414	63487	89217	93907
4.1.1 पीओएस आधारित $	8688.81	914.20	1068.93	1093.48	280769	28961	37499	36713
4.1.2 अन्य $	8952.25	823.59	942.23	1019.10	349645	34526	51718	57195
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	40145.54	3765.09	3407.02	3589.21	661385	65178	67109	67591
4.2.1 पीओएस आधारित $	20773.50	2165.50	2112.05	2292.51	377630	39437	43751	44162
4.2.2 अन्य $	19372.04	1599.59	1294.97	1296.71	283755	25741	23358	23429
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	49742.55	4372.11	6107.23	7008.24	197696	18153	25583	26896
5.1 वालेट	39987.01	3521.48	4870.19	5661.02	152065	13392	21041	21220
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	9755.54	850.63	1237.04	1347.22	45631	4761	4542	5676
5.2.1 पीओएस आधारित $	607.15	58.15	74.48	99.63	10690	1107	1287	1893
5.2.2 अन्य $	9148.39	792.48	1162.56	1247.59	34941	3654	3255	3784
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6703.70	719.40	577.00	660.33	5627190	618015	533223	640955
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6702.54	719.40	577.00	660.33	5625941	618015	533223	640955
6.2 अन्य	1.17	–	–	–	1249	–	–	–
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	442557.14	43252.72	64989.85	70857.70	41486430	4240059	4355329	4996908
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	444149.06	43416.20	65161.98	71050.48	147086278	14899180	15337107	17963898
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	437445.36	42696.80	64584.98	70390.15	141459089	14281164	14803884	17322943

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2020-21	2020	2021		वि. व. 2020-21	2020	2021	
		दिसं.	नवं.	दिसं.		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	258033.70	25296.64	45548.53	49881.01	9201212	901655	1324008	1433624
1.1 इंट्रा-बैंक $	25220.71	2183.03	3732.97	3927.18	1871390	174603	239989	254442
1.2 इंटर-बैंक $	232812.99	23113.62	41815.57	45953.83	7329822	727052	1084018	1179182
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	32493.63	3147.85	2860.67	3102.24	41581497	4079472	3937877	4530694
2.1 इंट्रा-बैंक @	6886.15	637.64	570.26	611.14	20601554	1934396	1788978	2082236
2.2 इंटर-बैंक @	25607.48	2510.20	2290.41	2491.10	20979943	2145077	2148899	2448458
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	60905.81	5680.37	5691.73	5928.20	2889826	266709	271730	280372
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना $	51.41	5.01	5.45	5.90	2560	246	276	295
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	60602.23	5650.86	5657.83	5893.54	2878025	265569	270515	279100
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	252.17	24.51	28.44	28.76	9240	893	939	977
4 पीओएस पर नकद निकासी $ (4.1 से 4.2)	394.77	39.89	4.82	3.89	1533	149	63	42
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	353.50	34.53	4.14	3.71	1484	142	39	35
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	41.27	5.37	0.68	0.18	49	6	24	7
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	9460.43	715.03	925.63	940.20	225420	19671	25112	25208
5.1 एईपीएस @	9460.43	715.03	925.63	940.20	225420	19671	25112	25208

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2021 तक	2020	2021	
		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	9602.51	9460.57	10015.90	10066.90
1.1 क्रेडिट कार्ड	620.49	603.97	675.83	689.49
1.2 डेबिट कार्ड	8982.02	8856.60	9340.07	9377.42
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	21952.60	20819.05	25918.94	26426.15
2.1 वालेट @	20052.10	19156.35	23408.81	23828.54
2.2 कार्ड @	1900.51	1662.70	2510.13	2597.62
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.39	2.33	2.42	2.41
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम $	2.14	2.08	2.13	2.11
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम $	0.25	0.25	0.29	0.30
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	4.04	3.56	5.57	5.91
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	47.20	45.85	52.92	54.98
6 भारत क्यूआर @	35.70	32.00	45.41	46.47
7 यूपीआई क्यूआर *	925.22	752.31	1373.33	1440.10

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड़ शामिल है।

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिल दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक श्रृंखला

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2019-20	2020		2021	
			फर.	दिसं.	जन.	फर.
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	**प्राप्तियां**	**159573**	**16911**	**16781**	**14261**	**14405**
	बकाया	**1078535**	**1046766**	**1196084**	**1210379**	**1224772**
1.1 कुल जमाराशियां	**प्राप्तियां**	**116389**	**11460**	**12407**	**9820**	**10143**
	बकाया	**734807**	**716363**	**827156**	**836976**	**847119**
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	25893	2690	3307	2049	2252
	बकाया	166140	156258	190437	192486	194738
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	36	-20	-21	-26	-23
	बकाया	3143	2939	3086	3060	3037
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	-1	-3	-3	0	57
	बकाया	9	-23	-17	-17	40
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	16510	1887	1053	1162	1135
	बकाया	209168	207059	217980	219142	220277
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	20334	2131	2014	1886	1950
	बकाया	76042	73728	90914	92800	94750
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	41795	4494	4330	3952	3798
	बकाया	166087	161115	195847	199799	203597
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	92618	90327	104601	105928	107099
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7097	6970	7324	7375	7418
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7536	7464	7330	7285	7267
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	58836	56354	76592	79211	81813
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	11821	281	1727	797	974
	बकाया	114222	115291	128912	129709	130683
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	1	0	0	0	0
	बकाया	-25	-25	-24	-24	-24
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	21	21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	**प्राप्तियां**	**30170**	**3937**	**3941**	**3909**	**3647**
	बकाया	**252190**	**248022**	**274905**	**278848**	**282483**
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	19495	2619	1923	1903	1843
	बकाया	117987	115127	129270	131173	133016
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	-101	1	-1	-1	0
	बकाया	162	-288	158	157	157
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-18168	-1120	-669	-603	-470
	बकाया	1135	3949	-5121	-5724	-6194
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	28972	2452	2677	2610	2274
	बकाया	122602	118507	140538	143148	145422
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	-4	0	8	0	0
	बकाया	-155	-180	-147	-147	-147
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-24	-15	3	0	0
	बकाया	-106	-99	-103	-103	-103
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	10565	11006	10310	10344	10332
1.3 लोक भविष्य निधि	**प्राप्तियां**	**13014**	**1514**	**433**	**532**	**615**
	बकाया	**91538**	**82381**	**94023**	**94555**	**95170**

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।
टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियाँ हैं। अर्थात सकल प्राप्तियाँ माइनस सकल भुगतान

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2020		2021		
	सितं.	दिसं.	मार्च	जन.	सितं.
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	**7137069**	**7357111**	**7635902**	**7882533**	**8235318**
1. वाणिज्य बैंक	38.55	37.81	37.77	35.99	37.82
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.34	0.25	0.27	0.34	0.35
3. बीमाकृत कंपनियां	25.33	25.64	25.30	25.83	24.18
4. म्यूच्युअल फंड	2.42	2.62	2.94	2.82	2.91
5. सहकारी बैंक	1.86	1.83	1.82	1.82	1.50
6. वित्तीय संस्थाएं	1.42	1.00	1.00	1.43	1.17
7. कॉरपोरेट	0.94	1.05	1.06	1.39	0.72
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	2.05	2.10	1.87	1.79	1.81
9. भविष्य निधियां	4.77	4.61	4.44	4.04	3.77
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	15.00	15.71	16.20	17.11	16.98
11. अन्य	7.32	7.37	7.33	7.43	8.79
11.1 राज्य सरकार	1.86	1.76	1.69	1.67	1.67

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2020		2021		
	सितं.	दिसं.	मार्च	जन.	सितं.
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	**3564979**	**3721573**	**3879982**	**4028849**	**4153508**
1. वाणिज्य बैंक	34.60	34.19	33.69	33.75	35.94
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.54	0.36	0.48	0.39	0.44
3. बीमाकृत कंपनियां	30.26	30.25	30.04	29.67	27.50
4. म्यूच्युअल फंड	1.96	1.92	1.82	1.74	1.97
5. सहकारी बैंक	4.19	4.11	4.05	4.12	3.60
6. वित्तीय संस्थाएं	1.92	1.88	1.86	1.79	1.72
7. कॉरपोरेट	0.39	0.45	0.49	1.45	1.32
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
9. भविष्य निधियां	21.31	21.20	22.00	21.09	18.27
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.81	0.77	0.88	0.85
11. अन्य	4.80	4.82	4.77	5.10	8.38
11.1 राज्य सरकार	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18

खज़ाना बिल					
श्रेणी	2020		2021		
	सितं.	दिसं.	मार्च	जन.	सितं.
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	**982286**	**839729**	**690646**	**901327**	**763582**
1. वाणिज्य बैंक	53.50	54.75	55.54	52.25	50.22
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	2.16	1.65	2.82	1.82	1.33
3. बीमाकृत कंपनियां	4.06	4.50	5.61	4.75	4.12
4. म्यूच्युअल फंड	19.90	18.98	17.80	19.93	17.72
5. सहकारी बैंक	1.63	1.61	2.43	1.60	1.32
6. वित्तीय संस्थाएं	1.34	1.11	1.24	2.56	2.12
7. कॉरपोरेट	1.63	2.01	3.16	3.00	2.40
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
9. भविष्य निधियां	0.00	0.09	0.22	0.10	0.37
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	4.80	0.68	0.49	2.58	2.63
11. अन्य	10.99	14.63	10.70	11.42	17.62
11.1 राज्य सरकार	7.76	13.27	5.98	7.97	12.64

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (सं.अ.)	2021-22 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	**4265969**	**4515946**	**5040747**	**5410887**	**6523916**	**7160694**
1.1 गतिविधियां	2537905	2635110	2882758	3074492	3906147	4254004
1.1.1 राजस्व	1878417	2029044	2224367	2446605	3259401	3242247
1.1.2 पूंजी	501213	519356	596774	588233	636062	922982
1.1.3 ऋण	158275	86710	61617	39654	10684	88775
1.2 गैर गतिविधियां	1672646	1812455	2078276	2253027	2526514	2810847
1.2.1 राजस्व	1555239	1741432	1965907	2109629	2334608	2602289
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	724448	814757	894520	955801	1082302	1244457
1.2.2 पूंजी	115775	69370	111029	141457	189487	177328
1.2.3 ऋण	1632	1654	1340	1941	2419	31230
1.3 अन्य	55417	68381	79713	83368	91255	95843
2. कुल प्राप्तियां	**4288432**	**4528422**	**5023352**	**5734166**	**6489736**	**7039032**
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3132201	3376416	3797731	3851563	3834126	4682025
2.1.1 कर प्राप्तियां	2622145	2978134	3278947	3231582	3175594	3829889
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1652377	1853859	2030050	2012578	2100982	2514708
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	965622	1121189	1246083	1216203	1071552	1311449
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	4146	3086	2814	2800	3060	3732
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	510056	398282	518783	619981	658532	852135
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	33220	34224	36273	31137	39830	33198
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	69063	142433	140287	110094	54861	201138
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	20942	42213	44667	59515	21151	19581
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	48122	100219	95621	50578	33710	181557
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	**1064704**	**997097**	**1102729**	**1449230**	**2634928**	**2277532**
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	1046708	989167	1097210	1440548	2580406	2276017
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	617123	144792	387091	571872	890012	-----
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	195816	-144847	325987	190241	107494	-----
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	429585	844375	710119	868676	1690394	-----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	17997	7931	5519	8682	54522	1514
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	1046708	989167	1097210	1440548	2580406	2276017
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	689821	794856	795845	971378	1778062	1620936
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	35038	71222	88961	209232	455724	367863
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	45688	42351	51004	38280	47300	45504
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-6436	18423	-18298	10411	-3450	5051
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	17792	25138	66289	-14227	29050	28868
3ख.1.6 नकद शेष	-22463	-12476	17395	-323279	34179	121663
3ख.1.7 अन्य	287268	49653	96014	548753	239540	86132
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	17997	7931	5519	8682	54522	1514
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	*27.7*	*26.4*	*26.7*	*26.6*	*33.0*	*32.1*
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	*27.9*	*26.5*	*26.6*	*28.2*	*32.9*	*31.6*
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	*20.3*	*19.8*	*20.1*	*18.9*	*19.4*	*21.0*
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	*17.0*	*17.4*	*17.4*	*15.9*	*16.1*	*17.2*
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	*6.9*	*5.8*	*5.8*	*7.1*	*13.3*	*10.2*

…: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बज़ट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	दिसंबर 2021 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	615	29	1996	29	1493	19
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	107	13	75	12	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	1316	23	1013	17
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	-	-	-	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	-	-	307	31	202	28
17	मेघालय	118	9	280	9	197	9
18	मिज़ोरम	-	-	139	23	-	-
19	नगालैंड	103	23	252	18	79	8
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	198	1	-	-	-	-
23	राजस्थान	1274	28	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	560	28	759	24	-	-
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	दिसंबर 2021 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खज़ाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	9131	899	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1959	3	--	-
3	असम	3971	60	--	-
4	बिहार	6168	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	5307	--	1	4300
6	गोवा	674	341	--	-
7	गुजरात	6926	528	--	2000
8	हरियाणा	856	1335	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	2500
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखंड	496	--	--	-
12	कर्नाटक	7378	--	--	38500
13	केरल	2362	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	1011	--	-
15	महाराष्ट्र	48889	909	--	25000
16	मणिपुर	170	111	--	-
17	मेघालय	799	46	9	-
18	मिज़ोरम	387	52	--	-
19	नगालैंड	1816	37	--	-
20	उड़ीसा	12367	1605	93	36273
21	पुदुचेरी	338	--	--	1280
22	पंजाब	2017	--	8	-
23	राजस्थान	--	--	129	5200
24	तमिलनाडु	7323	--	40	15165
25	तेलंगाना	6250	1359	--	-
26	त्रिपुरा	573	10	--	900
27	उत्तराखंड	1020	--	180	-
28	उत्तरप्रदेश	3798	150	--	-
29	पश्चिम बंगाल	9912	689	214	-
	कुल	**140885**	**9143**	**673**	**131118**

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22						2021 -22 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
						अक्टूबर		नवंबर		दिसंबर			
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल	निवल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	42415	33444	50896	41915	5000	3840	2000	840	3250	3250	36000	27989
2	अरुणाचल प्रदेश	1366	1287	767	767	-	-	-	-	-	-	400	400
3	असम	12906	10996	15030	14230	1600	1600	1000	500	2800	1800	9300	7800
4	बिहार	25601	22601	27285	24685	4000	3000	4000	4000	3000	2281	23000	21281
5	छत्तीसगढ़	11680	10980	13000	10500	2000	1500	-	-1000	-	-	4000	2500
6	गोवा	2600	2000	3354	3054	100	100	100	-100	400	300	1700	1200
7	गुजरात	38900	28600	44780	33280	5554	3554	-	-1000	-	-1500	17554	6054
8	हरियाणा	24677	20677	30000	25550	3000	2500	-	-500	-	-	16500	12200
9	हिमाचल प्रदेश	6580	4460	6000	3755	-	-100	2000	1795	1000	800	4000	3495
10	जम्मू और कश्मीर	7869	6760	9328	6020	-	-	400	225	1800	1100	6400	4825
11	झारखंड	7500	5656	9400	8900	1000	500	-	-	-	-	1500	500
12	कर्नाटक	48500	42500	69000	61900	6000	6000	4000	2500	12000	9500	22000	18000
13	केरल	18073	12617	28566	23066	2000	1000	-	-	1000	-1000	20000	15000
14	मध्य प्रदेश	22371	16550	45573	38773	2000	-1000	4000	4000	-	-	14000	11000
15	महाराष्ट्र	48498	32998	69000	50022	2500	-1000	3000	3000	3000	1000	54750	42750
16	मणिपुर	1757	1254	1302	1044	140	90	200	200	90	90	1177	1027
17	मेघालय	1344	1070	1777	1587	200	140	-	-50	328	328	1328	1118
18	मिज़ोरम	900	745	944	677	104	104	-	-	-	-	434	184
19	नगालैंड	1000	423	1721	1366	89	89	-	-	298	148	1287	1037
20	उड़ीसा	7500	6500	3000	500	-	-1000	-	-500	-	-473	-	-3973
21	पुदुचेरी	970	470	1390	790	-	-	125	125	250	250	499	499
22	पंजाब	27355	18470	32995	23467	1162	862	-	-500	1500	1150	13782	3682
23	राजस्थान	39092	24686	57359	44273	5000	3730	1500	617	3669	2669	35769	28304
24	सिक्किम	809	481	1292	1292	-	-	-	-	177	137	928	888
25	तमिलनाडु	62425	49826	87977	76796	4000	2740	4000	2260	5000	5000	52000	45000
26	तेलंगाना	37109	30697	43784	37365	1500	660	3000	2160	5500	5500	33500	27711
27	त्रिपुरा	2928	2578	1916	1631	-	-	-	-	-	-	300	150
28	उत्तराखंड	69703	52744	75500	59185	7500	5524	5000	2513	5000	2922	45000	29713
29	उत्तरप्रदेश	5100	4500	6200	5208	-	-	-	-	500	350	1700	700
30	पश्चिम बंगाल	56992	40882	59680	50180	5000	3500	3500	2500	9500	6950	47500	28777
	कुल	634521	487454	798816	651777	59449	37934	37825	23585	60062	42552	466308	339811

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।

3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।

4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।

4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।

4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।

4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।

7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।

2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

http://nsdp.rbi.org.in के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्वर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्ज़िम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकडे सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।

2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम$_2$ और एनएम$_3$ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।

2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।

2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थांओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।

एल$_1$ और एल$_2$ मासिक आधार पर और एल$_3$ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।

जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकडें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकडें अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकडें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अतंरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी सस्थांओं/शाखाओं के बीच के ऋण सबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ो से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का सकेंतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2018-19 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -
   - बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल है।
   - जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए है, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया हैं।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 29 मई 2020 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2020-21 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बज़ट 2020-21 से लिया गया है।
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।
1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुन:चुकौती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकौती से संबंधित है।
1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।
2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।
3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।
3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।
3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।
यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।
3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।
3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।
राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।
प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।
-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।
नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारो में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।
--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (**https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618**) में उपलब्ध हैं।

'वर्तमान सांख्यिकी' का टाइम सीरिज डाटा https://dbie.rbi.org.in पर उपलब्ध है।
विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2022	₹350 एक प्रति (कांउटर पर) ₹400 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,800 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,600 (एक वर्ष रियायती दर*) ₹3,840 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित@) ₹2,880 (एक वर्ष रियायती दर@)	15 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंडबुक 2020-21	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक 2020-21	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2020-21 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (कांउटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकांउट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (कांउटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (कांउटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (कांउटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (कांउटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 2, 2019	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 1, 2020	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 2, 2020	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (कांउटर पर)	50 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (http://dbie.rbi.org.in)।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।

* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

@ इलेक्ट्रानिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते है, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेशः

1. बिकी हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमि क और शैक्षिक सस्थांओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अकं उपलब्ध नहीं है।
4. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण (सोमवार से शुक्रवार) तक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंज़िल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मंबुई - 400 001 में किया जाएगा। बिक्री अनुभाग का सपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेलः spsdepr@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रेषणपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंज़िल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मंबुई - 400 001।

   एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैंक
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम.......... अभिदाता सं...........

6. प्रकाशनों को शीघ्रातिशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' **2 महीने के अंदर भेजी जाए।**
7. **कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdepr@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।**